

दूसरी आज़ादी

ફૂંસરી આખાદી

રામકુમા મલે

दूसरी आज़ादी

इस पुस्तक के बारे में

इतिहास का चक्र कायदे में चलना तो यो चाहिए था कि राजनीतिक आजादी के बाद आर्थिक व सामाजिक आजादी का सपना साकार होता, लेकिन राजनीतिक आजादी के बाद निहित स्वार्थ के लोग सत्ता के आम-भाग मोलबन्द होते गए। यथास्थितिवाद और उनके निहित स्वार्थ का रिश्ता धीरे-धीरे अटूट होता चला गया। तथा परिवर्तनवादी घोषणाओं और नारों का लक्ष्य यथास्थितिवाद की रक्षा करना-भाँझ बना रह गया। धीरे-धीरे स्वातंत्र्यपूर्व की चेतना बुझ गई। तेजस्वी, सेवाभावी और कर्मठ लोग सत्तालोलुप, स्वार्थी और कैरियरिस्ट राजनेताओं द्वारा किनारे फेंक दिए गए। समाज-जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जड़ता की जकड़न व्याप्त हो गई।

इसी पृष्ठभूमि में लोकनायक श्री जयप्रकाश ने समग्र प्राति का दर्शन दिया। तरणाई परिवर्तन का परचम लेकर लोक-समर्प के रास्ते पर बढ चली। यथास्थितिवाद के अजय दुर्ग टूटने को आ गए। इस पृष्ठभूमि में यथास्थितिवाद के रक्षक संयुक्त मोर्चे ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में आपातस्थिति लगाकर लाखों नेताओं, कार्यकर्ताओं और मर्षों में लगे लोगों को जेलों में बन्द कर नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन कर डाला। पारिवारिक तानाशाही अपने नग्न रूप में सामने आई। नतीजा यह हुआ कि हमें आजादी की लड़ाई एक दूसरे रूप में फिर से लड़नी पड़ी।

लोकनायक श्री जयप्रकाश के नेतृत्व, लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग व बलिदान और देश के निरक्षर से निरक्षर समाज की सुशिक्षित चेतना के कारण तानाशाही पराजित हुई। उसमें बाबू जगजीवनरामजी का योगदान भी उल्लेखनीय है।

यह सही है कि सामान्य जन, बुद्धिजीवी और गैर-काग्रेसी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को भीषण यातनाएँ भुगतनी पड़ी लेकिन मुझे लगता है कि इतने महान परिवर्तन के लिए चुकाया गया यह मूल्य अधिक नहीं था। इस विराट्

परिवर्तन की यह सामान्य कीमत ? ... निश्चय ही अपने देश के समाज-जीवन में कोई तर्कातीत तर्क (Super logic) कार्यरत रहा है। देश के प्रतिभाशाली लेखकों की ओर मैं इस आशा से देखा करता हूँ कि वे इस 'सुपरलॉजिक' की चोरफाड़ अपनी लेखनी से करें।

लेखनी राजनीति की मुखापेक्षी न हो, साहित्यकार राजनीति के कृपाकांक्षी न बनें, पत्रकार निर्भीक टीका-टिप्पणी करने के काम में किसी 'कमजोरी' या संकोच को कारण न बनने दें तभी इस युगान्तरकारी परिवर्तन की महत् संभावनाओं को साकार रूप दिया जा सकता है। वरना आप जानते हैं कि राज-नेता किस मिट्टी के बने होते हैं, कुर्सी उन्हें कैसे कैदी बना देती है, बाह-बाह के नारे क्रमशः कैसे ढोंगी होते जाते हैं, न्यस्त स्वार्थों की घेराबन्दी कितनी ताकत-वर होती जाती है।

श्री रामकुमार भ्रमर से मेरी भेंट पहली बार प्रिय श्री दीनानाथ (संपादक 'पांचजन्य') के यहां १९७०-७१ में हुई थी। बातचीत के दौरान मैंने पाया था कि भ्रमर स्वतंत्रचेता लेखक हैं और उस समय में जबकि अधिकतर बुद्धि-जीवी सत्ता की कृपाकांक्षा से सत्य की प्राप्ति के लिए होने वाले संपर्क का स्वर दबाए हुए थे, भ्रमर काफी स्पष्टवादी लगे। वाद में उनकी कई कृतियां मेरे देखने-पढ़ने में आईं और मुझे अच्छा लगा कि वे देश-समाज के प्रति जागरूक और सतर्क रहकर सोचते-लिखते हैं।

यह हो सकता है कि 'दूसरी आज़ादी' में श्री रामकुमार भ्रमर के विश्लेषण से मैं कहीं, किसी-किसी जगह सहमत न होऊँ, लेकिन मोटे तौर पर इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मैं श्री भ्रमर के दृष्टिकोण से समानुभूति महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी देश का साहित्यकार उस देश के समाज, संस्कृति और विचारों का इतिहासलेखन ही नहीं करता, भविष्य-द्रष्टा भी होता है। वह गुण-दोषों का विवेचन करता है और सत्य का सनातन प्रहरी होता है। शाश्वत मानवीय मूल्यों का रखवाला भी।

पिछले तीस वर्षों के ही नहीं, बल्कि इस सम्पूर्ण शताब्दी के इतिहास में आपातस्थिति के ये २० महीने अनहोनी घटनाओं से इतने लदे-बदे रहे हैं और इसने भारत के सामान्य जीवन और सोच-समझ में इतना युगान्तरकारी परिवर्तन किया है कि साहित्य, इतिहास, दर्शन और समाजशास्त्र के अनमोल ग्रन्थों की क्रान्तिकारी लहर पैदा हो सकती है। मुझे विश्वास है कि इस दृष्टि से भ्रमरजी की तरह अन्य स्वतंत्रचेता लेखक भी रचनाएं देंगे।

७ अप्रैल, १९७७

नई दिल्ली

—नाना देशमुख

लेखकीय

२६ जून, १९७५ ! एक ऐसा दिन, जब स्वतंत्रता के मूरज पर गुलामी की कानिष्ठ पोत दी गई। किन्ने की यह मुस्माखी ? हमारे अपनों ने और अपनों के दिए दर्द में ज्यादा तकलीफदेह कुछ नहीं होता। सारे देश ने यह दर्द भोगा है और लोकनायक जयप्रकाशजी के नेतृत्व में अहिंसात्मक शिष्ट प्रान्ति से इसका उपचार भी कर लिया है, किन्तु यह कमफ कभी नहीं जाएगी और इतिहास का एक पट्टा स्मरण बनी रहेगी।

जयप्रकाशजी के बिहार-आन्दोलन ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रजातंत्र की आठ में धीमे-धीमे देश को घन रहे राजतंत्र की चेतावनी दी थी और इस चेतावनी तथा पूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन ने युवा-शक्ति को संगठित रूप में संघर्ष की रक्षा के लिए मजबूत किया था। परिणाम हुआ राजतंत्र का मुछौटा उलट जाना और उसके निनात व्यक्तिवादी धिनीने रूप का उजागर होना। यह रूप था—दमरजेंगी।

इन दमरजेंगी ने भारतीय इतिहास को कुछ नारे दिए, नये अर्थ दिए। दमरजेंगी में साधारण देश की गरीबी और जन-शान्ति को नाम दिया गया—अनुशासन। मानसिक और धैर्यारिक हत्याओं को प्रचारित किया गया—प्रशासन। निर्माण के नाम पर व्याप्त नये भ्रष्टाचार का अर्थ हो गया—मत्ता। द्यूरोजेंगी कहलार्ड—व्यवस्था। तानाशाही का अर्थ हुआ—लोकतंत्र। कुमियों के मोह का नाम हुआ देश का आपातकाल। मन्दी की यह नई और दुष्ट परिभाषा जून १९७५ में लागू हुई और इस परिभाषा को मनवाने का वम घला पूरे बीस माह।

मुझे एक घटना याद आती है, बड़ी माघारण-भी घटना है, किन्तु लगता है कि योग माहों की भयानक उत्पादन-भरी गुलामी की भूमिका में यह घटना आज अचानक महत्वपूर्ण हो उठी है। लगता है जैसे उन समय के आने के पूर्व ही

परिवर्तन की यह सामान्य कीमत ? ...निश्चय ही अपने देश के समाज-जीवन में कोई तर्कातीत तर्क (Super logic) कार्यरत रहा है। देश के प्रतिभाशाली लेखकों की ओर मैं इस आशा से देखा करता हूँ कि वे इस 'सुपरलॉजिक' की चोरफाड़ अपनी लेखनी से करें।

लेखनी राजनीति की मुखापेक्षी न हो, साहित्यकार राजनीति के कृपाकांक्षी न बनें, पत्रकार निर्भीक टीका-टिप्पणी करने के काम में किसी 'कमजोरी' या संकोच को कारण न बनने दें तभी इस युगान्तरकारी परिवर्तन की महत् संभावनाओं को साकार रूप दिया जा सकता है। वरना आप जानते हैं कि राज-नेता किस मिट्टी के बने होते हैं, कुर्सी उन्हें कैसे कैदी बना देती है, वाह-वाह के नारे क्रमशः कैसे ढोंगी होते जाते हैं, न्यस्त स्वार्थों की घेराबन्दी कितनी ताकत-वर होती जाती है।

श्री रामकुमार भ्रमर से मेरी भेंट पहली बार प्रिय श्री दीनानाथ (संपादक 'पांचजन्य') के यहां १९७०-७१ में हुई थी। बातचीत के दौरान मैंने पाया था कि भ्रमर स्वतंत्रचेता लेखक हैं और उस समय में जबकि अधिकतर बुद्धि-जीवी सत्ता की कृपाकांक्षा से सत्य की प्राप्ति के लिए होने वाले संपर्प का स्वर दबाए हुए थे, भ्रमर काफी स्पष्टवादी लगे। वाद में उनकी कई कृतियां मेरे देखने-पढ़ने में आईं और मुझे अच्छा लगा कि वे देश-समाज के प्रति जागरूक और सतर्क रहकर सोचते-लिखते हैं।

यह हो सकता है कि 'दूसरी आज़ादी' में श्री रामकुमार भ्रमर के विश्लेषण से मैं कहीं, किसी-किसी जगह सहमत न होऊँ, लेकिन मोटे तौर पर इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान मैं श्री भ्रमर के दृष्टिकोण से समानुभूति महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी देश का साहित्यकार उस देश के समाज, संस्कृति और विचारों का इतिहासलेखन ही नहीं करता, भविष्य-द्रष्टा भी होता है। वह गुण-दोषों का विवेचन करता है और सत्य का सनातन प्रहरी होता है। शाश्वत मानवीय मूल्यों का रखवाला भी।

पिछले तीस वर्षों के ही नहीं, बल्कि इस सम्पूर्ण शताब्दी के इतिहास में आपातस्थिति के ये २० महीने अनहोनी घटनाओं से इतने लदे-बदे रहे हैं और इसने भारत के सामान्य जीवन और सोच-समझ में इतना युगान्तरकारी परिवर्तन किया है कि साहित्य, इतिहास, दर्शन और समाजशास्त्र के अनमोल ग्रन्थों की प्रान्तिकारी लहर पैदा हो सकती है। मुझे विश्वास है कि इस दृष्टि से भ्रमरजी की तरह अन्य स्वतंत्रचेता लेखक भी रचनाएं देंगे।

लेखकीय

२६ जून, १९७५ ! एक ऐसा दिन, जब स्वतंत्रता के मूरज पर गुलामी की अग्निच पोल दी गई । किसने की यह गुस्ताखी ? हमारे अपनों ने और अपनों के लिए दंड में ज्यादा तकरतीफदेह कुछ नहीं होता । सारे देश ने यह दंड भोगा है और लोकनायक जयप्रकाशजी के नेतृत्व में अहिंसात्मक शिष्ट शान्ति से इन्का उपचार भी कर लिया है, किन्तु यह कसक कभी नहीं जाएगी और इतिहास का एक कटु स्मरण बनी रहेगी ।

जयप्रकाशजी के बिहार-आन्दोलन ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार राजतंत्र की आड़ में धीमे-धीमे देश को घम रहे राजतंत्र की चेतावनी दी दी और इन चेतावनी तथा पूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन ने युवा-शक्ति को संगठित रूप में राजतंत्र की रक्षा के लिए मजबूत किया था । परिणाम हुआ राजतंत्र का कुदृष्ट उगट जाना और उसके नितात व्यक्तिवादी धिनौने रूप का उद्धार होना । यह रूप था—इमरजेंसी ।

इम इमरजेंसी ने भारतीय इतिहास को कुछ नारे दिए, नये दंड दिए । इमरजेंसी में लाघार देश की गरीबी और जन-शान्ति को नाम दिया—अनुशासन । मानसिक और वैचारिक हत्याओं को प्रचारित किया गया—अनुशासन निर्माण के नाम पर व्याप्त नंगे भ्रष्टाचार का अर्थ हो गया—मना । इमरजेंसी कहलाई—व्यवस्था । सानाशाही का अर्थ हुआ—लोकतंत्र । कुदृष्टि के अर्थ का नाम हुआ देश का आपातकाल । शब्दों की यह नई और दुष्ट शक्ति २६ जून १९७५ में लागू हुई और इस परिभाषा को मनवाने का श्रम २१ जून बीस माह ।

मुझे एक घटना याद आती है, बड़ी साधारण-सी घटना है, किन्तु घटना के कि बीस माहों की भयानक उत्पीड़न-भरी गुलामी की भूमिका में यह घटना अत्यंत अचानक महत्वपूर्ण हो उठी है । सगता है जैसे उस समय के आने के दृष्टि में

बहुत हद तक यह संकेत मिलने लगा था कि सत्ता का राजतंत्री मुखौटा किसी भी स्तर पर उतरकर कुर्सी-रखा प्रारंभ कर देगा। दो-चार राजनीतिक मित्रों से चर्चा भी की थी कि संभवतः इन्दिरा-शासन उस स्तर पर आ सकता है, किन्तु उन मित्रों का विचार था कि वैसा नहीं होगा।

१९७५ प्रारंभ या '७४ के अंत की बात है, मुझे ग्वालियर में विद्यार्थी परिपद् के संभागीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। जयप्रकाशजी का आन्दोलन काफी कुछ जोर पकड़ चुका था और सारे देश में ही युवा-शक्ति जाग्रत हो चुकी थी। उसी दौर की बात है। विद्यार्थी परिपद् के युवक दोस्तों से अपनी भाषणनुमा बातचीत में मैंने कहा कि सत्य और लोकतंत्र के लिए सन्नद्ध होकर सभीको जयप्रकाश बाबू के आन्दोलन का अंश बनना चाहिए और अपनी क्रियात्मक शक्ति को पूर्ण अनुशासन, निष्ठा और अहिंसात्मक ढंग से आन्दोलन में जोड़कर सत्ता-परिवर्तन की मांग करनी चाहिए। सहज भाव से मन की बातें कहकर मैं घर चला आया। लगभग एक घण्टे बाद ही एक उच्चाधिकारी (जिलास्तर) का बुलावा आ पहुंचा। यह सज्जन मेरी पुस्तकों के पाठक भी थे और उनसे मेरे खासे पारिवारिक सम्बन्ध भी थे। जब वहां पहुंचा तो देखा वे काफी गंभीर हैं। वे बोले कि बैठें। चाय का आर्डर देकर कुछ सोचते हुए उन्होंने बात शुरू की, "सुना है, आप अभी-अभी विद्यार्थी परिपद् के फंक्शन में गए थे?"

"गया तो था।" मैं बोला, पर चकित हुआ। यह तो कोई कारण नहीं हुआ बुलावे का? सोच ही रहा था कि उनका दूसरा प्रश्न आ गिरा, 'खबर है कि आपने वहां लड़कों को भड़काया है?"

मैं हैरान। पूछा, "भड़काया है? वह किस तरह?"

"यही कि जयप्रकाशजी के आन्दोलन में हिस्सा लो, तोड़फोड़ करो, ऊधम मचाओ..."

मुझे झल्लाहट आ गई, "किसीने आपको गलत-सलत बतलाया है। मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि लोकतंत्र के लिए अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग लेना चाहिए! और यह सभीका लोकतंत्रीय अधिकार है। आप बिलकुल उलटी बात कर रहे हैं!"

वह सहज हुए, "देखिए रामकुमारजी, आप हैं लेखक। इस शहर में आपको रहना है। मुना है कि जल्दी ही आप अपनी फिल्म की शूटिंग भी यहीं—

वहीं करनेवाले हैं, आपको उसमें शासन की सहायता भी चाहिएगी...और अगर आपका यही ऐटीट्यूड रहा तो—”

“तो आप मुझे बोर करेंगे...यही ना ?” मैंने चिढ़कर कहा ।

“नहीं, ऐसी बात नहीं है —” वह बोलते-बोलते कुछ हिनके, “अमन में मैं किसी किम्म की खुराफात नहीं चाहता —”

“आप लोकतंत्री नागरिक-अधिकार को खुराफात कह रहे हैं ?...” मैं पचासा ही झुझना गया । महमा मैंने गवाय किया, “मच कहिए मिन्टर...” वह आप कह रहे हैं या आपकी भोकरी...मेरा मतलब है—कुत्ती ?”

वह निराग स्वर में बोले, “क्या कहें भाई - करना पड़ता है ।”

तो इस ‘करना पड़ता है’ की लाचारी ने जमज. फँस रहे राजतंत्र को दमनकारी शक्तियाँ दे दी । यहाँ उबन घटना का ध्यान-मात्र इस कारण कर रहा हूँ कि लोकतंत्री शक्ति को बुचलने के लिए इमरजेंसी से पूर्व भी पूरी शक्ति लगाई जा रही थी, किन्तु जब जन-धर्मतोष को इस खुले दमन-चक्र में नहीं दबाया जा सके तो देश के आपातकाल का बहाना लेकर एक भयावह गुलामी की जनता पर थोप दी गई । रातोंरात मायों गिरफ्तारियाँ हुई । शीर्षस्थ जन-नेता जेलों में पहुँचा दिए गए । उन्हें कष्ट दिया गया । प्रेस मेंगरगिप से मरप का गन्ना पोंट डाला गया । कई छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, विचारशील अधिकारी, पत्रकार, लेखक-बालाकार अनजानी जगहों पर या तो कैद कर दिए गए या फिर नजरबन्द हो गए । और फूहड़ ढंग में प्रचार करके जन-माधायन को यह बात समझाने की कोशिश की जाने लगी कि यह सब देशहित में हो रहा है ।

इमरजेंसी की आड में मविधान में ४२वाँ मशोधन करके उसकी मूल आरमा का हुनन कर डाला गया ।

यह सब कैसे, क्यों, किसकी भूल, झाररत अथवा लाचारी में होता रहा यह विश्लेषण बाद की बात है, पर यह सब हुआ । भारत में ब्रिटिश राज की गुलामी के बाद प्रजातंत्र और समाजवाद का बुरका ओढ़कर जिस भारतीय साम्राज्यवाद का प्रारम्भ हुआ, उसकी कहानी किसी उपन्यास में कम रोचक, रोमांचक और मार्मिक नहीं है और ‘दूसरी आजादी’ इसका लेपा-जोपा है ।

दमन और गुलामी के पीछे भाड़ों का यह इतिहास मभवतः उस मधको नहीं बटोर पाएगा, जितना कुछ हुआ है, पर मैंने कोशिश की है कि इसमें जम-वार वह सब आए, जिसे मानसिक, शारीरिक और नैजातिक रूप में मेरे देश के

आदमी ने झेला है। इस पुस्तक में विभिन्न घटनाएं, संस्मरण और लोगों के इन्टरव्यू संकलित हैं। इसमें बहुत-से वे पात्र भी हैं, जिन्होंने मुगल सम्राटों के सूबेदारों की तरह राज्यों में व्यवहार किया, वे लोग भी हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थों के समझौते करके जयचन्दों की तरह अपनों से अपनों को ही गुलाम बनवाने की प्रक्रिया में भाग लिया, वे नगर-सेठ भी हैं, जिन्होंने व्यावसायिक स्वार्थों के लिए मानव-धर्म बेचने में भी लज्जा महसूस नहीं की। वे बुद्धिजीवी कलाकार, लेखक, पत्रकार भी हैं जिन्हें कोई भी देश राष्ट्रीय नैतिकता और मानव-अधिकारों की जन्मपत्रियां रचने का अधिकार देता है, और जिनकी बुद्धि से पीढ़ियां अपने अन्धेरे दूर करती हैं। यह पुस्तक एक हिसाब है, एक शीशा, जो हम सभीको अपने-अपने चेहरे दिखाने की कोशिश करती है।

आपातकाल की सबसे बड़ी देन है—अपनी और दूसरों की पहचान। अपने गुण-दोषों का लेखा-जोखा करना। यह पहचान किसी अगली गुलामी से बचाएगी, पर शर्त यही है कि हम अंग्रेजों के बाद दूसरी गुलामी की गिरफ्त में कैसे आए, कौन लाया, किन कमजोरियों के कारण यह सब हुआ—उसे समझें। और अगर यह पुस्तक मेरे किसी एक भी पाठक को अपनी पहचान करवा सकी, तो मेरा श्रम सफल होगा।

असल में हर इतिहास, सही-गलत, गुण-दोष समझने का एक संदर्भ-ग्रंथ होता है। इस पुस्तक को इसी ढंग से लिया जाना चाहिए।

२३/१४, रामजम रोड,
फरीनबाग, नई दिल्ली-११०००५

—रामकुमार भ्रमर

आपत्ति-काल के नाम से घोषी गई और गुधारवाद के नाम में प्रचारित की गई गुलामी के समय की यात करने में पूर्व राजनीतिक मूल्यों की बान करना अनिवार्य है। राजनीति शब्द को लेकर एक भ्रांति शायद भारत ही नहीं, सारी दुनिया में फैली हुई है। यह कि अंग्रेजी कहावत—'ऐवरी थिंग दूज फेयर इन नय एण्ड बार' की तरह राजनीति में भी नैतिक मूल्यों का कोई बन्धन नहीं है। विभिन्न देशों के अपने साम्प्रतिक मूल्यों के अनुसार हो सकता है कि इस तरह की यात उनके अपने यहां मही हो, पर भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति और ग्रंथों ने अपने-आपको कभी इतना गीमित, गकुचित और कंजुग नहीं बनाया कि वह केवल भौगोलिक सीमा रेखाओं की चीज बनकर रह जाएं। समूची भारतीय संस्कृति और ग्रंथों ने अपनी रचना शाश्वत मानवीय मूल्यों के आधार पर की है, तब मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति नैतिक मूल्यों में घरी हो सकती है।

जैसा कि होता रहा है, समय-समय पर भारत के सामाजिक, नैतिक, मानवीय मूल्यों को नष्ट-भ्रष्ट करने वाले विचारक, प्रशासक या हमलावर बाहर से आए, किन्तु भारत ने ऐसे लोगों को या तो अपनी बुनियादी नैतिकता और शक्ति में उछाड़ फेंका अथवा उन्हें अपने ही अन्त में आत्मसात् कर लिया। ऐसे मंत्रान्तिकालों में समय-समय पर इस देश में विचारक, नेता, विद्वान और संत पैदा हुए, जिन्होंने मूल्यों के बिछराव को समेटा और बिगड़े हुए को पुनः गवारा।

भारतीय राजनीति के आकाश में महात्मा गांधी का उदय ऐसे ही मंत्रान्तिकाल में हुआ था और उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से राजनीति को भी मानवीय और नैतिक आधार दिया था। इस तरह कांग्रेस—जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सैंकड़ों साल पुरानी जड़ें छोड़ डाली—मूलतः सैद्धांतिक और मानवीय मूल्यों

का राजनीतिक दल रहा। उस समय कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य था—अंग्रेजों से देश को मुक्त कराना। मुक्ति के इस ज़बरदस्त संघर्ष और अहिंसात्मक आंदोलन का आधार भी नैतिक मूल्य ही थे। मानवीय मूल्यों की राजनीति थी। निःसन्देह कांग्रेस की उस समय की राजनीति के मूल में मानवतावाद पहले था। किन्तु वैसी स्थिति स्वतंत्रता के बाद नहीं रही। कांग्रेस गांधीजी के प्रभाव से क्रमशः मुक्त होती गई। यह वहस की बात है कि गांधीजी ने स्वयं कांग्रेस को मुक्त किया अथवा कांग्रेस ने ही उन्हें अपने-आपसे मुक्त कर दिया, पर इतना सच है कि देश की आज़ादी के फौरन बाद ही कांग्रेस का अस्तित्व ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था और उसे नैतिक, सैद्धांतिक और मानवीय मूल्य देने वाले मंत का काम। इस कमी को बहुत-से लोगों ने गांधी की कमजोरी माना है, और बहुत-से लोगों ने गांधी की विरक्ति। बहरहाल यह सच है कि कांग्रेस अब वह संस्था नहीं रह गई थी, जिसका लक्ष्य विदेशी से लड़कर मुक्ति पाना था, बल्कि कांग्रेस का लक्ष्य हो गया था भारतीय राजनीति में येन-केन प्रकारेण सत्तारूढ़ रहना। सत्तावाद की इस राजनीति ने क्रमशः एक पवित्र मंस्था के भीतर से उन मूल्यों को तोड़ना-मरोड़ना या दरकिनार करना प्रारंभ कर दिया, जो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नैतिक रूप से सबसे कारगर और ईमानदार तरीके हो सकते थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में प्रभाव की राजनीतिक विरासत महात्माजी से पाई थी, किन्तु गांधी और नेहरू दोनों में वैयक्तिक अंतर था—अपनी तरह के राजनीतिज्ञ होने का। एक ओर गांधीजी एकदम सैद्धांतिक और मूल्यवादी राजनीति के विचारक थे, दूसरी ओर नेहरूजी उस तरह की सैद्धांतिक और मूल्य-बंधनों की राजनीति में अपने-आपको बंधित नहीं पाते थे। वैयक्तिक विमर्श किया जाए तो संभवतः इसका कारण था, गांधी और नेहरू का अपना-अपना सामाजिक परिवेश। एक ओर गांधी यदि नितान्त भारतीय संस्कारिता और समाज की देन थे, दूसरी ओर नेहरू पूर्णतः पाश्चात्य संस्कारिता और सामाजिकता में पले-बढ़े थे। इस तरह कांग्रेस में दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति का उदय इतना ताकतवर हुआ कि धीमे-धीमे कांग्रेस उन मानवीय मूल्यों से अज्ञान ही हटती चली गई, जिन्हें कभी गांधी ने कांग्रेस में स्थापित किया था।

स्वतंत्रता के बाद की कांग्रेस, एक नई कांग्रेस थी, जो निश्चित रूप से गांधीवादी कही जाती थी, किन्तु थी नहीं। यह कांग्रेस का संक्रमणकाल था।

एक महान मंथ्या, जो अंधेड़ों की दागता में देश की मुक्ति का पूरा मंथन-मुग अपने माथ वटोरे हुए थी, अचानक ही स्वतंत्रता के पश्चात् भीतरी तौर पर मथपंशील हो गई। टीक है कि कांग्रेस स्वतंत्र भारत की सत्ता सम्भालने हुए थी, किन्तु भीतर ही भीतर वह जंजर होने लगी थी। कारण था — मंथ्या के भीतर ही दो विचारों का मंथन। एक ओर नेहरू स्वयं और उनके हामी, उनकी तरह सोचने वाले थे, दूसरी ओर नितान्त गांधीवादी यथा बाबू राजेन्द्रप्रसाद, श्री मोरारजी भाई, जगजीवनराम, आचार्य कृपलानी आदि थे। कांग्रेस के विपटन की कहानी सामान्यतः व्यक्तियों के विपटन और स्वार्थों के कारण टकराव की कहानी कही जाती रही है, हाँ सचता है कि बाद में ऐसा हुआ भी हो, किन्तु स्वतंत्रता के तुरन्त बाद जिस तरह धीमे-धीमे कांग्रेस विपटन की ओर घट रही थी, तब वैसी कोई बात नहीं थी। मूल बात थी सोचने-ममझने के तरीकों की लड़ाई। मूल्यों का संघर्ष। ... एक ओर जवाहरलाल नेहरू का कल्पनाशील समाजवाद और जन्मशील मंस्कारों में सोचना था, दूसरी ओर वे लोग थे, जो गांधीवाद के नितान्त भारतीय अनुयायी थे। किन्तु कांग्रेस मंथ्या की गहरी जड़ों, पूर्वज नेताओं के आदर्शवाद और अनुशासन की दृढ़ता में बहुत लम्बे अर्से तक भीतर ही भीतर मुनगते हुए इस विद्रोह को जनता के सामने लम्बे समय तक उजागर नहीं होने दिया। हानाकि बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जो धीमे-धीमे अपने-आपको कांग्रेस की मन्तावादी शतरज से परे हटा ले गए। ऐसे लोगों को राजनीतिक मन्वार मिला था गांधी से। वे मिड्रात और राजनीतिक मूल्यों की शर्त पर समझौते नहीं कर सकने थे।

जिस शालीन दम में वे लोग अलग हुए, वह अपने-आपमें राजनीतिक मूल्यवाद का उदाहरण है। राजपि पुण्योत्तमदान टंडन, आचार्य कृपलानी, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राममनोहर लोहिया आदि अनेक तपस्वी थे, जिन्होंने सत्ता पर दोग न मटकर सम्पूर्ण अनुशासन और मन्कारिता के साथ अपने-आपको अलग कर लिया। यह समय वह था, जब कांग्रेस धीमे-धीमे व्यक्तिवाद की ओर घट रही थी। और इस व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे थे, वे लोग, जिनमें नेहरू की राजनीतिक विचारधारा के मथपंक कम थे, किन्तु नेहरू के प्रभावी व्यक्तित्व को चाटुवारिता में घराव करने वाले सदा थे। परिणामतः एक महान लोकतंत्रवादी और नैतिक मूल्यों में धना-बद्ध राजनीतिक दल कांग्रेस क्रमशः व्यक्तिवादी होता गया। होने-होते यह दल एक ऐसी पौज बनकर रह गया, जो किसी राजा के लिए राज्य बनाए रखती है, जिसके

दरवारी हां में हां मिलते हैं और कानून, विचार, सिद्धांत, कला सभी कुछ राजा की इच्छानुकूल चलते हैं ।

कांग्रेस में व्यक्तिवाद का आरंभ

यह विलकुल नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस में व्यक्तिवाद का जन्म केवल नेहरूजी से ही हुआ । संभवतः कांग्रेस में व्यक्तिवाद का आरंभ महात्मा गांधी के साथ ही हो गया था । उसकी हल्की-सी झलक उस समय मिली थी, जब नेताजी सुभास बोस ने कांग्रेस छोड़ी और दूसरी साफ झलक उस समय मिली, जब स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु कांग्रेस दल में बहुमत सरदार वल्लभभाई पटेल के पक्ष में गया और महात्मा गांधी ने ज़िद करके नेहरूजी को प्रधानमंत्री पद पर लाने की इच्छा व्यक्त की । पर वह समय केवल व्यक्तिवादी तानाशाही का नहीं, व्यक्तिवादी नैतिकता का भी था । उस नैतिकता का जिसकी बुनियाद में स्वयं महात्माजी ने ही सत्य, अहिंसा के शाश्वत नैतिक मूल्यों की स्थापना की थी । यही कारण था कि उन्होंने अपना व्यक्तिवाद किसी राजनीतिक झूठ या शतरंजी चाल के दगैर स्पष्टतः सरदार पटेल के सामने प्रस्तुत किया । चूंकि सारे दल में नैतिक और परम्परागत मूल्यों के प्रति आस्था थी, अतः सहज भाव से सरदार ने अपने 'बुजुर्ग नेता' की वैयक्तिक इच्छा को आदर दिया । पर बाद में व्यक्तिवाद से नैतिकता के समझौते और साफगोई की ईमानदारी वाली यह स्थिति नहीं रही । इसके बाद कांग्रेस में बढ़ता व्यक्तिवाद मूल्यों को कुचलता हुआ केवल निरंकुशवाद बनने लगा । राजनीति के नाम पर वही कुतर्की और मूल्यहीन कहावत लागू होने लगी 'ऐवरी थिंग इज़ फेयर...'

'सब कुछ सही है ! ...' और यह हुआ कांग्रेस की मूल व्यक्तिवादी राजनीति का आदर्श । इस व्यक्तिवाद ने अपनी राजनीतिक मोहरेवाजी प्रारंभ की पहले चुनाव से ही । १९५७ के चुनावों में मुझे याद है, कांग्रेस का चुनाव-चिह्न — चिह्न या दल न होकर केवल गांधी ही हो गया था । दीवारें गांधी से रंगी हुई थी । हर शासकीय कार्यालय में गांधी की तसवीरें लटकी हुई थीं । हर भाषण, हर प्रचार-पत्र गांधी का नाम लेता था, हर सिनेमाघर में गांधी की तसवीर वाली स्लाइट दिखाकर 'कांग्रेस को वोट दो' कहा जाता था । हर नेता कांग्रेसी टोपी लगाकर 'गांधी की जै', 'जै हिन्द !' ...या 'महात्मा गांधी जिन्दावाद' के नारे उछालकर सभा का प्रारंभ और अंत करता था...।

और मज्जेदार बात यह थी कि गांधी ने गांधी की उपस्थिति में ही कांग्रेस काय को गरव चुकी थी। गांधीवाद के नाम पर कांग्रेस आराम से चुनावी चुनाव भर रही थी और गांधी तथा गांधीवाद अमनियत में कांग्रेस से हजारों मील दूर रह गए थे। पर राजनीति का मिडान्त—मब मही है !...

इसलिए गांधी के नाम पर कांग्रेस को जिता ले जाना भी मही था। मुझे एक कहावत याद आती है और लगता है कि कोई भी महापुरुष राजनीति में एक गुटबिन्ध बनकर रह जाता है। कई बार दम गुटबिन्ध पर सब कुछ बनता है। मिडान्तों में हटा हुआ दम भी और मिडान्तों में हटा हुआ व्यक्ति भी...

कहावत की घटना है—

एक ग्राहक कार बनानेवाली हिन्दी बड़ी फर्म में पहुँचे और शे-मम में पहुँचकर उन्होंने दृष्टा व्यक्ति की कि उन्हें कार की ट्रायल दी जाए। तुरन्त व्यवस्था हुई। फर्म का ड्राइवर उन्हें कार में बिठानकर करीब बीस किलोमीटर ले गया, तभी अचानक कार बन्द हो गई। ड्राइवर सीट में उतरा, बाहर जाकर उसने बोनट खोला और फिर उसे बन्द करके निराश भाव से अपनी जगह आ बैठा। माथे पर हाथ रखा और खूप। ग्राहक ने परेशान होकर पूछा, 'क्यों भाई, क्या बात हुई ? कार क्यों बन्द हो गई ?'

ड्राइवर ने गहरी सांस ली। बोला, "क्या बताऊँ माहब ! कार में इंजिन तो है ही नहीं !"

"इंजिन नहीं है ?" आश्चर्य में ग्राहक चिल्लाया, "तब यह कार यहां तक कैसे दौड़ी घनी आर्द ?"

ड्राइवर ने जवाब दिया, "यह तो कम्पनी की गुटबिन्ध है माहब !..."

तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस और गांधी के बीच भी यही हुआ। गांधीजी जैंग तपस्वी राजनीतिज्ञ की गुटबिन्ध, दम में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पतन हो जाने के बावजूद, दल को चुनाव में भारी बहुमत की ओर खींच ले गई।

यानी कांग्रेस ने 'मब कुछ मही है' के मिडान्त पर गता में ममाए रहना तय किया। इस मिडान्त के तहत बहुत कुछ हुआ। चूँकि जन-साधारण प्रजा-तन्त्रीय व्यवस्था का प्रारंभिक दौर चल रहा था, अब बड़ी मुश्किल के माथे कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति और उसके भीतर का व्यक्तिवाद पनपना रहा।

इस व्यक्तिवाद का बहुत कुछ प्रभाव जवाहरलालजी में आया था और उस मारे शेर में, जब पहिलवाली प्रधानमंत्री थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी छाया की तरह उनके माथे पर रह करती थी। इन्दिराजी पर प्रमन इस व्यक्तिवाद ने

असर किया, अपने पिता के प्रभाव और व्यक्तित्व के कारण। एक तरह से जब यह कहा जाता है और बहुत-से लेखकों ने स्वीकारा भी है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सम्पूर्ण राजनीतिक विचार और योग्यता अपने पिता से शिष्य रूप में प्राप्त की, तब यह नहीं भूला जाना चाहिए कि इन्दिराजी अगर अपने पिता से राजनीतिक सूझ-बूझ पा रही थीं, तो बहुत हद तक वे जाने-अनजाने उस वैयक्तिकता को भी उभार रही थीं, जिसे उनके नीतिज्ञ पिता ने कांग्रेस पर हावी कर रखा था (या अनायास हो गई थी?) ! बहरहाल यह निश्चित था कि जवाहरलालजी के व्यक्तित्व से इन्दिराजी ने राजनीति कम और व्यक्तिवाद ज्यादा सीखा, जिसका दुष्परिणाम जून १९७५ से भारत में जारी किए गए आपातकाल और उससे पूर्व उनके प्रधानमंत्रित्व में पूरी कांग्रेस संस्था और देश ने भोगा। इस व्यक्तिवाद को ज्यादातर बढ़ावा कांग्रेस में ही पहुंचे उन लोगों से मिला, जो 'नये' के नाम पर नारेबाजियां किया करते थे और जिन्होंने कांग्रेस का वह संपर्पशील रूप निश्चय ही नहीं देखा था, जो स्वतंत्रता से पूर्व रहा था। स्पष्ट शब्दों में यदि यह कहा जाए कि कांग्रेस के भीतर 'नये खून' के नाम से अचानक जो पीढ़ी आने लगी थी, वह अवसरवादी और स्वार्थ-लिप्त ज्यादा थी, वनिस्वत देश के लिए कुछ करने वाले लोगों के। इन्दिराजी के भीतर बैठे राजनीतिज्ञ ने दूरदर्शिता से इस तरह के लोगों को खूब अच्छी तरह समझा और शायद उसी समय निर्णय कर लिया कि यही लोग हैं, जो आगे उनके काम आ सकते हैं। श्रीमती गांधी ने किस तरह, ऐसे लोगों को काम में लिया—बाद में जिक्र आएगा।

कांग्रेस के भीतर नेहरूजी के समय से पनपी व्यक्तिवादी राजनीति की चर्चा करते हुए वयोवृद्ध लेखक और हिन्दी पत्रकार श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की इन्दिराजी को लेकर वर्णित एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। यह घटना हालांकि प्रभाकरजी की तीव्र पत्रकारीय बुद्धि ने राजनीतिक आदर्श बना ली है, किन्तु बिना घुमाव-फिराव के यदि इस घटना पर ध्यान दिया जाए तो सहज समझ में आ जाता है कि नेहरू-परिवार ने किस 'मुगलिया ढंग' से हिन्दुस्तान के तख्त पर कब्ज़ा किए रहने की व्यक्तिवादी राजनीति चली थी।

श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने 'नया जीवन' के 'इंदिरा गांधी' अंक में लिखा है :

“...जो लोग अन्दरूनी खबर रखते हैं, उनका कहना है कि जवाहरलालजी

की बीमारी (१९६४ में; जब उन्हें पञ्जापान हुआ तब—भ्रमर) को देखने हुए मुरारजी भाई देसाई के पास यह सन्देश भेजा गया था कि वे इन्दिराजी को प्रधानमंत्री और अपने को उप-प्रधानमंत्री बनाकर भागन का नेतृत्व स्वीकार करें तो जवाहरलालजी को त्यागपत्र देने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसपर मुरारजी भाई का उत्तर था कि जवाहरलालजी त्यागपत्र दे दें, और गंगद-गदस्यों को अपने नेता का चुनाव करने दें। चुनाव इन्दिराजी के पक्ष में रहा तो मैं उनके साथ काम करूँगा और मेरे पक्ष में रहा तो वे मेरे साथ काम करेंगे।।।।।

प्रकट है कि कांग्रेस के भीतर बँटा नेहरू-परिवार का व्यक्तिवाद उन्नीसवीं सदी में हम राजनीतिक घटपट में जुट गया था कि किस तरह इन्दिराजी को जवाहरलालजी की विरासती कुर्मी पर पट्टा दिया जाए। श्री प्रभाकर का धर्मन (चाहे जिस बकीली घुमाव-फिराव से लिखा गया हो) यह प्रकट कर जाता है कि नेहरूजी की उपस्थिति में ही, श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री बनने का जोड़-तोड़ प्रारंभ हो चुका था। यदि श्री मुरारजी भाई देसाई ने उम्र समय यह उत्तर दिया कि कांग्रेस के गंगद-गदस्यों को प्रजातांत्रिक पद्धति से अपने नये नेता का चुनाव करने दिया जाए तो हमें कौन-सी गैरवाजिब बात थी? श्री देसाई का उत्तर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से एकदम गही था। अप-रोक्ष रूप में श्री देसाई ने अपने उत्तर में यह भी कह दिया था कि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में किसी पद के लिए दो व्यक्ति भी खड़े हो सकते हैं, फिर बहुमत जिसे चुनना चाहे—चुने।

प्रभाकरजी ने आगे लिखा है कि “मुरारजी के इस बड़े उत्तर के कारण ही जवाहरलालजी ने अपने उत्तराधिकारी रूप में श्री लालबहादुर शास्त्री को चुन लिया था।” यह दलील अपने-आपमें और भी ज्यादा हान्यस्पद है। भला किसी प्रजातंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि अपने धाद धारिण का चुनाव भी करने सके? यदि यह कहा जाता कि नेहरूजी ने अपनी राय या अपनी राय (जो उनकी निजी थी— कांग्रेस कार्यसमिति के एक सदस्य के नाते-भर) शास्त्रीजी के पक्ष में बनाई दी तो ज्यादा बेहतर होता।

२७ मई, १९६४ को श्री जवाहरलालजी की मृत्यु के बाद कांग्रेस दल ने कार्यसमिति में श्री शास्त्री को नेता चुना और वे प्रधानमंत्री हुए। श्री शास्त्री का मृत्युन राजनीतिक जीवन आदर्शवाद का उदाहरण रहा था। बाद में भी रहा। वे राजनीतिज्ञ अवश्य थे, किन्तु उनकी राजनीति मानवीय मूल्यों की

भारतीय राजनीति थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में श्रीमती गांधी को सूचना व प्रसारण मंत्री बनाया था। जबकि प्रभाकरजी लिखते हैं—
 “...इन्दिराजी का व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की दृष्टि से लालबहादुरजी से बड़ा था—प्रसिद्धि में भी और सम्पर्क में भी, इसीलिए लालबहादुरजी ने इन्दिराजी का नाम विदेश मंत्री के रूप में चुना, पर इन्दिराजी ने साफ इन्कार कर दिया। ‘...लालबहादुरजी की व्यवहारनिपुणता को ही इसका श्रेय है कि उन्होंने केन्द्रीय सूचना मंत्री बनना स्वीकार कर लिया।’”

मुझे स्मरण है, जब श्री शास्त्री ने स्नेह और आदरसहित श्रीमती गांधी को अपने मंत्रिमंडल में लिए जाने की घोषणा की, तब बुद्धिजीवी और सामान्य वर्ग में यही कहा गया था कि शास्त्रीजी आदर्श व्यक्ति हैं और उन्होंने स्वर्गीय जवाहरलालजी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही एक संवेदनात्मक कदम उठाया है। यह कितनी ओछी बात है कि श्री प्रभाकर जैसे सुलझे हुए और बुजुर्ग बुद्धिजीवी स्वर्गीय शास्त्री की योग्यता, सम्पर्क और प्रसिद्धि का इन्दिराजी के साथ ‘छोटा-बड़ा’ शब्दों में तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। इस तरह के लेखन-उदाहरण सामन्ती इतिहास की चीज हो सकते हैं, प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के निश्चित ही नहीं।

कुल मिलाकर यह कि नेहरू-परिवार की व्यक्तिवादी परम्परा को यदि स्वतंत्रता के बाद घुस आए कांग्रेस के अवसरवादी या मुखौटाधारी राजनीतिज्ञों ने बढ़ावा दिया तो दूसरी ओर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस स्थिति को बुद्धिजीवी वर्ग ने भी कम बढ़ावा नहीं दिया। व्यक्तिवाद का उमड़ता-धुमड़ता चेहरा यदि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद अपने ज्यादा स्पष्ट रूप में सामने आना शुरू हुआ तो उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप में बुद्धिजीवियों ने अपने ‘भाट-रूप’ पेश करने शुरू किए। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों से मुक्ति के बावजूद देश धीमे-धीमे एक परिवार-विशेष की सत्तनत के रूप में ढलने लगा। बौद्धिक दासता का जितना घिनौना रूप आपातकाल के दौरान देखने को मिला है, संभवतः ब्रिटिश राज में भी वैसा नहीं देखा गया था।

एक ओर यदि यह स्थिति थी, तो दूसरी ओर समझदार ‘शासक-परिवार’ ने विरोध या सत्य को कुचलने की विभिन्न पद्धतियां अपनाईं। मज्जेदार बात यह थी कि इन पद्धतियों पर बड़ी सुविधा से जनतंत्र का बुरका उड़ाया हुआ

भारतीय राजनीति थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में श्रीमती गांधी को सूचना व प्रसारण मंत्री बनाया था। जबकि प्रभाकरजी लिखते हैं—
 “...इन्दिराजी का व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की दृष्टि से लालबहादुरजी से बड़ा था—प्रसिद्धि में भी और सम्पर्क में भी, इसीलिए लालबहादुरजी ने इन्दिराजी का नाम विदेश मंत्री के रूप में चुना, पर इन्दिराजी ने साफ इन्कार कर दिया। ‘लालबहादुरजी की व्यवहारनिपुणता को ही इसका श्रेय है कि उन्होंने केन्द्रीय सूचना मंत्री बनना स्वीकार कर लिया।”

मुझे स्मरण है, जब श्री शास्त्री ने स्नेह और आदरसहित श्रीमती गांधी को अपने मंत्रिमंडल में लिए जाने की घोषणा की, तब बुद्धिजीवी और सामान्य वर्ग में यही कहा गया था कि शास्त्रीजी आदर्श व्यक्ति हैं और उन्होंने स्वर्गीय जवाहरलालजी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही एक संवेदनात्मक कदम उठाया है। यह कितनी ओछी बात है कि श्री प्रभाकर जैसे सुलझे हुए और बुजुर्ग बुद्धिजीवी स्वर्गीय शास्त्री की योग्यता, सम्पर्क और प्रसिद्धि का इन्दिराजी के साथ ‘छोटा-बड़ा’ शब्दों में तुलनात्मक अध्ययन करने लगें। इस तरह के लेखन-उदाहरण सामन्ती इतिहास की चीज़ हो सकते हैं, प्रजातन्त्रीय व्यवस्था के निश्चित ही नहीं।

कुल मिलाकर यह कि नेहरू-परिवार की व्यक्तिवादी परम्परा को यदि स्वतंत्रता के वाद घुस आए कांग्रेस के अवसरवादी या मुखौटाधारी राजनीतिज्ञों ने बढ़ावा दिया तो दूसरी ओर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस स्थिति को बुद्धिजीवी वर्ग ने भी कम बढ़ावा नहीं दिया। व्यक्तिवाद का उमड़ता-धुमड़ता चेहरा यदि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के बाद अपने ज्यादा स्पष्ट रूप में सामने आना शुरू हुआ तो उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप में बुद्धिजीवियों ने अपने ‘भाट-रूप’ पेश करने शुरू किए। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों से मुक्ति के बावजूद देश धीमे-धीमे एक परिवार-विशेष की सत्तनत के रूप में ढलने लगा। बौद्धिक दासता का जितना घनीना रूप आपातकाल के दौरान देखने को मिला है, संभवतः ब्रिटिश राज में भी वैसा नहीं देखा गया था।

एक ओर यदि यह स्थिति थी, तो दूसरी ओर समझदार ‘शासक-परिवार’ ने विरोध या सत्य को कुचलने की विभिन्न पद्धतियां अपनाईं। मजबूत बात यह थी कि इन पद्धतियों पर बड़ी सुविधा से जनतंत्र का बुरका उढ़ाया हुआ

था और सहजता के साथ सत्य को झूठ में ढालने की कोशिश की जा रही थी।

स्वर्गीय नेहरूजी के समय में विरोध का गला घोटने की राजनीतिक पद्धति बहुत 'शालीन' थी। रेडियो, टेलिविजन और समाचारपत्र सरकारी मुठ्ठी में थे तथा कई लोग विभिन्न ढंग से पुरस्कृत और सम्मानित किए जा रहे थे। कला-साहित्य का राजाश्रय दिए जाने की 'शालीन राजनीति' के हथियार से बड़ी सुविधा के साथ भौतिक आकर्षणों की ओर झुकनेवाले बुद्धिजीवियों के आलोचनात्मक दात भीथरे कर दिए जाते थे। जिन समाचारपत्रों में गलत के प्रति विद्रोह प्रकट किया जाता था, उनके सरकारी विज्ञापन बन्द कर दिए जाते थे या उन्हें 'साम्प्रदायिक', 'रूढ़िवादी' अथवा 'प्रतिक्रियावादी' कह दिया जाता था। देश का सारा प्रचार-तंत्र सरकार के हाथ में था ही और सरकार एक सम्राट् की थी, अतः बड़ी आसानी से किसी भी दल, व्यक्ति-विशेष या बुद्धिजीवी पर जो लांछन लगाना चाहते, लगा दिया जाता। यही नहीं, कांग्रेस दल में ही अगर इस पारिवारिक साम्राज्यवाद या नीतियों का विरोध होता तो ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप में जन-सामान्य के सामने गलत तरह प्रचारित किया जाने लगता। किसीको अमरीकी एजेण्ट, किसीको सी० आई०ए० एजेण्ट, किसीको साम्प्रदायिक, किसीको किसी राष्ट्रनेता का हत्यारा या किसीको देशद्रोही कहा जाने लगता। इस प्रचार-राजनीति में हथियार बनते थे वे लोग, जो किसी भी देश की पीढ़िया बनाते हैं और जिन्हे बुद्धिजीवी कहा जाता है। साम्राज्य पनप रहा था। इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वर उठानेवाले लोगों को क्रमशः सत्या से 'छाटा' जा रहा था।

ऐसे प्रचारक बुद्धिजीवियों का एक उदाहरण दू। प्रसिद्ध पत्रकार, फिल्म-कार श्री ख्वाजा अहमद अब्बास की एक पुस्तक इन्दिराजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रकाशित हुई थी, 'इन्दिरा गांधी - रिटर्न आफ दि रेड रोज़' और उसके फौरन बाद ही उन्हीकी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई 'इन्दिरा गांधी : सफलता के दस वर्ष'। दोनों ही पुस्तकें इन्दिराजी के प्रति काफी 'समर्पित भाव से' लिखी गई थी, किन्तु अब्बास साहब का स्वतन्त्रचेता मन कहीं न कहीं इस 'दुविधा से भारी था कि वे उतना कुछ समर्पण कर रहे हैं, जितना संभवतः उन्हे (उनके भीतर बैठे निर्णायक और ईमानदार बुद्धिजीवी को) नहीं करना चाहिए था। यही कारण हुआ कि श्री अब्बास ने इन्दिराजी पर लिखी अपनी दूसरी पुस्तक की भूमिका में दवे शब्दों में यह सफाई दी कि 'आज तक मुझपर

किसीने यह आरोप नहीं लगाया है कि मैं सत्ता पर प्रतिष्ठित लोगों का खुशामदी हूँ !” मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अगर श्री अब्बास वैसा नहीं करते रहे थे, तब इस सफाई की क्या आवश्यकता थी ?

इमरजेंसी के दौरान 'भाट-भाव के लेखन और 'पत्रकारिता' को जितना प्रोत्साहन मिला, स्वतंत्रता (?) के गत तीस वर्षों में नहीं मिला। और यह भी कि इस समय में जिस सीमा तक भारतीय बुद्धिजीवी ने 'मानसिक आत्म-समर्पण' किया, उस सीमा तक सोचना भी कष्टकर है। यह कहानी आगे कहीं कही जाएगी। फिलहाल कांग्रेसी राजनीति के भीतर जनमे भयानक व्यक्तिवादी साम्राज्यवाद के उत्कर्ष की कहानी सुनिए।

श्रीमती गांधी : प्रधानमंत्री

श्री गुलजारीलाल नन्दा ११ जनवरी, १९६६ को दूसरा बार कार्यकारी प्रधानमंत्री चुने गए। इस बार दल में नेता पद के लिए कई नाम उभरे थे—यथा श्री मुरारजी भाई, श्री यशवंतराव चव्हाण, और स्वयं श्री नन्दा। कभी-कभार जन-साधारण में एस० के० पाटिल का नाम भी उठता, पर कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया था कि असली टसल श्री मुरारजी भाई से ही होगी। विरोध में जो भी खड़ा हो। कांग्रेस की वैचारिक फूट और सामन्ती संघर्ष के इस संक्रमण-काल में देश किस व्यक्ति के हाथ जाएगा—लोगों में चर्चा होती, अटकलें लगाई जातीं। सूचना मंत्री रहने के दौरान श्रीमती गांधी ने अपने व्यक्तित्व की बड़ी सतर्कता के साथ इस रूप में नहीं उभरने दिया था कि वे 'दिग्गजों' की कोटि में गिनी जाकर विवादास्पद बन जाएं, बल्कि उन्होंने बड़ी समझदारी से अपने-आपको अत्यंत सरल, शांत और मृदु महिला के रूप में उभारा था। यही नहीं, उन्होंने अपने-आपको एक भारतीय महिला के सम्पूर्ण आदर्शों की प्रतीक भी बनाया था।^१ जबकि 'दिग्गजों' की स्थिति अलग थी।

१. इन्दिराजी उन दिनों जब किसी अर्ध-विकसित नगर-गांव की सभा में भाषण दिया करती थीं तब विशेष रूप से पल्लू सिर पर लिया करती थीं, जबकि सामान्यतः बैसा नहीं होता था। मूझे स्मरण है कि उन्होंने जन-साधारण को सांस्कृतिक संवेदना को भी गाढ़े-ब्रगाढ़े बड़े विभिन्न भारतीय धरातल पर अपने पद में उभारा। इसका उदाहरण है उनका इत्ताहावाद में यह कहना कि मैं आपकी बेटी हूँ जबकि कश्मीर में सुना गया था कि वह

राजनीतिक जुझार के दौर में वे परस्पर साथ रहकर भी प्रतिद्वंद्वी भाव से जन-सामान्य के सामने स्पष्ट थे। उन्होंने एक-दूसरे के बारे में दवे-मुदे ढग से जनता के बीच आलोचना करके अपने-आपको अजाने ही उजागर भी कर डाला था। स्वर्गीय नेहरू ने अपने समय में ही मुरारजी भाई को जबरदस्त व्यक्तित्व की तरह उभरते देखा था और उसी समय से मुरारजी को लेकर जनता के बीच एक खास तरह का प्रचार-तंत्र कार्य करने लगा था। इस प्रचार-तंत्र ने उन्हें नितान्त गांधीवादी और घोर प्रजातांत्रिक होते हुए भी एक 'डिक्टेटर' या 'जिद्दी राजनीतिज्ञ' के रूप में उभार दिया था। लोगों के बीच उनके व्यक्तित्व के प्रति शंकाएं और भय पैदा कर दिए गए थे।

इस स्थिति का लाभ श्रीमती इन्दिरा गांधी को बहुत मिला। बहुत हद तक इसका कारण श्री मुरारजी भाई का समझौतावादी राजनीतिज्ञ न होना भी था। इसके बावजूद मुरारजी अपने-आपमें इतने प्रभावशाली थे कि नेहरू के बाद अपने सभी साधियों की तुलना में जनता के बीच वे ही चर्चित थे। सहज था कि मुरारजी भाई के विरोध में वैयक्तिक रूप से हर दिग्गज महसूस कर रहा था कि वह टिक नहीं पाएगा। यह भी कि मुरारजी के दबंग व्यक्तित्व की कल्पना उनके 'दिग्गज' साधियों यथा, कामराज, अतुल्य धोप, चव्हाण आदि सभी को थी और ये सभी किसी न किसी स्तर पर महसूस कर रहे थे कि मुरारजी यदि प्रधानमंत्री बने तो उनका (दिग्गजों का) अपना प्रभाव कम हो जाएगा। तब क्या करे ?...

१० जनवरी को, जिस दिन शास्त्रीजी को हार्ट-अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हुई उसी दिन से दल के नेता पद को लेकर दिल्ली में जबरदस्त दौड़धूप और उलट-फेर चलती रही। 'दिग्गज' चिन्तित थे, उनमें से मुरारजी के सामने कोई नहीं ठहरेगा, तब किसे लाया जाए ? - विकल्प रूप में बार-बार एक चेहरा आ जाता—श्रीमती इन्दिरा गांधी। इस चेहरे के साथ राजनीतिक गुडविल भी थी और देखने-भालने और अब तक के व्यवहार से लग रहा था जैसे इस निर्विवाद चेहरे को अच्छी तरह काम में लिया जा सकता है। उस

मूलतः तो कश्मीरी ही हैं और रायबरेली में उन्होंने जनता को बताया कि वह रायबरेली की बहू हैं। क्या यह सब इसलिए नहीं था कि संतीय स्तर पर निर्भल हृदय भारतीयों की संवेदना जगाकर सहानुभूति पा ली जाए ? जबकि उपर्युक्त बातों से देश के लिए, जनता के सामने कौन-सा रचनात्मक और आतिशारी कदम रखा जाता था ?

क्षण 'दिग्गज' यह कल्पना भी नहीं कर सके थे कि अपने-आपको 'निर्विवाद और चमत्कारी ढंग से शांत' बनाए रखना भी एक राजनीति हो सकती है। यह संकेत दिग्गजों को उस समय भी नहीं मिला, जब धीमे से मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजनीति के धाकड़ खिलाड़ी श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने श्री मुरारजी भाई के विरुद्ध श्रीमती गांधी का नाम प्रस्तावित किया। यही नहीं, उन्होंने यह सूचना भी दी कि श्रीमती गांधी खुल्लमखुल्ला ढंग से दलीय चुनाव के मैदान में उतर सकती हैं।

यही हुआ। १६ जनवरी, १९६६ को दलीय चुनाव के मैदान में श्रीमती इन्दिरा गांधी, मुरारजी के विरुद्ध उतरीं और उन्होंने संसदीय दल में बहुमत से मुरारजी को हरा दिया। दिग्गजों ने समझा कि उनकी राजनीति सफल हुई जबकि वास्तव में श्रीमती गांधी की विजय उनकी अपनी राजनीतिक विजय थी और दिग्गजों की राजनीतिक पराजय।

नत्ता में आते ही प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने प्रचार-तंत्र का वही 'शालीन' प्रयोग प्रारंभ किया जो कभी उनके पिता जवाहरलालजी ने किया था। परिणाम हुआ, दलगत स्थिति किनारे हो गई, दल की लोकतंत्री कार्यपद्धति क्रमशः समाप्त या क्षीण होने लगी और श्रीमती इन्दिरा गांधी एक खास तरह जन-साधारण के सामने अपने-आपको घोर समाजवादी, लोकतंत्री और जन-हितैषी रूप में उभारने लगीं। यही कारण हुआ कि कांग्रेस में श्रीमती गांधी के एक वर्षीय सत्ता-काल के भीतर ही वैचारिक बलवा शुरू हो गया। यह बलवा पहले प्रधानमंत्री के सामने समझायश के रूप में आया, फिर धीमे-धीमे जनता के सामने भी उभरने लगा। प्रचार-तंत्र का कमाल यह था कि दल के वृद्ध 'दिग्गजों' को खास तरह के 'पूँजीवादी गुर्गों' के रूप में सामान्य लोगों के सामने लाया जा रहा था। जैसा कि मैंने पूर्व में लिखा, श्रीमती गांधी बहुत पहले उस 'नये खून' को पहचान चुकी थीं, जो केवल अवसरवादी और स्वार्थ-लिप्त था। सत्ताधारी होने के पश्चात् इन्दिराजी इस 'नये खून' को बढ़ावा देती रहीं थी और प्रचार-तंत्र के माध्यम से जनता के सामने उन्हें क्रांतिकारी होने का तमगा पहनाती रहीं थीं। इस तरह लोकतंत्रीय संस्था में धीमे-धीमे प्रचार के 'स्लो प्रायजनिंग' ने इन्दिराजी का बहुमत बनाया, व्यक्तिवाद की जड़ें स्थायी कीं। दुर्दुर्लभ राजनीतिज्ञ सर्वश्री कामराज, निजलिगप्पा, मुरारजी भाई आदि अब भी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास किए चले जा रहे थे, जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को दी थी। कुल मिलाकर यह कि एक ओर 'एवरी थिंग

‘इज फेंयर’ की नैतिक बंधनों से मुक्त राजनीति थी, दूसरी ओर नितांत भारतीय मूल्यों वाली गांधीवादी लोकतंत्रात्मक राजनीति थी, जो पल-पल इस विश्वास को सहेजे हुए चल रही थी कि जनता-जनार्दन से श्रेष्ठ निर्णायक कोई नहीं है और सत्य परखने के लिए जनता के पास समुचित शक्ति है।

इस सारे दौर को शायद श्रीमती गांधी कांग्रेस में व्यक्तिवादी ढंग से पूरी तरह कैश न भी करवा पातीं, किन्तु राजनीतिक चेतना के नाम पर संभवतः उतनी आतिकारी वैचारिक घरसी उस समय तक देशवासियों को नहीं मिली थी। दूसरी ओर देश के औसत समाचारपत्र और बुद्धिजीवी अपने-आपको शासकीय सुविधाओं के लिए एक तरह से गिरवी रखे हुए थे। तब कौन बचा या जो वैचारिक चेतना फैला सकता? विरोधी दलों की स्थिति और भी गई-चीनी थी। स्वतंत्रता के बाद निरंतर चले प्रचार-तंत्र ने विरोधियों को साम्प्रदायिक और सी० आई० ए० के एजेंट प्रचारित कर रखा था। सत्ता में अपने-आपको स्थापित किए रहने के मोह ने एक ओर श्रीमती गांधी को कांग्रेस में फूट पैदा करने की प्रेरणा दी तो दूसरी ओर उन्होंने हौले से भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए। वही कम्यूनिस्ट पार्टी, जिसने कभी अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के समय सारे देश से गहारी की थी। वह कम्यूनिस्ट पार्टी, जिसके राजनीतिक दर्शन-दाता और सिद्धांत-जनक ने इस आदर्श को गढ़ा है कि अपने-आपको मजबूत करने या सत्ता पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी देश में अराजकता पैदा कर डालना या फिर उस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में अस्थिरता ला देना। ऐसे सक्रांतिकाल में मार्क्सवाद को सुविधा से कब्जा करने के अवसर मिलते हैं।

और १९६६-६७ में भारतीय प्रजातंत्र उसी दौर से गुजर रहा था। श्रीमती गांधी के व्यक्तिवादी साम्राज्यवाद ने कांग्रेस को अपने ही भीतर हिला डाला था। जो दिग्गज कभी उन्हें अपने दल की सर्वोत्तमा बनाकर ले आए थे, वही अपनी गोटी की मार शेल रहे थे। लोकतांत्रिक मूल्यों से सस्था क्रमशः रिक्त हो रही थी। विरोधी दल बदनाम किए जा चुके थे। देश आर्थिक और सामाजिक संकट में था। कम्यूनिस्ट पार्टी ने सही अवसर जानकर अपनी ‘महान क्रांति’ की योजना बना रखी थी। यह क्रांति थी, बिगड़ते हुए को ज्यादा बिगाड़ डालने की। इस क्रांति के अनुसार महान सस्था में पड़ी दरार को ज्यादा चौड़ा कर डालना था। यहां तक कि कांग्रेस सस्था ही बकनाचूर

हो जाए। मुझे स्मरण है कि उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता खुलेआम जन-मंच पर आकर इन्दिराजी का समर्थन करने लगे थे। यह नहीं, उन्होंने सबसे पहले नारा दिया—‘इन्दिरा के हाथ मज़बूत करो!’ इसी समय में १९६७ का चुनाव आया। गरीबी हटाने और देश को बनाने की ऐसी-ऐसी सच्चावागी तसवीरें जनता के सामने दिखाई गई थीं कि लोग काल्पनिक सुख के संसार में खोए जा रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि यह सब इन्दिराजी केवल इसलिए नहीं कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बूढ़े लोग हैं, जिनकी राजनीतिक बुद्धि कुंठित हो चुकी है और जो भ्रष्टाचारी हैं अथवा अमेरिकी साम्राज्यवाद के गुग हैं। ऐसे लोग देश में गरीबी बढ़ा रहे हैं और अमीरों को ज़्यादा अमीर होने की सुविधाएं दिए जा रहे हैं। इस हवाई प्रचार को बल दे रहे थे बहुत-से बुद्धिजीवी, जिन्होंने भविष्य की कुछ आशाएं बटोर रखी थीं। किसीने यह कि जो श्रेष्ठ ‘भाट’ सिद्ध होगा, उसे या तो पुरस्काररूप में कोई ‘श्री’ मिल जाएगी, या फिर राज्यसभा की सदस्यता। यदि यह सब न भी मिल पाया तो इतना निश्चित ही है कि वे किसी सरकारी ऋण-योजना का ही लाभ उठा लेंगे। बहुत-से छुटभइए समाचारपत्र भ्रष्टाचार शुरू हो गए थे, जिनकी संख्या हजारों में थी और ये सभी पत्र परम सेवा भाव से इस प्रचार-तंत्र के पुर्जें बने हुए थे। मुझे ऐसे कई समाचारपत्रों का स्मरण है, जिन्हें निकलने के फौरन बाद ही विभिन्न प्रान्तों के विज्ञापन मिलने लगे थे, ताकि वे दीर्घजीवी हों। इसके विपरीत, मुझे यह भी स्मरण है कि उन समाचारपत्रों की हालत बुरी तरह खस्ता हो चुकी थी, जो इस व्यक्तिवाद का विरोध करते रहे थे या जो विरोधी दलों की बात को महत्त्व देकर काशित किया करते थे। कई पत्रों को तो इस सीमा तक दबाया गया था कि नका प्रकाशन ही बन्द हो जाए। यह नीति नई नहीं थी। श्री नेहरू के समय की ही थी। अन्तर इतना था स्वतंत्र विचारों का गला घोट देने की पद्धति उतनी क्रूर नेहरूजी के समय की ही थी, जितनी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के सत्तारूढ़ होने के बाद धीमे-धीमे-धीमे नेहरू से लेकर श्रीमती इन्दिरा (नेहरू) गांधी के सत्ताकाल का सारा समय यदि इस ढंग से देखा जाए तो यह सहज ही भी समझा जा सकता है कि वाप-वेटी में किस अनुपात तक व्यक्तिवाद समाया हुआ था। श्री गांधी के सत्ताकाल के प्रति उतने निर्मम नहीं हुए थे, जितनी श्रीमती गांधी

हुई। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि श्रीमती गांधी एकदम व्यक्तिवादी या 'राजा' स्वभाव की थी ?

फरवरी १९६७ के चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रचार-तंत्र की सहायता लगाकर देश में तूफानी दौरे किए और व्यक्तिगतः श्रीमती गांधी को इन चुनावी दौरों का लाभ भी मिला। चुनाव-परिणाम आए। पिछले (१९६२ के) लोकसभा-चुनाव में कांग्रेस को ३८१ स्थान मिले थे, जबकि इस बार केवल २८२ स्थान प्राप्त किए जा सके थे। पिछले चुनाव में भारतीय जनसंख्या के ७० प्रतिशत मत कांग्रेस के पक्ष में गए थे, जब कि इस बार यानी १९६७ में कांग्रेस को केवल ५५ प्रतिशत मिल सके थे। ठीक है कि कांग्रेस ने केन्द्र में बहुमत बटोर लिया था, किन्तु यह भी सिद्ध हो चुका था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्यक्तिवाद का विरोध जन-मानस में भी है। इस सबके बावजूद श्रीमती गांधी निजी तौर पर लाभ में रही थी। कांग्रेस जैसी गहरी जड़ों की संस्था को उखाड़ते हुए उन्होंने सौदा किया था इस चुनाव में, अपने विरोधी दिग्गजों को समाप्त करने का। भले ही इस सौदे ने कांग्रेस के व्यापक प्रभाव से भारतीय मतदाता की २७.७ करोड़ सख्या खो दी हो। दिल्ली में शासकीय स्तर पर इस विजय के ढिंढोरे पीटे गए। व्यक्तिसत्ता के हामियों और चाटुकारों ने खुशियों की दीवाली मनाई। पीली पत्रकारिता से भरे समाचार-पत्रों ने बड़े जोर-शोर से श्रीमती गांधी के चित्र प्रकाशित किए। यही नहीं, इस अवसर पर कवियों ने कविताएँ लिखी, रणकर्मियों ने नाटक किए। लेखकों ने इन्दिराजी पर पुस्तकें लिखनी शुरू कर डाली।

किन्तु उस समय ऐसे तथाकथित लोगो ने कल्पना भी नहीं की थी कि वे भारतीय लोकतन्त्र में इन्दिरा गांधी को स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजतंत्र की बुनियाद डाल रहे हैं।

१२ मार्च, १९६७ !

श्रीमती इन्दिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री चुन ली गईं। कांग्रेस कार्यसमिति में कुछ हद तक दवा-मुदा विरोध भी हुआ। ससदीय दल में चङ्-चङ् भी रही, किन्तु श्रीमती गांधी 'अवसरवादियों' की कृपा से पुनः सत्तारूढ़ हो गईं। इस स्थिति और श्रीमती गांधी के पुनः चुने जाने को 'नया जीवन' में ये टिप्पणी लिखकर श्री प्रभाकर ने अपनी तरह व्यक्त किया। मजेदार बात यह है कि श्री प्रभाकर की यह टिप्पणी अपने-आपमें श्रीमती इन्दिरा गांधी के उस

व्यक्तित्व को उजागर करती है, जो पूर्णतः सामन्ती है। उद्धृत करता हूँ :

“ इस अवसर पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परिपक्व राजनीतिज्ञता का परिचय दिया और अपनी पैतृक साहसिकता का भी। राजनीतिज्ञता का इस बात में कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज इस बार मुरारजी के पक्ष में थे, पर वे यह जानते थे कि बहुमत श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ है। इन्दिराजी ने आरम्भ में मुरारजी भाई को उप-प्रधानमंत्री मानने से जोरदार इनकार करके उनका उत्साह तोड़ा, बाद में पार्टी की इच्छा के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साफ-साफ कह भी दिया कि मंत्रिमंडल के निर्माण में मैं स्वतंत्र हूँ। इनमें उप-प्रधानमंत्री का कोई हाथ नहीं होगा।

“ इस प्रकार कामराज इस हद तक टूट गए कि मंत्रिमंडल के निर्माण में इन्दिराजी ने उनसे सलाह तक नहीं ली। और सुबह ६ बजे उन्हें अपने बंगले पर बुलाकर मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची दिखा दी और वे ‘ठीक ही है’ कहकर लौट आए। इन्दिराजी के हाथ में कुंजी यह थी कि मुरारजी भाई के साथ हो जाने से सदस्य उनके साथ सौदेबाजी करने की स्थिति से वंचित हो गए थे। अब उनसे लूठकर या ऐंठकर वे कहां जा सकते थे ? किसके नाम पर उन्हें धोस दे सकते थे ? इस प्रकार उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, यह उनकी बड़ी सफलता थी। इस सफलता का उन्होंने मंत्रिमंडल के निर्माण में साहस के साथ उपयोग किया।

“ इन्दिराजी का दूसरा साहसिक निर्णय था राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को खड़ा करना। कामराज डॉक्टर राधाकृष्णन को ही दोहराना चाहते थे। उनकी मुख्य दलील यह थी कि विरोधी पार्टियां भी इससे असहमत नहीं होंगी और चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। कामराज पराजय की मनोवृत्ति से ग्रसित थे पर इन्दिराजी ‘पोजीशन लेने’ की मनोवृत्ति में रहीं। स्पष्ट है कि चौथे आम चुनाव में पछाड़ खाई पार्टी की नेता होकर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थीं। इतिहास के देवता पार्टी को पुनः मजबूत बनाने के लिए उनके अगले दांव-पेंचों की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। यह उत्सुकता पैदा कर सकना वर्तमान परिस्थितियों में इन्दिराजी की एक बहुत बड़ी सफलता है।”

टिप्पणी के अनुसार, जहां यह लिखा गया है कि श्रीमती गांधी ने मुरारजी भाई को उप-प्रधानमंत्री मानने से जोरदार इनकार करके उनका (कामराज

का) उत्साह तोड़ा, बाद में पार्टी की इच्छा के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया—क्या यह बात अपने-आपमें इन्दिराजी की इस राजनीति को उजागर नहीं करती कि उन्होंने जानबूझकर अध्यक्ष और पार्टी की इच्छा की अवहेलना करके पार्टी और अध्यक्ष को अपने-आपसे गौण सिद्ध करने की 'नैतिक राजनीति' का उदाहरण दिया था ? एक ओर यदि यह पहलू है तो दूसरी ओर यह भी कि श्री प्रभाकर ने एक जगह लिखा है कि बहुमत इन्दिराजी के पक्ष में था, जबकि दूसरी ओर वे यह भी लिखते हैं कि इन्दिराजी ने "पार्टी की इच्छा के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ?" क्या यह बात अपने आपमें परस्पर-विरोधी नहीं है ?

टिप्पणी के दूसरे पैरे में लिखा गया है—"मंत्रिमंडल के निर्माण में इन्दिराजी ने उनसे (कामराज से) सलाह तक नहीं ली।"

विचित्र बात है ! संसदीय दल का नेता निश्चित ही महत्वपूर्ण होता है, किन्तु वह इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि अपने कार्यकलाप में दल के अध्यक्ष की सलाह तक न ले—यह कौन-सा लोकतांत्रिक आदर्श है ?

इसी टिप्पणी में आगे दूसरे पैरे में लिखा गया है—"इस प्रकार उन्होंने (श्रीमती गांधी ने) अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। यह उनकी बड़ी सफलता थी।"

निस्सन्देह सफलता थी, किन्तु लोकतांत्रिक नहीं, राजशाही की सफलता। व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का उदाहरण।

टिप्पणी के तीसरे पैरे में लिखा है—"कामराज डॉक्टर राधाकृष्णन को (राष्ट्रपति पद के लिए) दोहराना चाहते थे। उनकी इत्तिला यह थी कि विरोधी पार्टियाँ भी इससे असहमत नहीं होंगी और चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा।" जबकि इन्दिराजी ने राष्ट्रपतिपद के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम रखा था। क्या यह कथन साबित नहीं करता कि येन केन प्रकारेण श्रीमती गांधी अपने-आपको एक प्रजातांत्रिक दल पर हावी कर लेना चाहती थी ? वे कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेताओं को भी 'गिनने के लिए' तैयार न थीं। भले ही इस 'न गिनने की कोशिश में' राष्ट्रपति पद को लेकर चुनाववाजी की स्थिति आए। कामराजजी के उस प्रस्ताव में कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसा नाम है जिसपर विरोधी दल भी एतराज नहीं करेंगे, कौन-सी असोकतांत्रिक या प्रतिक्रियावाद था ?

उपर्युक्त टिप्पणी और तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को उद्धरित करने के पीछे मेरा केवल यह आशय है कि सत्ता में आते ही श्रीमती इन्दिरा गांधी का सारा रुख नितांत व्यक्तिवादी हो गया था और कांग्रेस एक तरह से लोकतंत्रीय संस्था नहीं, किसी एक व्यक्ति की एकाधिकारी 'फर्म' बनकर रह गई थी।

इन हालात का परिणाम यह हुआ कि एक बार कांग्रेस पुनः उसी विघटन के कगार पर आ खड़ी हुई, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद धीमे से प्रकट हुआ था। यह धीमापन उस समय मालूम नहीं पड़ा था, किन्तु इस बार का विघटन स्पष्टतः जनता के सामने होना था। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता भी यह चाहते थे कि लोगों को मालूम हो कि वे गलत से विद्रोह कर रहे हैं। संस्था में फैल रहे एकाधिकारवाद से वस्तु हैं और उन मूल्यों के लिए लड़ना चाहते हैं, जिन्हें कभी कांग्रेस में गांधी, लाजपतराय और बाल गंगाधर तिलक ने संजोया था।

पर ऐसे नेता भूल गए थे कि स्वतंत्रता-पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर था। स्वतंत्रता-पूर्व का समय था, जब कांग्रेस नेताओं ने जन-साधारण में चेतना सहज तरह से इसलिए फैला ली थी कि वे विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का आन्दोलन चला रहे थे, किन्तु अब अपने ही देश में, अपने ही आदमी की उस सत्ता को उखाड़ फेंकने या उसके विरोध में जनमत बनाने की बात थी, जो अपनी वुनियाद में जवाहरलाल नेहरू जैसा नाम लिए हुए था, जिसपर कांग्रेस की मोहर लगी हुई थी और जिसने प्रचार के बड़े साधनों द्वारा अपने-आपको संस्था से कहीं ऊंचा बना रखा था।

पर बुजुर्ग नेता यह स्थिति नहीं समझ सके और यदि समझी भी तो उस गहराई के साथ नहीं, जिस गहराई के साथ इस स्थिति को श्रीमती इन्दिरा गांधी समझ चुकी थीं और अपनी रणनीति भी तय कर चुकी थीं। यही नहीं, श्रीमती इन्दिरा गांधी के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बावजूद पुराने नेता अपनी और उनकी स्थिति का ठीक तरह जायजा नहीं ले पाए। जबकि उसी समय पल-पल यह स्पष्ट होने लगा था कि हर दृष्टि से श्रीमती गांधी संस्था से ऊंची हो गई हैं और उनका व्यक्तित्व बहुमत पर उसी तरह हावी होने लगा है जैसे किसी राजा का सारे राज्य पर हो जाता है।

कांग्रेस के कुछ बुजुर्ग ('बूढ़े' नहीं) नेताओं ने उस समय ऐसे वक्तव्य भी दिए, जिनमें जनता को यह बतलाने की कोशिश की गई थी कि श्रीमती गांधी क्रमशः समाजवाद का नारा लगाकर राजवाद की ओर बढ़ रही है, हालांकि श्रीमती गांधी अपने राजवाद को दबाए हुए बार-बार कभी रेडियो, कभी टेली-विज़न और कभी जन-मञ्च से 'एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों' के विरुद्ध भाषण दिया करती थीं। एक बार इसपर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिगप्पा ने कहा भी था कि "महत्वपूर्ण है कार्य करना और देश को आगे ले जाना। एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध चीखने-शोर मचाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है।" श्री निजलिगप्पा का यह कथन 'करनी और कयनी' में भेद-दर्शन की बात थी किन्तु इस आदर्शवादी नीति का इन्दिरा-शासन में कोई महत्व नहीं रह गया। उल्टे एक दूरदेश पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने श्री निजलिगप्पा के उक्त कथन को अपनी तरह उपयोग करके उन्हींके विरुद्ध प्रमाणित कर दिया।

की गूँज थी, इन्दिरा गांधी को अंतिम रूप से विश्वास दिला दिया कि कांग्रेस की इन दो प्रवृत्तियों में अब कोई समझौता नहीं हो सकता..."

श्री अन्नासाहेब के पत्रकारीय करिश्मे की सराहना करने का जी होता है। किसी स्थिति-विशेष के साथ वक्तव्य के कुछ अंश या शब्दों का अपनी तरह अर्थ निकालने को करिश्मा ही माना जाना चाहिए। एक तरह से उपर्युक्त लेखन में श्री अन्नासाहेब ने निजलिगप्पा और मुरारजी भाई को बड़ी सुविधा से निजी उद्योग के एकाधिकारवाद का समर्थक प्रकट कर दिया, जबकि उसी बात का अर्थ कुछ और था। वह निस्सन्देह नहीं, जो निकाला गया। एक तरह से कांग्रेस के भीतर उठे व्यक्तिवाद और लोकतंत्री संघर्ष को, कम्युनिस्ट पत्रों, प्रचारकों और इन्दिराजी के शासन-तंत्र ने बड़ी सुविधा से जनता के सामने जो नया रूप दिया वह था—समाजवादी और पूंजीवादी गुटों का संघर्ष! जबकि सच में यह संघर्ष हो रहा था इन्दिराजी के एकाधिकारवाद और कांग्रेस के लोकतंत्रवाद में। पर प्रचार-तंत्र की ताकत बहुत होती है। वही हिटलरी पद्धति। हिटलर का युद्ध-प्रचार अधिकारी गोयबल्स कहा करता था—“एक झूठ को हजार बार दोहराओ तो वह सच बन जाता है...” उसी ढंग से कांग्रेस के पुराने नेताओं यथा कामराज, निजलिगप्पा, मुरारजी भाई आदि के बारे में यह झूठ कि वे पूंजीवादी शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, इतनी बार कहा, लिखा, फैलाया और सुनाया गया कि जनता में उनके प्रति खासी भ्रांति फैल गई। विशेषकर श्री मुरारजी भाई के बारे में। यों भी श्री मुरारजी भाई स्वर्गीय श्री जवाहरलालजी के समय से ही प्रधानमंत्री पद के सबसे ताकतवर उत्तराधिकारी थे। उनके बारे में इसी तरह का योजनावद्ध प्रचार नेहरूजी के समय से ही चलता रहा था, इन्दिराजी ने उस प्रचार को लाख गुना कर दिया। और उसका लाभ उन्हें (इन्दिराजी को) वाद में बहुत मिला।

प्रचार के दम पर देश की सत्ता हथियाए रखने की प्रवृत्ति ने अपने रंग दिखलाने शुरू कर दिए थे। जनता को नये-नये सम्मोहन-स्वप्न दिखाए जा रहे थे और केवल कथनी चल रही थी। मीटिंगें, भाषण, पोस्टर सभी कुछ सिर्फ नये-नये नारों और चमत्कारों से भरे सुनहरे लोक जनता को दिखाते रहते। काम करने वाले लोग इस स्थिति को सह नहीं पा रहे थे। परिणाम हुआ दरार बढ़ते जाना। यह दरार इतनी बढ़ी कि विस्फोट की सीमा पर जा टहरी। इस सीमा को श्रीमती गांधी ने उस समय अन्तिम बार कुरेदा जब अचानक श्री मुरारजी भाई से वित्त विभाग अपने हाथ में ले लिया और

समाचारपत्रों द्वारा जनता को एक वक्तव्य में खबर दी गई कि विभागों की बदला-बदली प्रधानमंत्री का अधिकार है, हालांकि ऐसा करते हुए भी श्री मुरारजी भाई उप-प्रधानमंत्री बने रहेगे तथा उनका मान-सम्मान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। श्री मुरारजी भाई ही नहीं, देश के तमाम मुलझे हुए व्यक्तियों को यह निरंकुश एकाधिकारवाद और राजनीतिक अशिष्टता बुरी लगी। परिणाम हुआ श्री देसाई का मंत्रिमंडल से तुरन्त त्यागपत्र और इस त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के विघटन का स्पष्ट संकेत।

श्री प्रभाकर ने इस त्यागपत्र पर 'नया जीवन' में अपनी प्रतिक्रिया इस तरह व्यक्त की है—“श्री मुरारजी भाई ने राजनीति छोड़कर भावुकता की वैसाखी सभाल ली।” जबकि श्री देसाई ने भी साचाय होकर वही रास्ता अपनाया था जो बहुत पहले कांग्रेस में कभी आचार्य कृपलानी, राजपि टंडन या बाद में बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने अपनाया था। पर बहुत देर हो चुकी थी। प्रचार के नुकीले दांतों ने सत्य को जगह-जगह से काट डाला था। इसके बावजूद गांधीवादी मुरारजी भाई ने वही किया जो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति और नैतिक मूल्यों का हामी नीतिज्ञ कर सकता था।

श्रीमती गांधी ने मुरारजी के हटते ही तुरंत एक प्रचारात्मक पत्रा फेंका—
१४ प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके। राष्ट्रीयकरण की इस घोषणा के साथ पुनः सम्प्रदायों की लाखों क्यारिया हिन्दुस्तान की गरीबी के सामने फेंक दी गईं। इस तरह यह सिद्ध कर दिया गया कि मुरारजी भाई और उनके साथी ही थे, जिनके कारण इन्दिराजी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। इस स्थिति का राजनीतिक वर्णन करते हुए श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिखते हैं—“इन्दिराजी प्रगतिशील शासक के रूप में अपने आकार से कई फुट लम्बी हो गईं और मुरारजी देसाई और उनके साथी प्रतिक्रियावाद के प्रेतों के हुलिया में सामने आ गए।”

यदि आज के सदर्थ में देखा जाए, तो स्थिति कुछ और ही नजर आती है। उपर्युक्त शब्द पढ़ते हुए मुझे लगता है कि इन्दिरा शासन के शक्तिशाली प्रचार-तत्त्व ने (आश्चर्यजनक रूप से ही सही, पर सच में) गहरी पैंठ के पत्र-कारों को भी कम प्रभावित नहीं किया था। अगर ऐसा न होता तो संभवतः प्रभाकरजी मुरारजी प्रभृति राजनीतिज्ञों के बारे में उस प्रचारात्मक फ्रेम में न सोचते, जिसमें सोचते हुए लगते हैं। मुरारजी या उसी तरह के पुराने कांग्रेसजनों के बारे में बहुत जल्दबाजी से सोचना बहुत गलत हुआ, यह आज

की गूँज थी, इन्दिरा गांधी को अंतिम रूप से विश्वास दिला दिया कि कांग्रेस की इन दो प्रवृत्तियों में अब कोई समझौता नहीं हो सकता..."

श्री अन्वास के पत्रकारीय करिश्मे की सराहना करने का जी होता है। किसी स्थिति-विशेष के साथ वक्तव्य के कुछ अंश या शब्दों का अपनी तरह अर्थ निकालने को करिश्मा ही माना जाना चाहिए। एक तरह से उपर्युक्त लेखन में श्री अन्वास ने निजलिगप्पा और मुरारजी भाई को बड़ी सुविधा से निजी उद्योग के एकाधिकारवाद का समर्थक प्रकट कर दिया, जब कि उसी बात का अर्थ कुछ और था। वह निस्सन्देह नहीं, जो निकाला गया। एक तरह से कांग्रेस के भीतर उठे व्यक्तिवादी और लोकतंत्री संघर्ष को, कम्युनिस्ट पत्रों, प्रचारकों और इन्दिराजी के शासन-तंत्र ने बड़ी सुविधा से जनता के सामने जो नया रूप दिया वह था—समाजवादी और पूंजीवादी गुटों का संघर्ष! जबकि सच में यह संघर्ष हो रहा था इन्दिराजी के एकाधिकारवाद और कांग्रेस के लोकतंत्रवाद में। पर प्रचार-तंत्र की ताकत बहुत होती है। वही हिटलरी पद्धति। हिटलर का युद्ध-प्रचार अधिकारी गोयबल्स कहा करता था—“एक झूठ को हजार बार दोहराओ तो वह सच बन जाता है...” उसी ढंग से कांग्रेस के पुराने नेताओं यथा कामराज, निजलिगप्पा, मुरारजी भाई आदि के बारे यह झूठ कि वे पूंजीवादी शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, इतनी बार कहा, लिखा, फैलाया और सुनाया गया कि जनता में उनके प्रति खासी भ्रांति फैल गई। विशेषकर श्री मुरारजी भाई के बारे में। यों भी श्री मुरारजी भाई स्वर्गीय श्री जवाहरलालजी के समय से ही प्रधानमंत्री पद के सबसे ताकतवर उत्तराधिकारी थे। उनके बारे में इसी तरह का योजनाबद्ध प्रचार नेहरूजी के समय से ही चलता रहा था, इन्दिराजी ने उस प्रचार को लाख गुना कर दिया। और उसका लाभ उन्हें (इन्दिराजी को) वाद में बहुत मिला।

प्रचार के दम पर देश की सत्ता हथियाए रखने की प्रवृत्ति ने अपने रंग दिखलाने शुरू कर दिए थे। जनता को नये-नये सम्मोहन-स्वप्न दिखाए जा रहे थे और केवल कथनी चल रही थी। मीटिंगें, भाषण, पोस्टर सभी कुछ सिर्फ नये-नये नारों और चमत्कारों से भरे सुनहरे लोक जनता को दिखाते रहते। काम करने वाले लोग इस स्थिति को सह नहीं पा रहे थे। परिणाम हुआ दरार बढ़ते जाना। यह दरार इतनी बड़ी कि विस्फोट की सीमा पर जा ठहरी। इस सीमा को श्रीमती गांधी ने उस समय अन्तिम बार कुरेदा जब अचानक श्री मुरारजी भाई से वित्त विभाग अपने हाथ में ले लिया और

समाचारपत्रों द्वारा जनता को एक वक्तव्य में खबर दी गई कि विभागों की बदला-बदली प्रधानमंत्री का अधिकार है, हालांकि ऐसा करते हुए भी श्री मुरारजी भाई उप-प्रधानमंत्री बने रहेंगे तथा उनका मान-सम्मान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। श्री मुरारजी भाई ही नहीं, देश के तमाम सुलझे हुए व्यक्तियों को यह निरंकुश एकाधिकारवाद और राजनीतिक अशिष्टता बुरी लगी। परिणाम हुआ श्री देसाई का मंत्रिमंडल से तुरन्त त्यागपत्र और इस त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के विघटन का स्पष्ट संकेत।

श्री प्रभाकर ने इस त्यागपत्र पर 'नया जीवन' में अपनी प्रतिक्रिया इस तरह व्यक्त की है—“श्री मुरारजी भाई ने राजनीति छोड़कर भावुकता की बँसाखी संभाल ली।” जबकि श्री देसाई ने भी साधारण होकर वही रास्ता अपनाया था जो बहुत पहले कांग्रेस में कभी आचार्य कृपसानी, राजपि टंडन या बाद में बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने अपनाया था। पर बहुत देर हो चुकी थी। प्रचार के तुकिले दांतों ने सत्य को जगह-जगह से काट डाला था। इसके बावजूद गांधीवादी मुरारजी भाई ने वही किया जो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति और नैतिक मूल्यों का हामी नीतिज्ञ कर सकता था।

श्रीमती गांधी ने मुरारजी के हटते ही तुरंत एक प्रचारात्मक पत्ता फेंका— १४ प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके। राष्ट्रीयकरण की इस घोषणा के साथ पुनः संजवागों की साखों क्यारिया हिन्दुस्तान की गरीबी के सामने फेंक दी गईं। इस तरह यह मिद्ध कर दिया गया कि मुरारजी भाई और उनके साथी ही थे, जिनके कारण इन्दिराजी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। इस स्थिति का राजनीतिक वर्णन करते हुए श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिखते हैं—“इन्दिराजी प्रगतिशील शासक के रूप में अपने आकार से कई फुट लम्बी हो गईं और मुरारजी देसाई और उनके साथी प्रतिक्रियावाद के प्रेतों के हुलिया में सामने आ गए।”

यदि आज के संदर्भ में देखा जाए, तो स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। उपर्युक्त शब्द पढ़ते हुए मुझे लगता है कि इन्दिरा शासन के शक्तिशाली प्रचार-नंत्र ने (आश्चर्यजनक रूप से ही सही, पर सच में) गहरी पैठ के पत्र-कारों को भी कम प्रभावित नहीं किया था। अगर ऐसा न होता तो सभवतः प्रभाकरजी मुरारजी प्रभृति राजनीतिज्ञों के बारे में उस प्रचारात्मक फ्रेम में न सोचते, जिसमें सोचते हुए लगते हैं। मुरारजी या उसी तरह के पुराने कांग्रेसजनों के बारे में बहुत जल्दबाजी से सोचना बहुत गलत हुआ, यह आज

करोड़ों लोगों के सामने प्रकट हो चुका है। मुरारजी घोर गांधीवादी हैं और मेरा खयाल है कि उप-प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना गांधीजी के उस वाक्य पर ही आधारित था, जिसमें वह कहते हैं—“मेरी मृत्यु के बाद यदि अहिंसा (सत्य) का नाश हो जाए तो मान लेना चाहिए कि मुझमें अहिंसा (सत्य) थी ही नहीं।”

एक अन्य स्थान पर वापू ने अहिंसा को सत्य का पर्याय ही माना है। तो यदि वापू के उपर्युक्त कथन के आधार पर माना जाए कि मुरारजी भाई ने सत्य या अहिंसा के नाम पर त्यागपत्र दिया था और वह थोड़े-से समय के लिए गलत तरह प्रचारित कर लिया गया तो इससे उसका सत्य तो नहीं मरा। आज जब आपातकाल अपनी ही मौत मर चुका है, तब वह सत्य सामने है। और यह भी कि जिस पद को ठोकर मारकर उन्होंने अपने सत्य की रक्षा की थी, उससे बड़ा पद जनता ने उन्हें असत्य के हाथों से छीनकर सौंप दिया है।

कांग्रेसी शीशमहल : पहली दरार

श्रीमती गांधी ने समझ लिया था कि अब निष्कण्टक राज्य उनके हाथ में है। इसका पहला राजनीतिक चमत्कार उन्होंने उस समय दिखाया जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार श्री संजीव रेड्डी से अचानक अपना समर्थन वापस ले लिया और श्री वी० वी० गिरि के लिए समर्थन की घोषणा की। एक नया नारा भारतीय राजनीति के आकाश पर गूँजा—‘आत्मा की आवाज़ !’ इस नारे के तहत श्रीमती गांधी की सुविधा-जीवी राजनीति ने कांग्रेस संस्था का अनुशासन पहली बार खुल्लमखुल्ला ढंग से तोड़ दिया। यह कहकर कि कांग्रेस दल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं। इस अनुशासन-तोड़ करिश्मे के परिणाम स्वरूप—श्री संजीव रेड्डी, जो कांग्रेस के अपने उम्मीदवार थे, पराजित हुए स्वतंत्र उम्मीदवार श्री वी० वी० गिरि ने राष्ट्रपति-चुनाव जीता तथा पदारूढ़ हुए।

इस दरार ने भारतीय कांग्रेस को टुकड़े-टुकड़े कर डाला। कांग्रेस के नाम पड़ गए। एक थी कांग्रेस, जिसकी सत्ता थी और जिसमें अस्थिर

सम्भाला था दावू जगजीवन राम ने। (सामान्यतः इसे कांग्रेस न कहकर जन-सामान्य में 'इन्दिराजी की कांग्रेस' कहा जाता था)^१ जबकि दिग्गजों ने जिस कांग्रेस को सम्मान लिया था, उसे कहा जाता था—संगठन कांग्रेस। तत्कालीन नंसद में इन्दिरा-कांग्रेस के सदस्य थे २२०, जबकि संगठन कांग्रेस के ६५ सदस्य थे। दोनों को चुनाव-आयोग ने असंग-अलग चुनाव-चिह्न भी प्रदत्त कर दिए थे।

कांग्रेस की इस दरार को इन्दिराजी के पक्ष की ओर से एक श्रेयपूर्ण कार्य का जामा पहनाया गया और प्रचारित किया गया कि वस्तुस्थिति में गिरि की विजय और कांग्रेस और संगठन कांग्रेस बन जाना, कांग्रेस का सुदृढीकरण होना है। इस तरह पूंजीवादी ताकतों पर समाजवादी ताकतों की विजय हुई है। विशेष रूप से इस शान्तिकारी (?) विचार का सर्वाधिक प्रचार कर रहे थे भारतीय कम्युनिस्ट, जो अपरोक्ष रूप से एक महान राजनीतिक दल को लगभग 'फिमडू' बना चुके थे।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण और श्री बी० बी० गिरि की चुनाव-विजय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री प्रभाकर और अब्बास दोनों एक ही बात लिखते हैं। यह मजेदार इत्फाक है कि दोनों ने ही असंग-अलग मौकों पर टैक्सी-वालों और कुलियों को नाचते हुए देखा था। श्री प्रभाकर ने गिरि की जीत पर यह नाच देखा था जबकि श्री अब्बास ने बैंक राष्ट्रीयकरण पर। बाद में इमरजेंसी के दौरान जो नाच हुआ, उसका बयान मेरे पढ़ने में उस दौरान नहीं आया। वह नाच किन्हीं दो आदमियों ने नहीं, सारे देश ने देखा था और उस नृत्य-नाटिका का वर्णन करना ही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है।

द्वारे-द्वारे, हसीन नारे

करोड़ों लोगों को बतलाया गया कि करोड़ों लोग खुश हैं। कारण है—सत्तारूढ दल से उस भीड़ का छंट जाना, जो 'प्रगतिशील' और 'सुधारवादी' नीतियों के आड़े आकर 'क्रांतिकारी प्रधानमंत्री' को कुछ करने नहीं दे रहे थे। दिल्ली की छाती पर देश के कोने-कोने से 'बलो दिल्ली घुमाए' कहकर

१. यह बताने-आपने एक हास्यास्पद किन्तु दुःखद बात थी कि एक महान सभ्यता किसी ध्वस्त-विशेष का 'जैवी ट्रांज़िस्टर' बन जाए।

करोड़ों लोगों के सामने प्रकट हो चुका है। मुरारजी घोर गांधीवादी हैं और मेरा खयाल है कि उप-प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना गांधीजी के उस वाक्य पर ही आधारित था, जिसमें वह कहते हैं—“मेरी मृत्यु के बाद यदि अहिंसा (सत्य) का नाश हो जाए तो मान लेना चाहिए कि मुझमें अहिंसा (सत्य) थी ही नहीं।”

एक अन्य स्थान पर वापू ने अहिंसा को सत्य का पर्याय ही माना है। तो यदि वापू के उपर्युक्त कथन के आधार पर माना जाए कि मुरारजी भाई ने सत्य या अहिंसा के नाम पर त्यागपत्र दिया था और वह थोड़े-से समय के लिए गलत तरह प्रचारित कर लिया गया तो इससे उसका सत्य तो नहीं मरा। आज जब आपातकाल अपनी ही मौत मर चुका है, तब वह सत्य सामने है। और यह भी कि जिस पद को ठोकर मारकर उन्होंने अपने सत्य की रक्षा की थी, उससे बड़ा पद जनता ने उन्हें असत्य के हाथों से छीनकर सौंप दिया है।

कांग्रेसी शीशमहल : पहली दरार

श्रीमती गांधी ने समझ लिया था कि अब निष्कण्टक राज्य उनके हाथ में है। इसका पहला राजनीतिक चमत्कार उन्होंने उस समय दिखाया जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार श्री संजीव रेड्डी से अचानक अपना समर्थन वापस ले लिया और श्री बी० बी० गिरि के लिए समर्थन की घोषणा की। एक नया नारा भारतीय राजनीति के आकाश पर गूँजा—‘आत्मा की आवाज़ !’ इस नारे के तहत श्रीमती गांधी की सुविधा-जीवी राजनीति ने कांग्रेस संस्था का अनुशासन पहली बार खुल्लमखुल्ला ढंग से तोड़ दिया। यह कहकर कि कांग्रेस दल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं। इस अनुशासन-तोड़ करिश्मे के परिणाम-स्वरूप—श्री संजीव रेड्डी, जो कांग्रेस के अपने उम्मीदवार थे, पराजित हुए। स्वतंत्र उम्मीदवार श्री बी० बी० गिरि ने राष्ट्रपति-चुनाव जीता तथा पदार्हूट हुए।

इस दरार ने भारतीय कांग्रेस को टुकड़े-टुकड़े कर डाला। कांग्रेस के दो नाम पड़ गए। एक थी कांग्रेस, जिसकी सत्ता थी और जिसमें अध्यक्ष पद

सम्भाला था दावू जगजीवन राम ने। (सामान्यतः इसे कांग्रेस न कहकर जन-सामान्य में 'इन्दिराजी की कांग्रेस' कहा जाता था) जबकि दिग्गजों ने जिस कांग्रेस को सम्भाल लिया था, उसे कहा जाता था—संगठन कांग्रेस। तत्कालीन संसद में इन्दिरा-कांग्रेस के सदस्य थे २२०, जबकि संगठन कांग्रेस के ६५ सदस्य थे। दोनों को चुनाव-आयोग ने अलग-अलग चुनाव-चिह्न भी प्रदत्त कर दिए थे।

कांग्रेस की इस दरार को इन्दिराजी के पक्ष की ओर से एक श्रेयपूर्ण कार्य का जामा पहनाया गया और प्रचारित किया गया कि वस्तुस्थिति में गिरि की विजय और कांग्रेस और संगठन कांग्रेस बन जाना, कांग्रेस का शुद्धीकरण होना है। इस तरह पूंजीवादी ताकतों पर समाजवादी ताकतों की विजय हुई है। विशेष रूप से इस क्रान्तिकारी (?) विचार का सर्वाधिक प्रचार कर रहे थे भारतीय कम्युनिस्ट, जो अपरोक्ष रूप से एक महान राजनीतिक दल को लगभग 'फिसट्टी' बना चुके थे।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण और श्री बी० बी० गिरि की चुनाव-विजय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री प्रभाकर और अब्बास दोनों एक ही बात लिखते हैं। यह मजेदार इत्फाक है कि दोनों ने ही अलग-अलग मौकों पर टैंक्सी-वालों और कुतियों को नाचते हुए देखा था। श्री प्रभाकर ने गिरि की जीत पर यह नाच देखा था जबकि श्री अब्बास ने बैंक राष्ट्रीयकरण पर। बाद में इमरजेंसी के दौरान जो नाच हुआ, उसका क्या भयान भरे पड़ने में उस दौरान नहीं आया। वह नाच किन्हीं दो आदमियों ने नहीं, सारे देश ने देखा था और उस नृत्य-नाटिका का वर्णन करना ही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है।

द्वारे-द्वारे, हसीन नारे

करोड़ों लोगों को धतलाया गया कि करोड़ों लोग खुश हैं। कारण है—सत्ताह्व दन से उस भीड़ का छंट जाना, जो 'प्रगतिशील' और 'सुधारवादी' नीतियों के आड़े आकर 'क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्री' को कुछ करने नहीं दे रहे थे। दिल्ली की छाती पर देश के कोने-कोने से 'चलो दिल्ली घुमाएं' कहकर

१. यह अपने-आपमें एक हास्यास्पद किन्तु दुर्घट बात थी कि एक महान सत्ता किस व्यक्ति-विशेष का 'जैबी ट्राजिस्टर' बन जाए।

चार-छह महीने के बाद लाखों लोग ले आए जाते। इन लोगों का काम होता केवल यह कि भीड़ बनकर राजधानी में चीखने लगे—‘इन्दिरा गांधी जिन्दावाद!’ ‘पूँजीवादियों के ऐजेण्टों का नाश हो!’ इत्यादि। फिर यह भीड़ राजधानी में जहां-तहां बिखर जाती। अजनबी, परेशान, विस्मित चेहरों की सहमी हुई भीड़। कौतुक-भरी निगाहों से राजधानी की सड़कें देखते, लालकिला घूमते और चांदनी चौक की सैर करते हुए भोले-भाले लोग अपने-अपने घरों को खाना हो लेते।

राष्ट्रीयकरण की नीति निस्सन्देह ही अच्छी नीति थी, किन्तु कोई भी नीति उस समय उपयोगी हो पाती है, जब उसके क्रियान्वय पर योजनाबद्ध और बहुमुखी विचार किया जाए। वैसा न होकर हुआ यह था कि एक अच्छी नीति का हसीन नारे के अर्थ में उपयोग किया गया था। और लचर ढंग से लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। ताकि सामान्य जन और भोला-भाला नागरिक समझे कि सुधारवादी प्रगतिशीलता लागू हो गई है। (इसलिए कि रोड़े छंट गए हैं।)

मुझे स्मरण है, राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश लागू होने के बाद सीधी-सादी एक हवा माहौल में उछली थी कि बैंक अपने हो गए हैं और अब देश के किसी भी व्यक्ति को अपना काम बढ़ाने, नया रोजगार शुरू करने या और-और योजनाओं के लिए पैसा मिलने में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। सब खुश थे—पर कुछ समझदार लोग परेशान। उन्हें लग रहा था कि जिस जल्दबाजी में यह सब किया गया है, वह राष्ट्रीयकरण के नाम से सत्ताधारी दल और श्रीमती गांधी का जनता के लिए राजीकरण ज्यादा है और उससे भी ज्यादा है अपने वैचारिक विरोधियों को खास तरह बदनाम करने की कुचैष्टा। यदि ऐसा न होता तो वेसवरी के साथ इस घोषणा की कोई तुक ही नहीं थी। वेसवरी का इससे बड़ा उदाहरण और सुवृत्त क्या हो सकता है कि खाजा साहब लिखते हैं—“उन्होंने यह साहसिक कदम अपनी निजी प्रेरणा से ही उठाया था, यद्यपि वित्त मन्त्रालय के अधिकारी और रिजर्व बैंक के गवर्नर विरोध करते और उन्हें निरुत्साहित करते रहते। उन्होंने अपने विचारों से सहानुभूति रखने वाले कुछ चुने हुए अफसरों और (या सरकारी सामन्तों? —भ्रमर) की सलाह से यह काम किया। एक विशेष कमरा उन्हें दे दिया

गया, जहा बैठकर उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित अध्यादेश को तैयार किया। सारी कारेंवाई इतनी तेजी से और इतने गुप्त रूप से पूरी की गई कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मन्त्री को तेजी के साथ यह कहते सुना गया कि 'प्रधानमंत्री को वित्त विभाग लिए हुए तीन दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया।' एक घण्टे के भीतर ही मन्त्रिमंडल की एक आपत्कालीन बैठक के लिए उस मन्त्री को बुला लिया गया था। इसपर प्रधानमंत्री ने बैंकिंग कम्पनियों के (व्यवसायों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश १९६६ पर अपने सभी सहयोगियों का एकमत समर्थन प्राप्त कर लिया।"

यह विवरण अपरोक्ष रूप से ही सही, किन्तु इस स्थिति को किसी न किसी रूप में प्रकट करता है कि एक गंभीर काम को भी किस उतावली में इसलिए किया गया था, ताकि वह एक खूबसूरत और सुभावने नारे का काम दे। यह नारा पर्याप्त काम दे भी गया। अयोजनावद्ध कार्य के कारण बैंकों को और जन-साधारण्य को बाद में कितनी उलझन हुई, यह बतलाने की बात नहीं है। एक अच्छी योजना थी, जो सही तरह लागू की जाने पर तुरन्त उपयोगी हो सकती थी परन्तु उसके लिए अनुकूल हालात पैदा करने आवश्यक थे। पर हुआ यह कि जल्दबाजी के कारण वही योजना खंड-खंड रूप में बरसी में ठीक-ठिकाने आ पाई। नारेबाजी का यह तंत कब तक चलेगा? इस पहलू पर विचार करने की समस्या उस समय थी ही नहीं, समस्या थी अपने-आपको काफ़ीटी पुख्तापन देने को। भले ही इस पुख्तापन के लिए 'गरीबी हटाने' के नाम पर सीधे-सादे नागरिकों को दिमागी तौर से छला जाए। यह छल लम्बा चला। इतना लम्बा कि छुद इन्दिराजी को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ होगा। एक जोरदार नारे की उछाल से उन्होंने ज़रूर समझ लिया था कि लोगों की भासूमियत को बड़ी आसानी से भुनाया जा सकता है। कितना, कहा, कैसे-कैसे भुनाया गया—यह वयान क्रमशः आया।

राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र, हर जगह आदर्शवाद से भरे प्रवचन अपना एक आलकारिक जायका रखते हैं। और इस जायके को इन्दिरा-शासन के दौरान जनता ने खूब चटखारे ले-लेकर महसूस किया है। बाद में बदहजमी से दुखी भी हुई है। श्रीमती गांधी के विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोगों से कहे गए कुछ शब्द मुझे याद आते हैं और आज जब मैं यहां अश-रूप में उन्हें उद्धृत कर रहा हूं, तब श्रीमती गांधी की सराहना करना चाहता हूं कि इस

देश के लोगों की एक खास नस 'भोलापन' खूब समझदारी से पकड़ी थी। अत्यंत मार्मिक शब्दों के साथ इस नस को हौले से दबाकर वोट दुह लेने का कमाल निस्सन्देह ही विलक्षण था।

“...ऐसी नीतियों का निश्चित निर्धारण आवश्यक है, जो गरीबों और जरूरतमन्दों की हित-चिन्ता के साथ अपने-आपको संतुलित स्थिति में जोड़ें...”
—इन्दिरा गांधी (वजट प्रस्तुतीकरण, १९७०)

“...देश में क्रांतिकारी कार्यक्रम विधि-सम्मत ढंग से लागू करने के लिए तत्पर होना होगा...” —इन्दिरा गांधी (एक भाषण, १९६६)

“... हम जनता के जीवन को स्वतंत्र-फल से समृद्ध-सम्पन्न करके उसे घर, और जीवन की सम्पूर्ण सुख-सुविधाएं देने में समर्थ हैं—इतिहास को यह वतलाना होगा।” —इन्दिरा गांधी (एक भाषण)

“जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए...” —इन्दिरा गांधी (एक पत्रकार से भेंट, ५ नवंबर, १९६६)

मगर ये चाकलेटी बातें किसपर असर कर रही थीं? उस बड़े वर्ग पर, जिसके मन में गांधी और कांग्रेस के प्रति श्रद्धा थी और जो श्रीमती इन्दिरा गांधी को उसी क्रम में देखता था, जबकि एक बड़ा वर्ग था जो यह भी महसूस कर रहा था कि हर रोज़ जनता की जीभ पर चाशनी फैलानेवाली इन बातों के बावजूद सक्रिय रूप में कुछ भी नहीं हो पा रहा है।

‘कुछ भी नहीं हो रहा है’ इस बात को विरोधी भी किरंतर दोहरा रहे थे, किन्तु उनकी साधनहीनता, आर्थिक लाचारी और शासकीय प्रचार-तंत्र की शक्ति ने उन्हें अपनी बात कह पाने या समझा पाने के सारे अवसर नहीं दिए थे। परिणाम हो रहा था, निरंतर इन्दिरावाद का फैलते जाना। बाद और बायदों की इस आंधी के दौरान ही चुनाव आया।

१९७१!

२७ दिसम्बर, १९७० को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि ने लोकसभा भंग करने और मध्यावधि चुनाव कराए जाने का आदेश प्रसारित किया। इससे पूर्व ही श्रीमती इन्दिरा गांधी के पक्ष से इस सिलसिले में प्रचार होने लगा था कि इस चुनाव का मूल कारण है जनता से सम्पूर्ण समर्थन प्राप्त करना, ताकि पूर्ण शक्ति, विश्वास और जन-समर्थन के साथ नई नीतियों को लागू करने के क्रांतिकारी कदम श्रीमती गांधी उठा सकें। इस टिप्पणी के साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि विरोधियों के कुतर्कों और बेहूदा

ढंग के विरोध के कारण ही श्रीमती गांधी सही तरह कार्य नहीं कर पा रही हैं।

इसके विपरीत विरोधी दलों के विभिन्न नेताओं ने राजनीतिक हालात पर बारीकी से गौर कर यह नतीजा निकाला था कि इन्दिराजी प्रजातांत्रिक दल की बंसाखी लगाकर क्रमशः तानाशाही की स्थिति तक पहुंचना चाहती है और इस तानाशाही को जन-स्वीकृति की मोहर से देश में लागू किया जाएगा। अनेक शीर्षस्थ नेताओं के तत्कालीन भाषण-अंश इस बात के गवाह हैं कि लगभग सभी नेता श्रीमती गांधी की राजनीतिक विचारधारा और व्यक्तिवाद को भली तरह समझ चुके थे। तपस्वी, कर्मठ और शांत स्वभाव राजनीतिज्ञ आचार्य कृपलानी ने उसी समय कह दिया था—“इन्दिरा गांधी को जिताना एक तरह से देश को तानाशाही की ओर धकेलना है। आज जिस अराजकता की बाढ में देश उलझ गया है, वह इन्दिरा गांधी की ही देन है।”

श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने एक भाषण में जनता से अपील की थी कि वे उस समय के महागठबंधन (संगठन कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल) को जिताएं ताकि लोकतंत्र जीवित रह सके। तथाकथित नई कांग्रेस को जिताने का मतलब होगा एक महान लोकतांत्रिक देश से लोकतंत्र की जड़ खोद डालना। श्री वाजपेयी ने विश्वास प्रकट किया था कि जनता भी उस तरह समझ पा रही होगी, जिस तरह देश के औसत पुराने और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ स्थिति की जटिलता समझ पा रहे हैं।

पर आचार्य कृपलानी, कामराज, अतुल्य घोष, अटलबिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे राजनीतिज्ञ यह अन्तर नहीं कर सके थे कि जिस बारीकी, दूरदर्शिता और गंभीरता से वे इन्दिरा-शासन के भविष्य की तसवीर देख रहे हैं, भारत का सीधा, सरल, लोकतंत्री मतदाता उस तरह नहीं देख पा रहा है। एक और कारण था—मतदाता के सामने फैला विशाल और असीमित सरकारी प्रचार-तंत्र के अतिरिक्त कांग्रेस का अपना शक्तिशाली आर्थिक तंत्र—जो सही स्थिति न तो उसे समझने का अवसर दे रहा था और न ही विरोधी दलों की बात सुन-समझ पाने की स्थितियां रहने दे रहा था।

इस सबके अलावा थे, चाटुकार पत्रकार, लेखक (बुद्धिजीवी ?) जो टिप्पणियां लिखकर, नये-नये नारों की सर्जना करके या पुस्तकें लिखकर निरंतर

उस शक्ति को बढ़ावा दे रहे थे, जो आगे चलकर उन्हींकी ज़वान बन्द करने वाली थी, उन्हींकी नाक में नकेल डालनेवाली थी और उन्हींके ज्ञान (अज्ञान) पर उन्हींको ज्ञानदान करनेवाली थी।

इस सबके साथ थी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की दोगली राजनीति, जिस राजनीति ने हमेशा ही देश में अस्थायित्व और अराजकता के निर्माण की धरती पैदा की थी। स्वतंत्रता-आन्दोलन में वह साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति की पक्षधर रही तो दूसरी ओर कांग्रेस में उसने गांधीवाद का मुखौटा ओढ़कर अपने आदमी धमाने और गड़बड़ी फैलाकर अनुशासनहीनता का वातावरण बनाने का रोल अदा किया। देश में राजनीतिक गड़बड़ी फैलाने की दूरदर्शी निगाह ने ही कम्यूनिस्टों को उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ किया था। लोकतंत्री नेताओं की तरह कम्यूनिस्ट नेता भी अच्छी तरह समझ चुके थे कि श्रीमती गांधी अन्ततोगत्वा उसी राह पर जानेवाली हैं, जिस राह पर कभी हिटलर जर्मनी में आया था—किन्तु यह राह निश्चित रूप से जन-असंतोष की जनक होनेवाली है और असंतोष की आपाधापी ही 'कम्यूनिस्टिक क्रांति' की ज़मीन बनती है। ज़मीन बनाने के लिए उन्होंने इन्दिरा गांधी के समर्थन में वह-वह दीर्घे लगाई कि अचरज होता था। लगता था जैसे इन्दिरा गांधी और उनकी पॉकेट-प्रांजिस्टर कांग्रेस को जिताने की जितनी चिन्ता कम्यूनिस्टों को है, शायद कांग्रेसियों को भी उतनी नहीं है।

जिस शान्तिवाद की बात व्यक्तिरूप में उछालते हुए लोग कांग्रेस में मसीहा बन गए, वह भारतीय जन-मानस और संस्कृति में ही व्याप्त है। धैर्य, संयम और विश्वास के शाश्वत नैतिक मूल्यों पर भारतीय हमेशा ही खड़ा रहा है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद जितनी नारेबाजी की, उस नारेबाजी और राजनीतिक दावपेंच में उलझे हुए भारतीय मतदाता ने एक बार फिर श्रीमती गांधी और उनके दल को महागठबंधन के विरुद्ध भारी मतों से जिताया।

श्रीमती गांधी की विजय पर तीव्रबुद्धि (?) पत्रकारों ने भारी-भारी टिप्पणियाँ और संपादकीय लिखकर कहा कि यह विजय जन-विजय है। सचमुच यह अचरज की बात है कि उतने अनुभवी और समझदार कहे जानेवाले पत्रकार और राजनीति-समीक्षक यह कैसे भूल गए कि तानाशाही भी लोकतंत्र का रूप धरकर आती रही है—विश्व-इतिहास गवाह है। क्या इसका कारण यह था कि ऐसे पत्रकार जानते नहीं थे कि इन्दिराजी का व्यक्तिवादी रूप क्या है और उनके

स्वभाव में किस अंश का ज्यादा जोर है ? मैं नहीं मान सकता कि नहीं जानते थे । सच यह है कि जानते-समझते हुए भी वे इस सबका समर्थन कर रहे थे... राजकीय कृपा के लोभ में ।

यह कि ऐसे लोग जानते थे कि उनका हथ क्या होगा ? या यह कि व्यक्तिवादी स्वभाव को समझ लेने के पश्चात् सुख-साधनों के मोह ने उन्हें चुपचाप एक गलत स्थिति को समर्थित करते रहने के लिए बाध्य किया था ?

और जो बाध्य नहीं हुए थे या जो अपने धर्म के प्रति मुस्तीद थे, बाद में हुए उनके हथ ने बहुत-सो के मुहों पर ताले डाल दिए थे । इसका बड़ा उदाहरण रहे श्री वर्गिस (हिन्दुस्तान टाइम्स के संपादक), जिन्हें सच बोलने की बहुत कुछ सजा भोगनी पड़ी । लोकसभा में और बाहर वर्गिस की सेवा-मुक्ति को लेकर विवाद उठा था जिसपर श्रीमती गांधी ने एक वक्तव्य देकर कहा था कि वर्गिस की सेवा-मुक्ति के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम ।

श्री वर्गिस हिन्दुस्तान टाइम्स लि० के अधिकारी थे और बाहरी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री या किसी मंत्री से उनका क्या सम्बन्ध बनता था कि उन्हें निकाला जाए या रखा जाए—पर इस तरह सोचते हुए यह कैसे भूला जा सकता है कि सत्ता-शक्ति के कुछ अदृश्य हाथ होते हैं और इन हाथों की सीमा अनन्त है । इस अनन्त की शक्ति आपातकाल के दौरान देश में खूब देखी गई है ।

। मार्च १९७१ के नया जीवन' में सम्पादक ने लिखा—“...यह जीत है श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति जनता की सहज चेतना से भरे विश्वास की । ”

और इस शानदार जन-समर्थन और जीत का लाभ क्या उठाया गया ? 'जनता की सहज चेतना से भरे विश्वास' के प्रति उस जनता को क्या भोगना पड़ा ? ...अंश रूप में वही, जो कभी एडाल्फ हिटलर के समय जर्मनी की घरती ने भोगा था ! पर वह विवरण बाद में, पहले व्यक्तिवाद और फिर तानाशाही के क्रमशः जमते पंरों की सक्षिप्त कहानी का सिलसिला ।

१९७१ के चुनाव में जितने हसीन नारे उछले थे, यथा — स्यायित्व, साम्प्रदायिकता से रक्षा, पूंजीवादी एजेण्टों से बचाव, लोकतन्त्र की स्थापना, अराधना आदि उनसे वही ज्यादा नारे देश के आसमान पर इन्दिराजी के बहुमत से विजयी होकर आने के बाद उछलने शुरू हुए । नारों पर देश को चलाने की यह तरीकीब नई नहीं थी । यह तरीकीब धिरासत में मिली हुई थी । और यह समझ

भी कि आसमान का मौसम देखकर कब कौन-सा नारा पतंग की तरह उड़ाने से जनता की आंखें ऊपर ही टंगी रह जाती हैं।

१९७१ के चुनाव के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की फिज़ा पूर्वापेक्षा कई हजार गुना बढ़ा दी गई थी। यह फिज़ा 'जनता के लिए जनता की बात' के अर्थों में बनाई गई थी। फूहड़ और उथली शब्दवाज़ी से उन गणमान्य नेताओं, यहां तक कि लोकतंत्री दलों के नाम उछाले जाने लगे थे, जिनका देश के स्वतंत्रता-संघर्ष में एक ऊंचा स्थान था। श्री प्रभाकर ने अपना एक संस्मरण लिखते हुए कुछ-कुछ इसी तरह की बात स्वयं भी की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में वयान किया है कि उनके कुछ मित्रों ने १९७१ के चुनाव के दौरान जब उन्हें यह समाचार दिया कि जनसंघ, संगठन कांग्रेस, वी० के० डी० और सोशलिस्ट पार्टी गठबंधन करके इन्दिरा जी और उनकी कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने (श्री प्रभाकर ने) फरमाया — "यारो, चार कोढ़न मिल जाएं तो क्या एक नूरजहां बन जाती है?"

ऐसी ही नारेवाज़ी इन्दिराजी के मंच से भी होती थी। इसकी स्वीकारोक्ति करते हुए ख्वाज़ा अहमद अब्बास लिखते हैं— "अधिकतर लोग समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के इन्दिरा गांधी के मंच से दिए गए वेगशील नारों से आकर्षित हुए थे..."

नारेवाज़ी पर सत्ता में जिए जाने के इस सिद्धांत के नये न होने की बात मैंने शुरू में की थी। यह नारेवाज़ी नेहरूजी से शुरू हुई थी और कांग्रेस में इसका इतिहास काफी पुराना है। उदाहरण के रूप में डॉ० राममनोहर लोहिया ने नेहरू सरकार पर आरोप लगाया था— "सबसे पहला आरोप मैं इस सरकार के खिलाफ यह लगाना चाहता हूँ कि यह अज्ञान के आधार पर बांझ और परिणामहीन लफ्फाज़ी तथा शब्दजोश के ऊपर अपना कामकाज चल रही है।"

यही नहीं, इसी भाषण में डॉ० लोहिया ने आगे कहा था— "प्रधानमंत्री साहब वामपंथी कहते हैं अपने को, शायद दिखाऊ वामपंथी हैं। उनके मुंह में वामपंथ और समाजवाद रहता है, लेकिन उनके हाथों में पूंजीवाद भी नहीं, सामन्तवाद रहता है!"

१. २१ अगस्त, १९६३ को लोकसभा में डॉ० लोहिया का भाषण, जो कांग्रेस के विरुद्ध पहले अविश्वास-प्रस्ताव पर दिया गया।

जाहिर है और जैसा कि मैं पूर्व में लिख चुका हूँ, यह विरोसती सामन्तवाद १९७१ के चुनाव में जबरदस्त लोकमत पाकर उस बावलेपन पर आ पहुँचा जिसे सम्पूर्ण तानाशाही कहा जाता है और इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे थे वे लोग, जिनकी अंगुलियों में ईश्वर ने कलम इसलिये साँपी है कि वे मानवीय मूल्यों की रक्षा करें। मानव के जन्मसिद्ध अधिकार स्वातन्त्र्य के रखवाले बनें।

एक उदाहरण है—श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का यह लिखना—
 "....युग का तकाजा है कि इस कल्पना की पूर्ति के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी फ्रांस के जनरल दिगान जैसा रूप लें और हरेक देशभक्त अपने-अपने स्थान पर अपने-अपने कर्तव्य का पालन करे।"

केन्द्र की सम्पूर्ण शक्ति हाथ में ले लेने के बावजूद श्रीमती गांधी यह निरंतर महसूस कर रही थी कि उस समय तक 'अपना चक्र' ठीक तरह नहीं घूम सकेगा, जब तक कि राज्यों को लौट-पलटकर उनमें अपने आदमियों को न बैठा दिया जाए। सहज ही था यह। जब जो मुगल सम्राट् आया करता था, वह साम्राज्य को अपनी तरह चालित करने के लिए सूबेदार बदल दिया करता था। यही हुआ ७१ के बाद। एक ओर केन्द्र-स्तर पर सूबेदार, हुबलदार बदलते गए, दूसरी ओर राज्य-स्तर पर नायकों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। यही कारण था कि ५ मार्च, १९७२ में देश के सोलह राज्यों और दो केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में मतदान आरंभ हुआ। देश एक बार फिर 'जलेबिया नारो' की चाखनी से भीग गया। जनता की घेतना से भरे विश्वास ने पुन रगत दिखलाई और संविद सरकारों को बड़ी सुविधा से गिरा लिया गया। अब अपने सूबेदार थे, अपने जमादार। राज-काज आरंभ हुआ।

इस सारे दौर में श्रीमती इन्दिरा गांधी को अधिनायकवाद की ओर बढ़ने के लिए भारतीय पत्रकार निरंतर उत्साहित कर रहे थे। एक ओर बहुल-सं कम्यूनिस्ट लेखक और पार्टी के सदस्य-लेखक थे, जिनके सोच मार्क्सवाद की फ्रेम में बंधे-बंधाए निकलते थे, दूसरी ओर तयाकथित गांधीवादी काफ़ेमी भी थे, जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इन्दिराजी के उन्नेजित व्यक्तिवाद को अधिनायकवाद में बदलने के लिए उत्साहित कर रहे थे। इस सन्दर्भ में प्रभाकरजी

की एक टिप्पणी, जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं ही बड़े गौरव के साथ किया है, देता हूँ :

“...अधकचरा संविधान आपके रास्ते में बाधक है। तब भी कोई बात नहीं। प्रजातन्त्र अपनी रक्षा के लिए आपको जनरल दिगाल की तरह प्रजातन्त्री अधिनायक के अधिकार देने को सहर्ष तैयार है।”

अधिनायकवाद के साथ प्रजातन्त्र ! कितनी हास्यास्पद स्थिति है ! ऐसे ही जैसे कहा जाए कि हम किसी मदांघ को यह अधिकार देते हैं कि यह अपना महान धर्म लाठी के जोर पर संसार में फैला दे।

और कौन दे रहा था यह अधिकार ? प्रभाकरजी ? हां, शायद सिर्फ प्रभाकरजी। इस देश में इस तरह के कितने ‘सिर्फ’ रहे होंगे ? पर इस तरह के जितने ‘गिने-चुने सिर्फ’ थे, उनके पास अपनी बात कहने-सुनाने के साधन थे, परिचय थे। परिणाम हुआ एक गलत रास्ते पर जाते राहगीर का और गलत हो जाना। वह राहगीर, जो मंच से कह कुछ रहा था और जीवन में कर कुछ रहा था। वह राहगीर, जो रास्ते की सही बतलाते हुए अपने साथ-साथ चलने वाले लोगों को भी गलत रास्ते चलाता चला गया।

बेहद मज्जेदार बात यह थी कि १९७१ में शासनारूढ़ होते ही श्रीमती इन्दिरा गांधी व्यक्तिवादी न रहकर अधिनायकवादी हो गई। ‘जन-अदालत’ के नाम पर उन्होंने सत्तारोहण किया था, उसी जन-अदालत में चुनाव के दौरान कभी उन्होंने विरोधी दलों पर आरोप लगाए थे—एक बार बोली थीं, “आज मैं संघ के नेताओं से पूछना चाहूंगी कि उनमें से कितने ऐसे अत्याचारों को सहते हैं और उनका मुकाबला करने का दावा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनमें से कितनों ने, खतरे झेलने की बात छोड़िए, आज़ादी के भी नारे लगाए हैं ? उनमें से कितनों ने अपनी गलियों में, और अपने घरों में आज़ादी के झंडे ऊंचे किए हैं ?”

और उसी जन-अदालत का गला उन्होंने आपातकाल के दौरान घोट दिया। उसी जन-अदालत का जिसने उन्हें ‘छत्रपति’ बनाया था। आपातकाल के बीस माह उस रुंधे हुए संघर्ष की तकलीफदेह कहानी हैं, जिसे तानाशाही के पंजों से मुक्ति के लिए जनता ने किया।

वही जन-अदालत थी, जिसने उन बीस माहों में भूल-सुधार किया और श्रीमती गांधी ने अपनी मोहक भाषा और पूर्वजों के त्याग के नाम पर जिन

करोड़ों लोगों के दिमाग में विरोधियों के प्रति विचित्र-सा कल्पित भय समो दिया था, उन्हें स्वीकार किया।

प्रगतिशील कार्यक्रम लागू करने की पुकार लगाकर श्रीमती गांधी ने १९७१ के चुनावों में जिस जन-अदालत के द्वारा अपने को जबरदस्त समर्थन में स्थापित किया था, बाद में उसी जन-अदालत की शक्ति और सार्वभौमिकता का मजाक उड़ाना शुरू हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार जनता को जो लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त थे, उनका हनन किया गया और इसकी बुनियाद पड़ी, ४ अगस्त के उस दिन जब ३८४ मतों के भारी बहुमत से संविधान का २४वाँ मंशोधन संसद में स्वीकार लिया गया। इस मंशोधन के अनुसार अब संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। हैरानी और दुःख की बात यह है कि इस मंशोधन विधेयक को सदन में स्वीकृति के लिए पेश करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने उत्साहित स्वर में कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र और समाजवाद की दिशा में एक क्रान्तिकारी और महान कदम है।

कैसी विरोधाभास की स्थिति थी? श्रीमती गांधी ने १९७१ का अपना चुनाव-प्रचार करते हुए लोकतंत्र, जनता, जन-अदालत और मानवीय मूल्यों की दुहाई दी थी, उन्हीं श्रीमती गांधी ने बड़े गौरव के साथ संविधान में अपने अधिनायकवाद की रक्षा के लिए जो चाहे परिवर्तन करने की एक औपचारिक स्वीकृति ली। मुझे याद आता है, अगस्त माह में जब तानाशाही की स्पष्ट बुनियाद पड़ी, तब चाटुकार लेखक, कवि, पत्रकार यह कहते नहीं अघा रहे थे कि अब देश में क्रांति का समय आया है। अब तक हम जिस संविधान पर खड़े थे, वह प्रतिश्रियावादी किस्म का था।

पर कुछ लोग थे, जिन्होंने आगामी खतरे को खूब भाप लिया। वे समझ चुके थे कि सर्वशक्तिसम्पन्न बनने की दिशा में यह पहला कदम है। ऐसे लोगों, पत्रकारों और नेताओं ने तत्काल वक्तव्य देकर इस मंशोधन को गलत भी बतलाया था। उन आगामी खतरो का भी संकेत किया था, जिन्हें बाद में जनमानस ने भोगा, पर इससे पहले कि सामान्य लोग स्थिति को समझ सकें, श्रीमती गांधी ने एक जबरदस्त स्टंट फेंककर लोगों का ध्यान उस ओर से हटा लिया। ठीक ४ दिन बाद ही (६ अगस्त, १९७१ को) संसद में पुनः एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ। इसके अनुसार भूतपूर्व शासकों के विरोधाधिकार समाप्त किए जाने थे।

सचमुच तुरूप चाल की इस राजनीति की मैं बार-बार सराहना करना चाहूंगा। भोलेभाले करोड़ों लोगों को राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार-समाप्ति के इस २६वें संशोधन विधेयक की खुशी में याद ही नहीं रहा था कि उससे पहले, सिर्फ चार दिन पहले, श्रीमती गांधी ने २४वें विधेयक के द्वारा एक अफलातूनी ताकत भी हासिल कर ली है।

विरोधी चिल्लाए, गलत के प्रति विरोध की कुछ आवाजें जनता में से भी उठीं, किन्तु शासकीय प्रोपेगण्डे के सामने वे नक्कारखाने में तूती की आवाज सिद्ध हुईं। हां सकता था कि कुछ गुनगुनी आवाज जनता तक पहुंचती, किन्तु फौरन वाद, यानी ६ अगस्त १९७१ को ही राजधानी दिल्ली में किराये के लाखों लोग लाकर एक जन-रैली निकाली गई और कहा गया कि इन्दिराजी के क्रांतिकारी कामों के समर्थन में भारतीय जनता हर्ष व्यक्त करने राजधानी में आई है।

अजीब बात यह थी कि इस रैली में, जिसमें लगभग आठ लाख व्यक्ति बतलाए गए थे, ज्यादातर लोग वे थे, जो दूर-दराज गांवों से दिल्ली-दर्शन करने आए थे। ऐसे कुछ लोगों से मेरी भी भेंट हुई थी, क्योंकि वे मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव से आए हुए थे और मुझसे मिलने इसलिए आए थे कि उनके गांव में मेरी रिश्तेदारी है।

ऐसे ही एक महाशय मेरे पास आकर बहुत खेदपूर्वक बतलाने लगे थे कि हम तो खाना, भत्ता और दिल्ली घूमने के चक्कर में चले आए, पर यहां आकर मालूम हुआ है कि खाने-पीने का कोई ठिकाना नहीं है। यही नहीं, वे इस बात से भी चिन्तित थे कि क्या मालूम यहां से वापसी के लिए वह ट्रक उपलब्ध हो सकेगा या नहीं, जो उन्हें ढोकर ग्वालियर से ले आया था।

रैली में हुई भीड़ के दर्शन र्भने स्वयं किए थे। शाम को पांच बजे अंसारी रोड की एक गली में, जिसके पिछवाड़े की ओर राजघाट रोड है, लाखों की संख्या में पर्यटकीय और स्थानीय, मंद और बच्चे भेड़ों के गल्लों की श्रृंखलाओं में घूमते नजर आ रहे थे। ये लोग सिरों पर समान की पोटलियां या हाथों में थैले लिए हुए बदहवाश दीखते थे। बतलाया गया था कि ये सभी महान विचारों के समर्थक हैं, और श्रीमती गांधी के क्रांतिकारी दृष्टिकोण और कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए दूर-दराज से आए हुए हैं। जबकि सच यह था कि उन्हें चरका देकर दिल्ली शहर में ढो लाया गया था और अब वे एक महानगर की अजनबी गहराइयों और माहौल में घबराए हुए उन बाहनों को तलाश कर रहे

थे, जो उन्हें रामलीला मैदान में एकजुट बनाकर शहर के जिस हिस्से में जगह मिली, जा दुबके थे।

इस रैली में नारों को और हसीन बनाया गया। वही पुराना नारा, जो १९७१ से पहले के चुनाव में भी उठा था—गरीबी हटाने का नारा। इस बार बदल गया था। अब उसके कवित्वपूर्ण शब्द आमसभा की छाती पर लटके हुए थे—‘गरीबी हटाएँ, समाजवाद लाएँगे।’

जन-क्रांति की पहली चिनगारी

इमरजेंसी के दौरान और उसके पूर्व ऐसी पुस्तकों की एक बाढ़ मिलती है, जिनके हर सर्जक ने श्रीमती गांधी के कार्यकलापों की प्रशंसा करते हुए उन्हें निरंतर अधिनायकवाद की ओर बढ़ाया और हर ऐसे लेखक ने एक-दूसरे से आगे बढ़कर श्रीमती गांधी के लिए वफादारी के वायदे किए। सबसे दिलचस्प बात यह थी ऐसा हर कृतिकार अपने को उसी ढंग से घोर समाजवादी और लोकतांत्रिक सिद्ध करने में लगा हुआ था, जिस तरह श्रीमती गांधी प्रशासन में नारे फैलाती रही थी। और जिस तरह इन नारों के अनुसार भारत का हर विरोधी दल साम्प्रदायिक, तानाशाह या पूँजीपतियों का गुर्गा बना हुआ था, उसी तरह इन टिप्पणीकारों या लेखकों के लिए वह था। सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, सगठन कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल और कई दल एकभाव से इन्हीं परिभाषाओं में प्रचारित किए जा रहे थे और एकमात्र दल बचा था, श्रीमती गांधी का कांग्रेस दल जो समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता, अहिंसा, शान्ति, श्रुति और प्रगतिशीलता में ओतप्रोत था। क्या यह बात अपने-आपमें कम विस्मयजनक है कि देश की आवादी के अस्सी प्रतिशत में बड़े दल मतलब थे और केवल बीस प्रतिशत को घटोरकर बना ली गई मोड़ कांग्रेस सही थी?

१९७१ के लोकसभा चुनावों तक हर चुनाव में नये-नये नारे उछलते रहे थे, वायदे फिकते रहे थे। ‘गरीबी हटाई’ जाती रही थी, कुमियाँ मुहंशो हटाई रही थी, किन्तु श्रीमती गांधी और उनके साथी निरंतर यह महसूस कर रहे थे कि अब जनता में व्याप्त असंतोष, भ्रष्टाचार और बेकारी को दूर करने के लिए दल की राह से नहीं गया-बनाया जा सकता, जिनसे अब तक राज चलता रहा है। तब क्या किया जाए?

तब एकमात्र चारा था, सुशासन की स्थापना करके भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, नौकरशाही, बढ़ते पूंजीवाद और सामाजिक विषमताओं से जनता को छुटकारा दिलाना। पर यह छुटकारा कौन दिलाएगा, किस तरह दिलाएगा? जिन अवसरवादियों की भीड़ लेकर श्रीमती गांधी ने सत्तातंत्र्य हथिया लिया है, वे तो निहित स्वार्थीवाले हैं। स्वयं श्रीमती गांधी जो कुछ करती आई हैं, वह केवल कुर्सी के मोह में हुआ है... तब इस जन-असंतोष को कैसे थामा जाए?

जन-असंतोष को थामने के लिए अब नारे बोदे सिद्ध होने लगे थे। भूखे, नंगे लोगों को रोटी की जगह नारे नहीं खिलाए जा सकते थे। लम्बी जवानी और अपनी उम्र के खूबसूरत दिनों को वेचकर जिस शिक्षा की युवकों ने प्राप्ति की थी, उन्हें आदर्श की बोदी बातों से नहीं समझाया जा सकता था। और इस सबके अतिरिक्त इन्दिरा-शासन के पास कोई भी कार्यक्रम नहीं था। जो कार्यक्रम था, वह सत्ता पाते ही पूरा हो चुका था। इसके बाद सवाल पैदा हुआ सत्ता पर जमे रहने का। पर कैसे जमे रहें? ...यानी कार्यक्रम रहा कुर्सी पर जमे रहने का।

विरोधी दल तूती की आवाज़ से ही सही, किन्तु निरंतर जन-साधारण को जतला रहे थे कि यह सब इस कारण है, क्योंकि वे एक आदर्शहीन और नकली शासन में जी रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी कमज़ोर आवाज़ जनता तक पहुंचेगी जरूर! ...और वह हुआ।

• गुजरात की उसी धरती पर हुआ, जिसपर कभी गांधी की अहिंसा ने जन्म लिया था और शांतिपूर्ण तरीके से देश में स्वतंत्रता की लड़ाई सम्भाली थी। गुजरात आन्दोलन को सामान्यतः पत्रकारों और राजनीतिक समीक्षकों ने एक प्रांतीय और क्षेत्रीय आन्दोलन कह दिया है। बहुत-से राजाश्रयी लेखकों ने उसे महज़ विरोधी दलों द्वारा भड़काया गया एक हिंसात्मक, उग्र और असामाजिक तत्त्वों का आन्दोलन बतलाया है, किन्तु मुझे लगता है कि गुजरात का छात्र-आन्दोलन वस्तुतः आज़ादी की दूसरी लड़ाई का पहला शंखनाद था, जिसकी गूँज सबसे पहले पूरे देश में सुनी गई और जिसका प्रभाव बाद में बिहार से एक विशाल विस्फोट के रूप में हुआ।

एक पत्रकार ने लिखा है कि "गुजरात आन्दोलन दुनिया का सबसे बेतुका आन्दोलन था, जिसमें अवयस्क मताधिकार द्वारा मांग की गई थी कि विधान सभाओं को तोड़ दो।" मूल सत्य को विसराकर एक कोई तर्क ढूंढ़ लेना—(और

तर्क भी ऐसा जो सचमुच तर्क हो) और फिर जवाब ही है। क्या अवयस्क मताधिकार द्वारा विधा चाहिए? पत्रकार महोदय क्या कहेंगे? इस वहस में लन की विशिष्ट बातें बतलाना चाहूंगा। जब एक देश की सत्ता अगर वेदम सिद्ध हो चुकी थी तो देश लड़खड़ाया हुआ था। भ्रष्टाचार, जमाखोरी, काल

और गरीबी व आर्थिक असमानता चरम पर पहुँचा हुआ था। वसा-स्थात में छात्रों ने अपने शासन-कर्ताओं से माग की कि यदि वे शासन सम्भाल नहीं सकते, तो उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। यही नहीं, जब कुर्सी-चिपकू कांग्रेस नेता नहीं माने तब बाध्य होकर छात्रों ने आन्दोलन प्रारंभ किया, सभाएँ की, घेराव करके विधान सभा-सदस्यों से माग की कि वे कुर्सी छोड़ दें और नये लोग चुने जाएँ। विरोधी दल स्वयं भी देश की हालत से अस्त हो चुके थे। इससे पहले कि जनता उनसे माग करती, उन्होंने स्वयं ही विधान सभा से त्यागपत्र दे दिए। पर कांग्रेसी? लम्बी-लम्बी लागतें लगाकर हासिल की गई कुर्सियों को कैसे छोड़ा जाए? वे हाई कमान का मुँह देखने लगे। इस भाव से कि आप आदेश करें तो हम पदत्याग करें, क्योंकि हमें तो सबसे पहले अपने कांग्रेस टिकिट के लिए चुना था, जनता तो वाद की चीज है।

और हाई कमान चुप! जनता की माग, नई पीढ़ी की आवाज और प्रात में फैली भयानक भ्रुखमरी के बावजूद चुप!

छात्र-आंदोलन जोर पकड़ता गया। निरीह लोग गोलियों से भून डाले गए। पट्टे-लिसे बेरोजगार जवानों को जेलों में ठूस दिया गया। परिणाम हुआ एक शान्तिपूर्ण आन्दोलन का 'क्रांति' के रूप में बदल जाना। अब एक ओर कांग्रेसी शासन की राइफलें थी, दूसरी ओर निहत्थी जनता के निरीह चेहरे, पर ये चेहरे अनंत थे और राइफलें गिनती की। हिंसक मशौन और निहत्थे मनुष्य के इस युद्ध को देश के विरोधी नेता सह नहीं सके। उन्होंने धुले दिल से जन-आन्दोलन का समर्थन किया। लोकनायक जयप्रकाश पहली बार स्पष्टतः कांग्रेस शासन के विरोध में आए और उन्होंने कहा कि अहिंसक आन्दोलनों के प्रति हिंसारमक रव लेना कांग्रेस की गांधीवादी परम्परा के अनुकूल नहीं है। जन-आन्दोलन को कुचलना जनतन्त्रीय पद्धति के विपरीत है। जो जनता स्वच्छ प्रशासन की माग कर रही है उसके साथ जयप्रकाश हैं। परिणाम हुआ जन-आन्दोलन और जोर पकड़ गया। इधर श्री मुरारजी

तब एक भूत कर दिया। इन्दिरा-शासन को घुटने टेकने पड़े। गुजरात में भूतजीत हुई। विधान सभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

गुजरात के आन्दोलन की सफलता ने सारे देश के सुलगते असन्तोष को सहसा विस्फोटक बना दिया। देश की नई पीढ़ी जाग गई और उसने एक बार फिर उसी इन्कलाव को अपनाया जो दुःशासन को दूर करने के लिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपनाया जा सकता था।

गुजरात के छात्र-आन्दोलन को लेकर श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर अपनी पत्रिका 'नया जीवन' के 'इन्दिरा अंक' में लिखते हैं—“दुर्भाग्यवश विरोधी दलों ने इसे अपनी जीत समझा और सोचा कि जो सत्ता हम चुनावों में जीतकर नहीं पा सके, वह विधान सभा को तोड़कर पा सकेंगे। बिहार भी मंत्रिमंडलों की बदला-बदली से अव्यवस्थित हो रहा था। बस, विरोधी दल बिहार की विधान सभा को तोड़ने पर पिल पड़े।”

क्या बेहतरीन और बारीक राजनीतिक दृष्टि है! एक ओर प्रभाकरजी लिखते हैं कि विरोधी दल बिहार की विधान सभा तोड़ने पर पिल पड़े और दूसरी ओर यह भी फरमा रहे हैं कि “बिहार भी मंत्रिमंडलों की बदला-बदली से अस्तव्यस्त हो रहा था।”

एकदम विरोधाभास! वही मसल हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब बिहार अस्त-व्यस्त हो ही रहा था और वहां एक वेपदी की सरकार चल रही थी तो अगर उस हालत में कोई जन-आन्दोलन उठा या विरोधी दलों ने नई और स्थायी सरकार के लिए व्यवस्था की मांग रखी तो कौन-सा अपराध किया?

एक अव्यवस्थित सरकार और मंत्रिमंडलीय उलटफेर के दौरान किसी शासन-तंत्र की क्या दशा हो सकती है? यह समझने या समझने के लिए माथापच्ची करने या किसी ज्ञानकेन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सहज ही यह समझा जा सकता है कि कोढ़ में अगर खाज ही लग जाए तो क्या होगा? भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता के अभिषाप में डूबे देश को जो भी नाममात्र की शासन-व्यवस्था मिली हुई हो, अगर वह भी ढिलमिल हो जाए, रोज़ मंत्री डूबें-उबरें तो प्रशासन और देश का क्या हाल हो सकता है? वही हो रहा था बिहार में...

बिहार के जन-आन्दोलन में वे बुनियादी मांगें उठाई गईं, जो केवल

बिहार की ही नहीं, सारे देश की थीं। भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमते, बेरोजगारी, निकम्मी शिक्षा-पद्धति आदि। इन प्रश्नों को कौन नकार सकता था? ठीक है कि बहुत-से विरोधी दल इस आन्दोलन के साथ थे, हमेशा रहे, किन्तु उन सभी ने एकमत होकर इस अहिंसक आन्दोलन या आति का नेतृत्व करने के लिए जय बाबू से निवेदन किया। यह सहज था। उन दिनों और उसके कुछ पूर्व जयप्रकाशजी के वक्तव्य आए थे, जिनमें उन्होंने देश की कष्ट दशा के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। उसी तरह, जिस तरह देश के बहुत-से तपस्वी नेता चिन्तित थे। आन्दोलन को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए था, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठा हुआ हो, जिसके विगत में महान आतिकारी का प्रेरणापूर्ण इतिहास हो और जिसका तन-मन देश की आत्मा में रचा-बसा हो। और वह व्यक्तिव जयप्रकाशजी के पास था। यदि सहज भाव से उनका नाम आने पर सभी दलों ने अपने छोटे-छोटे दायरों से हटकर एकमत होकर उनकी सत्ता और नेतृत्व स्वीकार किया तो इसपर कांग्रेसियों और कांग्रेस समर्थक लेखक-पत्रकारों के चौखला जाने की क्या बात थी?

सुरेश राम ने एक लेख में लिखा है—“मुवा पीढ़ी ने जयप्रकाश से प्रार्थना की कि वह उनका नेतृत्व करें। उन्होंने नौजवानों से कहा कि आपको शान्ति और अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा और निःस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लगना होगा। वे राजी थे। इसपर जयप्रकाश ने बागडोर अपने हाथ में ले ली।”*

सच थी उक्त स्थिति, किन्तु चौखलाए हुए कांग्रेसनिष्ठ (या इन्दिरा-निष्ठ?) लेखक कांग्रेस और इन्दिरा गांधी से कहीं ज्यादा चौखला उठे। क्या इसलिए कि इन्दिराजी की तरह वे भी इस महान आन्दोलन की चपेट में आकर उजागर होने लगे थे? मुझे एक शब्द याद आता है—लेंगवोट। बंगला शब्द है। एक विशालाकार नाव के साथ आठ-दस नावें जुड़ी रहती है और जब विशाल नाव डूबती है तो उससे जुड़ी हुई नावें भी डूब जाती है। जयप्रकाश के महान आन्दोलन के तूफान ने इन्दिरा शासन और उसके बहुत-से लेंगवोट मंत्रियों, अधिकारियों, लेखकों व पत्रकारों को उसी तरह थपेड़े देने धरु कर दिए, परिणाम हुआ विशाल नाव के डूबने से पूर्व इन लेंगवोटों का उलट-पुलट हो

जाना। असन्तुलित होकर इन लेंगवोटों ने जो जल-नृत्य किया, उसका वर्णन कहीं और करूंगा।

और विशाल नाव ? वह भी कम उछालें नहीं ले रही थी। इस तरह क्रांति का आरंभ और दमन का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी कहानी खत्म हुई—१९७७ के आम चुनावों में। पर यह कहानी का प्रारंभ है।

बिहार आंदोलन में बीखलाहट किस कदर बढ़ी, इसका प्रमाण है श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में बहुत-से समाचारपत्रों और पुस्तकों में वह लिखा जाना, जो उन्होंने कभी नहीं कहा। मुझे स्मरण है कि जयप्रकाशजी के आंदोलन को लेकर एक ओर भारी जन-चर्चा थी, दूसरी ओर सुलझे हुए बुद्धिजीवी निरंतर उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं ने जन-चेतना के लिए आंदोलन की समग्र पृष्ठभूमि जतलाते हुए बार-बार जन-मानस को तैयार किया था कि वह 'समग्र क्रांति' के इस अहिंसात्मक आंदोलन का अंग बनें और देश को एक नई व्यवस्था देने के लिए आगे आएँ। हिन्दी में 'धर्मयुग' के सम्पादक डॉ० धर्मवीर भारती ने बिहार आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके निरंतर बढ़ते रूप को लेखों और चित्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। और भी बहुत-से हिन्दी-अंग्रेजी दैनिक, साप्ताहिक पत्र थे जो इस काम में आगे आए थे। जिन मूल प्रश्नों को लेकर आंदोलन का श्रीगणेश हुआ था, उन्हें स्वीकारते हुए भी बहुत-से लोग वैयक्तिक रूप से श्रीमती गांधी के प्रति वफादारी निवाहने में लगे हुए थे। मुझे ऐसे बहुत-से लोगों की विरोधी बातें स्मरण हो आई हैं :

श्री राजा अहमद अन्नास ने अपनी पुस्तक* में लिखा है—“भारत में दरअसल अन्न की कमी नहीं है। इस मानव-निर्मित कमी की जिम्मेदारी नागरशाही द्वारा अन्न के अकुशल वितरण पर है। वह अन्न निगम के गोदामों में हजारों टन गेहूं और चावल सड़ने देती है। और पास ही लोग भूख से मरते रहते हैं। लेकिन इस पागलपन में एक पद्धति दीख पड़ती है क्योंकि उनके इस गोलमाल से अनाज के जमाखोरों, व्यापारियों और मुनाफाखोरों को भारी लाभ पहुंचाता है।”

इसी पुस्तक में एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं—“जनता की कठिनाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें सहा नहीं जा सकता। सिर्फ दो साल

* इन्दिरा गांधी : सफाई के दस वर्ष (१९७६-१९८०)

पहले उन्होंने जनता में जो ऊंची आशाएं जगाई थी, उनके कारण निराशा और सन्ताप की अनुभूति और भी प्रखर बन उठी है।”

एक अन्य स्थान पर इन्हीं लेखक महोदय ने ‘भारतीय स्थिति के (किन्हीं?) मित्रतापूर्ण आलोचक’ की राय को व्यक्त करने की मजदूरी बतलाते हुए लिखा है—“एक ईमानदार आदमी के लिए भारत में शांति के साथ रहना असंभव बन चुका है। बच्चों के दूध के डिब्बे की खरीद से लेकर कॉलेज में प्रवेश लेने तक, हर बात में कालावाजारी के तरीके इतने आम बन चुके हैं कि वे उसे बेईमान बनाकर ही छोड़ते हैं...”

श्री अम्बास ने चेतावनी दी थी कि यदि श्रीमती गांधी इन सारे हालात पर ध्यान नहीं देती और प्रशासन पर सुव्यवस्था का अकुश नहीं लगाती, तब ‘वह उनके लिए खतरनाक होगा।’

एक ओर देश की विपन्न स्थितियों और प्रशासनिक असफलताओं को अम्बास स्वीकार रहे थे, दूसरी ओर व्यक्तिपूजा में भी लगे हुए थे। यह सब लिख देने के बाद श्री अम्बास—जो उन्हींके अनुसार श्रीमती गांधी के शुभ-चिन्तक और मित्र हैं—उन्हे यह सुझाव भी देते हैं।

“अन्न को लेकर हुए दंगे, राशन की दुकानों की सूट, बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन, खतरनाक सामाजिक अशांति के चिह्न मात्र हैं। मजाक की ही बात है कि प्रगतिशील नारों का इस्तेमाल करके प्रतिक्रियावादी और अधानुगामी अपनी शक्तियों को पहले से ही एकत्र करते रहे हैं और आंदोलन को बढ़ाते रहे हैं।”

एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं—“यदि इन्दिरा गांधी अपने शुभ-चिन्तकों की चेतावनियों को नहीं सुनती तो शीघ्र ही उन्हे उनके और भारत के मोर्चाबन्द शत्रुओं की चोटों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि मित्र सिर्फ चेतावनी देता है—शत्रु चोट करता है।”

क्या ही जायकेदार कलमबयानी है! देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढाँचे की हर दरार स्वीकारते हुए उस दरार के प्रति इकलाव लाने वाले विरोधियों को अम्बास साहब बड़ी सुविधा से ‘उनका’ (इन्दिराजी का) और ‘भारत का’ शत्रु बतला रहे हैं। अशांति की सम्पूर्ण सत्ता स्वीकारते हुए उसे ‘चिह्न मात्र’ बतलाना भी क्या कम बड़ा मजाक है?

यही स्थिति है, बहुत-से ‘शुभचिन्तक पत्रकारों’ की। यदि जयप्रकाशजी के आंदोलन में अहिंसात्मक रैलियाँ और प्रदर्शनों के द्वारा श्रीमती गांधी और

उनकी सरकार से स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकारों और देश की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थितियों को सुधारकर सुशासन की मांग की जा रही थी तब समझ में नहीं आता कि इसमें भारत के प्रति कौन-सी शत्रुता थी ?

पर लेखन की 'जी-हुजूरी पद्धति' बड़े बेहूदा और कुतार्किक ढंग से श्रीमती गांधी का जय-जयकार करने में लगी रही, जबकि स्वतंत्रचेता बुद्धिजीवी, निरंतर 'समग्र क्रांति' से सहमति प्रकट करते रहे। चूंकि जयप्रकाशजी का आंदोलन सत्य की बुनियाद पर खड़ा था और छिछोरे राजनीतिक स्वार्थों से ऊंचा था अतः सहज भाव से जन-मानस में गहरे व्याप्त होता गया।

श्रीमती गांधी ने अपने अधिनायक स्वभाव के तहत आंदोलन के बारे में कहा—“गुजरात में जो कुछ हुआ, वह दूसरी बात थी। बिहार की विधान-सभा को किसी भी हालत में भंग नहीं किया जाएगा !”

संभवतः उस समय तक श्रीमती गांधी का खयाल था कि यह आंदोलन बिहार विधान सभा को गिराने के लिए ही है। यह भी अदूरदर्शितापूर्ण या ओछे राजनीतिक विचार की बात थी। आंदोलन जिस ज़मीन पर खड़ा था, वह ज़मीन केवल बिहार की नहीं थी। वह समान रूप से सारे देश की ज़मीन थी। देश की बुनियादी जरूरतों और सुधारों की ज़मीन थी। जबकि जयप्रकाशजी बार-बार यह कहते रहे थे कि यह मात्र किसी प्रदेश की सत्ता अथवा समस्या का आंदोलन नहीं है। ५ जून, १९७४ को पटना में जिस शाम विशाल जन-रैली हुई, उसमें जय बाबू ने स्पष्टतः घोषणा कर दी थी—“यह आंदोलन रुकेगा नहीं। यह समग्र क्रांति का आंदोलन है और इसका उद्देश्य केवल किसी विधान सभा का विघटन नहीं है, बल्कि यह तो एक महान रास्ते की पहली मंजिल है।”

सही था। जिन प्रश्नों पर बिहार-आंदोलन प्रारंभ हुआ, वे मात्र बिहार के प्रश्न नहीं थे। वे समूचे देश के थे। वे बिहार-आंदोलन से पूर्व गुजरात की जन-क्रांति के भी रहे थे। क्या यह छोटी-सी बात नहीं समझी जा सकती थी कि भूख सिर्फ बिहार की नहीं है, सारे देश की है। बेरोजगार, लाचार लोगों की छटपटाहट किसी प्रदेश के दायरे में नहीं बंधी है, सारे देश की आग बन रही है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी देश के एक टुकड़े-भर में नहीं है, समूचे देश में है। तब श्रीमती गांधी जैसे राजनीतिज्ञ उसे मात्र बिहार आंदोलन कहें—समग्र मांगों की रूपरेखा में—हास्यास्पद है।

गुजरात की विधान सभा भंग हुई थी। जन-क्रांति सफल रही। मुद्दे वही

थे, जो बाद में बिहार में विस्फोट के कारण बने, फिर सारे देश में। तब श्रीमती गांधी का यह कहना कि 'गुजरात में जो कुछ हुआ, वह दूसरी बात थी' समझ में नहीं आता। उसके बाद अगली धोपणा—“बिहार की विधान सभा को किसी भी हालत में भंग नहीं किया जाएगा।” राजहठ नहीं, तब क्या था? निस्सन्देह यह हठपूर्ण धोपणा श्रीमती गांधी के अधिनायकवादी स्वभाव का ही अंग थी।

५ जून, १९७४ के जिस जुलूस या रैली का जिक्र मैंने ऊपर किया है उसमें 'इन्दिरा ग्रेड' ने गोली चलाई थी।^१

किन्तु श्री प्रभाकर अपनी पत्रिका में इस तरह के सत्यो को दरकिनार करते हुए कहते हैं—“साफ-साफ अपनी बात कहूं कि वे (आंदोलनकारी) समझ गए कि हुल्लड़शाही आंदोलन से वे इन्दिराजी को नहीं हटा सकते, इसके लिए हिंसात्मक रूप लेना चाहिए।”

इस आंदोलन में जनसंघ भी शरीक था और हर दल की तरह उसके कार्यकर्त्ता भी समर्पण-भाव से जयवावू की अनुशासनबद्ध शांतिपूर्ण क्रांति में भाग ले रहे थे, किन्तु बदनाम करने वाली भाषा का उपयोग करते हुए श्रीमती गांधी ने एक जन-सभा में कहा—“ये संधी चीखते-चिल्लाते हैं, जलाते हैं और अल्पमत जनता को मारते हैं!”

जबकि स्थिति का सच इस तरह था—

१ पटना में ८ अप्रैल को आंदोलनकारियों ने एक मौन जुलूस निकाला था। इस जुलूस में केवल मांगों के बैनर लेकर लोग निकले। इसी तरह के प्रदर्शन अन्य स्थानों पर भी आयोजित हुए और फिर वे सिलसिले से होने लगे। इस आंदोलन का न दल था, न नाम। यह केवल जन-आंदोलन था और इसमें सभी विरोधी दलों के लोग तथा बड़ी मात्रा में जनता मौजूद थी। स्वयं प्रभाकरजी ने स्वीकार किया है कि जयप्रकाशजी ने नेतृत्व सम्भालते हुए आरम्भ बहुत उत्तम ढंग से किया। उन्होंने अहिंसा को आंदोलन की अनिवार्य शर्त बताते हुए उसे क्षेत्रों में बाटा था। स्पष्टतः उन्होंने एक जनमुखा में घोषित कर दिया था—“समग्र क्रांति का यह आंदोलन दल-विहीन राजनीति

१. ५ जून, १९७४ को जब पटना में एक जुलूस निकल रहा था तो इन्दिरा ग्रेड की तरफ से उसपर गोली चलाई गई।—मुरेश राम, इतिहास, पृष्ठ २२२

का प्रतीक होगा।" श्री प्रभाकर लिखते हैं—“आंदोलन को रैलियों के रूप में चौराहे पर ला पटका !”

भाषा और शब्द कितने ही व्यंग्यात्मक क्यों न हों, यह तो स्पष्ट है ही कि जयवाक् का आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था, जबकि सब कुछ मानते-जानते हुए इस आंदोलन का प्रचार शासकीय और राजकृपा के समर्पणवादी पत्र-कारीय स्तर पर हिंसात्मक कहकर किया जा रहा था। जितना भूठ और वेवुनियादी प्रचार गत पांच वरसों में भारत में हुआ, उतना संसार के किसी भी देश में, इतने अल्पकाल में नहीं हुआ।

मराठी की मुप्रसिद्ध लेखिका दुर्गा भागवत कहती हैं—“मगर सबसे बड़ा अफसोस यह है कि कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो हिन्दी के अधिकांश लेखक सरकार के चापलूस हो गए। जबकि हिन्दी प्रदेश की जनता ने खुलकर इस महान संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान दिया। जब जनता इस संघर्ष में जुटी थी, तब हिन्दी लेखक सरकारी प्रचार का अंग बनकर उसकी टांग खींच रहा था। यह चुनी-चुनाई नहीं, आंखों देखी बात है। कुछ वरिष्ठ लेखकों और संपादकों ने सरकारी दमन का पक्ष लिया। उसका प्रचार किया और जनता के साथ धोखा किया।”^१

सरकार और सरकारी लेखक प्रचार कर रहे थे कि जयप्रकाशजी का आंदोलन हुल्लड़बाजी से पूर्ण हिंसात्मक आंदोलन है, जबकि उस दौरान जो घट रहा था, वह एकदम विपरीत था।

गया में शात प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पुलिस ने भयानक गोलीवारी की। इस गोलीवारी के परिणामस्वरूप दस लोगों ने जान से हाथ धोए और सैकड़ों हताहत हुए। पर पिछले लेखक कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसात्मक रूप ले लिया था। गया में जो लोग मरे, उनमें एक भी पुलिसमैन नहीं था। मृतक सीधे-सादे नागरिक थे—कुछ किसान और कुछ मजदूर। किन्तु झूठे प्रचार-तंत्र की शक्ति के सामने घटनास्थलों से हजारों-लाखों मील दूर बैठे उस भोले देशवासी को कौन बतला सकेगा कि गोलियां प्रदर्शनकारियों के पास नहीं होतीं, होती हैं सत्ता के पास। और वे दसों आदमी गोलियों से मरे थे।

किन्तु इस दमन ने चेतना को ज्यादा तीव्र किया। पटना में ही एक और

बड़ा जुलूस निकला। इसमें हजारों वंडल थे और इन वंडलों में गांव-गांव से जनता के दस्तखत जुटाए गए थे कि शासन-व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। कहते हैं, यह जुलूस छह मील लम्बा और पूर्णतः अनुशासनवद्ध था। जयवावू स्वयं नेतृत्व कर रहे थे।

पर जैसाकि श्रीमती दुर्गा भागवत ने कहा है, हिन्दी के लेखक जन-आंदोलन से गहरी कर रहे थे। कुछ लोग राज्यसभा में पहुंचने का चक्कर खा रहे थे और कुछ लोग अपने अखबारों या ऐसे ही किसी छोटे-मोटे कारोबार के निहित स्वार्थ में लिप्त होकर ऊलजलूस बातें कह और लिख रहे थे। आंदोलन के मूल मुद्दों को जन-साधारण तक न पहुंचाकर वे व्यक्तिगत रूप में श्री जयप्रकाश नारायण पर कीचड़ उछालने में लगे हुए थे। कुछ लोग टूट पड़े थे जनसंघ पर, और विलकुल उसी भापा में, जिस भापा में, कांग्रेसी प्रचार-तंत्र या व्यक्तिगत रूप से श्रीमती गांधी बोलती रही थी, आरोप लगाने लगे थे। आंदोलन के सत्य-रूप को तोड़-मरोड़कर जनता के सामने पेश कर रहे थे। विशेष रूप से कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट लेखक इस पड्यत्र में शरीक रहे। उस सारे दौर में उनके विचार, प्रचार तथा लेखन-सभाषण का हर अंश देश और जनता के साथ विश्वासघात की एक तकलीफदेह स्मृति है।

बुद्धिजीवियों का एक पूरा दल ही संगठित रूप में एकत्र होकर वह भापा और आरोप बोलने लगा, जो उसके अपने दिमाग या बुद्धि के नहीं थे, बल्कि कांग्रेसी नेताओं की बुद्धि की राजनीतिक उगलन थे। व्यक्तिगत रूप में जयप्रकाशजी, मुरारजी भाई, कृपलानीजी, अटलबिहारी वाजपेयी आदि पर जो कीचड़ उछाला गया, वह उसी भापा और शब्दों में था, जिस भापा और शब्दों के साथ कांग्रेसी सत्ताधारी बोलते रहे थे। ऐसे कुछ उदाहरण हैं :

मंसद सदस्य कृष्णकांत को २५ जुलाई, १९७५ को कांग्रेस की महासचिव श्रीमती चन्द्रशेखर ने एक पत्र लिखा था और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के उस प्रस्ताव की याद दिलाई थी, जिसमें कांग्रेस जनो को हिदायत दी गई थी कि श्री जयप्रकाश नारायण का समग्र फाति दर्शन और आंदोलन फासिस्टों का मसूबा है और सारे देश में इसका विरोध किया जाना चाहिए।

इसी स्वर में हजार कदम आगे बोलते हुए श्री प्रभाकर ने लिखा—“जो लोग सारे देश में हतुलड मचाकर और कुछ नेताओं की हत्या करके प्रजातंत्री हुकूमत की जगह फासिस्ट डिक्टेटरी कायम करने की सब तैयारियां पूरी कर

का प्रतीक होगा।" श्री प्रभाकर लिखते हैं—“आंदोलन को रैलियों के रूप में चोराहे पर ला पटका !”

भाषा और शब्द कितने ही व्यंग्यात्मक क्यों न हों, यह तो स्पष्ट है ही कि जयबाबू का आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था, जबकि सब कुछ मानते-जानते हुए इस आंदोलन का प्रचार शासकीय और राजकृपा के समर्पणवादी पत्र-कारीय स्तर पर हिंसात्मक कहकर किया जा रहा था। जितना झूठ और धुनियारी प्रचार गत पांच बरसों में भारत में हुआ, उतना संसार के किसी भी देश में, इतने अल्पकाल में नहीं हुआ।

मराठी की सुप्रसिद्ध लेखिका दुर्गा भागवत कहती हैं—“मगर सबसे बड़ा अफमोस यह है कि कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो हिन्दी के अधिकांश लेखक सरकार के चापलूस हो गए। जबकि हिन्दी प्रदेश की जनता ने खुलकर इस महान संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान दिया। जब जनता इस संघर्ष में जुटी थी, तब हिन्दी लेखक सरकारी प्रचार का अंग बनकर उसकी टांग खींच रहा था। यह मुनी-मुनाई नहीं, आंखों देखी बात है। कुछ बरिष्ठ लेखकों और संपादकों ने सरकारी दमन का पक्ष लिया। उसका प्रचार किया और जनता के साथ धोखा किया।”

सरकार और सरकारी लेखक प्रचार कर रहे थे कि जयप्रकाशजी का आंदोलन हुल्लड़बाजी से पूर्ण हिंसात्मक आंदोलन है, जबकि उस दौरान जो घट रहा था, वह एकदम विपरीत था।

गया में शांत प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पुलिस ने भयानक गोलीबारी की। इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप दस लोगों ने जान से हाथ धोए और नौकड़ों हताहत हुए। पर पिटू लेखक कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसात्मक रूप ले लिया था। गया में जो लोग मरे, उनमें एक भी पुलिसमैन नहीं था। मृतक सीधे-सादे नागरिक थे—कुछ किसान और कुछ मजदूर। किन्तु झूठे प्रचार-तंत्र की शक्ति के सामने घटनास्थलों से हजारों-लाखों मील दूर बैठे उस भोले देशवासी को कौन बतला सकेगा कि गोलियां प्रदर्शनकारियों के पास नहीं होतीं, होती हैं सत्ता के पास। और वे दसों आदमी गोलियों से मरे थे।

किन्तु इस दमन ने चेतना को ज्यादा तीव्र किया। पटना में ही एक और

बड़ा जुलूस निकला। इसमें हजारों बंडल थे और इन बंडलों में गांव-गांव से जनता के दस्तखत जुटाए गए थे कि शासन-व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। कहते हैं, यह जुलूस छह मील लम्बा और पूर्णतः अनुशासनवद्ध था। जयवाज स्वयं नेतृत्व कर रहे थे।

पर जैसा कि श्रीमती दुर्गा भागवत ने कहा है, हिन्दी के लेखक जन-आंदोलन से गहरी कर रहे थे। कुछ लोग राज्यसभा में पहुंचने का चक्कर चला रहे थे और कुछ लोग अपने अखबारों या ऐसे ही किसी छोटे-मोटे कारोबार के निहित स्वार्थ में लिप्त होकर ऊलजलूल बातें कह और लिख रहे थे। आंदोलन के मूल मुद्दों को जन-साधारण तक न पहुंचाकर वे व्यक्तिगत रूप में श्री जयप्रकाश नारायण पर कीचड़ उछालने में लगे हुए थे। कुछ लोग टूट पड़े थे जनसंघ पर, और बिल्कुल उम्मी भापा में, जिस भापा में, कांग्रेसी प्रचार-तंत्र या व्यक्तिगत रूप से श्रीमती गांधी बोलती रही थी, आरोप लगाने लगे थे। आंदोलन के सत्य-रूप को तोड़-भरोड़कर जनता के सामने पेश कर रहे थे। विरोध रूप से कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट लेखक इस पडयत्न में शरीक रहे। उस सारे दौर में उनके विचार, प्रचार तथा लेखन-सभाषण का हर अंश देश और जनता के साथ विश्वासघात की एक तकलीफदेह स्मृति है।

बुद्धिजीवियों का एक पूरा दल ही मगठित रूप में एकजुट होकर वह भापा और आरोप बोलने लगा, जो उसके अपने दिमाग या बुद्धि के नहीं थे, बल्कि कांग्रेसी नेताओं की बुद्धि की राजनीतिक उगलन थे। व्यक्तिगत रूप में जयप्रकाशजी, मुरारजी भाई, कृपलानीजी, अटलबिहारी वाजपेयी आदि पर जो कीचड़ उछाला गया, वह उसी भापा और शब्दों में था, जिस भापा और शब्दों के साथ कांग्रेसी सत्ताधारी बोलते रहे थे। ऐसे कुछ उदाहरण हैं।

मंसूर सदस्य कृष्णकांत को २५ जुलाई, १९७५ को कांग्रेस की महासचिव श्रीमती चन्द्रशेखर ने एक पत्र लिखा था और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के उस प्रस्ताव की याद दिलाई थी, जिसमें कांग्रेस जनों को हिदायत दी गई थी कि श्री जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति दर्शन और आंदोलन फासिस्टों का ममूबा है और सारे देश में इसका विरोध किया जाना चाहिए।

इसी स्वर में हजार कदम आगे बोलते हुए श्री प्रभाकर ने लिखा—“जो लोग सारे देश में झुलड़ मचाकर और कुछ नेताओं की हत्या करके प्रजातंत्री हुकूमत की जगह फासिस्ट डिक्टेटरी कायम करने की सब तैयारियाँ कर

चुके थे इमजेंसी ने पहले ही कदम पर उनकी आजादी छीन ली है।”

कांग्रेसी नेताओं ने सी० आई० ए० का खासा होआ उन दिनों खड़ा कर रखा था। यह होआ एक राजनीतिक चक्र के रूप में उपयोग किया जाना था और इस हीवे को उन्होंने धीमे-धीमे जयप्रकाशजी के आंदोलन से जोड़ना शुरू कर दिया। इस हीवे को श्री प्रभाकर ने स्पष्टतः सी० आई० ए० नाम न देकर जिष्ट ढंग से उपयोग कर लिया। लिखते हैं—“आंदोलन के भीतर घुसे विदेशी एजेण्ट अपने हिंसा-जाल को गरम करते जा रहे थे।”

एक ओर यह स्थिति थी, दूसरी ओर उन पत्र-पत्रिकाओं की कमी नहीं थी जो श्रीमती गांधी का एक वक्तव्य आते ही बिलकुल उसी भाव से सम्पादकीय टिप्पणियां लिखकर आंदोलन का उसी तरह विवेचन करने लगते थे। इस जबरदस्त हवा का परिणाम यह हुआ था कि बहुत-से सुलझे हुए लोगों को, जो आंदोलन के समर्थन में बोलते थे और देश में एक रचनात्मक परिवर्तन तथा सामाजिक-राजनीतिक क्रांति की बात करते थे, निरंतर गलत समझा और बतलाया जाने लगा। कई बार यह समझाते हुए अजीब-अजीब तर्क ऐसे लोगों से सुनने को मिला करते। मुझे याद है, एक दिन मैं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री वासु भट्टाचार्य के यहां बैठा हुआ था। यहां-वहां की बातें चल रही थीं कि बिहार-आंदोलन की चर्चा निकल आई। वासु इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यह जन-आंदोलन है और उसके मूल में सामाजिक-आर्थिक विपमताओं के सुलझाव का प्रश्न है, बल्कि उनका विचार था यह महज राजनीतिक आंदोलन है और इस आंदोलन का मतलब सत्ता से श्रीमती गांधी या कि कांग्रेस को ही उखाड़ फेंकना है। जब वहस हो गई और काफी लम्बी चल चुकी तब अचानक वासु ने अपने सामने पड़ा हुआ ‘धर्मयुग’ का अंक उठाकर मेरी ओर उछाल दिया, बोले, “देखो इसे और बतलाओ कि इन चेहरों पर कोई क्रांति का भाव नजर आता है?”

मैं हैरान हुआ, “क्या मतलब?”

“मतलब यह कि ये जो आंदोलनकारियों के रंगीन और ब्लैक एण्ड व्हाइट चित्र छपे हैं, इनमें देखो—गौर से चेहरे देखो और फिर बतलाओ कि इनमें से एक भी क्रांतिकारी नजर आता है?”

“तब यह क्या है? क्या फोटो नकली हैं? डॉ० भारती ने अपने ड्राइंग-रूम में माटल झाड़वा करके पंचिका लिए हैं?” मैंने व्यंग्य से कहा।

वासु सरत नाराज हो बोले, “तुम बेकार वहस मत करो, इन लोगों को

देखो। ये सब निश्चिन्त, हंसते हुए नजर आ रहे हैं—इनके चेहरों पर क्रांति कहां है ?” सहसा वह सहज हुए। कहा, “यह सब राजनीतिक छल-प्रपंच है। जन-क्रांति-प्रांति कुछ नहीं !”

विचित्र तर्क था और इस तर्क के उत्तर में अपने-आपको विचित्र बनाना मुझे स्वीकार न था। हंसकर चुप हो गया।

तो, यह एक मिसाल है। क्रोध, आवेश और प्रचार की शक्ति के कारण बेहद सुलझे हुए बुद्धिजीवी भी भटक रहे थे। वे चित्रों में क्रांति ढूँढ रहे थे और भावों से यह समझना चाहते थे कि महंगाई, भुखमरी, बेकारी और भ्रष्टाचार है भी या नहीं। इस विचार-प्रचार की आंधी में भी यह नहीं सोचा जा रहा था कि आंदोलन वे करते हैं, जिनमें विरोध की शक्ति और माहा होना है।

बहरहाल वे फोटो-मुख—जिनके चेहरे पर वासु भट्टाचार्य को क्रांति नहीं दिख रही थी—क्रांति कर रहे थे और कांग्रेसी सत्तावाद की साठियाँ और गोलियाँ भी सह रहे थे। वे सीधे-सादे आदमी थे, ऐक्टर नहीं थे, इसलिए ऐक्टिंग न करके केवल क्रांति ही कर पा रहे थे।

इस जन-आन्दोलन के प्रति घोर मानवतावादी संत विनोबा भावे का रुख अजीब था। लोग उस समय बड़े हैरान हुए थे, जब आचार्य विनोबा भावे ने मलत के प्रति विरोध को केवल ‘ऊधम’ शब्द से सम्बोधित कर डाला। यही नहीं, उन्होंने सर्वसेवा सभ से प्रकाशित एक पुस्तिका में जयप्रकाशजी के आन्दोलन को एक तरह से वेतुका बतलाते हुए कहा कि शिक्षा पद्धति के दोष, महंगाई, मूल्यबुद्धि और इसी तरह के दोष आन्दोलन से कैसे मिटेंगे ?

यह तर्क भी अपने-आपमें विचित्र था। क्या आन्दोलन से दोष मिटते हैं ? दोष मिटाने की शक्ति जिनके पास थी, उन्हें यह आन्दोलन चेतावनी दे रहा था कि तुम इसे मिटाओ। यदि नहीं मिटा सकते तब कुतियाँ छोड़ दो। विनोबाजी अपने विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस के भ्रष्ट शासन के प्रति अजीब-से सम्मोहित दीख रहे थे। यही कारण था कि जब विनोबाजी को पटना (जून १९७४) में निकले जय बाबू के जुलूस पर इन्दिरा ब्रिगेड द्वारा गोली चलाए जाने की घटना की सूचना दी गई और पूछा गया कि उनकी क्या राय है, तब उन्होंने कहा—“पटना में जो कुछ भला-बुरा हुआ, वह सब भगवान को समर्पण।”

क्या मतलब हुआ ? यह सवाद किसी और तरह ही सही, पर अनायास

महाभारत के उस कांड की याद दिला देता है जब युधिष्ठिर जैसे सत्यव्रती भी कतराकर कह बैठे थे—'अथवत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा'।

गांधीजी के बाद सारे देश ने धर्म, सत्य और न्याय के लिए सदा विनोबाजी की ओर देखा है और वही विनोबाजी सत्य और असत्य के बीच से शब्द बचाकर निकल गए ! यही नहीं, उन्होंने आन्दोलन के प्रति टुकड़ों-टुकड़ों में विचित्र तर्क-विचार प्रस्तुत किए।

निस्सन्देह जयप्रकाशजी को विनोबाजी के इन विचारों और अनवृक्ष बदलाव पर दुख हुआ होगा, किन्तु क्रांतिधर्मी यों नहीं थका करते। सुरेश राम ने विनोबाजी के इस बदलाव के लिए स्पष्टतः लिखा है—“...विनोबाजी कांग्रेस सरकार से टक्कर लेना नहीं चाहते थे !”

कुल मिलाकर यह कि विनोबाजी जन-आन्दोलन के कभी समर्थक नहीं रहे, उल्टे (आगे कहीं लिखा जाएगा) उन्होंने अनेक बार एमर्जेन्सी के दौरान इन्दिराजी की तानाशाही को बड़े शालीन ढंग से और चुने हुए शब्द देकर समर्थित ही कर दिया। आन्दोलन के प्रति विनोबाजी के असमर्थन की बात करते हुए स्वयं जयप्रकाशजी ने अपनी जेल-टायरी में लिखा है—“मैंने अपने विचार सर्वसेवा संघ के माध्यम से कुछ चुने हुए लोगों और विनोबाजी के सामने रखे, लेकिन न तो विनोबाजी मेरे विचारों से सहमत हुए, न मैं उनके विचारों से।”

यह कोई नई बात नहीं थी। क्रांति और संघर्ष में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के समर्थन, असमर्थन की स्थितियाँ सदा ही आती रही हैं, पर किसी भी क्रांति के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण होता है जन-समर्थन, जो जय बाबू के साथ था और वही उनकी शक्ति थी। इस शक्ति से ही वे भ्रष्ट शासन-तंत्र को चलावनी दे रहे थे, गंमगं कर रहे थे।

आन्दोलन निरंतर तेज होता जा रहा था और उसकी तेजी के साथ-साथ कांग्रेस सरकार की लड़गड़ाहट-धोपलाहट बढ़ती जा रही थी। बिहार सरकार को ऐसे केन्द्रीय संकेत मिले थे कि आन्दोलन को सम्पूर्ण शक्ति से दबा दिया जाए, जबकि सरकारी तौर पर बार-बार प्रचार किया जा रहा था कि

1. "I put forward my own arguments, which will be found in the account of our conversation circulated by the Sarva Seva Sangh among a few selected persons. However Vinobaji was not persuaded, nor was I."

जयप्रकाशजी का आन्दोलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का पड़यंत्र है। किन्तु आन्दोलन किसी व्यक्ति या दलीय राजनीति के छोटे स्वार्थों पर नहीं टिका था, जिसे प्रचार के बल पर कुचल दिया जाता या दमन से दबा दिया जाता। जयप्रकाशजी का आन्दोलन जन-आन्दोलन था। जैसे-जैसे शासकीय कुप्रचार में तेजी आती गई, वैसे-वैसे वह जगल की आग की तरह बढ़ता-फैलता चला गया। असन्तुलित होकर कांग्रेस पक्ष के एक समझदार (?) नेता ने कहा—
“जयप्रकाश पागल हो गए हैं। ये देश में आग लगा रहे हैं!”

और जय बाबू का उत्तर था—“आग तो लगी हुई है, किन्तु नजर नहीं आ रही है। तुम्हारी कुर्सियों के नीचे आग सुलग रही है...”

पर यह आग सुलगाई किसने थी? जयप्रकाशजी के आन्दोलन ने? नहीं! “बल्कि कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजेवाद और सत्ता के दुरुपयोग से जनता को त्रस्त करते रहने के कई वरसों ने। जयप्रकाश का आन्दोलन मात्र न्याय की एक पुकार था, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति-विशेष की सत्ता उलटने या किसी संस्था को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उसके शुद्धीकरण का था। सत्य की प्राप्ति का था। घुटते-पिमते भारतवासी को माघी जैसे एक जन-नेता की आवश्यकता थी और उसने जयप्रकाशजी को बूढ़ लिया था।

कुल मिलाकर यह कि बेहूश प्रचार के बावजूद असत्य अपने-आपको जीवित नहीं रख पा रहा था। आन्दोलन गाव-गाव में फैल गया था, उसने बिहार की सीमाएं पार करके धीमे-धीमे उत्तरप्रदेश को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था।

४ नवम्बर को पटना में आन्दोलनकारियों पर कांग्रेसी शासन की पुलिस ने जबरदस्त लाठी-प्रहार किया। अश्रुगैम छोड़ी गई और भारी मद्धा में आन्दोलनकारी हताहत हुए। पटना की सड़कों और गलियों में निहत्थे आन्दोलनकारियों के घायल, कराहते हुए शरीर पड़े रहे, किन्तु आन्दोलन थमा नहीं। जयप्रकाशजी पर भी लाठीप्रहार हुआ। उनके साथ थे नानाजी देशमुख। जब जयप्रकाशजी लाठी-प्रहार से चोट खाकर गिर पड़े तो नानाजी उनके गिरे हुए शरीर पर ओट की तरह लेट गए और कई लाठियां सही। एक प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे बतलाया था कि यदि उस पल नानाजी बहा न होते तो शायद हम एक और गांधी को खो बैठते।

मुझे उसी क्षण लाला लाजपतरायजी का स्मरण हो आया था, जिन्होंने क्रूर ब्रिटिश शासन की लाठियों के प्रहार सहें थे और बाद में कहा था कि उनके

शरीर पर जितनी चोटें आई हैं, उतनी चोटें ब्रिटिश शासन ने अपने-आपको पहुंचाई है ...^१

जयप्रकाशजी पर हुआ लाठी-प्रहार कांग्रेसी शासन का स्वयं पर लाठी-प्रहार था। इस घटना की पूरे देश के लोकतंत्री जन-मानस में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई। विद्वानों और कर्मनिष्ठ पत्रकार-लेखकों ने समझ लिया कि अब इन्दिरा-शासन की समाप्ति के दिन आ पहुंचे हैं। इस अमानवीय अत्याचार पर कई प्रमुख पत्रों ने टिप्पणियां लिखकर शासन की इस अदूरदर्शितापूर्ण और दमनकारी प्रवृत्ति की निंदा की। जयप्रकाशजी ने दुख के साथ कहा—“अंग्रेजी राज में भी ऐसी क्रूरता नहीं देखी गई। अपने लम्बे, पचास वर्षीय राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसी वर्चस्वता कभी नहीं देखी।”

लोकतंत्र की आड़ में बैठे राजतंत्र से अब जन-मानस की घृणा चरम पर पहुंच चुकी थी। किन्तु विनाश काले विपरीत बुद्धिः। शासन की दमनकारी और अप्रजातान्त्रिक कार्यवाहियों में तनिक अन्तर नहीं आया। काश ! ... इन्दिराजी उस क्षण समझकर सावधान हुई होतीं कि यह दमन और गोलीबारी एक दिन एक महान संस्था और उनके अपने अधिनायकवाद का अंत कर देगी। जयप्रकाशजी पर हुआ लाठी-प्रहार उसी दिन सौ साल पुरानी कांग्रेस के संस्थागत ढांचे को जगह-जगह से तोड़ चुका था।

जयप्रकाशजी ने अगले दिन, यानी ५ नवम्बर को पटना-बन्द और फिर ६ नवम्बर को बिहार-बन्द का आह्वान किया। लोकनायक का आदेश जनता ने सिर झुकाकर मान्य किया। उन दिनों के जन-रोष और बन्द की सफलता की कल्पना इससे की जा सकती है कि पटना में एक व्यापारी को अपने ट्रक से माल उतारने के लिए मजदूर तक नहीं मिले थे। बिहार आन्दोलन के दौरान कुछेक बुद्धिजीवी अत्यंत सक्रिय रूप में सामने आए। उपन्यासकार श्री फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने अपनी अस्वस्वता की परवाह न कर विभिन्न जुलूसों में भाग लिया और प्रदर्शनों में लाठियां सहीं। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सरकार की दमन-नीति के विरोध में उन्होंने राजबलंकरण त्यागा और जेल में यातनाएं सहीं।

१. ब्रिटिश राज में जब साइमन कमिशन का आगमन हुआ तब लाला लाजपत राय शान्तिपूर्ण ढंग से उसके वायकाट में प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं उनपर लाठी प्रहार हुआ था।

नागार्जुन ने चौराहे-चौराहे क्रतिकारी कविताएं सुनाई और अलख जमाया। आन्दोलन तीव्र से तीव्रतर होता गया।

पर इन्दिरा-शासन और उसके ढोलकी निरंतर आन्दोलन को बदनाम करने के लिए अजीबोगरीब प्रचार में जुटे हुए थे। इस प्रचार का घुणित रूप उस समय सामने आया, जब रेल मंत्री श्री नलितनारायण मिथ की बिहार में हत्या हो गई। श्री मिथ की हत्या एक सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम थी, किन्तु राजनीतिक स्तर पर इस हत्या और जयप्रकाशजी के आन्दोलन को जोड़ने का कुप्रचार आरंभ हो गया। कहां से, किस तरह, किसने इसे प्रारंभ किया, तय नहीं है पर मुझे अच्छी तरह याद है कि छोटे से छोटा कांग्रेस कार्यकर्ता बेहूदा ढंग से मिथजी के हत्याकांड को आन्दोलन से जोड़ता फिरता था। ऐसे कई लोगों के मुंह से मैंने कुतर्कों के साथ इस घटना को सुना है। सत्य की खोज पुलिस करे और न्याय न्यायालय दे, इसके पहले ही इस प्रचार में घटना को इस तरह उभारा जाने लगा, जैसे जो-जो साहेबान उसका बयान कर रहे हैं, वे आन्दोलन और हत्याकांड, दोनों, से बेहद करीबी हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी जिम्मेदार पद पर बैठी महिला कह बैठी—“सब जानते हैं कि जयप्रकाशजी का असली निशाना कौन है? सलित बाबू की हत्या एक बड़े निशाने का पूर्वाभ्यास है!”

मगर छोखले प्रचार से न तो व्यक्ति जीते हैं, न मस्याएं खड़ी रहती हैं। असत्य बहुत दिनों सत्य को छिपाए नहीं रख सकता। अंधेरे में सूरज को निगलने की ताकत नहीं होती। मिथजी की हत्या और आन्दोलन को जोड़ने का छिछोरा प्रचार भी जल्दी ही उजागर हो गया।

श्रीमती गांधी की इस तरह की बातों के गैरजिम्मेदाराना ढंग पर स्वयं जयप्रकाशजी ने लिखा है—“मैं समझ चुका हूं कि इस तरह की व्यर्थ बातों पर न तो भारत का कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है और न ही कोई लोकतांत्रिक देश उन्हें मान सकता है।”

एक ओर जयप्रकाशजी योयी बातों की परवाह नहीं कर रहे थे, दूसरी ओर ‘नया जीवन’ के सम्पादकजी टिप्पणी लिखकर जय बाबू के बारे में उल्टा

1. “I am convinced that neither the people of India nor of the western democracies will ever be persuaded to swallow her lips.”

और अन्धा आरोप कर रहे थे—“जिस विचारक के विचारों में विद्वानों के मन की विसंगति दूर करने की क्षमता थी, हुताशा में वह विसंगतियों के ढेर लगा रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री जय बाबू के नेतृत्व और व्यक्तित्व में क्या तुलना ? एक घोर संकट के समय देश का नेतृत्व कर रही है और दूसरा चुनाव की तैयारी के लिए जनता के पास न जाकर चुनी हुई विधान सभा को तोड़ने की शोब्देवाजी कर रहा है।”

इन्दिराजी के जिस संवाद को मैंने पूर्व में लिखा है और उसके बाद जयप्रकाशजी की जेल-डायरी का जो उद्धरण दिया है, उससे पाठक सहज अन्दाजा लगा सकते हैं कि इन्दिराजी और जय बाबू—दोनों में से हुताशा का शिकार कौन था ? उथली शोब्देवाजी कौन कर रहा था ? नेतृत्व और व्यक्तित्व किसके पास था ? कुर्सी के पास कौन था और जनता के पास कौन था ?

“और संपादक ‘नया जीवन’ जनता से पास थे या कुर्सी के पास थे ?

जनवरी १९७५ तक आन्दोलन इतना तीव्र हो चुका था कि देश-भर में हर प्रान्त के मुख्यमंत्री को केन्द्र सरकार से विशेष सतर्कता वरतने की हिदायतें देते हुए कठोरता से दमन कर डालने को कहा गया था। पुलिस के विशेष दस्ते बिहार और कई जगहों पर भेजकर दमन कार्यवाही तेज कर दी गई थी।

मार्च १९७५ में सात विरोधी दलों के नेताओं के साथ जयप्रकाशजी के नेतृत्व में दिल्ली में विशाल जुलूस आयोजित हुआ। कई किलोमीटर लम्बे इस जुलूस ने राजधानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए संसद-भवन तक यात्रा की और राज्यसभाध्यक्ष श्री वी० डी० जत्ती एवं लोकसभा के अध्यक्ष दिल्ली के सामने एक मांगपत्र प्रस्तुत करते हुए उसपर तुरंत कार्रवाई के लिए कहा। इस मांगपत्र में बहुत-सी बातें कही गई थीं और वे क्षेत्रीय स्तर की नहीं थीं, बल्कि देशव्यापी समस्याओं की ओर तुरंत ध्यान देने की थीं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे :

- भूमिसुधार किया जाए ताकि भूमिहीन लोगों को भूमि मिल सके और ग्राम-विकास हो सके।
- आर्थिक असमानता को खाई पाटी जाए।
- महंगाई पर काबू किया जाए। राष्ट्रीय आय की दर के अनुपात में मूल्य हों।
- बिहार विधान सभा और मंत्रिमंडल को भंग करके नये चुनाव कराए जाएं।

- जीवन के लिए भ्रष्टाचारों की आवश्यकताओं को देखते हुए न्यूनतम भ्रष्टाचारी मिले।
- शासकीय व्यय में कटौती की जाए। भ्रष्टाचार दूर हो।
- चुनावों में निष्पक्षता लाई जाए। जनतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए। और समाज के कमजोर वर्गों को उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के सारे साधन जुटाए जाएं।
- कृषि के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि ग्रामों की अर्थ-व्यवस्था का समुचित विकास हो सके।
- राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो।
- शिक्षा-व्यवस्था में सुधार किया जाए।

और भी अनेक महत्वपूर्ण मांगें थी, जिनसे देश को एक सही व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक विकास तथा स्थायित्व मिलना था।

जनता की मांगें 'जनता के प्रतिनिधियों' तक पहुंचाई गईं, पर कुछ नहीं हुआ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलता रहा।

जनता की मांगों की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्या इसलिए कि सरकार बेखबर थी? या इसलिए कि सरकार को लगता था कि वे समस्याएं, जो मांगपत्र में उठाई गई थी, देश में नहीं हैं? नहीं। कांग्रेसी शासन सत्य से जानकार था, किन्तु राजनीति और कुर्सी से बिलग होकर सोचने-समझने की उनकी शक्ति ही जाती रही थी। यदि शक्ति होती तो देश के सामने न तो आज की विषम परिस्थितियां खड़ी होती और न जयप्रकाशजी को एक बार फिर आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ती। इन्दिरा-सरकार ने जिस संकुचित भाव से देश की राजनीतिक स्थिति को देखा था, उसी संकुचित भाव से जयप्रकाशजी के आन्दोलन को देखती रही। यही कारण था कि बार-बार जन-मंच से श्रीमती गांधी आन्दोलन के विरुद्ध बोलते हुए कहती रही कि यह सब उन्हें उखाड़ने और अपदस्थ करने तथा सत्ता में पहुंचने के लिए किया जा रहा है। जबकि सब था यह कि आन्दोलन का जरूरिया उतना छोटा नहीं था, जितना श्रीमती गांधी का था। आन्दोलन का जरूरिया था देश की बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के लिए लापरवाह कांग्रेस शासन को ध्यान दिलाना और न ध्यान देने की स्थिति में उससे मांग करना कि निष्क्रिय नेतृत्व की देश को आवश्यकता नहीं है, अतः उन्हें पद-त्याग कर पुनः जनता अदालत में विश्वास पाने के लिए आना चाहिए।

निश्चित रूप से मेरी राय है कि इस तरह के लेखन और चापलूसी से भरी बातों ने श्रीमती गांधी के अधिनायकवादी स्वभाव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया। अपनी डांवाडोल राजनीतिक स्थिति और जनता के जन-जन में व्याप्त विरोधी विचारों को देखते हुए ही उन्होंने एक खतरनाक किन्तु भयावह निर्णय कर कर डाला। यह निर्णय था—आपातकाल! “इमजेंसी!”

‘नया जीवन’ के टिप्पणीकार ने लिखा है—“हाईकोर्ट के फैसले ने, इसमें शक नहीं, इन्दिराजी को वैसे ही झकझोर दिया, जैसे १९६२ में चीन के आक्रमण ने जवाहरलालजी को...”

और इस झकझोर से गुजरती इन्दिराजी सही-गलत का भेद न करके किसी भी तरह अपनी सत्ता बचाए रखने पर तुल गईं। उनकी हठधर्मिता पर वे सब हैरान थे, जो गांधीजी के सत्य-अहिंसा पर विश्वास करते रहे थे और जो अब तक मानते आए थे कि इन्दिराजी कांग्रेस के महान आदर्शों की विरासत सम्भाले रहेगी। इसके बावजूद कि कांग्रेस दल में बहुत-से जनतन्त्रवादियों की निष्ठा खत्म होती जा रही थी (यह निष्ठा जयप्रकाशजी के आन्दोलन के दौरान श्रीमती गांधी की अधिनायकवादी मनोवृत्ति के कारण ज्यादा टूटी थी) भीतरी तौर पर कांग्रेस में भी विद्रोह पनप रहा था। सर्वश्री चन्द्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत और रामधन जिन्हें युवा तुर्क कहा जाता था और जो कभी श्रीमती गांधी पर अपना समूचा विश्वास करके कि वे जनतन्त्र की रक्षक सिद्ध होंगी और समाजवादी नीतियों को देश में लागू करने के लिए अगुआ बनेंगी, जबर-दस्त समर्थन देते रहे थे, दबा-दबा विरोध प्रकट कर रहे थे। इन नेताओं में काम करने की लतक थी, उन्हें कांग्रेस के मूल जनवाद की पहचान भी थी और वे जनतन्त्र में पूरा विश्वास रखते थे, पर अब महसूस करने लगे थे कि इन्दिरा गांधी क्रमशः तानाशाही की ओर बढ़ रही है। इसकी स्पष्ट झलक उस समय मिली थी, जब श्री कृष्णकांत ने ११ मई, १९७५ को ‘धर्मयुग’ के लिए विशेष रूप से दी गई एक भेंट-वार्ता में कांग्रेस-सदस्यों को ज़िद से बाज़ आने तथा राष्ट्रहित में श्री जयप्रकाश नारायण से वार्ता करके समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने की बात की। उन्होंने आर्थिक पहलुओं पर जयप्रकाशजी से बातचीत करने के लिए विशेष बल दिया था।

प्रकटतः कांग्रेसी स्वयं अनुभव करने लगे थे कि श्रीमती गांधी गलत रास्ते पर जा रही हैं। किन्तु श्रीमती गांधी ने जन-आन्दोलन को अपनी प्रणियता का

प्रश्न बना लिया, राष्ट्र के हिताहित का विचार न करते हुए अपने अधिनायक-वादी स्वभाव को ज्यादा तेज बनाना जारी रखा। कांग्रेस की जनतंत्रीय व्यवस्था केवल एक व्यक्ति का खेल बनकर रह गई।

रामलीला मैदान में २५ जून, १९७५ को एक विशाल सभा हुई, जिसमें श्री नारायण ने जनता को संबोधित किया। इस सभा में जयप्रकाशजी ने प्रधानमंत्री से मांग की कि न्यायालय और कांग्रेस के महान सिद्धांतों का आदर करते हुए श्रीमती गांधी को चाहिए कि वे त्यागपत्र दे दें। यदि वे ऐसा नहीं करतीं तो जनता को बाध्य होकर राजधानी में प्रदर्शन करने पड़ेंगे। और ऐसे ही शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सारे प्रदेशों में उस समय तक किए जाते रहेंगे, जब तक कि श्रीमती गांधी त्यागपत्र नहीं देतीं।

जय बाबू ने भाषण में यह भी कहा कि राजधानी में ये प्रदर्शन सात दिनों तक चलते रहेंगे। सभा में नारे लगाए गए और जनता ने एकमत होकर जय बाबू की मांग का समर्थन किया।

काली, लंबी रात

२५ जून की रात शुरू हुई। १२ बजे के बाद २६ जून का दिन भी रात में जनम ले रहा था। एक रात सत्ता के दिमाग में छद्म हुई थी जो अचानक सारे देश पर बरस पड़ी और जिसने आने वाले सैकड़ों दिन काले कर डाले ! ... यह रात थी—आपातकाल की घोषणा ! सारे देश में यह रात पुलिस की तैज गतिविधियों और सत्ता के निरंकुशवाद से भर उठी। २५-२६ जून की रात को दो बजे श्री जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार कर लिए गए। श्री मुरारजी भाई और अन्य सभी प्रमुख नेताओं को जेलों में पहुंचाया गया। ये नेता कहां, किस जगह ले जाए गए थे—किसीको सूचना तक नहीं दी गई।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के नाम एक भाषण में कहा कि आपातकाल इसलिए लगाया जा रहा है, क्योंकि देश की आंतरिक स्थिरता गतरे में पड़ गई है। विदेशी शक्तियों से संचालित लोग इन गड़बड़ियों के कारण हैं। कानून और व्यवस्था बिगड़ चुकी है और इस अराजकता में असामाजिक तत्त्व हावी हो रहे हैं। उनके (श्रीमती गांधी के) सामने इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया था कि वे शस्त्री के साथ अराजकता पर काबू करें और असामाजिक तत्त्वों को कुचन डालें।

कौन थे ये असामाजिक तत्त्व ? जयप्रकाश नारायण ? मुरारजी भाई ? अटलबिहारी वाजपेयी ? अशोक मेहता ? चन्द्रशेखर ?...

उत्तर नहीं है ! इतिहास कहता रहेगा कि इस आपातकाल रूपी काली घिनीनी रात से शुरू हुई तानाशाही के पास कोई कारण नहीं था । सिर्फ झूठे और वेबुनियाद आरोपों से भरे प्रचार के अतिरिक्त !

सच के मुंह पर ताला डाल दिया गया । अखबारों पर सेंसर, जन-सभाओं और जन-प्रदर्शनों पर रोक, गिरफ्तारी का कारण जानने पर रोक । आपातकाल ! ...किसका आपातकाल ? देश का ?

नहीं, कुछ कुर्सियों का ! जो सत्य-अहिंसा की शक्ति के सामने लड़खड़ा गई थी । जिनके पैरों में भ्रष्टाचार, अन्याय और वर्चस्व का धुन लग चुका था ।

प्रचार-तंत्र ने आश्चर्यजनक रूप से तेजी पकड़ी । एक गलत कार्रवाई के प्रति सारे देश के जन-मानस में आक्रोश और घृणा की सहर थी । क्या व्यक्ति-स्वातंत्र्य, मूल मानव-अधिकारों और न्याय की हत्या कर देने का नाम जनतंत्र है ? यह एक नई परिभाषा थी, जो आपातकाल के रूप में, उस संस्था का नेतृत्व कर रही थी, जिसने उक्त सारे नारे लेकर ब्रिटिश शासन की गुलामी के विरुद्ध कभी झुकलाव किया था । क्या ये वही कांग्रेसी हैं ? क्या वह वही सत्ता है ? क्या इन्हे ही हमने अपनी रक्षा के लिए देश के आसन सौंपे थे ?

नहीं ! देशवासी ठगे गए !

आपातकाल के नाम से सारे देश में तानाशाही की स्थापना हुई । करोड़ों लोग चुपचाप, निराश, धकी निगाहों से विस्मय और आतंक के साथ अमानवीय अत्याचार देख-सह रहे थे । न कोई निमम था, न कानून, न व्यवस्था, न व्यक्ति-भेद । जो कुछ था, वह सिर्फ एक—श्रीमती इन्दिरा गांधी !

तानाशाही आएगी—पिछले कई बरसों से कई नेता कहते रहे थे । जनसंघ ने १९७० के आम चुनावों में निरन्तर दोहराया था कि श्रीमती गांधी के भीतर तानाशाह बैठा हुआ है, जो हिटलर और मुसोलिनी में था । उस क्षण कांग्रेस-मंच से जन-स्तर पर और शासकीय स्तर पर निरन्तर प्रचार किया जाता रहा था कि विरोधी दल देश के लिए कोई कार्यक्रम लेकर नहीं सड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें श्रीमती इन्दिरा गांधी से व्यक्तिगत टाह है और इसीलिए उन्होंने नारा दिया है—‘इन्दिरा हटाओ !’

श्रीमती गांधी ने उस अवसर पर अनेक चुनाव-सभाओं को सम्बोधित

करते हुए कहा था—“संघ ने मुझे हिटलर और मुसोलिनी का संयुक्त रूप बतलाया है, पर सच यह है कि भारत में हिटलर के उत्तराधिकारी वही हैं !”

इस आपातकाल ने साबित कर दिया—क्या है सच ! लाख-लाख मुंहों से जनसंघ-नेताओं के लिए किए गए कुप्रचार ने जन-सामान्य को बरगलाया, किन्तु आपातकाल ने सच सामने उजागर कर डाला। कौन था तानाशाह !

मुझे याद है, एक बार श्रीमती गांधी ने अटलबिहारी वाजपेयी से चिढ़कर, व्यक्तिगत रूप से क्रोधावेश से ऊल-जलूल बोलते हुए कह दिया था—“अटलजी लोकसभा में हाथ उठा-उठाकर इस तरह बोलते हैं, जैसे हिटलर हैं !”

इसपर श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने एक आमसभा में चुटकी ली। कहा—“इन्दिराजी कहती हैं कि मैं हाथ उठा-उठाकर बोलता हूँ। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि है कोई ऐसा आदमी, जो टांग उठाकर बोलता हो ?”

बहरहाल यह बात हुई राजनीतिक चुटकियों की, किन्तु चुटकी अर्थहीन नहीं होती। अक्सर उसमें भविष्य के सत्य की कोई तेजस्वी किरण छिपी रहती है। इन्दिराजी ने अपने शासन-काल में जनसंघ को लेकर जिस तरह, जितनी बार हिटलर का नाम और तानाशाही शब्द दोहराया था, वह निश्चित रूप से उनके अनजाने ही उनके मन में कहीं न कहीं समाया हुआ था और जयप्रकाशजी के आन्दोलन से बीखला-घबराकर वह विचार एक विस्फोट की तरह उबलकर साकार रूप में सबके सामने आ गया।

मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अनजाने ही आदमी उस सबको बोलता रहता है, जो उसके अन्तर्मन में कहीं न कहीं बैठा होता है। इन्दिराजी का बार-बार जनसंघ के नाम पर ‘हिटलर ! हिटलर !’ चीखते रहना, उनके अन्तर्मन में बैठे हुए हिटलर के कारण ही होता था। और यह हिटलर उबल आया था। उसके पास गोयबलस किस्म के कई प्रचारमंत्री थे और आइखमैन किस्म के कई खतरनाक हत्यारे थे।

जनता के बीच एक ओर रेडियो, टेलीविजन, गूँसे कर दिए गए; अखबार और अनुदान-सम्मान प्राप्त कलाकार आपातकाल का गुणगान कर रहे थे और ‘देश को बचा लिया’ के गीत गुनगुना रहे थे, दूसरी ओर कुछ लोग थे जो लम्बी-लम्बी पोथियाँ या वाक्यांश लिखकर समर्थन का गाना गा रहे थे। व्यक्तिगत रूप से इन्दिराजी का गुणगान भी कर रहे थे।

श्री राजा अहमद अब्बास ने लिखा है—“पिछले वर्ष उन्होंने जिस आपात-स्थिति की घोषणा की, उसने जादू-सा कर दिया। जाने कितनों को उन्होंने जेल

के सीखचों के अन्दर कर दिया। उन लोगों को, जिन्हे बहुत पहले ही जेल में होना चाहिए था ! " जो भूत बातों से नहीं मानते थे, उनको बड़ी निर्ममता के साथ लातों से ठीक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने साबित कर दिखाया है कि पूरे मंत्रिमंडल में अकेली वे ही 'मर्द' हैं !"

एक और स्थान पर इसी पुस्तक में इन्दिराजी को घोर शोकतंत्रवादी सिद्ध करते हुए अब्बास कहते हैं—“किसी जनतंत्रीय नेता के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए दस वर्षों की अवधि पर्याप्त होती है। श्रीमती गांधी के प्रमंग में तुलना कर पाना एक कठिन कार्य है, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी तुलना उनके यशस्वी और नेकदिल पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से की जा सकती है। दोनों ही समाजवादी और राजनीतिशास्त्री (स्टेट्समैन) रहे हैं, लेकिन जबकि पिता एक आदर्शवादी थे, साहस और सज्जनता के सागर थे, बेटी यथार्थ की घरा पर खड़ी रहनेवाली, कर्म में अग्नि में तपा फैलाद है। उनको कानूनी अदालतों ने पंगु बना रखा था। बहुत-से अतिकारी मुद्धार जो वे करना चाहती थी इसलिए नहीं कर पाईं कि या तो उनको उनके उन बरिष्ठ समकालीनों ने काट दिया था, जिनसे वे घिरी रहती थी, या उनकी राह में अदालतें आ जाती थी, जो संविधान का अर्थ निकालती थीं।”

आपातकाल के समयन में सम्पादक 'नया जीवन' लिखते हैं— 'पिछले दस वर्षों में विरोधी दलों के नेताओं ने रात-दिन परिश्रम किया था। कृपालु प्रधान-मंत्री ने उन सबको आरामगाहों में भेज दिया और उनके लिए भोजनादि की उत्तम व्यवस्था कर दी। जैसे शरीर का मोटापा होता है, वैसे ही अकल का भी मोटापा होता है। वह इन नेताओं को भी हो गया था कि मारे देश की जनता हमारे साथ है, पर इनकी गिरफ्तारियों पर शहर और प्रदेश तो क्या रोते, इनके मुहल्लेवालों तक ने उस दिन ताश की चौकड़ी में हड़ताल नहीं की। इमजैसी की उपयुक्तता के लिए और किस जाच-पड़ताल की जरूरत है ?”

ऐसे कई थे हमारे देश के पत्रकार, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के अधिनायकवाद में उनसे भी चार हाथ आगे जाकर 'घन्य-घन्य' की पुकारें लगा रहे थे और दमन के क्रूर दौर में सामाजिक-राजनीतिक जीवन के साथ 'ताश की चौकड़ी' पर बैठे हुए थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी तानाशाही स्थापित कर देंगी, यह अगर विरोधी कहते रहे थे तो कांग्रेस में भी बहुतों ने आशका व्यक्त की थी। 'धर्मयुग' को दी गई एक भेंट में युवा तुर्क रामधन ने बहुत पहले स्पष्टतः कह दिया था कि

श्रीमती गांधी आपातकाल की घोषणा करके तानाशाही लाएंगी। २५ जून, १९७५ की शाम को 'धर्मयुग' के उदयन शर्मा ने कृष्णकांत से भेंट की थी। कृष्णकांत बोले थे—'तानाशाही की संभावना है !'

और कांग्रेस की दशा क्या हो चुकी थी ! ऐसे, जैसे भेड़ों का एक गल्ला है, जिसे अकेला गड़रिया जी चाहे जिस दशा में हांक सकता है। तब क्या वह कांग्रेस बची थी ? यदि सचमुच कांग्रेस संस्था में सिद्धांत और सिद्धांतवादी कांग्रेसजन शेष रहे होते तो जयप्रकाशजी को यह न लिखना पड़ता :

“कौन है, जिसे सच्चा कांग्रेसी कहा जाएगा ? क्यों बहुत दबी-दबी बातें करते हैं ? इससे जाहिर होता है कि बहुत कम, या नाममात्र के लिए सच्चे कांग्रेसी बचे हैं। चन्द्रशेखर और रामधन की गिरफ्तारी के बाद जो सच्चे कांग्रेसी बचे थे, उनके पास विद्रोह करने का पर्याप्त साहस नहीं था। और युवा तुकों की बदला-बदली और उनकी गिरफ्तारी के बाद, जो भी दूसरे कांग्रेसी बचे थे, वे केवल स्वयंसेवी और 'जी-हुजूरी' करने वाले यानी 'यस मैन' थे।”

केवल जय बाबू ने ही नहीं, बहुत पहले अनेक कांग्रेसियों ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि कांग्रेस नाम से जो दल सत्ता पर सवार है, वह कांग्रेस नहीं है। कृष्णकांत ने तो बड़ी बुलन्दी से इस सत्य को स्वीकार किया था। जब आपातकाल की घोषणा हुई, तब उन्होंने उसका विरोध किया और उसे एक तरह से अप्रजातान्त्रिक बतलाया। इसपर कांग्रेस की महासचिव श्रीमती चन्द्रशेखर ने उन्हें एक पत्र लिखा और उस पत्र का उत्तर ४८ घण्टे के भीतर-भीतर देने का निर्देश किया। कारण था, कृष्णकांत द्वारा संसद में स्पष्ट रूप से अपने मौलिक विचार प्रकट करना। जिनके अनुसार आपातकाल की घोषणा को उन्होंने गलत ठहराया था। कृष्णकांत और अन्य युवा तुकों से दल के भीतर

1. “Why have they meekly submitted ? It seems that there are in reality very few true Congressmen.”

“And after the arrest of Chandra Shekhar and Ramdhan and the excommunication of the other young turks, these true congressmen also have not courage enough to rebel. Most of the others have no ideological convictions and are pure self-seekers and Jee-huzurs (yes-men).”

Prison Diary by Jaiprakash Narain, page 14

निरंतर बढ़ते जाते अधिनायकवाद को लेकर पहले ही खीचातानी चल रही थी। अधिनायकवाद के परिणामस्वरूप ही उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष, सभी कांग्रेस समितियों की सदस्यता और प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित कर चुके थे, किन्तु संसद में उनके जोरदार विरोध के बाद निश्चित किया गया था कि कृष्णकांत को दल से ही निकाल बाहर किया जाए। अपने-आपमें मज्जदार और अत्यंत हास्यास्पद बात यह है कि ये सारी कार्रवाई उस व्यक्ति के इशारे पर हो रही थी जो कभी स्वयं ही 'आरमा की आवाज' का नारा देकर संस्था में धीमे-धीमे अधिनायकवादी सत्ता अपनाता गया। यदि कृष्णकांत ने संस्था के लोकतंत्री रूप और वैचारिक विरोध की स्वतंत्रता के आधार पर एक गलत काम का विरोध किया तो यह अपराध था या एक ईमानदार और सच्चे कांग्रेसी का सत्य? यही कारण था कि कृष्णकांत ने श्रीमती चन्द्रशेखर के पत्र का उत्तर देते हुए निर्भीकता से लिखा :

“...कांग्रेस में मिसो-जुली विचारधाराओं का शुरू से ही प्रतिनिधित्व होता रहा है। इसने कभी बन्द दरवाजों वाली नीति नहीं अपनाई और न ही सर्व-सत्तात्मक दलों की तरह कार्य किया।” आगे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दल के भीतर समा गए अधिनायकवादी रुख और देश पर लादे जा रहे फासिस्ट को चुनौती दी थी, “आपने अपने पत्र में ‘धर्मयुग’ के इण्टरव्यू की बात उठाई है। जैसा कि आप जानती हैं, चाहे वह वाम की हो या दक्षिण की, मैं हर प्रकार की अधिनायकवादी विचारधारा के खिलाफ हूँ मेरा अतीत और मेरी गतिविधियाँ खुली किताब हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी फासिस्ट या अन्य किसी अधिनायकवादी नीति को मेरे समर्थन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।”

. इस सारे सन्दर्भ के साथ, बाद में, जब तानाशाही की पराजय हुई और लोकतंत्र ने पुनः देश को सही नेतृत्व दिया, तब ‘धर्मयुग’ को दिए एक इण्टरव्यू में कृष्णकांत ने कहा—“यह कांग्रेस, कांग्रेस नहीं रही। यह तो दो संस्था नहीं है, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। जिसके लिए मेरा पूरा परिवार जेल गया था—डंडे खाए थे। यह मुर्दा कांग्रेस है। यदि अंग्रेजों के जमाने में यह कांग्रेस और कांग्रेसी होते तो अंग्रेजों से मिल जाते और देश को बेच खाते।”

राजस्थान से जनता पार्टी के नेता और हाल में चुनकर आए संसद-सदस्य श्री भैरोसिंह शेखावत ने एक मुलाकात में मुझे बतलाया था कि आपातकाल

लगाने के लिए जितने भी तयाकथित कारण इन्दिरा-शासन ने जनता के सामने बतलाए थे, उनमें से एक भी सच नहीं था। सच तो यह था कि सत्ता डग-मगाने लगी थी और उसपर स्थायी रहने के लिए अकारण ही कारण ढूँढ़ लिए गए थे। श्री शेखावत से जब मैंने यह पूछा कि क्या श्रीमती गांधी की सत्ता जयप्रकाशजी के आंदोलन के कारण हिल गई थी ?

“हां।” श्री शेखावत ने उत्तर दिया, “पर आपातकाल लागू करने का कारण केवल आंदोलन नहीं था, और बहुत कुछ थे। सबसे बड़ा कारण था, उनके अपने दल में ही भीतरी तौर पर आंदोलन के सत्त्यों को स्वीकार लिया जाना। श्रीमती गांधी महसूस कर रही थीं कि दल में दवा-घुटा ही सही, पर असंतोष है।”

“पर यह विरोध उभर तो नहीं सका ?” मेरा प्रश्न था।

“इससे पहले कि ठीक तरह उभर पाए, उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए तानाशाही स्थापित कर दी।”

“क्या आपको आशंका थी कि श्रीमती गांधी ऐसी अप्रजातांत्रिक रख अपना सकती हैं ?”

“वेशक !” शेखावतजी का उत्तर था, “यह समझने के लिए श्रीमती गांधी के शासन वाले पिछले कई साल हम लोगों के सामने थे।”

किन्तु महान अहिंसक क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाशजी को उस समय तक विश्वास नहीं था कि इन्दिरा गांधी वैसा अलोकतांत्रिक कदम उठा सकती हैं। क्या इसलिए कि जय बाबू एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा विचारक और क्रांतदर्शी हैं ? या यह कि जयप्रकाशजी के राजनीतिक संस्कारों में सत्तालिप्सा की वैसी घिनीनी कल्पना ही नहीं हो सकती थी ? या इसलिए कि जयप्रकाशजी ने—जिन्होंने स्वयं अनेक बार यह स्वीकार लिया था कि अधिनायकवाद है, पर वह इस सीमा तक जा सकता है—कल्पना नहीं की थी ? जय बाबू ने अपनी जेल-डायरी में २१ जुलाई, १९७५ को आश्चर्य, अविश्वास और दुःख प्रकट करते हुए लिखा—“मेरा विश्वास गलत हो गया कि किसी जनतंत्र में किसी शांतिपूर्ण और जनतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए कोई प्रधानमंत्री तमाम सामान्य और असामान्य कानूनों का उपयोग करके जनतंत्र को ही खत्म कर डालेगा। मेरा यह विश्वास भी गलत हो गया कि कोई प्रधानमंत्री यदि ऐसे तरीके अपनाए तो, उसके वरिष्ठतम साथी और

उसका दल, जिसकी उच्चतम जनतांत्रिक परम्पराएं हैं, उसे ऐसा करने की स्वीकृति देंगे, किन्तु वह सब हुआ जो अविश्वसनीय है !”

इस तरह जय बाबू का अविश्वसनीय, बेहुतों का विश्वसनीय तथा चाटुकार नेताओं और बुद्धिजीवियों का प्रशंसनीय घट गया था।

२६ जून, १९७५ की लम्बी काली रात के प्रारंभ के साथ ही देश के समाचार-विचार क्षेत्र में अंधेरा कर दिया गया। यह किसी भी तानाशाही का सबसे तीखा और खतरनाक प्रारंभ होता है, जब लोगों का सोचना-समझना बन्द कर दिया जाए और देशहित के नाम पर हर शासकीय कदम के पहलुओं को केवल एक नज़रिये से, जो कि सत्ताघारों का नज़रिया होता है, दिखलाया जाने लगे।

भारत रक्षा अधिनियम के तहत युद्धकाल के लिए सेंसर के अधिकार धारा ४८ के अनुसार भारत सरकार को मिले थे। उस समय बंगला देश का युद्ध (सन् १९७१) चल रहा था। पर धारा ४८ के अन्तर्गत मिले इस अधिकार का उपयोग आपातकाल में किया जाने लगा। इसपर सोचने की आवश्यकता नहीं समझी गई कि उक्त अधिकार किस स्थिति में उपयोग किए जाने चाहिए। वे आवाज़ें घोंट डाली गई थी, या घोड़ी जा रही थी, जो पूछ सकती थी। इस तरह जनता को वह बतलाया जाने लगा, जिसे श्रीमती गांधी की तानाशाही बतलाना चाहती थी और वह सब गुम हो गया जो देश में घट रहा था।

समाचारपत्रों को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी फोन पर क्या छपना है, क्या नहीं—ये सूचनाएं प्रसारित करने लगे। इनमें भी सतत समाचार थे होते थे, जिनका संबंध व्यक्तिगत रूप से सत्ताधारियों या तानाशाही के

1. "I went wrong in assuming that a Prime Minister in a democracy would use all the normal and abnormal laws to defeat a peaceful democratic movement, but would not destroy democracy itself and substitute for it a totalitarian system. I could not believe that even if the Prime Minister wanted to do it, her senior colleagues and her party, which has had such high democratic tradition, would permit it. But the unbelievable has happened."

समर्थकों से था। उन सभी समाचारों पर पाबन्दी थी जो तानाशाही के विरोधी हो सकते थे या उसके बारे में विचार प्रस्तुत कर सकते थे। यहां तक कि किसी भी किस्म की ज्यादाती को प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। यदि ऐसा किया जाता तो समाचारपत्र के संपादक और प्रकाशक को आंमुका (मीसा) में गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था तथा अखबार के दफ्तर पर ताला लगाया जा सकता था।

मुझे स्मरण है कि आपातकाल की घोषणा के बाद दिल्ली और देश के विभिन्न नगरों से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचारपत्रों ने अपने सम्पादकीय के स्थान पर ब्लैकबॉर्डर लगाकर खाली जगह छोड़ दी थी। यह एक तरह का मौन और शिष्ट विरोध था कि जनतंत्र और विचार प्रकटीकरण के मूल मानव-अधिकार की हत्या की जा रही है और वे उसका विरोध करते हैं। दिल्ली के एक पत्र ने तो ऐसी खाली जगह पर मोटे-मोटे टाइप में छपा था—‘हमारी आवाज़ छीन ली गई है।’

निरंकुश तानाशाही के इस घिनौने चक्र का संचालन श्रीमती गांधी के अत्यन्त विश्वसनीय साथी श्री विद्याचरण शुक्ल कर रहे थे और उन्होंने कितनी बफादारी और ‘ईमानदारी’ के साथ अपना यह कर्म-धर्म निवाहा, इसी पुस्तक में कहीं आगे पढ़ने को मिलेगा।

और यह कार्रवाई उस दिमाग से निकली थी जो कभी चीख-चीखकर लोकतंत्र, प्रेस-स्वतंत्रता और मुक्त समाज की दुहाई दिया करता था। कितना दोहरा चेहरा? कितना झूठ और कितना सत्य? पाठक स्वयं ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। स्वराज़ा अहमद अक्वास ने अपनी पुस्तक^१ में विवरण दिया है:

“विरोधी दलों के इस आरोप का जिक्र करते हुए कि इन्दिरा गांधी लोकतंत्र को नष्ट कर रही हैं, उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी उन्हें (विरोधी दलों को—भ्रमर) यह मौका दे रही हैं कि वे जनता के मत यदि ले सकें तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर आएँ। क्या इसका मतलब लोकतन्त्र का अन्त होता है? तब वे अखबार वालों की ओर मुड़ीं। वे वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे। इन्दिराजी ने कहा कि आप जानते हैं कि कौन इन्दिरा गांधी के पक्ष में लिख रहा है और कौन उसके विरुद्ध लिख रहा है। क्या हम आपको यहां आने से

और जो आप चाहे वह लिखने से रोकते हैं ? तानाशाही विरोधी अखबारों का गला घोटने से शुरू होती है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या किन्ही अखबारों को दबोचा गया है ?”

और आपातकाल में क्या हो रहा था ? देशहित के नाम पर किसका गला घोंटा गया था ? इन्दिराजी हमेशा दुहाई देती रही और कहती रही कि “तानाशाही विरोधी अखबारों का गला घोटने से शुरू होती है।” और क्या इस घात से इनकार किया जा सकता है कि उन्होंने वह स्वयं किया ?

और जिस स्तर पर किया—वह उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। गत दिनों जनता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय ने एक प्रेस-विज्ञप्ति निकालकर उन समाचारों की सूची दी थी, जिन्हे देशहित (?) में आपातकाल के दौरान सेंसर द्वारा निर्देशित किया गया था कि वे किस तरह छपें या न छपें।

○ अभिनेत्री नरगिस पर विशेष कृपालुता दिखाते हुए २८ मई, १९७६ को सेंसर ने अखबारों को हुक्म दिया कि दूकान से सामान घुराने के आरोप में नरगिस की गिरफ्तारी के बारे में सन्दर्भ की समाचार-सूचना प्रकाशित न की जाए।

○ १६ जुलाई १९७६ को श्री जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों के बारे में समाचार प्रकाशित करने पर रोक लगाते हुए बतलाया गया कि कानून व व्यवस्था के हित में ऐसा किया जाना चाहिए।

○ आंध्रप्रदेश न्यायालय के एक न्यायाधीश के स्थानांतरण का समाचार प्रकाशित न किया जाए। निर्देश—८ जून, १९७६।

○ श्री जेठमलानी, जो इण्डियन थार कौंसिल के अध्यक्ष हैं और उस समय अमेरिका में थे, उनके बारे में, ६ सितम्बर, ७६ को आदेश हुआ कि उनसे सम्बन्धित कोई समाचार न छपा जाए। यदि छपा जाए तो सेंसर को दिपला लिया जाए।

○ १९ दिसम्बर, १९७६ को अखबारों को निर्देश मिला कि कांग्रेस पार्टी के भीतरी झगड़ों और युवक कांग्रेस तथा अखिल भारतीय कांग्रेस के बीच के झगड़ों को किसी भी रूप में प्रकाशित न किया जाए।

○ २ जून, १९७६ को उद्योगपति डी० पी० गोयनका के बारे में कोई भी समाचार न छापने का निर्देश।

○ १ अप्रैल, १९७६ को निर्देश हुए कि परिवार नियोजन-सम्बन्धी किसी

भी किस्म का आलोचनात्मक समाचार, यहां तक कि संपादक के नाम पत्र भी, प्रकाशित न किया जाए।

○ तुर्कमान गेट पर हुए वर्वर अत्याचारों को लेकर २१ अप्रैल, १९७६ को सेंसर आदेश हुआ कि वही विवरण प्रकाशित हों, जो सरकार दे। यहां तक कि शीर्षक भी वही जाए जो सेंसर से पास हो।

○ २८ अप्रैल, १९७६ के सेंसर आदेश के अनुसार उस समारोह का कोई भी चित्र या समाचार प्रकाशित नहीं किया जाना था, जिसमें से श्री संजय गांधी उठकर चले गए थे।

○ जूनियर वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय तक जुलूस ले जाकर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के समाचार प्रकाशन पर २६ मार्च, १९७६ को रोक लगाई गई।

○ १० अगस्त, १९७६ को आदेश दिए गए कि सुब्रह्मण्यस्वामी के बारे में कोई समाचार प्रकाशित न किया जाए।

○ १५ मार्च, १९७६ को सेंसर ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के सम्बन्ध में किसी भी तरह की रपट, टिप्पणी या समाचार के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। यदि कुछ छपा जाना है, तो पहले सेंसर कराया जाए।

○ २६ फरवरी, १९७६ को तमिलनाडु में राष्ट्रपति-शासन लागू किए जाने के आदेश पर श्री करुणानिधि द्वारा दिल्ली और मद्रास के उच्च न्यायालयों में दायर की गई याचिकाओं का समाचार प्रकाशित न किया जाना निर्देशित हुआ।

○ श्री तुलमोहनराम के मुकदमे की रिपोर्ट छापने से पहले सेंसर कराई जाए—निर्देश दिनांक : ३ फरवरी, १९७६।

सितम्बर, १९७५ से दिसम्बर, १९७५ तक जो सेंसर आदेश हुए, उनमें से कुछ हैं :

○ दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ियों को तहस-नहस कर दिए जाने के सम्बन्ध में कोई भी समाचार, चित्र, टिप्पणी, रपट प्रकाशित करने के पूर्व सेंसर को बतलाई जाए।

○ बोनस को लेकर जो सांकेतिक हड़तालें हुईं, उनके समाचार प्रकाशित न किए जाएं।

○ छह सूत्री कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रपति के आदेश पर किसी भी किस्म की टिप्पणी किए जाने पर रोक ।

○ आमुका (मोसा) में नज़रबन्द किए गए व्यक्तियों द्वारा अपने मुलाकातियों पर रोक लगाने को लेकर हुए सरकारी आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्रकाशित न किया जाए ।

○ बाबू जयप्रकाश नारायण की बम्बई-यात्रा का समाचार सेंसर किया जाए तथा उनका चित्र प्रकाशित न किया जाए ।

○ तिहाड़ जेल में हुई घटनाओं के बारे में कोई भी समाचार प्रकाशित न किया जाए ।

○ बम्बई अपील केस पर न्यायाधीश खन्ना का निर्णय प्रकाशित न किया जाए ।

ये कुछ उदाहरण थे सेंसर द्वारा तथाकथित 'देशहित' में रोके गए समाचारों के ।

आपातकाल की घोषणा के फौरन बाद इन्दिराजी स्वयं और उनके विशिष्ट साथी यथा बसोबस, ओम मेहता, विद्याचरण शुक्ल, जिनके पास क्रमशः सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग—रक्षा, गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय थे, निरंतर एकस्वर होकर इस प्रचार में लग गए थे कि केवल देश को ही नहीं, देश के भूधन्य सत्ताधारी नेताओं को खतरा बढ़ गया था । कहा जा रहा था कि जयप्रकाशजी के आंदोलन को विदेशी शक्तिमा चला रही थी, इसलिए आपातकाल लागू करना अनिवार्य हो चुका था । श्रीमती गांधी ने यहाँ तक कह डाला कि इस आंदोलन का मकसद सरकार का कामकाज ठप्प कर डालना था । एक व्यक्ति (जयप्रकाशजी) असैनिक कर्मचारियों और सेना में बिद्रोह भड़काने की कोशिश कर रहा था ।

इस कुप्रचार का खडन कौन करता ? जिनके पास जवाब थे और जिनके पास सच था, वे जेलों में थे या कालकोठरियों में भयानक नारकीय यत्नवाएं देकर सताए जा रहे थे । स्वयं जयप्रकाशजी ने इस बेबुनियाद और दुसह प्रचार को लेकर चंडीगढ़ से प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्र लिखा । खेद और दुःख की बात यह थी कि उस अंधेरी काली रात के रहस्यकांड में इस पत्र को भी श्रीमती गांधी पचा गई । बाद में यह पत्र जनता पार्टी ने अखबारों को प्रकाशनार्थ वितरित किया ।

यह पत्र विभिन्न भारतीय मापाओं के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ

था और इसका प्रत्येक शब्द एक अहिंसावादी आंदोलनकारी की व्यथा से पूर्ण ही नहीं है, उन तकों से भरा हुआ है, जिनका उत्तर इन्दिराजी के पास था ही नहीं।^१ यहाँ उस पत्र को संक्षेप में उद्धृत कर रहा हूँ :

प्रिय प्रधानमंत्री,

मैं आपके भाषणों और भेंट-वार्त्ताओं के वृत्तांत पढ़कर अवाक् रह गया हूँ। यही एक बात कि आपको अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ कहना पड़ रहा है, आपके मन का चोर प्रकट कर देती है। अखबारों का और सब प्रकार की असहमति का मुंह बन्द कर आलोचना या खंडन के भय से मुक्त होकर आप असत्य और मनगढ़ंत बातें कहे चली जा रही हैं।

आपके आलाप की टेक, जैसा मैं समझ पाया हूँ, यह है कि (क) सरकार को ठप्प कर देने की योजना थी, (ख) एक व्यक्ति असैनिक कर्म-चारियों और सैनिकों में विद्रोह फैलाने का प्रयत्न कर रहा था।

चूँकि इस आक्षेप का पात्र मैं ही हूँ, इसलिए बात साफ हो जाने दीजिए। हो सकता है कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी न हो क्योंकि आप जितना असत्य बोलतीं और तथ्यों की तोड़-मरोड़ करती हैं, वह सब जान-बूझकर और इच्छा से करती हैं। पर कम से कम सत्य दर्ज तो हो जाएगा। सरकार को ठप्प करने की कोई योजना नहीं थी और यह बात आप भी जानती हैं। तथ्य ये हैं—

भारत के सब राज्यों में बिहार ही था, जहाँ कोई जन-आंदोलन हो रहा था। वह फैल रहा था...और गांवों में गहरे पैठता जा रहा था...यदि आपने जनता सरकार के कार्यक्रम को देखा हो तो आपने पाया होगा कि बहुलांश में वह रचनात्मक था जैसे सावजनिक वितरण व्यवस्था को नियमित करना, प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार रोकना, भूमि-गुधार कानून लागू करना, समझौते और पंचाट के चिरप्रचलित तरीके से विवाद निपटाना, हरिजनों को न्याय दिलाना और तिलक और दहेज जैसी सामाजिक गुरीतियों को दूर करना आदि। इस सबमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे किसी तरह भी विध्वंसक कहा जा सके...नगर-क्षेत्रों में आंदोलन की तेजी के दिनों में कुछ दिन के लिए धरना और पिकेटींग द्वारा सरकारी

कार्यालयों का काम रोकने का प्रयत्न किया गया। पटना में जब भी विधान सभा की बैठक होती, सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए समझाने के और भीतर जाने से रोकने के शांतिमय प्रयत्न होते। ये सब कार्यक्रम सिविल नाफरमानी के सोचे-समझे कार्यक्रम थे। और राज्य-भर में हजारों आदमियों-औरतों ने इसमें गिरफ्तारियां दी थी।

यदि यही सब बिहार सरकार को ठप्प करने का प्रयत्न है तो कहना होगा कि यह उसी तरह का प्रयत्न था, जैसाकि ब्रितानी सरकार को ठप्प करने के लिए आजादी की लड़ाई के दिनों में असहयोग और सत्याग्रह द्वारा किया गया था। आपका एक अत्यंत प्रिय प्रश्न है कि निर्वाचित सरकारों और निर्वाचित विधानमंडलों को हटने के लिए कहने का किसीको क्या अधिकार है? पर इसका उत्तर न जाने कितनी धार सुविख्यात संविधान-विदों और अन्य योग्य व्यक्तियों द्वारा दिया जा चुका है।

उत्तर यह है कि किसी लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार यदि भ्रष्ट हो जाए और कुशासन करती रहे तो उससे त्यागपत्र मांगने का अधिकार जनता के पास अवश्य होता है। और यदि कोई विधानमंडल हो जो ऐसी सरकार को समर्थन देता ही चला जाए तो उस विधानमंडल को भी हटाना होगा ताकि जनता अपने बेहतर प्रतिनिधि चुन सके। बिहार सरकार को विद्यार्थियों की मांगों पर बातचीत से निबटारा करने का अवसर था परन्तु उसने मर्घप अर्थात् बेमिसाल दमन का तरीका बेहतर समझा। ऐसा ही उत्तरप्रदेश सरकार ने भी किया। अगर दोनों सरकारों ने बातचीत का रास्ता छोड़ न दिया होता तो कोई आंदोलन ही न हुआ होता।

मैं यह पहली वृक्षने की कोशिश करता रहा हू कि इन सरकारों ने अक्लमंदी क्यों नहीं दिखाई और इस नतीजे पर पहुंचा हू कि उनकी सबसे बड़ी बाधा थी भ्रष्टाचार। किसी न किसी बजह से ये सरकारें अपने भीतर, विशेष रूप से सर्वोच्च स्तर पर, मल्लिस्तर पर ही, भ्रष्टाचार को दूर करने में असमर्थ रही हैं। और आंदोलन मुख्यतया भ्रष्टाचार के ही विरुद्ध था। विशेष करके सरकार और प्रशासन के भ्रष्टाचार थे।

प्रिय प्रधानमंत्री, सरकार ठप्प करने की कोई योजना नहीं थी, थी तो आपकी अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक के लिए, एक साधारण निरीह और अल्पकालिक सत्याग्रह की योजना थी। कुछ चुने हुए लोग आपके मकान के सामने या नजदीक में इस मांग के समर्थन में सत्या-

ग्रह करते कि आप अपनी अपील पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक के लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें, इसमें विध्वंसक या खतरनाक कोई भी चीज़ मुझे नहीं दिखाई देती।... लोकतंत्र में नागरिक को यह दीखने पर कि सुनवाई या सुधार के सब रास्ते बन्द हो गए हैं, सिविल नाफरमानी का जन्मसिद्ध अधिकार रहता है।...

और अखबारों की आज़ादी का क्यों दमन किया गया है? इसलिए नहीं कि भारतीय अखबार गैरजिम्मेदार, बेईमान या सरकार-विरोधी थे; वास्तव में आज़ादी मिली रहने पर अखबारों ने जितनी जिम्मेदारी, ईमानदारी और न्याय का परिचय भारत में दिया है, उतना कहीं और नहीं मिला; असलियत यह है कि उनके खिलाफ आपका गुस्सा, आपके त्यागपत्र के सवाल पर पैदा हुआ था। क्योंकि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कुछ अखबारों ने जो लिखा था, वह आपको बिलकुल वर्दाश नहीं हुआ।

ऐसा छपा है कि आपने कहा कि लोकतंत्र राष्ट्र से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। श्रीमती प्रधानमंत्री, क्या आप अपनेको बहुत बड़ा नहीं समझ रही हैं जो ऐसा कहती हैं? राष्ट्र की चिन्ता करने वाला व्यक्ति एक आप ही नहीं हैं। जिन्हें आपने नजरबन्द या गिरफ्तार किया है, उनमें से अनेक हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए आपके मुकाबले कहीं ज्यादा कुछ किया है। और उनमें से हर एक आप ही की तरह देशभक्त है। इसलिए कृपा करके हमें राष्ट्र के सम्बन्ध में उपदेश देकर हमारे जख्मों पर नमक न छिड़किए।

यही नहीं, आपके इस विकल्प की धारणा ही गलत है। लोकतंत्र और राष्ट्र के बीच में एक ही चीज़ चुनी जा सकती है, ऐसा नहीं है। यह राष्ट्र के हित के लिए ही था कि भारतीय जनता ने अपनी संविधान-सभा में २६ नवम्बर, १९४६ को घोषित किया था कि हम भारत के जन भारत को एक प्रभुसत्तासम्पन्न लोकतंत्रीय गणराज्य बनाने का दृढ़ निश्चय करके अपने को यह संविधान देते हैं।

मैंने यह सब साफ-साफ बिना कुछ छिपाए लिखा है, ऐसा न तो मैंने गुस्से में किया है, न आपसे बहस में पार पाने के लिए। मैंने तो आपके नामने उस नग्न सत्य को रख दिया है जिसको आप ढकने या तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश करती हैं।

यह अप्रिय कर्तव्य कर चुकने पर चलते-चलते दो शब्द सलाह के भी

बहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि मैं बूढ़ हो चुका हूँ। अपने जीवन में मुझे जो करना था, कर चुका। और प्रभा के गुजर जाने के बाद अब न मेरा कुछ है, और न मुझे किसी व्यक्ति के लिए जीते रहने की इच्छा ही है। मैंने विद्यालय से निकलने के बाद अपना सारा जीवन देश को ही दिया है और बदले में कुछ मागा नहीं। इसलिए मैं आपके राज में एक कैदी की हैसियत से मर कर भी सन्तुष्ट रहूँगा।

क्या आप मेरे जैसे एक व्यक्ति की सलाह मानेंगी? मेहरवानी करके उस नींव को मत उजाड़िए, जिसे आपके महान पिता सहित अन्य राष्ट्र-निर्माताओं ने डाला है। आपने जो रास्ता पकड़ा है उसपर चलकर सिवाय कलह और क्लेश के कुछ हासिल न होगा—बहु जनता, जिसने ब्रितानी साम्राज्यवाद से मोर्चा लिया, और उसे नीचा दिखाया, सर्वसत्ता की ग्लानि और कुत्सा हमेशा-हमेशा बर्दाश्त नहीं करती रहेगी।

आपने देश में भटकाव की बात की है, पर क्या उसकी वजह विरोधी दल या मैं था? भटकाव की वजह थी निर्णय, दिशा और प्रयत्न का अभाव। आप उसी वक्त स्फूर्ति और मुस्ती दिखाती हैं, जब आपकी निजी हैमियत पर कोई आच आ रही आपको दीखती है। एक बार उधर से निश्चिन्त हो जाने पर फिर भटकाव शुरू हो जाता है।

प्रिय इन्दिराजी, कृपया अपने को राष्ट्र न समझने लीजिए। आप अमर नहीं हैं, भारत है। आपने प्रतिपक्ष पर और मुझपर हर तरह की दुष्टता का अभियोग लगाया है, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप सही काम करें, उदाहरण के लिए अपने २० सूत्री कार्यक्रम चलाएं, मन्त्रिस्तरी पर भ्रष्टाचार मिटाएं, चुनाव-सम्बन्धी मुद्धार करें, प्रतिपक्ष को विश्वासपात्र बनाएं और उसकी सलाह सुनें तो आपको हमसे से हर एक का हार्दिक सहयोग मिलेगा। इसके लिए आपको लोकतन्त्र को ध्वस्त करने की जरूरत नहीं है। अगला कदम आपके हाथ में है और आप ही को फैसला करना है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ईश्वर आपकी रक्षा करे !

— जयप्रकाश

लोकनायक का यह पत्र ऐसा सच था, जिसे एक बार पढ़कर प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी दूसरी बार उसका सामना नहीं कर सकी होंगी। और चूँकि सामना नहीं कर सकी होगी, अतः उत्तर देने का साहस ही कहा से आता ?

पर इन्दिराजी को, उनके हर कदम पर उनके चापलूस साथी तथा समाचारपत्र बतलाते रहे थे कि वे अपार संयमी, धैर्यशील और साहसी हैं और ये संयम, धैर्य व साहस—सारे गुण आपातकाल में खूब दीख रहे थे।

यों इस साहस के कई नमूने आपातकाल से पूर्व भी सामने आने लगे थे। अपने विरोधी को सह न पाने पर वे जिस लोकतांत्रिक पद्धति (?) के धैर्य का प्रदर्शन करती रही थीं, उसका वर्णन प्रणस्ति-भाव से अक्बास ने अपनी पुस्तक में किया है—“थोड़े ही दिनों में उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प से बतला दिया है कि वे क्या हैं। उन्होंने उन धुरंधरों को धकेलकर बाहर कर दिया। कड़्यों को तो उन्होंने विभिन्न कारणों से जेल के दरवाजे भी दिखा दिए। कई लोगों को उन्होंने कम महत्त्व की जगहों पर बिठा दिया, जैसे कि किसी मामूली से राज्य का राज्यपाल बनाना।”

जो लोग इससे पूर्व इस तरह की बातें करते रहे थे कि इन्दिराजी घोर प्रजातांत्रिक हैं, उनके पास अक्बास के उपर्युक्त कथन का क्या उत्तर है? क्या लोकतांत्रिकता यही होती है कि सत्य से कतराया जाए? या जय बाबू के पत्र में लिखे अनुसार आप जितना असत्य बोलतीं और तथ्यों की तोड़-मरोड़ करती हैं वह सब जानबूझकर करती हैं, लोकतांत्रिक है, ? या लोकतांत्रिकता यह है कि कड़्यों को विभिन्न कारणों से जेल के दरवाजे दिखा दिए जाएं? क्या यह भी लोकतांत्रिकता ही है कि गलत लोगों के प्रति राजनीतिक ममत्व दिखाया जाए?

भिवानी (हरियाणा) से बंसीलाल को चुनाव में हराकर विजई हुई श्रीमती चन्द्रावती ने ‘दिनमान’ के महेश्वरदयालु गंगवार को बतलाया था,^१ “चन्द्रावती जब हरियाणा में ही चौधरी बंसीलाल के मंत्रिमंडल में उपमंत्री थीं, तब रिवासा कांड हुआ। इसमें मुख्यमंत्री बंसीलाल का पुत्र था। किन्तु बंसीलाल के पुत्र की रक्षा के लिए पुलिस ने जो अमानवीय आचरण किया, उसे लेकर चन्द्रावती ने गुना विद्रोह कर दिया। यही नहीं, उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से भी भेंट की और उन्हें सत्य से अवगत कराया, किन्तु चन्द्रावतीजी कहती हैं—“प्रधानमंत्री ने मेरी बात तो सुनी, किन्तु उसपर कोई ध्यान नहीं दिया।”

१. इन्दिरा गांधी : मफ़लता के दम बर्ष, पृ० १८३

२. दिनमान, ३-६ अप्रैल, १९७७

ये राजनीतिक भ्रमत्व भी क्या लोकतंत्र की परम्परा थी ? राजनीतिक भ्रमता के बहुत-से उदाहरण हैं और इसी पुस्तक में किसी अन्य जगह आएंगे, किंतु यहा बात करता हू उस व्यक्तित्व की, जिसे बहुत-से लोग आज भी यों कहकर उथले ढग से ढाल जाते हैं, कि श्रीमती गांधी का दोष नहीं था । दोष था उन लोगों का, जो चाटुकार भाव से उन्हें वरगलाते रहते थे या उन्हें अंधेरे में रखते थे या उनकी आड़ में ज्यादातिया करके उन्हें नीचा दिखा रहे थे ।

यदि ऐसे लोगों के उपर्युक्त तर्क सही है, तब मैं ही क्या, कोई भी यह बात नहीं मानेगा कि वह व्यक्ति जो 'वरगलाने' में आ जाता हो, वह व्यक्ति जिसे चाटुकार प्रभावित कर लेते हों, वह व्यक्ति, जिसे अपनी छाह तले क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी ही न हो—निस्संदेह रूप से उसे उस सर्वोच्च शक्ति का मालिक नहीं होना चाहिए, जो लोकतंत्र में करोड़ों आदमियों का विश्वास पाकर मिल जाती है । यदि यह सब था तब भी दोषी श्रीमती गांधी ही ठहरती हैं ।

किन्तु मैं नहीं मानता कि श्रीमती गांधी गैर जानकार थी । बल्कि मैं यह मानता हूँ—श्रीमती गांधी समझ चुकी थी कि संविधान को निरंतर कमजोर करते जाने से एक दिन ऐसी सावंधीम सत्ता उनके (कांग्रेस के नहीं) हाथ आ चुकेगी, जब वे सुविधा के साथ दमन-चक्र चलाकर करोड़ों आवाजों को एकदम चुप कर देंगी । और वह सब आपातकाल में शुरू हो चुका था । सम्पूर्ण शक्ति के साथ । जिन विशिष्ट व्यक्तियों की 'एकदम निजी समिति' में इस कदम को जनतांत्रिक ठहराते हुए आगे ले जाने का राजनीतिक दांव खेला गया होगा—उनकी भी प्रसशा की जानी चाहिए । सम्पूर्ण योजना को उन्होंने बड़े सलीके से प्रारंभ किया । श्रीमती गांधी और उनके विश्वस्त साथी यह अच्छी तरह जानते थे कि इस देश के उस सामान्य जन को, जो एक-दो नारो से ही सच्चवागो में घूमने लगता है, बड़ी सुविधा के साथ कुछ दिखाकर भटकाया जा सकता है और उस भटकाव के दौरान उसकी चेतनहीनता का लाभ उठाते हुए कहीं ज्यादा सुविधा के साथ उसे गूगा भी बनाया जा सकता है ।

इसी योजनान्तर्गत बड़े पैमाने पर प्रचार-तत्व सक्रिय हुआ । मोटियों ली जाने लगी । टेलिविज़न पर विशेष कार्यक्रम तैयार होने लगे । रेडियो खास किस्म के गीत गुनगुनाने लगा और जगह-जगह बैनर लगे नज़र आने लगे । गावों से लेकर हर सरकारी और निजी कार्यालय में पोस्टरो की बाढ़ दीखने लगी । लगता था कि हिन्दुस्तान एक नई किस्म के चुनाव-प्रचार में जीने लगा

है। ऐसा शक्तिशाली प्रचार, जिसे किसी भी चुनाव में नहीं देखा गया था। सारे देश में 'अपने लोगों के अपने लोग' और उनके 'अपने लोग' छोटी-छोटी मीटिंगें करके प्रस्ताव पास करने लगे—'हम श्रीमती गांधी के महान क्रांतिकारी कार्यक्रम के साथ हैं और आपातकाल का स्वागत करते हैं!'

लगभग हर शहर से समाचार-पत्रों में यह स्वागत नज़र आने लगा। ऐसे ही जैसे झूमरी तलैया से फरमायश की जाती है। क्या यह कम हास्यास्पद स्थिति है कि किसी देश में आपातकालीन स्थिति का स्वागत किया जाए?

प्रचार-तंत्र चलता रहा। इस तरह कि इस तंत्र के दौर में कहां क्या हो रहा है, लोगों को ठीक तरह मालूम ही नहीं हो सका। अचानक खबरें वरसनी शुरू हुईं। सनसनीखेज और रोमांचक। ये खबरें थीं—हाजी मस्तान, वखिया, यूसुफ पटेल आदि तस्करों की गिरफ्तारियों की। देश गद्गद हो गया। इसे कहते हैं क्रांतिकारी काम। सारे गलत लोग वन्द कर दिए गए हैं। पर इस गलत को सही करने की आड़ में निजी स्वार्थ की कितनी खिचड़ी पकती रही, लोगों को मालूम ही नहीं हो पा रहा था। ये खबरें जनता तक पहुंचा रहे थे वे लोग, जो भूमिगत हो चुके थे। भूमिगत आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ लोगों ने कितना काम किया, इसका वर्णन किसी और जगह करूंगा।

गलत को सही किए जाने का ही नाम 'आपातकाल' है। इस प्रचार के अन्तर्गत जो काम दिखाया गया, वह था नाजायज़ कब्ज़े हटाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से लागू करना, मुनाफाखोरी वन्द करना और कृषि-सुधार कार्यक्रम को तेज़ करना... इस सबसे गरीबी हटनेवाली थी, अमन-चैन आने वाला था और देश आगे बढ़ने वाला था।

सचमुच उस समय लोगों को यही लगा था। यह तो कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि इस सारे दौर का मतलब है—तानाशाही!... हिटलर और मुसोलिनी के बारे में बहुत सुना था इस देश ने, पढ़ा भी था... पर अनुभव हुआ उस दौर में, कहते हैं जिसे विनोबा बाबा ने कहा—'अनुशासन-पर्व'।

'अनुशासन-पर्व' या 'दुःशासन-पर्व' ?

बसों, स्कूटरों, ट्रेनों, सरकारी आफिसों और नेशनल हाईवे पर सारे देश में बिचारे पड़े होटलों और सरायों में बीस सूत्री कार्यक्रम के इशतहार लगे हुए

थे। कही कागज़ की शक्ल में, कही वार्निश से लिखे हुए और कही गेरू या खड़िया से अंकित। ये सूत्र श्रीमती गांधी ने दिए थे और सारे देश में इस तरह लागू किए जा रहे थे।

आपातकाल से पहले लागू क्यों नहीं किए जा सके? एक प्रश्न दिमाग में कौंधता। पर इमर्जेंसी का नियम था कि सवाल दिमाग में ही कौंधता, बुझता, झुलझाता रहना चाहिए, इसलिए सवाल सिर्फ कौंधता ही रहा।

पर यह सवाल सिर्फ सामान्य व्यक्ति के दिमाग में कौंधा हो, ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में भी कौंधता था, जो ये सूत्र लागू करने चले थे, जिन्होंने बोर्ड बनवाए थे, बैनर लगवाए थे, नारे लिखवाए थे। कारण था, अपनी ही अन्तरात्मा की ताड़ना। और खुद ही यहाँ-वहाँ सफाई देते घूमते कि ये सूत्र थे तो पहले ही, पर सविधान गलत था और देश गलत लोगों के बहुमत के हाथों में था, अतः लागू नहीं किए जा सके थे। पर आज देश 'सही के हाथ' में आ गया था और सविधान सही किया जा रहा था, बचा-बूचा और किया जाना था अतः अब ये सूत्र लागू हो रहे थे।

अचानक पता लगा कि आसमान में एक सितारा और था, जिसका नाम इससे पहले दुनिया वालों को मालूम नहीं था। ठीक उसी टोन में, जिस तरह 'नेपच्यून' नाम का सितारा आकाश में है, यह किसी वैज्ञानिक ने काफी देर बाद पता लगाया था। मगर हिन्दुस्तान के इस राजनीतिक सितारे का पता किसी विशेष वैज्ञानिक ने लगाया या खुदबखुद सितारा ही चीखने लगा कि 'देखो रे भाई, मैं सितारा हूँ, मुझे देखो'—मालूम नहीं। इतना सच है कि सितारा उग आया था। नाम भी पता लगा था जनता को—सजय गांधी।

अब इस 'अनुशासन पर्व' में अनुशासित ढंग से सितारे के गुणों की परख शुरू हुई। परख कर रहे थे राज्यों के मुख्यमंत्री; यथा, सर्वथी श्यामाचरण (चारण) शुक्ल (मध्यप्रदेश), नारायणदत्त तिवारी (उत्तरप्रदेश), ज्ञानी जैल (जेल) सिंह (पंजाब) आदि। इन राजनीतिक-वैज्ञानिकों के प्रधान थे—देवकान्त बरुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष।

परंप में बहुत-सी बातें पता लगी थी देश को। यह कि सजय गांधी युवा नेता हैं। यह कि सजय गांधी क्रांतदर्शी हैं। यह कि सजय गांधी (इलस्ट्रेटेड वीकली के अनुसार) 'मैन आफ द इयर' हैं। यह कि सजय गांधी में अपूर्व मंगलन-शक्ति है और यह कि सजय गांधी श्रीमती गांधी के अनुसार कांग्रेस की मदद के लिए आए हैं... और मोहम्मद यूनस फरमा रहे थे कि सजय गांधी

इसलिए राजनीति में आए हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि विरोधियों ने उनपर आरोप लगा-लगाकर उन्हें बुरी तरह तंग कर डाला था और इस कारण उनकी माताजी श्रीमती गांधी को बार-बार जवाब देना पड़ता था !'

तो इस तरह आए भारतीय राजनीति में नये नक्षत्र। और जब नक्षत्र आए तो अपने साथ कुछ चकाचौंध लाना भी जरूरी था। वे ले आए—चार सूत्र। और ये चार सूत्र भी बीस के साथ दीड़ लगाने लगे। कभी बीस आगे, कभी बीस आगे, कभी बीस आगे, कभी बीस आगे, कभी बीस आगे, कभी बीस आगे...

तो इस तरह भारत के आपातकाल की राजनीतिक आकाशगंगा शुरू हुई। होते-होते यह होने लगा कि हर सुबह अखबार उठाओ तो एक ओर संजय गांधी का 'तेजस्वी' चित्र देखो और 'ओजस्वी' भाषण पढ़ो और दूसरी ओर देखो कि श्रीमती गांधी ने देश को क्या सन्देश दिया है या 'असामाजिक तत्त्वों' के बारे में जनता को क्या बतलाया है। बीच का इण्ट्रो लगा होता श्री देवकांत बरुआ का जो कह रहे थे कि 'इन्दिरा इज़ इण्डिया एण्ड इण्डिया इज़ इन्दिरा' (इन्दिरा भारत है और भारत इन्दिरा है)। यह होतीं पैसठ करोड़ आदमियों के बहुभाषा-भाषी देश और देशवासियों की खबरें। राज्यों से समाचार यह थे कि ज़िला विलासपुर में नसबन्दी अभियान ज़ोरों पर हैं य लखनऊ में बीस सूत्री कार्यक्रम से क्रांति हो गई है।

टेलिविज़न का बटन ऑन कीजिए। म्यूज़िक पर एक भड़के के साथ यावाज निकल रही होती है—'दो पर सत्र करो, देश का संकट हरो।' यह था देश का आपातकाल !...

पर नहीं, देश का आपातकाल तो वह था जो न अखबारों में था, और न देखने की इजाज़त थी... आपातकाल था तुर्कमान गेट पर ! आपातकाल था उन झुगियों पर, जिनमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, और ऐसे ही महानगरों में करोड़ों लोग सिर्फ जी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे... या जेलों में दमन सह रहे निरपराध दम तोड़ रहे थे...

वह था आपातकाल ! और वही था विनोबाजी का अनुशासन-पर्व ! और वही था देश का लोकतंत्र, जिसे इन्दिराजी ने कृपापूर्वक दिया था और वही था सत्य-अहिंसा से लदी-बदी कांग्रेस का धर्म, जिसके तहत देश जैसे-तैसे जी रहा था।

प्रेम में सरशिव एक ऐसा हथियार था, जिने उन्नीस माहों तक सब का गला घुरी तरह दबाए रखा। यही कारण था कि आपातकाल के दौरान घटी घटनाएँ, जिनमें बहुत-से बेमुनाहों की हत्याओं और अन्धे कानून से प्राप्त सत्ता के कारण मैकडो वरवादियाँ के किस्से थे, लोगो तक नहीं पहुँच सके। दूसरी आज़ादी के तुरंत बाद ये किस्से सामने आने शुरू हुए, कुद्देक उन लोगो की गरदनो के भीतर ही घुटे रह गए थे, जो दमन के कारण गलत प्रशासकों और पुलिस के क्रूर अत्याचार के पजो में फँसी हुई थी।

२२ जून, १९७६ को बुलडोजरों का एक काफिला गुडगाव रोड पर देखा गया। काफिले के लाग बड़े उत्साहपूर्वक चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ये बुलडोजर भारति कम्पनी के रास्ते की ओर वैसे सभालखा गाव में जा पहुँचे। यह छोटा-सा गरीब गाव धीमे-धीमे थम की शक्ति पर प्रगति कर रहा था और प्रगति के दौर में उसकी अर्धविकसित स्थिति के कारण पचीसो घर और दुकानें कुछ कच्चे और कुछ पक्के थे। बुलडोजरो का उत्साही काफिला देखने के लिए उसीक ग्रामीण स्त्री-पुरुष और बच्चे बाहर आ गए थे। दृष्टाकार बुलडोजरों के भीमजर्न ने भी उन्हें चौंकाया और विस्मित किया था, पर उन्हें नहीं मालूम था कि थोड़ी ही देर बाद उनका विस्मय करण फ़इन में बदल जाएगा। कुछ लोग, जिनमें अधिकारी और साधारण कर्मचारी थे, बाहनों से उतरे और रौंदीली चाल में यहाँ-वहाँ पहुँचकर इलाके का निरीक्षण करने लगे। ग्रामीण हैरानी से उन्हें देख रहे थे कि वे वहाँ क्या कुछ करने वाले हैं। मुख्य मार्ग में सभालखा गाव की ओर दृष्टिपात करते हुए अधिकारियों ने अपना कार्यक्षेत्र निश्चित किया। थोड़ी ही देर में आदेश हुए कि भारति कम्पनी की ओर रास्ते में पड़ने वाला मारा इसाका, जिसपर फसले और कहीं-कहीं दमूब बेल भी लगे थे, साफ कर दिया जाए।

ग्रामीणो ने हक्के-बक्के रहकर आदेश सुना और उसके तुरंत बाद कातर स्वर में अधिकारियों से प्रार्थना की कि आखिर कारण क्या है? उनकी फसलें और भेत किसलिए तबाह किए जा रहे हैं?

ग्रामीण धीमे-धीमे और बात की बात में बुलडोजरो ने हरी-भरी फमनों वाले भेत तबाह करके समतल धरती बना डाली। स्त्रियाँ-पुरुष रोते-चीखते रहे, किन्तु कोई मुननेवाला नहीं था। यही नहीं, बुलडोजरो ने बहुत-सी कच्ची-पक्की दुकानों और मकानों को धरासायी कर दिया। एक मकान में पुलिसमैन की विधवा विमलादेवी अपने छोटे-छोटे पाँच बच्चों के साथ दिन काट रही थीं।

वह बच्चों को लिए हुए चीखती-गिड़गिड़ाती रही कि उसके घर को न तोड़ा जाए किन्तु वे सब उच्चस्तरीय आदेशों से बहरे बने हुए थे। यह मकान विमलादेवी ने कर्जा लेकर बनवाया था। किसानों ने ट्यूबवेल भी कर्ज पर लगवाए हुए थे, पर अब सब कुछ व्यर्थ हो चुका था। सरकारी सूचना दी गई कि अब यहां 'ट्रांसपोर्ट नगर' बनेगा।

क्यों ?

इसका कोई उत्तर नहीं था, सिवाय इसके कि 'ऊपर से हुबम' हुआ है। बुलडोजरों से सफाई करने का आदेश तत्कालीन निगमायुक्त बहादुरराम टमटा ने दिया था और 'नवभारत टाइम्स' के अनुसार टमटाजी को यह हुबम श्री संजय गांधी ने दिया था। और श्री संजय गांधी के दिमाग से यह हुबम क्यों निकला था ? इसका पता 'नवभारत टाइम्स' के संवाददाता ने यह लगाया कि मारुति कम्पनी की ओर जाते हुए संजयजी को इस अर्ध-विकसित ग्राम की गुरुपता नहीं पचती थी और उनका 'मूड' खराब हो जाता था, अतः उन्होंने निश्चय किया कि सौन्दर्य के लिए गांव को ही मिटा दिया जाए।

उस धरती पर ७० दुकानें बन रही हैं। करीनेदार और खूबसूरत। कहते हैं कि ये दुकानें युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बनाई जा रही थीं।

पुलिसमैन की लाचार विधवा श्रीमती विमला आज भी अपने पांच बच्चों को ज्यों-त्यों करके एक भुग्गी में पाल रही है। ग्रामीण अपनी समतल की गई १३० बीघा धरती देखकर आठ-आठ आंसू रोते रहते हैं। ट्यूबवेल ग्रामीण पड़े हैं।

दूसरा गुधार (?) बुलडोजरों ने दिल्ली के कश्मीरी गेट क्षेत्र में किया। एक जगह गत २६ वर्षों से एक पुराना विद्यालय 'विद्या भवन' स्कूल चल रहा था। इस स्कूल में ३० से अधिक कर्मचारी थे और सात सौ से अधिक बच्चे शिक्षा पाते थे। अचानक २६ अप्रैल, १९७६ को इस विद्यालय के प्रबन्धक श्री गर्ग ने (जो जनगंध सीट पर निगम पार्षद भी रह चुके थे) देखा कि ३०० पुलिसमैन ने स्कूल की इमारत को घेर लिया है। उनके साथ सेना का एक बुलडोजर भी था। कारण कुछ भी न बतलाते हुए अध्यापकों से कहा गया कि ये स्कूल के बाहर आ जाएं। अध्यापक बहुत गिड़गिड़ाए, प्रार्थना की कि यह उनकी रोजी ही नहीं है, बल्कि शिक्षा-दान का मन्दिर भी है। एक तरह से

तीर्थ ही है, पर कोई बात न सुनी गई। थोड़ी ही देर में सरकारी सेवक स्कूल के भीतर-बाहर समा गए। फर्नीचर, पंखे और सारा सामान तोड़-फोड़ डाला गया। बुलडोजर ने दैत्यगर्जना की और स्कूल की इमारत के २५ कमरे धराशायी कर डाले। पढ़नेवाले बच्चों का भविष्य क्या हुआ होगा? और वे अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिनकी स्कूल के कारण रोजी चलती थी, कहते हैं कि आज तक भटक रहे हैं। गत दिनों स्कूल के व्यवस्थापक श्री गर्ग ने समाचारपत्रों के सवाददाताओं से अपनी यह दुखगाथा सुनाई तब उनकी आंखें छलछला आई थी। उनका कहना था कि उन्हें मिली सूचना के अनुसार यह सारी कार्रवाई श्री राजय गांधी के हुक्म पर हुई थी। पर क्यों हुई थी, इसका कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था।

मुझे लगता है कि न समझ पाने का कारण नहीं होना चाहिए। क्या कारणहीन व्यवस्था को समझ लेना ही काफी नहीं है?

१६ अप्रैल, १९७६ को तुर्कमान गेट पर जो भयानक गोलीकांड हुआ, और उसमें जिस तरह निरौह स्त्री-पुरुषों और बच्चों की जानें गईं, उसका स्मरण-भर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तत्कालीन गृह उपमन्त्री श्री मोहसिन ने इस घटना के बारे में बतलाया था कि तुर्कमान गेट की घटनाओं और गोलीकांड का कारण प्रतिबन्धित सस्याएँ थी। उन्होंने कहा था कि यहां जो कुछ शासकीय कार्य चल रहा था, वह पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार था और उस कार्य में जब 'असामाजिक तत्वों' ने (श्री मोहसिन के अनुसार) गड़बड़ी फैलाई और हिंसात्मक हरकतों की, तब लाचार होकर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।

क्या था पूर्वनिश्चित शासकीय कार्यक्रम? विवरण देता हूँ। इस सप्पन इलाके में रहनेवालों की दशा सुधारने के लिए सन् १९३० में महात्मा गांधी ने और बाद में श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र के लिए पुनर्निर्माण योजना बनवाई थी। इस योजना को नाम दिया गया था—'दिल्ली गेट, अजमेरी गेट स्कीम' बाद में सन् १९६२ में मास्टर प्लान बना और इस क्षेत्र के विकास का विशेष प्रावधान हुआ। इस प्लान के तहत धीमे-धीमे कार्य चल रहा था। अनेक परिवारों को पुनर्वास-मुविधाएँ भी दी जा रही थी, किन्तु आपातकाल के दौरान एकदम सब कुछ सुधारने के लिए रात में सूरज उगाने का वह आश्चर्यजनक चमत्कार किया गया कि कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए और मैकड़ों परिवार बेघरबार हो गए।

श्री मोहसिन के अनुसार लोगों की भलाई का यह महान कार्यक्रम जब चला तो १२ अप्रैल, से १८ अप्रैल, १९७६ तक कई परिवारों को जहां-तहां रहने-सहने की सुविधाएं देते हुए वहां से हटाया गया किन्तु १६ अप्रैल को 'असामाजिक तत्वों' द्वारा गड़बड़ी किए जाने के कारण गोली चली और ६ व्यक्ति मारे गए तथा कुछ घायल हुए। (और जो गायब हो गए ?)

श्री मंजय गांधी और वेगम ख्खराना सुलताना (जो अपने को संजयजी की निजी सचिव कहती थी) ने भी इस इलाके का दौरा किया। कहा जाता है कि श्री गांधी ने उन तक गुहार करनेवाले लोगों को आश्वासन भी दिया कि उनके मकान नहीं टूटेंगे, किन्तु कार्रवाई चलती रही। बुलडोजरों के शोर से इलाका धरधराना रहा और मकान अर्थात् धरती पर बिछते रहे। परिणाम हुआ महिलाओं और पुरुषों का लाचार और शान्त आन्दोलन। उन्होंने बुलडोजरों के आगे बैठकर चीखना-पुकारना शुरू किया कि यदि उन्हें इसी तरह उजाड़ना है तो वे नहीं जीना चाहते।

बतलाया जाता है कि पुनर्वास के नाम पर बहुत-से परिवारों को दिल्ली के दूर कोने-कोनों में पहुंचाया जा रहा था। इस व्यवस्था में एक ही परिवार के विभिन्न लोगों को जब भिन्न-भिन्न जगह रखा जाने लगा, तब उन्होंने मांग की कि उन्हें एक जगह रखा जाए। यह भी कि उन्हें शहर से उतनी दूर क्यों काटा जा रहा है ? पर जब सुनवाई नहीं हुई तब वे धरना देने लगे।

नाराज अधिकारियों ने हुक्म दिया कि यदि ये लोग नहीं मानते तो इनके ऊपर से बुलडोजर निकाल दिए जाएं, पर काम न रोका जाए ! श्री मोहसिन ने कहा था कि शगड़े की पुरुआत 'असामाजिक तत्वों' ने की, पर उसी इलाके की महिला फारुखा वेगम के उमर्क का जवाब मोहसिन के पास गया है कि औरते अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर के बुलडोजरों के सामने लेट गई थीं। गया ये बच्चे शगड़ा करने पहुंचे थे ? वे स्त्रियां और बच्चे असामाजिक तत्व थे, जिनसे प्रशासनिक व्यवस्था को खतरा था ?

दोपहर दो बजे पुलिस नक्रिय हुई। स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को घसीटते, दुत्कारते, पीटते और बाल पकड़कर खींचते हुए यहां-वहां उछाला-पटका जाने लगा। पुलिसवाले घरों में घुस गए और बरतन सामान बाहर फेंक दिया या तोड़फोड़ डाला। बुलडोजरों की मंज्या १४ थी। वे बुलडोजर नक्रिय हो चुके थे और अंधाधुंध मकान गिराए जा रहे थे। अनेक स्त्रियों को उनके घरों के भीतर पहुंचकर वालों से घसीटते हुए बाहर लाया गया और

उनके गहने नोच लिए गए। ये गहने कहा गए, इसका अब तक पता नहीं है। बहुत-सी औरतें वेइज्जत हुईं। बिजली-पानी की लाइनों पहले ही काट दी गई थी। उजड़े हुए बहुत-से लोग बाहर मैदान में पड़े रो रहे थे। कुछ लोग घबराकर समर्पण कर बैठे कि 'आपकी मरजी ही पूरी करेंगे साहब, पर थोड़ी मोहलत दीजिए।'।

जवाब मिला—'मौत भी कभी मोहलत देती है?' हंसी, व्यंग्य और क्रूर आनंद लेते हुए पुलिस वाले इस सारी स्थिति से मनोरंजन कर रहे थे। अनेक स्त्रियों के कपड़े फट गए थे और वे लगभग नग्न हुई जा रही थी।

अब्दुल रजाक इस सागी आपाधापी में अपनी बच्चों को बचाने-गोखने के लिए भाग रहा था कि उसी बंदहवासी की हालत में एक गोली आई और उसकी बांह चीर गई। घबराया हुआ अब्दुल लड़खड़ाकर निकलने लगा कि तभी दूसरी गोली ने उसकी कमर को भेद डाला ! अब्दुल गिर पड़ा। बाद में अस्पताल में उसकी जान बच गई। अब्दुल रजाक ने अपने गोलीयों के घाव, जो अब पिनीनी तानाशाही के स्मरण बनकर निशान रूप में उसके जिस्म पर मौजूद हैं, पत्रकारों को दिखाए।^१

फारुखा बेगम कहती हैं कि औरतों की वेइज्जती की गई और मरदों को इस बुरी तरह मारा गया कि उसके ही नहीं, दसियों लोगों के देखते-देखते कई के सिर वहीं खुल गए। छून से सरोबार लोगों को खींच-खींचकर गाड़ियों में डाला गया और न जाने कहाँ ले जाया गया। यही नहीं, इन फारुखा बेगम के अनुसार बहुत-सी औरतों को उनके छोटे-छोटे बच्चों के साथ चिलचिलाती धूप में बिठा दिया गया और पहरा लगा दिया गया। ये पहरे बाले पानी तक नहीं देते

१. 'वर्तमान गेट पर गोली चलने के बाद ४५ दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया। औरतों को बेइज्जत किया गया। पुरुषों पर अमानुषिक अत्याचार किए गए। सजद गांधी से कर्फ्यू उठाने की प्रार्थना की गई तो उन्होंने जवाब दिया—'इन लोगों को कड़ा सचक मिलना चाहिए।' मैंने इन सितसिते में कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिराजी से मिलने की कोशिश की, पर मुझे वक्त नहीं दिया गया। अन्त में मैंने एक पत्र में सारे हाताहत लिखकर उन्हें सूचित किया। नतीजा यह हुआ कि मुझे परिवार नियोजन की विरोधी घोषित कर दिया गया। मैं स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने मिलने पर उन्होंने यही कहा कि वे इस मामले में साधारण और बसहूय हैं।' (श्रीमती मुन्ना जोशी का पत्र, जो उन्होंने कांग्रेस अध्वक्ष श्री सी०के० बरुजा को लिखा)

थे। फागुआ ने गिरफ्तार औरतों की संख्या पचास-साठ बतलाई, और दिल्ली सोसायटी के सम्पादक सईद खां के अनुसार मरनेवाले लगभग २५ हैं।

श्री मोहम्मिन ने घटना शुरू होने का समय १ बजे बतलाया है। उनका कहना है कि दोपहर १ बजे से 'फजल-ए-इलाही' मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लगभग शुरू हुआ था। नर्सिंग होम की ओर से पथराव हुआ। बाद में पुलिस को लाठी-गोली और अश्रुगैस का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने इस सारे कांड में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या ४५३ बतलाई थी।

बुलडोजरों ने पूरी रात काम किया और कई कच्ची-पक्की इमारतें ध्वस्त कर टालीं। इस दौरान तमाम सामान भी चकनाचूर हो गया। पर हत्याएं? उनमें बच्चों से भी परहेज नहीं बरता गया। इस अमानवीय क्रूरता के परिणाम-स्वरूप जहीरुद्दीन नामक व्यक्ति के दो बच्चे मारे गए। उसके साले की मौत भी हुई, जो सिर्फ २३ वर्ष का था और जिसका विवाह हुए कुल दस महीने हुए थे। जहीरुद्दीन का साला, जहीरुद्दीन के बच्चों को बचाने के लिए दौड़ रहा था।

यह सारा विवरण 'नवभारत टाइम्स' में धितीन्द्रमोहन श्रीवास्तव ने लिखा था। इससे कहीं ज्यादा विस्तृत विवरण 'इण्डियन ऐक्सप्रेस' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुआ।

'अनुशासन-पर्व' की ये कुछ वानगियां हैं। वे, जो जीना-मरना सिखा रही थी और जिसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने (हाल के चुनाव के दौरान) बिहार में दो दिवसीय दौरे पर एक भाषण में कहा था—“जनता को स्वयं इस बात का फैसला करना होगा कि क्या वे कांग्रेस के मूलभूत सिद्धान्तों व अदर्शों (लोकतंत्र, समाजवाद, और धर्मनिरपेक्षता) को बनाए रखना चाहते हैं, या उनको जो अनुशासनहीनता, दांगा-फसाद और तोड़-फोड़ में विश्वास करते हैं, उनको लाना चाहते हैं? किसी चीज को बिगाड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होता है।”

तुर्कमान गेट पर जो कुछ हुआ क्या वह बनाया जा रहा था? वह, जो विद्याभवन स्कूल में घटा, निर्माण था? और वह जो राजयजी का मूठ बरकरार रखने के लिए गुड़गांव रोड के उस छोटे-से गांव में घटा—निर्माण था?

६ दिसम्बर, १९७५ को हिन्दू ऐज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित तीन स्कूलों में जो घटना घटी, क्या वह भी देश की प्रगति के लिए था? सोसायटी द्वारा

मंचालित उक्त तीनों स्कूलों के सैकड़ों बच्चों और शिक्षकों को पुलिस के जबर-दस्त हमले ने अकचका दिया था। उस दिन अचानक ही तीनों स्कूलों में पुलिस घुस पड़ी और पड़ते हुए बच्चों को खींच-खींचकर बाहर निकाल दिया गया था। सोसायटी के पदाधिकारी मागेगम शर्मा के अनुसार कई बच्चों को पुलिस ने बुरी तरह पीटा तथा शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। लगभग मघा मौ अध्यापक बेकार कर दिए गए और बच्चों की शिक्षा अस्त-व्यस्त कर डाली गई। बहुत खोज के बाद कारण सुना गया था कि इस सोसायटी के अध्यक्ष चूकि भूतपूर्व महापौर साला हसराम गुप्त हैं, अतः इसे यह दमन महना पड़ा है। किन्तु सालाजी से कांग्रेस की तानाशाही को क्या शिकायत है, यह मालूम नहीं हो सका।

आपातकाल के नाम पर देश की प्रगति का जो ढोंग प्रचारित किया जा रहा था, क्या वह सब यही था? अपने विरोधी विचारवालों को तहस-नहस कर डालने के अर्धे तानाशाही ख्याल में यह भी नहीं सोचा गया कि एक स्कूल से हजारों परिवारों का भविष्य जुड़ा रहता है। उन परिवारों से देश का भविष्य जुड़ा रहता है और चूकि यह देश है इसलिए कांग्रेस या किसी भी दल का अस्तित्व है।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने एक सार्वजनिक सभा में राजनीतिक बदियों के साथ हुए आपातकाल के अशिष्ट व्यवहार का उदाहरण देते हुए बतलाया था कि खालियर की राजमाता विजयाराजे सिन्धिया के साथ क्या बर्ताव हुआ। श्री वाजपेयी के उक्त भाषण के कुछ अंश यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ—
“भारतीय जनमंच में शामिल होने के कारण तथा श्री जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के संघर्ष में भाग लेने के कारण राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिन्धिया को महल से निकलकर जेल में जाना पड़ा। और जेल में उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, सुनें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजनीतिक पुरुष बदियों के लिए पृथक् बाडें होता है, किन्तु राजनीतिक महिलाओं के लिए कोई पृथक् बाडें नहीं है। चोरी, जेवकतरी, हत्या और वेश्यावृत्ति के अपराध में पकड़ी गई औरतों के साथ उन्हें महीनों जेल में रखा गया।”

श्री वाजपेयी ने बतलाया था कि वे तिहाड़ जेल (दिल्ली) कई बार गए और उनकी कोठरी के सामने से गुजरे। श्री वाजपेयी ने वहां की स्थिति का

वर्णन करते हुए कहा कि जहाँ राजमाता रखी गई थीं, उसके सामने सुअरों का वाड़ा था। चौबीसों घंटे इतनी गंदगी रहती थी कि नाक पर बिना कपड़ा रखे हुए वहाँ से गुज़रना तक मुश्किल होता था।

तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष करनेवाले राजनीतिज्ञों की यह दशा थी और ऐसे भी कई उदाहरण हैं, जब ताड़ना-प्रताड़ना देकर अकारण ही निरपराध लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया या एक तरह से उनकी हत्या ही कर डाली गई। जॉर्ज फर्नांडिस के एक परिचित परिवार को केवल इसी कारण ज़बरदस्त मरणान्तक कष्ट झेलने पड़े क्योंकि उक्त परिवार के लोग जॉर्ज के मित्र थे। और जॉर्ज तानाशाही के विरुद्ध वगावत का एक नाम था।

बड़ीदा डायनामाइट कांड में जॉर्ज को उलझाया गया। जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई, सभी विरोधी नेताओं की पकड़-धकड़ में जॉर्ज की खोज भी की जाने लगी। जॉर्ज फर्नांडिस अपने मित्रों, शुभचिन्तकों और जनसहयोग में भूमिगत हो गए। क्योंकि आपातकाल के दमन ने इन्दिरा-शासन को अलोकप्रिय बना दिया था अतः पुलिस सिरतोड़ कोशिश के बावजूद जॉर्ज को नहीं पा रही थी। जैसाकि तानाशाही या सामन्तवाद में हमेशा से होता रहा है, जॉर्ज के शुभचिन्तकों और मित्रों को डराया, धमकाया जाने लगा या उनका दमन प्रारंभ हुआ। इसी सिलसिले में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी के यहां पुलिसवाने जा पहुंचे। स्नेहलता रेड्डी सोशलिस्ट पार्टी से पुराना सम्बन्ध भी रखती थीं।^१

स्नेहलता रेड्डी और उसके परिवार पर आपातकाल के प्रारंभ से ही दमन-चक्र प्रारंभ हो चुका था। उनकी बेटी नंदना को अनेक बार पुलिस ने तंग किया और पूछताछ की। नंदना की गतिविधियों पर भी इस तरह नज़र रखी जाने लगी, जैसे नंदना बहुत खतरनाक अपराधी हो। २७ अप्रैल को स्नेहलता रेड्डी और उनके पति श्री पट्टाभिरामा रेड्डी रात के समय बंगलौर से मद्रास गए थे। उनकी अनुपस्थिति में पुलिस घर पहुंची और उनके बेटे कोणार्क को जगाकर पूछा गया कि उसके माता-पिता कहां हैं? जब कोणार्क ने बतलाया कि वे बाहर गए हैं तो पुलिस वाने उसे तंग करते हुए पुलिस वाने

१. स्नेहलता रेड्डी कन्नड़ फिल्म 'सत्कार' में चन्द्र की अपनी भूमिका के लिए अपूर्व प्रशंसा लाने पर चुकी थी। इस फिल्म का निर्माण उनके पति पट्टाभिरामा रेड्डी ने ही किया था।

ले गए और इधर-धर पर सारा सामान उलट-पुलट करते हुए ध्वंश धाना-तलाशी करते रहे। परिवारजनों और यहां तक कि नौकरों को भी बेइन्तिहा तम किया गया। उपर स्नेहलता और उसके पति बार-बार अपने घर बंगलौर को फोन मिलाकर परिवारजनों से सम्पर्क साधने की चेष्टा कर रहे थे, किन्तु फोन काट दिया गया था। लाचार होकर उन्होंने पड़ोसी के महा फोन किया, जहां से मालूम हुआ कि कोणाक को पुलिस ने पकड़ लिया है और उस समय तक छोड़ा नहीं है। घबराए हुए रेड्डी दम्पति कार से बंगलौर आए। पर बंगलौर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे रात-भर कार्लटन हाउस में बंटे रहे। कोणाक की कोई सूचना उन्हें नहीं दी जा रही थी। बाद में उन्हें अलग-अलग ले जाकर फर्नांडिस के बारे में ऊटपटांग सवालता किए जाने लगे। घबराई हुई बिह्वल स्नेहलता ने कह दिया कि 'यह सब कुछ बतला देगी यदि उसके पति और बच्चे को घर जाने दिया जाए।' इसपर पति और बच्चा तो छोड़ दिए गए किन्तु स्नेहलता को भीमा में बन्द कर दिया गया। अब दिन-दिन-भर उसे 'जो मालूम है बतलाने के लिए' दबाव डाला जाने लगा। मच यह था कि वह कुछ भी नहीं जानती थी। उसने बतलाया कि मैं कुछ नहीं जानती। इसपर भयानक यत्नशाए दी जाने लगी। स्नेहलता को कानकोठरी में डाल दिया गया और 'सी' बनास मिली। परिणाम हुआ उसका बीमार हो जाना। स्नेहलता को दमा पहले से ही था, किन्तु ठीक तरह इलाज और ध्येयवा न मिल पाने के कारण दौरा पड़ गया। कहते हैं कि इस दौर में डॉक्टर ने जेलवालों को हिदायत दी थी कि उसे तुरन्त अस्पताल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वह मानसिक घुटन के कारण दिल की मरीज भी बन चुकी है, पर उपेक्षा कर दी गई। बाद में परिवारजनों के बहुत कुछ कहने-मुनने पर स्नेहलता को एक माह के लिए पैरोल पर रिहा किया गया, तथा दिन का दौरा पड़ने से स्नेहलता का अन्त हो गया। प्रधर विचारों वाली एक अभिनेत्री को देश में छो दिया।

जॉर्ज फर्नांडिस के बड़े भाई श्री लारेंस फर्नांडिस की कहानी भी कम दर्द-नाक नहीं है। लारेंस एक सीधे-सरस आदमी हैं और एक छापाखाना चलाते हैं। १ मई, १९७६ को लारेंस के घर पर दस्तक हुई। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सादा कपड़ों में खड़े हुए हैं। इन लोगों ने बतलाया कि उन्हें थाने बुलाया गया है। लारेंस ने ज्यादा 'ना-नुच' नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि पुनिग का दमनचक्र इस दौर में कितना अमानुषिक हो चुका है। उन्होंने सोचा कि थाने में जो कुछ भी पूछा जाएगा, उसका समाधानकारक उत्तर देकर लारेंस

चले आएंगे। वे थाने पहुंचे, किन्तु कहते हैं कि उनसे विना कोई सवाल किए ही एकदम मारपीट शुरू कर दी गई। उन्हें नंगा कर दिया गया और बेंत बरसाए जाने लगे। हर बार पूछा जाता कि वे बतलाएं जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ हैं? किन्तु लारेंस बेचारे क्या बतलाते? लारेंस को वेददीं से मारा गया। बीच में उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक देने के भी प्रस्ताव आए, किन्तु भाग्यवश ये प्रस्ताव पास नहीं हो सके और लारेंस की सांसें ज्यों-त्यों करके चलती रहीं।

लारेंस को जिस थाने में पूछताछ के लिए ले जाया गया था, उसके पास वाले कमरे से उन्होंने स्त्री-स्वर में एक दर्दनाक चीख सुनी थी। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि वह चीख स्नेहलता रेड्डी की थी, जो उन्हींकी तरह केवल जॉर्ज के बारे में पूछताछ करने के लिए अत्याचार सह रही थी। बाद में लारेंस के बाल-दाढ़ी मुड़ाकर और घायल स्थिति पर औपचारिक इलाज करके बंगलौर से १५० किलोमीटर दूर किसी नगर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और औपचारिक वयान हुए। लारेंस को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उनके शरीर पर अनेक जगह प्लास्टर चढ़ चुका था। उस यंत्रणाकाल के दौरान कई बार लारेंस ने पुलिसवालों से प्रार्थना भी की थी कि उनके शरीर-कष्ट अब इतने असह्य हो चुके हैं कि उन्हें गोली मार दी जाए! किन्तु लारेंस जीवित रह गए।

इस तरह के अमानुषिक अत्याचारों से कितने लोग मरे होंगे। कितने लोगों ने तानाशाही के उन अंधेरे उन्नीस माहों में अपनी सांसें तोड़ दी होंगी—गिनती नहीं है। हाल में एक व्यक्तव्य देकर कुछ नेताओं ने दिल्ली के उन मौसा वन्दियों की रहस्यमय मृत्युओं पर जांच की मांग की है, जो जेल में दम तोड़ बैठे। ये तीनों थे—सर्वश्री वैजनाथ कपिल, तिलकराज नहला, और मोहनलाल जाटव। श्री कपिल और नहला जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जबकि मोहनलाल भारतीय लोक दल के।

बहुत-से नाम हैं, जो अब क्रमशः सामने आ रहे हैं, किन्तु कितने नाम होंगे जो कभी सामने नहीं आ पाएंगे और जिन्होंने अपनी सांसें देकर तानाशाही की जड़ों में मट्टा डाला था।

उपर्युक्त उदाहरणों के बाद भी पिछले दिनों जब मैंने श्रीमती गांधी के एक भाषण-अंश को 'दिनमान' में पढ़ा तो मुझे हैरानी होने लगी थी कि क्या इस सबको घटा देने के बाद कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है?

श्रीमती गांधी ने चुनाव के दौरान किसी सभा में कहा—“मैं सेविका के

रूप में जनता का सहयोग मागने आई हूँ, जिससे समाजवाद और लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा की जा सके। मेरी पार्टी अपनी उपलब्धियों के आधार पर दोबारा चुने जाने के लिए आपके सम्मुख आई है। इसमें शक नहीं है कि हमने अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है—”

आपातकाल के नाम से देश को मानसिक रूप में पंगु बनाने वाले लोग अगर लोकतन्त्र शब्द का उच्चारण करें तो कैसा सगता है? किन उपलब्धियों के आधार पर कांग्रेस भारतीय मतदाता से वोट माग रही थी? और किन लोगों के लिए? क्या उनके लिए जिनके बारे में ‘टाइम्स ऑफ इण्डिया’ ने १३ अप्रैल, १९७७ के अपने सम्पादकीय में लिखा है :

“भूतपूर्व स्पीकर श्री बलिराम भगत ने कहा कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष श्री सीताराम केसरी और मुख्यमंत्री की हिलाई के कारण वे चुनाव में हार गए। इसपर केसरी ने उत्तर दिया कि बलिराम भगत इसलिए हारे हैं क्योंकि उन्होंने स्वातंत्र्य-संग्राम में बिना जेल जाए ही ताम्रपत्र हाँपिया लिया था और मतदाता उनकी यह हरकत नापसन्द करते थे। डा० राममुनग सिंह ने भी कहा कि मतदाताओं को यह मालूम हो गया था कि बलिराम भगत ने दिल्ली में तीन मकान बनवा लिए हैं।”

आपातकाल को लेकर सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत रूप में श्रीमती गांधी चुनाव में और उससे पूर्व बराबर कहती रही थी कि इस दौरान देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। इन उपलब्धियों में यह विशेष रूप से बतलाया जाना था कि महंगाई कम हो गई है और लोगों की जरूरत की सभी चीजें, जो कि आपातकाल से पूर्व अक्सर मुनाफाखोर लोग बाजार से माँग कर दिया करते थे, उपलब्ध हैं। यदि आँकड़ों को देखा जाए तो यह प्रचार भी व्यर्थ साबित होता है। आपातकाल के प्रारम्भ में कीमती पर अस्तर पड़ा था, किन्तु कुछ ही माहों बाद वे उसी गति से बेकायू होने लगी थी, जिस गति में पहले रही थी। यही नहीं मँने मामान्वत. दुकानदारों को उपेक्षा के साथ यह कहने भी मुना था कि ‘हो गया, जितना होना था, अब आग कुछ नहीं होगा।’ जाहिर था कि जिस भय की बुनियाद पर श्रीमती गांधी मुद्धार को व्यवहार रूप में लाना चाहती थी, वह क्रमशः प्रभावहीन होता जा रहा था। हा, यदि भय था तो उन लोगों में जो मुक्त विचार रखते थे और जो इस निश्चित नतीजे तक पहुँच चुके थे कि आपातकाल महज सत्ता को बचाए रखने और लोक-तंत्रीय स्वरो को कुचल डालने का एक राजनीतिक कुचक्र है—घोड़े ही दिनों

में लोगों ने यह भी समझ लिया था कि अब एक तानाशाही में जीते जाना ही उनकी नियति है। ऐसी तानाशाही जो पारिवारिक रूप से बाद में श्री संजय गांधी के हाथ पहुंचनेवाली है।

संसार के किसी भी देश के इतिहास में उसके राजनीतिक आकाश पर संजय गांधी की तरह उगनेवाले सितारे का प्रमाण नहीं मिलता। यह प्रमाण केवल भारत ने ही दिया। बल्कि यों कहा जाना ज्यादा उचित होगा कि यह प्रमाण भारतीय जनमानस ने नहीं, उस तानाशाही ने दिया, जिसकी सुरक्षा में गैरजिम्मेदार व्यक्ति, ज्यादा गैरजिम्मेदारी और धांधली में पनपे। सामान्यतः बहुत-से लोगों के मुंह में एक तर्क यह सुना है कि श्रीमती गांधी पूरी तरह से अंधेरे में रखी जा रही थीं और उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी आड़ में संजय गांधी या उनके लेफ्टिनेंट क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह के तर्क देनेवालों के लिए चुनाव के बाद 'व्लिट्ज' के दिल्ली व्यूरो से ए० राघवन द्वारा लिखे गए निम्न शब्द काफी हैं :

“प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा शर्मनाक हार खानी पड़ी। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने उड्ड वेटे के प्रति गहरी ममता संजोये रहीं और उसने जो कुछ हरकतें कीं, उन्होंने चुनाव-अभियान के आखिरी दिनों में उनका न तो विरोध किया और न ही उससे अपना नाता तोड़ा।”

“...दक्षिण में जहां संजय अपना दुष्ट प्रभाव नहीं डाल सके या इसके लिए उन्हें समय नहीं मिला वहां चुनाव में शासक पार्टी को अपूर्व विजय प्राप्त हुई...”

“...श्रीमती गांधी अपने वेटे के भौतिक और राजनीतिक दुराचारों से घनिष्ठ रूप से परिचित थीं। हमें ऐसे वीसियों मित्रों और शुभचिन्तकों का पता है, जिन्होंने उनसे इस भयानक स्थिति में दखल देने की प्रार्थना की थी, लेकिन उन्हें बेखुशी के साथ टाल दिया गया। इन्दिराजी की शह से संजय के पाप और भी बढ़कर गांधी और नेहरू की कांग्रेस को ले डूबे।”

‘व्लिट्ज’ का उपर्युक्त कथन मैंने विशेष रूप से इस कारण उद्धृत किया है, क्योंकि नेहरू परिवार के प्रति ‘व्लिट्ज’ के मन में भी कम ममता नहीं रही है, पर एक स्थिति ऐसी आई जब व्लिट्ज को सचाई की विपैली कड़वाहट ताचारी में उगलनी पड़ी और जैसे ही चुनाव-घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल

और जन-मानस के उछड़ाव को लेकर उसने लिखना आरंभ कर दिया।

आश्चर्यजनक किन्तु दुःसह सत्य यह है कि चुनाव में अपनी तानाशाही की जबरदस्त पराजय के बावजूद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मंजय गांधी को लेकर कहा कि संजय पर दोष मटना व्यर्थ है।

मैंने पूर्व में आर्थिक उपलब्धियों या कुल देश के ही हर क्षेत्र की सामाजिक, साम्प्रतिक, उपलब्धियों की बात की है, जिन्हें लेकर चुनाव में दोन पीटा जाता रहा था कि बोट काप्रेस को ही मिन्नने चाहिए क्योंकि देश ने बड़ी तरक्की की है। तरक्की किस तरह हुई, कैसी हुई इसका लेना-जोखा करते हुए 'स्निट्ज' ने लिखा—“इमजेंसी की घोषणा के दो दिन बाद ही प्रधानमंत्री ने अपने पहले ब्राइकास्ट में व्यवसायियों को अभयदान दे दिया। तब में आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने बड़े व्यवसायियों को शक्तिशाली बनाकर उनकी आश्रमक शक्ति को बढ़ाया ही। दूसरी तरफ अधिकारियों ने अनिवार्य बचत योजना, बोनम में कटौती आदि के जरिये मजदूरों और कर्मचारियों पर आक्रमण किया।”

“और जैसे-जैसे इमजेंसी का वक्त गुजरता गया, उसका आर्थिक प्रगति का दावा खत्म हो गया और वह दरअसल दमन का हथियार बन गई। तमाम व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का दमन कर दिया गया।”

किन्तु इस दमन-चक्र में कुछ लोगों के हाथों में असीम शक्ति जा पहुंची थी। वे हाथ, जो राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस दल के नहीं, एक तरह से श्रीमती गांधी और संजय के निजी हाथ थे। इन हाथों के जरिये ठीक हिटलरी पद्धति से तानाशाही का चक्र चलता रहा था। सर्वश्री बसीलाल, ओम मेहता, विद्याचरण शुक्ल के पास ऐसे विभाग थे, जिनके माध्यम से किसी भी देश का शासन-संघ चलता है। इन उप-तानाशाहों ने उन्नीस माहों के भीतर आश्चर्य-जनक और अविश्वसनीय राजनीतिक करिश्मे किए।

इमजेंसी के दौरान फिल्म-उद्योग के साथ मूचना और प्रसारण मंत्रालय कैसी-कैसी नाटकीय हरकतें करता रहा, इसका विवरण देते हुए ऑल इण्डिया फिल्म प्रोड्यूसर्स कौंसिल के अध्यक्ष जी० पी० सिप्पी ने एक वक्तव्य में डेरों आरोप लगाए और प्रमाण दिए। श्री सिप्पी ने सेंसरशिप को व्यवसाय और कला के लिए 'दमघोट' नीति बतलाते हुए कहा था कि जब-जब फिल्म-निर्माताओं ने सेंसरशिप में ढील की माग की, तब-तब उन्हें और ज्यादा तेज कैची का सामना करना पड़ा। यही नहीं, कई निर्माताओं को तो कुछ लोगों की

क्योंकि उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के बीच इतनी रहस्यपूर्ण बातें, घटनाएं या पोलें होती हैं कि जिनके भय से वे किसी भी पल मुक्त नहीं रहे पाते। इस स्थिति का लाभ आपातकाल में सरकार ने खूब उठाया। इसका मज्जेदार उदाहरण है चुनाव के दौरान दैनिक समाचार पत्रों में पूरे-पूरे पृष्ठ के वे विज्ञापन, जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर श्री सुनीलदत्त और नरगिस दत्त ने दिया। पिछले पृष्ठों पर मैंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अखबारों को दिए गए निर्देशों में जिन समाचारों का उल्लेख किया है, उनमें नरगिस-सम्बन्धी एक समाचार है। क्या यह माना जाना चाहिए कि चुनाव के दौरान उस समाचार को रोके जाने के बदले में कांग्रेस पक्ष का समर्थन करते हुए ऐसे विज्ञापन दिए जा रहे थे? इसके बावजूद फिल्म उद्योग के कुछ लोग जिस बुलन्दी और निर्भयता के साथ तानाशाही के विरुद्ध जन-मंच पर आए, उसकी सराहना करनी चाहिए। स्वतंत्रता के तीस बरसों में फिल्म उद्योग में यह एक क्रांति ही थी कि पहली बार उद्योग के कुछ लोग जन-मंच पर आकर सत्ता के विरोध में अपनी ईमानदार आवाज़ बुलन्द करें। खास तौर से उन स्थितियों में, जिनमें कि भारतीय फिल्म उद्योग सिर्फ रहस्यों की सुरंग बना हुआ है और उद्योग वालों को इनकमटैक्स, काले रुपये और उसी तरह के काले किस्सों के बीच किसी न किसी स्तर पर गुंथे रहना होता है।

तानाशाही में कला और कलाकार की किस तरह हत्या की जाती है, इसका प्रमाण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उस निर्देश से मिल सकता है, जिसके अनुसार कलाकारों के व्यक्तिगत कला-जीवन को भी मुक्त नहीं रहने दिया गया था। एक आदेश के अनुसार उनपर पाबन्दी लगा दी गई थी कि वे स्वतंत्र रूप से दिए जाने वाले किसी भी संस्था के पुरस्कार को न लें, न किसी ऐसे समारोह में जाएं। इस पाबन्दी में आपातकाल के दौरान कौन-सा देशहित किया जा रहा था?

एक ओर श्री शुक्ल¹ और उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय फिल्म उद्योग में

-
1. "Shri Shukla was a curse on the Film Industry. He behaved like a dictator. Disobeying his orders, was just like a death-knell! He boosted non-entity Sanjay Gandhi in press, over radio and T.V. He imposed upon several film personalities to participate in Sanjay Gandhi's rallies and Youth Congress programmes." (Film Information, 26 March, 1977)

निजी तानाशाही चलाए हुए थे, दूसरी ओर वे साहित्य और रंगमंच पर भी खासी दखलबन्दाजी कर रहे थे। जन-मंच से होने वाले भाषण ही नहीं, गान्धितिक कार्यक्रमों पर भी जबरदस्त पाबन्दी थी। इस पाबन्दी के परिणामस्वरूप केवल वे कार्यक्रम हो पा रहे थे, जिनमें किसी न किसी रूप में तानाशाही का प्रचार किया जा सकता था। कलात्मकता लगभग नष्ट हो चुकी थी और विचार का मूल मानवीय स्तर ही समाप्त हो गया था। १९७४ में मैंने एक तीन अंकी नाटक लिखा था 'विकल्प'।^१ पाटलिपि को अन्तिम रूप देते-देते २६ जून को आपातकाल प्रारम्भ हो गया। इस नाटक का कथ्य था आज की राजनीति में बिखराव और दिशाहीनता की स्थिति। विरोधी और सत्ताधारी दोनों के ही भटकाव पर व्यंग्य करते हुए मैंने जतलाया था कि बार-बार यह प्रचार करना कि 'देश के हालात खराब हैं' झूठ है, सच तो यह है कि व्यक्ति के हालात खराब हैं। और इन खराबी का कारण देश नहीं, बल्कि हम हैं जो नैतिक मूल्यों को बिसरा बैठे हैं। इस नाटक के मंचन और प्रकाशन दोनों ही केवल इस कारण खटाई में पड़ गए, क्योंकि इसमें राजनीतिक चरित्र थे या एक तरह से सत्ताधारियों के ढोंग उजागर हुए थे, उसी तरह जिस तरह सामाजिक जीवन के अन्य लोगों के मुँहोटे बतलाए गए थे। किसी दल-विरोध या विचार-विरोध का प्रचार न होते हुए भी नाटक कुछ सरकारों की राय में 'खतरनाक' करार दे दिया गया था।

मुद्रामिद्ध नाट्य निर्देशक-लेखक और मेरे मित्र बृजमोहन शाह को भी इस आपातकाल उर्फ तानाशाही का एक खट्टा अनुभव हुआ। रवानियर की एक नाट्य मस्या उनका 'मुद्रमन' नामक नाटक उन्हीं के निर्देशन में अभिनीति करने जा रही थी, किन्तु मैसेर आड़े आ गई। चूँकि नाटक की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लम्बी रिहर्सलें की जा चुकी थी। हाल बुक हो चुका था, अतः संयोजक मस्या खासा घन व्यवहार कर चुकी थी। मैसेर ने जब उसपर कलम चलाई तो कुल नाटक का रूप ही विचित्र ढंग से प्रभावहीन होकर रह गया। नाटक का कथ्य था—मुद्र का विरोध और मुद्रवादियों के अमानवीय हथकण्डों को उजागर करना।

वर्तमान यह हुई आपातकाल की कलात्मक उपलब्धियाँ (?)। एक

१. शब्द 'विकल्प' का प्रकाशन, 'तरस्वती विहार' २१ दयानन्द मार्ग, दरियापुर, नई दिल्ली ११०००२, से हुआ है।

उपलब्धि हुई वयोवृद्ध लेखक गुरुदत्त को। बहुत पहले उनका एक उपन्यास 'मधु' प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में उन्होंने चुनावी भ्रष्टाचार का वर्णन किया था। अचानक एक सुबह मुझे भालूम हुआ कि गुरुदत्तजी को मीस में बन्द कर दिया गया है। कारण? वह उपन्यास, जो उन्होंने बहुत पहले लिखा था। जीवन के सन्ध्याकाल में बैठे वृद्ध लेखक के साथ हुए इस वर्ताव पर मुझे ही नहीं, सभी बुद्धिजीवियों और कलाकारों को गहरी वेदना हुई उससे भी आगे बढ़कर यह समाचार मिला कि उक्त उपन्यास के प्रकाशक से एक लाख रुपया नकद की जमानत मांगी गई है, ताकि आगे कभी वे उस तरह की (जिसमें कांग्रेसी भ्रष्टाचार की चर्चा हो) पुस्तक प्रकाशित करने का 'दुस्साहस' न करें।

भयानक मानसिक यंत्रणा से भरे उस तानाशाही समय को लेकर कई लोगों से जब यह सुनने को मिलता है कि दुष्काल को दुःस्वप्न की तरह भुला दिया जाए तो तकलीफ ज़्यादा गहरी हो उठती है। आर्थिक या भौतिक हानि को आदमी एक बार भुलाने की कोशिश कर सकता है, किन्तु समूचे मानस को झकझोर डालनेवाली कटु स्मृति उतनी सहजता से नहीं भुलाई जा सकती।

अन्धेरगर्दी और अनवृक्ष तानाशाही के समय में ही चुनावों को लेकर अटक-बाजियां शुरू हो गई थीं कि अब संभवतः श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव करवाएंगी। लाखों लोगों ने फुसफुसाहटों के बीच हैरत जाहिर की थी कि इन्दिराजी चुनाव करवाने की भूल कर सकती है? मैं 'भूल' शब्द का जान-बूझकर उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस सामान्त्यवर्ग में नहीं था, जो जनता से हजारों मील दूर गलतफहमी में जी रहा था कि देश ने उपलब्धियों के ढेर कर लिए हैं; विरोध का गला दबाया चुका है और चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद हो रहा है। मैं जनता के उस वर्ग में जी रहा था, जो उस अटकल-दोर में ही यह अच्छी तरह समझ सकता था, उन लाखों लोगों की तरह, जिन्होंने तानाशाही का भयावह आतंक देखा-भोगा था। लोग चुप थे और इन्दिराजी के संस्येई मूकदेदार समझ रहे थे कि लोग खुश हैं। लोग घुटे हुए थे

१. 'मधु' का लाभप्रेरी संस्करण राजपाल एण्ट सन्ज दिल्ली से प्रकाशित हुआ था, और पॉकेट संस्करण के प्रकाशक हैं—हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लिमिटेड, दिल्ली-३२।

और कांग्रेस का झाल था कि 'सब कुछ पा जाने के आनन्दान्तिरेक में' उनके गले रंधे हुए हैं। लोग बेचैन थे और इन्दिराजी समझ रही थीं कि लोग घोट देना चाहते हैं। वयवितक स्तर पर जिन राजनेताओं को आपातकाल की अमोघ शक्ति से जेलों में बन्द कर रखा गया था, उन्हें लेकर समझा जा रहा था कि जनता को उनमें लगाव नहीं है। कई लोगों को इसी तरह समझा जा रहा था।

चुनाव होंगे— यह मुरमुरी राजधानी से मंभवत दिगम्बर, १९७६ में उठी और इस मुरमुरी को लेकर दबी-भुदी फुमफुमाहटें फैल गईं। क्या श्रीमती गांधी नहीं जानती हैं कि चुनावों का मतलब होगा, कांग्रेस का मफाया या खबरदस्त पराजय? या श्रीमती इन्दिरा गांधी यह समझ रही हैं कि लोगों ने तानाशाही तंत्र को स्वीकृति दे दी है? या फिर इन्दिराजी अपने घंटे की मनमानियों में परेशान होकर 'इस पार उस पार' का खेल खेलना चाहती हैं या भीतरी तौर पर देश में गड़बड़ शुरू हो गई है? या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में श्रीमती गांधी के लोकतंत्रीय कुर्कवाले तानाशाह रूप को पसन्द नहीं किया जा रहा है? या श्री मुद्रहाण्य स्वामी, श्रीमती सैला फर्नांडिस और केदारनाथ माहनी जैसे विरोधी लोगों के विदेश पड़च जाने के कारण श्रीमती गांधी के तानाशाही तंत्र के कारण उनकी बदनामी हुई है? या फिर देश की समस्याएं भीतरी तौर पर जटिल हो गई हैं? और या कांग्रेस में भीतरी तौर पर गड़बड़ होने लगी है? अथवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंच के भूमिगत आन्दोलन ने तानाशाही को खोपला कर दिया है?

ये विभिन्न अनुमान, तर्क और कारण थे, जिन्हें लेकर चुनावों पर अटकलें लगाई जा रही थीं। चुनाव होंगे इस मुरमुरी के साथ ही एक निश्चित राय गांवों तक में सुनी गई थी कि श्रीमती गांधी ऐसी भूल करके अपने-आपको उलझन में डालना नहीं चाहेंगी, इसलिए चुनाव नहीं होंगे। विरोधी नेताओं की जेलों की कालकोटरियों में ही मटा-मटाकर मार डाला जाएगा।

चुनाव की खबर और अटकलवाजियों ने इतना जोर पकड़ा कि जनवरी, १९७७ प्रारंभ होते-होते गृहमंत्री श्री ओम भटना ने एक बक्तव्य देकर देश को सूचना दी कि चुनावों को लेकर बेकार ही अनुमान लगाए जा रहे हैं। निकट भविष्य में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। राजनीतिक पर्यवेक्षक चर्चित हो गए। विशेषकर इसलिए क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती भारत के कांग्रेसी

शासन की प्रतिष्ठा देखते हुए पर्यवेक्षकों ने यही निष्कर्ष निकाला था कि बदनामी से उबरने के लिए श्रीमती गांधी चुनाव करवाएंगी। पर्यवेक्षकों ने और भी बहुत-से अनुमान प्रस्तुत किए थे और देश की आंतरिक स्थिति, कांग्रेस की भीतरी तौर पर दलगत स्थिति और निरंकुश जनता की ऊब इसी नतीजे पर पहुंचा रही थी कि श्रीमती गांधी अब चुनावों का आसरा लेंगी। थोड़े समय से कई नज़रबन्द नेताओं की रिहाई और उनमें से कुछ के साथ हुई गुप्त वार्ता, चुनाव कमीशन को दिए गए सतर्कता-संकेत और कमीशन का कुछ सक्रिय होना, तथा कांग्रेस नेताओं के वक्तव्य, सभी कुछ से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं रहा था कि श्रीमती गांधी संभवतः चुनाव करवाने का निर्णय ले चुकी हैं। पर ओम मेहता के वक्तव्य ने इन सारी अटकलों को मटियामेट कर दिया था।

किन्तु श्रीमती गांधी चुनाव क्यों करवाएंगी ? क्या केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती प्रतिष्ठा के कारण ? निश्चय ही ऐसा नहीं था। कम से कम सिर्फ यही कारण नहीं था। मुझे लगता था कि यदि श्रीमती गांधी चुनाव का निर्णय लेती हैं तो केवल उपर्युक्त कारण से नहीं, बल्कि इस तरह की 'रिस्क' के केवल इसलिए उठानेवाली होंगी क्योंकि अन्दरूनी तौर पर प्रशासनिक हालत खस्ता होने लगी हैं।

आपातकाल के दौरान बड़ी-बड़ी उपलब्धियों का प्रचार करते हुए भी अन्ततोगत्वा शासकीय स्तर पर यह स्वीकार लिया गया था कि कीमतें बढ़ने लगी हैं और कीमतें बढ़ने का कारण कपास, तेल या तिलहन की कमी न होकर उनकी सट्टेबाज़ी और कालाबाज़ारी है। इस सट्टेबाज़ी और कालाबाज़ारी और को बढ़ावा कौन दे रहा था ? तानाशाही के दौर में पनपे अपने लोग और उनके अपने लोग। नौकरशाही और भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका था और इस सबपर काबू पाना सरकार के लिए ही कठिन होने लगा था। मजदूरों में वोनस के मामले को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा था तथा मिल-मालिक तालाबन्दी करने में जुट गए थे। भीतरी तौर पर कांग्रेस दल में ही आपातकाल हटाने की मांग उठने लगी थी और श्रीमती गांधी संभवतः महसूस कर रही थीं कि लोकतन्त्र-कम-तानाशाही का यह डबल रोल बहुत लम्बा नहीं चलाया जा सकता।

कुछ लोगों का अनुमान है कि श्रीमती गांधी मूलतः इस कारण परेशान थीं कि संजयवाद के उत्कर्ष ने कांग्रेस दल के भीतर खासा विद्रोह पैदा कर दिया

था। पुराने और तोड़े काग्रेसी श्रीमती गांधी की सत्ता और तानाशाही में तो ज्यो-र्यो करके समझौता किए चले जा रहे थे, किन्तु उनमें से ज्यादातर मंजूर की राजनीतिक छुदाई को नहीं सह पा रहे थे। इस स्थिति को बहुत दिनों तक इन्दिराजी ने भीतरी घर्षण करके दबाए-छिपाए रखा था, किन्तु बाद में वैसा कर पाना असंभव हो चुका था तथा नन्दिनी सतपथी और उसके बाद मिट्ठारं शंकर राय-विवाद ने काले दही की ये हाडी चौराहे पर सा फोड़ी थी।

बहरहाल देशवासियों ने अविश्वसनीय ढंग से १९७७ की १८ जनवरी को रात में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी का अप्रत्याशित सन्देश सुना, जिसमें उन्होंने मार्च माह में लोकसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा की। इसी दिन श्रीमती गांधी ने यह सूचना भी दी कि आपात स्थिति में ढील दी जा रही है, ताकि मान्य राजनीतिक दल चुनाव गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। अगले ही दिन दो प्रमुख नेताओं की रिहाई के समाचार जनता ने समाचार पत्रों में पढ़े। ये थे सर्वप्रथम मोरारजी देसाई और लालकृष्ण अडवाणी।

श्रीमती गांधी की उपर्युक्त घोषणा ने दबे-रखे स्वरो को बोलने की स्वीकृति दी, हालांकि शंका, भय और आतंक से सस्त चेहरे उस समय भी परेगान दीखते थे, क्योंकि आपातस्थिति में 'थोड़ी ढील' किम्बवा मुमावदार शब्द उन्हें सहज नहीं होने दे रहा था। इसके बावजूद महसूस किया जा रहा था कि अंधेरी लम्बी सुरंग में अनायास ही कोई रोशनी की किरण उग आई है।

लोकतंत्र या तानाशाही : चुनाव

२३ जनवरी को जनता पार्टी के निर्माण की घोषणा हुई। इस पार्टी के तहत सगठन कांग्रेस, जनगंध, भारतीय क्रांति दल और सोशलिस्ट पार्टी एकत्र हो गए थे। उन्होंने एक झंडा, एक निशान, एक विचार का निर्णय लिया था और घोषणा की थी कि उपर्युक्त चारों ही दलों ने जनता पार्टी में विलय का निश्चय कर लिया है। यह एक सनसनीखेज और तीखी खबर थी, जिसके कारण मतदाता गंभीर होकर इन सभी दलों के बारे में सोचने लगा था। वह चुन था कि इस राजनीतिक छुड़ीकरण ने देश की राजनीति को एक निश्चित और स्थायी दिशा दी है, जब वह कांग्रेस के विवक्षित रूप में जनता पार्टी के बारे में सोच सकता था।

इस नंदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वह वक्तव्य, जिसे उन्होंने चुनाव-घोषणा पर हर्ष व्यक्त करते हुए दिया था। श्री नारायण ने कहा था कि विरोधी दल यदि एक होकर अपने-आपको एक-दूसरे में विलीन कर लेने पर तैयार होते हैं तब वे उनका चुनाव-प्रचार करने को भी तैयार हैं। इसके साथ-साथ श्री नारायण ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि वे ऐसा न करके 'अपनी-अपनी ढफली, अपना-अपना राग' ही अलापते रहेंगे, तब श्री नारायण चुनाव से अलग रहने के लिए बाध्य होंगे।

इस घोषणा का सभी विरोधी दलों पर प्रभाव हुआ। सभी दल गत उन्नीस माहों के दमन-चक्र में यह पूरी तरह अनुभव कर चुके थे कि उन्हें यदि लोकतंत्र और अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो विखराव की स्थिति त्याग कर एक होना पड़ेगा और उस निश्चित विचार के साथ जुड़ना होगा जो जयप्रकाश बाबू ने दिया है और जिसके अनुसार समग्र क्रांति का जन्म हुआ है। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर अनेक विरोधी नेता महसूस करने लगे थे कि जनता उन्हें व्यक्ति-रूप में नहीं, विचारधारा के रूप में स्वीकार करने को तैयार है और यदि ऐसा नहीं होता तो किसी भी पल जनता ही उन्हें कचरे के ढेर में फेंक सकती है। यही कारण है कि आम चुनाव में विजय के बाद जब जनता पार्टी के नेता श्री रामधन से धर्मयुग के उदयन शर्मा ने प्रश्न किया कि, "जनता पार्टी के अन्दर भी कुछ लोगों ने सत्ता-संघर्ष का अजीबोगरीब खेल दिखाया। क्या इन प्रवृत्तियों पर काबू पाकर जनता पार्टी एकजुट रह सकेगी?"

श्री रामधन ने उत्तर दिया, "जनता पार्टी एकजुट रहेगी, क्योंकि उसे एकजुट रहना पड़ेगा। जनता का दबाव इतना है कि वह पार्टी में दरार डालने वाले का राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म कर देगी।"

प्रकट है कि एक स्थिति यह भी थी। इस तरह लोकनायक के समग्र क्रांति दर्शन, देश की राजनीतिक चेतना, और जनमानस की अपेक्षाओं ने बिखरे हुए दलों को इस निश्चित विचार तक पहुंचाया कि ध्रुवीकरण का मार्ग ही देश और उनके अपने लिए श्रेयस्कर है। इस तरह स्वतंत्रता के तीस वर्षों बाद एक जबरदस्त राजनीतिक शक्ति भारत में तैयार हुई। इस शक्ति के सामने कांग्रेस के बाद, वेधुनियाद और गलत प्रचार ने घुटने टेक दिए।

जनता पार्टी की घोषणा ने कांग्रेसी इन्दिरा खेमे में हड़बड़ी फैला दी। इस हड़बड़ी के बहुत-से कारण थे। एक बड़ा कारण था—आपातकाल में हुआ अत्याचार और तानाशाही अंधेरे का अनुभव, दूसरा उससे भी बड़ा कारण था

एक न्यायिक तर्क कि विरोधी दलों को चुनाव के लिए समय बहुत कम दिया गया था। सहज ही था कि जन-साधारण ने एक निश्चित निष्कर्ष यह निवाला कि ऐसा जानबूझकर किया गया है, क्योंकि श्रीमती गांधी चाहती हैं कि विरोधी दलों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर ही न मिले। साधनहीन तो वे हैं ही। सहज था कि जनता की सहानुभूति इस सत्तागत 'बेईमानी' के कारण जनता पार्टी की ओर जाए। तिसपर सबसे बड़ी बात थी राजनीतिक धुंधीकरण। इस बड़े काम ने देश को एक स्पष्ट नतीजा दे दिया था कि विरोधियों के पास निश्चित विचार और सह्य है जिसने उन्हें एकमत करके तानाशाही के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। उससे भी बड़ी युनियाद जनता पार्टी के पास थी, उसके नेताओं पर चलाया गया क्रूर दमन-चक्र। इन भारी बातों के बाद घोषणा के सुरत बाद, लगभग दो सप्ताह के भीतर ही इन्दिराजी और कांग्रेस इन स्थितियों की गंभीरता को पूरी तरह भाप गए। जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं द्वारा जन-मन पर बड़ी जाने वाली बातों ने ही सिद्ध करना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस और श्रीमती गांधी का व्यक्तिगत प्रभाव किस लिजलिजी हालत में जा पहुंचा है।

जयप्रकाशजी ने सबसे पहले एक वक्तव्य देकर जनता पार्टी के चुनाव-अभियान का प्रारंभ किया और कहा कि यह चुनाव देश का निर्णायक चुनाव है और इसमें यह फैसला होने वाला है कि देश तानाशाही को चुनता है अथवा लोकतंत्र को।

मैं समझता हूं कि यह सम्पूर्ण चुनाव उपर्युक्त दो पक्षियों की बुनियाद पर ही हुआ और जनता ने मत भी इसी आधार पर दिए।

देश में धीमे-धीमे राजनीतिक चेतना और खोया हुआ विश्वास जाग रहा था। यार-थार विरोधी नेताओं को अपनी सभाओं में बहना होता था कि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें। चुनावी नारों में ज्यादा पोस्टर विरोधी दल की ओर से इस आशय के लगाए गए थे कि भय को निवानकर वोट दें। इन चुनाव में विरोधी दल को एक बहुत बड़ी परेशानी यह आ रही थी कि आपातकाल के तानाशाही युग ने सामान्य जन को बुरी तरह भयभीत कर रखा था। मतदान से पूर्व उसकी चेतना और बिखरे हुए विश्वास को बटोरना विरोधी दलों के लिए अत्यावश्यक हो गया था।

घोषणा-पत्रों के दौरों में भी सिद्धांततः कांग्रेस और जनता पार्टी की लगे बातों पर मतदाता ने ज्यादा विचार किया। यह भी कांग्रेस का यह रहना

पिछले आमचुनाव की तरह ही इस बार भी विरोधियों ने खिचड़ी बनकर कांग्रेस को हराने का संकल्प उठाया है, और जनता को यह निर्णय करना है कि वह विभिन्न दलों से मिलकर बनी जनता पार्टी को वोट दे या कि कांग्रेस नाम की एक जमात को। श्रीमती गांधी अपने हर भाषण में दोहरा रही थीं कि केन्द्र में स्थाई सरकार के लिए केवल कांग्रेस ही है, जिसे वोट मिलना चाहिए। देश के राजनीतिक स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है और मतदाता को इसी आधार पर निर्णय लेना है, जबकि विरोधी दल का सबसे बड़ा नारा था— 'लोकतंत्र या तानाशाही—मतदाता चुन लें कि क्या सही है, क्या गलत !'

और मतदाता शांत भाव से दोनों ही पक्षों की बातें सुन रहा था। यह अपने-आप में विचित्र बात थी कि राजनीतिक दलों को जबरदस्त गहमागहमी के बावजूद मतदाता एकदम प्रतिक्रियाहीन बना हुआ था। हां, राजनीतिक स्तर पर दोनों ही ओर अपनी-अपनी तरह अटकलें लगाई जा रही थीं। जैसा कि पिछले हर भारतीय चुनाव में होता रहा था, मतदाता को लेकर निरंतर एक गलतफहमी राजनीतिक स्तर पर यह रही कि जिसका प्रचार जोरदार होगा और जो 'अपनी जोरदार हवा फैला सकेगा' वोट उसीको जाएंगे। हालांकि चुनाव के नतीजों ने बाद में यह राजनीतिक गलतफहमी बुरी तरह धो डाली कि 'मतदाता बुद्धि पर नहीं, प्रचार पर चलता है'।

प्रतिक्रिया का पहला चमत्कार उस समय हुआ, जब दिल्ली में रामलीला मैदान में जनता पार्टी की एक आमसभा हुई, किन्तु उससे पहले एक ऐसा राजनीतिक उलटफेर हुआ, जिसने कांग्रेस पक्ष को बुरी तरह लड़खड़ा दिया। यह उलटफेर था सर्वश्री जगजीवन राम, हेमवतीनन्दन बहुगुणा, नन्दिनी सतपथी आदि कांग्रेसी नेताओं का कांग्रेस-त्याग। इस त्याग का कारण था दल में आंतरिक रूप से लोकतंत्र की हत्या करना। स्पष्टतः यह तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की बगावत थी।

बहुत-सी राजनीतिक उखाड़-पछाड़ और अटकलें लगनी शुरू हुईं। यह कि श्री जगजीवन राम ने उस समय वैसा क्यों नहीं किया, जबकि देश पर आपातस्थिति के नाम से तानाशाही थोपी गई थी और बवंर दमन तथा अत्याचार चल रहे थे? श्रीमती गांधी ने बाबूजी के त्यागपत्र पर आश्चर्य और दुःख प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें जगजीवनराम से ऐसी आशा नहीं थी। यह भी कि त्यागपत्र देने के कुछ देर पूर्व श्री जगजीवनराम श्रीमती गांधी के पास बैठे

हुए देर तक बाने करते रहे थे और उस समय उन्होंने, उन्हें ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया था।

श्री जयजीवनराम ने इन मारे सवालियों और राजनीतिक कुरेदनों का उत्तर बड़ी साफगोई से यह कहकर दे दिया कि आपातस्थिति जारी करने के पूर्व मंत्रिमंडल में उनमें बिलकुल सलाह नहीं ली गई थी। वे कभी इन तानाशाही के समर्थक नहीं रहे और स्पष्ट शब्दों में 'राजनीतिक रूप में मोका दे रहे थे कि क्या उन्हें इस सबसे अलग हो जाना है। आठ-दस दिन की गरमागरमी के बाद यह विवाद ठंडा हो गया और एक नई किस्म का भविष्य उभर आया, जिसके अनुसार कांग्रेस की स्थिति एकदम टाढाढोल हो चुकी थी और देशी-विदेशी सभी राजनीतिक समोशक इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि यह चुनाव बहुत 'काटे का' होगा और इसमें कांग्रेस की पराजय नहीं हुई तो हालत खस्ता हो जाने की पूरी आशंका है।

रामलीला मैदान में एक विशाल आम-सभा में श्री मजबूत गांधी भाषण करनेवाले थे। शहर में इस आगम की घोषणा करते हुए कांग्रेस की ओर से पोस्टर भी लगाए जा चुके थे, प्रचार भी चल रहा था, पर अचानक एक परिवर्तन हुआ। उस आम सभा में श्रीमती गांधी ने भाषण दिया और मजबूत गायब हो गए। यह घटना बहुत छोटी-सी थी, बिल्कुल इसमें मुलकें हुए लोगों को यह समझने में सन्निक भी दिक्कत नहीं हुई कि कांग्रेस का चुनाव-अभियान ही नहीं, विश्वास भी लड़खड़ा उठा है और भीतरी तौर पर श्रीमती गांधी तथा उनका दल निरंतर यह महसूस करने लगे हैं कि उनकी हालत खराब है।

जब कि उसी मैदान में दूसरे दिन जनता पार्टी की आमसभा में चुनाव के राजनीतिक भविष्य का आसार दिखाना प्रारंभ कर दिया। इस आमसभा में दस लाख से ज्यादा लोग पहुँचे और उन्होंने अत्यंत शान्तिपूर्वक विभिन्न नेताओं के भाषण सुने। लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण के अनिश्चित दश मन्त्रों में सर्वश्री मुरारजी देसाई, जयजीवनराम, अटलबिहारी वाजपेयी, हेमवतीनन्दन बहुगुणा आदि अनेक नेता उपस्थित थे। सम्भवतः दोनों ही पक्षों की ओर से अब तक प्रतिप्रियाहीन बने रहे भारतीय मतदाता की यह मौन प्रतिक्रिया थी, जिसने प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था कि मतदाता जनता पार्टी के साथ हैं। सबसे बड़ी बात थी, इस आमसभा में श्रोताओं द्वारा विरोधियों को चुनाव लड़ने के लिए धन दिया जाना। जब मंच से यह अपील की गई कि 'हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, अतः हम आपसे बोट भी चाहते हैं'

और नोट भी चाहते हैं' तब कहते हैं कि लोगों ने रुपये और रेजगारी की शक्ल में जितना बना, पैसा दिया। लगभग १ लाख तीस हजार रुपया इस आमसभा में जनता ने जनता पार्टी को दिया।

यह एक विलक्षण घटना थी और इस घटना के कारण तानाशाही के अस्वीकार की मौन घोषणा मतदाता ने कर दी थी।

अचानक कांग्रेस की रणनीति में आश्चर्यजनक बदलाव आया। निस्सन्देह ही यह बदलाव चुनाव का रुख देखकर हुआ था। ऐसे प्रमाण हैं कि भीतरी तौर पर कांग्रेस में टिकट को लेकर कांग्रेस के पूर्व-इतिहास की ही तरह 'मारामारी' चल रही थी। मंजय गांधी की युवा कांग्रेस 'युवाशक्ति' के नाम पर बड़ी संख्या में टिकटों की मांग कर रही थी, जबकि बहुत-से पुराने बुजुर्ग नेताओं का विरोध भी किया जा रहा था। प्रारंभ की चुनावी शतरंज और श्रीमती इन्दिरा गांधी का व्यक्तिगत रुख, दोनों ही इस मामले में युवा कांग्रेस की ओर झुकाव प्रकट करते रहे थे। जिस तरह एक वर्ष में युवाशक्ति के नाम पर मंजयवाद पनपा था, और जिस तरह सत्ता की गुप्त सहायता उसके उत्कर्ष में महायक रही थी, उससे भी प्रकट होता था कि इस चुनाव के कांग्रेस टिकट मंजयवादियों की जेब में ज्यादा जाएंगे। यही आसार थे, जिनके आधार पर युवक कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती अम्बिका सोनी ने 'दिनमान' को दी एक भेंट में यह पूछे जाने पर कि "युवा कांग्रेस ने कितने स्थानों की मांग की है और विभिन्न प्रदेशों, विशेषकर दिल्ली से आपके कितने उम्मीदवार खड़े होंगे?" कहा था—“ठीक संख्या का तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि हमें काफी टिकट मिलेंगे। दिल्ली में हम कम से कम तीन-चार उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहेंगे।”

पर श्री जगजीवनराम, बहुगुणा और सतपथी के अलग होते ही, जिस तरह दल से लोग निकलने लगे, उसने श्रीमती गांधी और बरुआजी को यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि उन्हें 'टिकट-प्रसादम्' की नीति पर पुनर्विचार करना होगा। इस पुनर्विचार का परिणाम था, युवा कांग्रेस के 'डिक्टेसन' का नई रणनीति के साथ ही हवा में उड़ जाना। अब नई रणनीति के अनुसार कांग्रेस के उपेक्षित बूढ़ों की कद्र शुरू हुई। इस कद्रदानी का एक कारण और भी था। यह सोचा जाने लगा था कि हर बूढ़े कांग्रेसी का

अपने इलाके में निजी प्रभाव है और अब कांग्रेस को अपनी गुडविल में ज्यादा व्यक्तियों की गुडविल पर लड़ना होगा। परिणामतः कुछ राजस्वानों को त्यागपत्र दिलवाकर चुनावी मैदान में उतारा गया, कुछ वूटों को मर-जोयों लिया गया। हालांकि चुनावी राजनीति का एक टटपुजिया हमकण्डा कांग्रेस ने गोहाटी अधिवेशन में भी शुरू कर लिया था, जिसके अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पुनः दुनिया जाने लगा था। यह दुलार इन आड़े बदन पर काम आया (कितना आया यह तो चुनाव-अविष्य ने मांमने रिया) पर कांग्रेस ने तुरंत कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चुनावी-मटजोह कर लिया। इन मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी भूल गई कि थोड़ी देर पहले ही उसके अनुसार कांग्रेस में सी० आई० ए० एंजेंट घुसे हुए थे और कांग्रेस भी भूल गई कि जवाब में उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मरव बगाना था कि स्वाधीनता-आन्दोलन में उन्होंने गहारी की थी। ये 'तांको और न मोको ठोर' वाली कहानी शुरू हुई।

गज यह कि कांग्रेसी नेमे ये हताशा का दौर शुरू हो गया, जबकि विरोधी खोरखोर और लगन में जनमन का प्यार अजित करते जा रहे थे। बहुत कुछ कारण कांग्रेस के घोषणा-पत्र का खोखलापन भी था, जिसमें 'पूर्व-उपलब्धियों का स्मरण दिनाते हुए आर्थिक विकास का आग्रह' दिया गया था। कहा गया था कि कांग्रेस पूर्व-निर्णय के अनुसार गरीबी हटाने, विपमना मिटाने और अन्याय समाप्त करने के लिए कृत-संकल्प है। मुझे स्मरण आता है कि घोषणापत्र की ये बातें या शब्द-विशेष पत्रक में और मेरे तीन-चार मित्र देर तक हंसते रहे थे। हंसने का कारण था—अन्याय मिटाने, गरीबी मिटाने और पूर्व-उपलब्धियां गिनवाने वाला ब्योरा... क्योंकि बीते हुए १६ माहों ने हर इस शब्द के विरुद्ध काम करके जतना दिया था कि कागज पर जितनी आगानी में शब्द लिखे जा सकते हैं, उसमें वही ज्यादा आसानी से उन मय पर पुनाई भी की जा सकती है।

हताशा का दौर हो था जो कांग्रेसी नेताओं से अजजतून बाने कहलवाने लगा। उत्तेजना, उछड़ाव और आवेश में थोमनी गांधी ने विरोधी दल पर येतुके आरोप करने शुरू कर दिए। ठीक उसी भाषा में, जिस भाषा में इनने पूर्व

१. एक मध्यप्रदेशीय कहावत, जिसका अर्थ है—हो साधारण का समझौता, जिसमें अन्य / वही समझौता नहीं हो सकता।

श्री जयप्रकाश नारायण के अहिंसात्मक आन्दोलन से घबराकर वह कह वैठी थीं—“श्री मिश्र की हत्या एक बड़े निशाने का पूर्वाभ्यास है!” इस बार चुनाव सभाओं में वे कहने लगी थीं—“मुजीबुर्रहमान और उनके परिवार के सदस्यों के साथ क्या-क्या जुल्म नहीं हुए, क्या विरोधियों की नीयत इस देश में वही सच करने की है? और यदि है तो उन्हें यह बात खुलकर करनी चाहिए! इस तरह की वेबुनियाद बातें वर्दाशत नहीं की जा सकती!”

अपरोध रूप से श्रीमती गांधी एक तरह से यही प्रचार करने लगी थीं कि विरोधी उनकी हत्या करना चाहते हैं! इस उथले ढंग की बेसिर-पैर वाली बातें लोगों की संवेदनात्मक सहानुभूति जगाने के डरावे से कही जा रही थीं। परन्तु उलटा ही असर हुआ। विशेष रूप से उस स्थिति में जब विरोधी दलों के नेता उन्नीस महीने तक भयानक यंत्रणाएं भोगकर जेलों से निकले थे और उनके कई कार्यकर्ता अपनी जान खो बैठे थे। यह ऐसे ही था जैसे ‘भेड़िया आया’, ‘भेड़िया आया’ का शोर मचाया जाए।

यही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता पार्टी की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। उसमें साम्प्रदायिक और तोड़फोड़ करने वाले तत्त्व हैं। मगर ये सारी बातें करते हुए श्रीमती गांधी यह भूल गई थीं कि १९७१ के चुनाव की तरह अब भूठे प्रचार का जादू काम नहीं करने वाला है और यह भी कि यह प्रयास करने के बाद उन्नीस महीनों की तानाशाही में भारतीय मतदाता यह तमाशा भी देख चुका था कि दमन, हिंसा, आतंक और अन्याय में किसका विश्वास है। कुल मिलाकर यह कि इस बार कांग्रेस के पास अपने विरोधी को काटने के लिए न कोई तर्क रह गया था, न कोई कारण और न ही कोई प्रमाण। इसके विपरीत विरोधियों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था और जनता को समझाने के लिए बहुत कुछ था।

श्रीमती गांधी ने २८ फरवरी को बिहार में अपनी चुनाव-सभा में कहा—“आज जो लोग हमपर तानाशाह होने का आरोप लगा रहे हैं, वे एकदम झूठी और वेबुनियाद बातें कर रहे हैं। यदि यह बात सच होती तो आज चुनाव नहीं होते। चुनाव करवाने का मतलब ही है कि लोकतंत्र में हमारी आस्था है।”

किन्तु श्रीमती गांधी उस सत्य को कैसे नकार सकती हैं कि हर तानाशाही की वेबुनियाद लोकतंत्रीय विश्वास को लेकर ही पड़ती है। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जर्मनी की सत्ता में आगमन एक लोकतंत्रीय पद्धति से ही हुआ था। उसने सत्तास्व होते ही क्रमशः तानाशाही व्यक्तित्व उजागर किया

और उसपर जनता की स्वीकृति-मोहर लगवाने के लिए सोवन्त्र या आइम्बर बनाए रखा। यही नहीं, हिटलर ने क्रमशः १९३४, १९३६, १९३८ और १९३९ में आमचुनाव करवाकर अपनी तानाशाही सत्ता को तोरतत्रीय सरकार का जाभा पहनाए रखकर जन-स्वीकृति प्राप्त की थी। इन ऐतिहासिक सत्य के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी का तर्क एकदम बोदा साबित हो जाता है कि वह तानाशाह नहीं है।

काग्रेस प्रारंभ से ही सत्ता में रही थी अतः प्रचार-पट्ट की दृष्टि से उसके पाम गर्वाधिक साधन थे। ये साधन पिछले चुनावों में हमेशा ही कारगर मिळ गए थे। शक्तिशाली आर्थिक बुनियादवाली इस संस्था के साथ प्रचार की वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध थीं, जो दूसरे दलों के पास कभी भी नहीं रही थी। पर इस चुनाव में प्रचार की साधनहीनता के बावजूद जनता पार्टी का जितना जोर देया गया, उतना पिछले चुनावों में कांग्रेसी प्रचार और मत्तानाशिन के बावजूद नहीं देया गया। चुनाव के मतोंजो ने भी यह साबित कर दिया कि अब जन-चेतना प्रचार के आधार पर निर्णायक बुद्धि नहीं बनाती। गणेश मंत्री ने अपने एक लेख में लिखा—“१९७७ के चुनाव-परिणामों ने कम से कम हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में एक बात और स्पष्ट की है। यह कि तिरुं प्रचार के दूत पर लोगों का मन नहीं जीता जा सकता।”

गत चुनावों में प्रचार के दल-यूते पर बहुत-से राष्ट्रनेताओं की तगवीर घुघली करने की कोशिश की गई थी और कुछ हद तक सफल भी रही थी, किन्तु इन बार वह स्थिति नहीं रही। मंत्री ने इसी लेख में आगे लिखा—“पूरी आपातस्थिति के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सर्वथी जार्ज फर्नांडिस, अटलबिहारी वाजपेयी और अन्य प्रमुख विरोधी नेताओं के विरुद्ध एकतरफा घुआधार प्रचार हुआ, पर आपातस्थिति में दीन मिलते ही यह स्पष्ट हो गया कि सारे प्रचार से लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा उनके अन्य सहयोगियों-नेताओं की प्रतिभा घुघली नहीं हुई है, वस्तुतः वह पहले से अधिक उज्ज्वल हो गई है।”

यहां यह उदाहरण दे देना भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत रूप से राज-नेताओं को किम तरह इन्दिरा सरकार के चापलूस लोग बदनाम करने में लगे हुए थे। ‘नया जीवन’ में टिप्पणी करते हुए उसके सम्पादक ने लिखा—“गांधी

दिया है कि क्या जनता पार्टी तथा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम भी है या उसके अस्तित्व का आधार केवल विरोध है ! यदि जनता पार्टी का आधार केवल विरोध है तो वह विरोध की बेंचों पर ही क्या बुरी है ? उसे सत्ता में क्यों भेजा जाए ? वास्तविकता यह है कि सत्ता की अपनी शक्तें होती हैं, जिनसे कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छी तरह परिचित है ।”

यही ‘दिनमान’ (२७ मार्च-२ अप्रैल का अंक) सम्पादकीय में प्रकाशित करता है—“१६ महीने के दमन के विरुद्ध जनता ने दलों को एक होने और कांग्रेस का विकल्प देने को बाध्य किया । वे एक हुए क्योंकि उन्होंने वक्त का तकाजा पहचाना...” मुझे लगता है कि सामान्य जन और तीव्र घटनाभेदी दृष्टि की पत्रकारिता में यही अन्तर है कि अगर जनता १६ महीने के दमनचक्र में ‘वक्त का तकाजा’ पहचानी तो ‘दिनमान’ ने सिर्फ मार्च महीने-भर में (यानी २७ फरवरी और २७ मार्च के बीच) ‘वक्त का तकाजा’ पहचान लिया ।

‘वक्त के तकाजे’ की पहचान का कमाल यह है कि वही ‘दिनमान’, जिसके अनुसार २७ फरवरी के अंक तक कहने के लिए ये शब्द थे—“सत्ता की अपनी शक्तें होती हैं, जिनसे कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह परिचित है या कि जनता पार्टी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का कार्यक्रम निषेधात्मक है अचानक बदलकर ३ अप्रैल के अंक में नियमानुसार हो गए—आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की ‘लोकशाही’ को लोकसत्ता में सही प्रतिनिधित्व मिला है । या जनता पार्टी के विशाल समूह में निश्चित ही ऐसा माननेवालों को कभी नहीं है, जो कहते हैं कि लोकशाही की स्थापना के लिए निहित स्वार्थों से लड़ाई की सच्ची शुरुआत अब हुई है ।

यह सचमुच एक तकलीफदेह सच है कि औसत हिन्दी समाचारपत्र ‘वक्त के तकाजे’ के अनुसार लिखते-छपते रहे । इस प्रतिकारी लड़ाई को, जिसे आज प्रगति के रूप में ढोल बजा-बजाकर वही लोग गुना रहे हैं, कभी इसीको केवल अराजकता और देशघाती पड़्यंत्र निरूपित करते रहे थे । यह एक कड़वा सच है कि इस प्रगति के गौरवशाली इतिहास में स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी, माग्यननाल चतुर्वेदी या रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसा कोई भी नाम नहीं है । इसका सेहरा बुद्धिजीवी के सिर नहीं, बल्कि उस तथ्याकथित ‘अशिक्षित’ के सिर है, जिसे बुद्धिवाद के थोड़े दप में हमेशा ही उपेक्षित किया जाता रहा है । यही नहीं, इस प्रगति ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि निरक्षर होने का मतलब अशिक्षित होना नहीं होता । शिक्षा किताबों से नहीं, सिद्धांतों, विचारों और

मस्कारों से मिलती है। और इसी कठोर यथार्थ की देन था वह माहौल जिसे इन्दिराजी और उनकी कांग्रेस चुनाव में झेल रही थी।

इस चुनाव ने बहुतों के चेहरे उजागर किए। विशेषकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वह चेहरा जिसपर कहावत लागू होती है—मुंह में राम बगल में छुरी। इस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में बड़ी दोहरी बातें की और मुझे लगता है कि उनके दोहरेपन को इन बातों ने ही छुव अच्छी तरह समझा जा सकता है और शायद चुनाव में गमझा भी गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने दावा किया कि उसने सदा ही नकारात्मक प्रवृत्तियों का विरोध किया है। मुझे खूब याद है कि आपानकान नामु करने बाद भारतीय कम्युनिस्ट ही थे, जो आगे बढ़कर कह रहे थे—यही सही है। यही होना चाहिए था। दल ने प्रजातांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध विभिन्न बानूनों के उपयोग का विरोध किया, यह भी घोषणा-पत्र में कहा गया था, जब कि यही दल था जिसने मविधान में मशोधन हो नहीं, उसमें आगे बढ़कर सम्पूर्ण मविधान को ही समाप्त करके 'नव रचना' का नारा लगाया था। घोषणा-पत्र ने जनता को सूचना दी कि अनेक राज्यों में उसके कामकर्ता जेलों में पड़े हैं। यह बहुत बड़ा झूठ था। सच तो यह है कि श्रीमती गांधी की सानाशाही कम्युनिस्ट पार्टी के कंधों पर चढ़कर ही मारे देश में घूम रही थी। अपने कंधों को भगा कांग्रेस कैसे काट सकती थी और जब गजब गांधी ने यह गलती की तो तुरन्त 'यवन का तकाजा' समझकर कांग्रेस ने चुनाव-अवसर पर उसे सम्भाल लिया हानाकि यह दोस्ती भी कांग्रेस को कम मंहगी नहीं पड़ी।

कांग्रेस और कम्युनिस्टों में मोटो का बटवारा बड़ी रूठा-राटी के बाद हुआ और जिस तरह हुआ, वह भी अपने-आपमें विचित्र था। चुनाव के दिनों, मैं मध्य-प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के ग्रह-में गांवों-शहरों में रहा और मैंने कांग्रेस-कम्युनिस्ट-दोस्ती का समस्कार-दर्शन भी किया। ग्वानियर की लोकमभा सीट पर समाजवादी और गरीबपरस्त कांग्रेस ने इटक के एक नेता को (जिन्हें विरमाजी का भरपूर स्नेह-सहयोग प्राप्त बताया जाता है) अपना उम्मीदवार बनाया था। चूंकि उक्त कांग्रेसी उम्मीदवार मजदूर नेता था, अतः कम्युनिस्टों ने तुरन्त अपना उम्मीदवार अट्टा दिया। जब मैंने यह जानकारी की कि ऐसा क्यों हुआ है और 'दोस्ती' में यह किस तरह का न्याय है तो एक कम्युनिस्ट ने बतलाया, यह तो हमारे अस्तित्व का प्रश्न है गाहव...
सेवर यूनिपन में हम लोग कांग्रेस को समर्थन देने लगे तो हम ही दब

मेरा प्रश्न था, “क्या इसपर कांग्रेस पक्ष से एतराज नहीं हुआ ?”

“हुआ होगा, पर यह हमारा फैसला था !”

“मगर सोचिए, आप लोग आपस में एक-दूसरे के वोट काट लेंगे तो जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाएगा !”

“जीत जाए !” उपेक्षा से वह कम्युनिस्ट बोला, “कम से कम लेबर यूनियन में तो एक असर रहेगा कि साहब कम्युनिस्ट अलग हैं, कांग्रेस अलग हैं। अगर कांग्रेस को अपना उम्मीदवार जिताना था तब यूनियन के आदमी को टिकट न देती।”

“पर यह तो विल्लीवाली मसल हुई।” मैंने कहा, “खाए नहीं तो लुढ़का ही दे।”

“यही समझ लीजिए !” उन्होंने उत्तर दिया और चलते हो गए।

तो यह थे तानाशाही के कन्धे, जिनपर केवल मीठे वायदों, ऊपरी वक्तव्यों और दोस्ती के झुझारों का भवखन लगा हुआ था जिसपर सवार होकर हर कदम के साथ कांग्रेस फिसलती रही थी। पर इस चुनाव में कन्धे रोल तो अदा कर रहे थे, किन्तु अर्थों के लिए।

चुनाव-वातावरण में जैसे-जैसे तेज़ी आती गई और कांग्रेस ने महसूस किया कि १९७१ की “इन्दिरा गांधी (आंधी) अब काम नहीं कर पा रही है, तब छोटे से बड़े नेताओं तक ने हल्की और सस्ती भाषा में ओछे आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसका मतलब यह विलकुल नहीं है कि ओछी बातों का उपयोग जनता पार्टी या और दलों की ओर से नहीं हुआ, किन्तु यहां मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हल्के स्तर पर अगर हल्की बात होती है तो वह इसलिए धम्य है क्योंकि उस तरह की बात करनेवाला एक महत्त्वहीन या नामहीन आदमी होता है। किन्तु जब इस तरह की बात अखिल भारतीय नेता स्तर पर होती है तो निस्सन्देह ही एक बुरी बात है। उत्तेजित और बोखलाए हुए बंसीलाल ने तो यहां तक कह डाला कि जगजीवनराम दो कोड़ी का आदमी है। उत्तर में जगजीवनरामजी ने भिवानी (हरियाणा) पहुंचकर एक जनसभा में कहा— श्री बंसीलाल कहते हैं कि जगजीवनराम दो कोड़ी के आदमी हैं, तो मैं उनके चुनाव-क्षेत्र में यह देखने जा रहा हूं कि बंसीलाल कितने करोड़ के आदमी हैं। कुछ-कुछ इसी तरह की बातें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी आदि के बारे में कांग्रेस के बड़े नेता जनता के बीच करते रहे, परिणाम हुआ लोगों पर यह असर कि अब कांग्रेस जैसी पुरानी

और आदर्शवादी मस्या अपना विगत भूलकर छिटोरपन पर उतर आई है। जब कि विरोधी नेता पूर्णतः मंथत थे। मुझे दिल्ली में हुई 'बोट बनव' की एक आमसभा में दिया गया थी अटलबिहारी वाजपेयी का भाषण याद है, जिनमें उन्होंने अपनी सभा से कुछ देर पहले ही समाप्त हुई श्रीमती गांधी की आमसभा के बारे में यह सुनकर कि लोगो ने हल्नइवाजी की थी, जनता को फटकारा। उन्होंने कहा कि यदि आप कांग्रेस को सभा को सुनना नहीं चाहते, तब उन सभाओं में आपको नहीं जाना चाहिए। अगर यदि आप जाते हैं, तब आपको उस सभा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। आगे ऐसी कोई बात हुई तो मैं अनशन करूंगा। श्री वाजपेयी ने अपरोक्ष रूप से यह भी चेतावनी दी कि विरोधी के लिए जनता का ऐसा उत्तेजनापूर्ण समर्थन एक स्थिति पर आकर उन्हींको (विरोधियों को) बदनाम करने लगता है, जिनका समर्थन करनेवाला है। श्री वाजपेयी ने जिस तरह लोगो को सताइ निगाकर गहो नागरिक बन्धुपालन के लिए कहा, उस सबको भुनते हुए भी श्रोता शांत बैठे रहे। उन्हें भूल का अहमाम भी हुआ होगा, किन्तु वाजपेयीजी की बात और निष्ठ सवाह के प्रति सम्पूर्ण आस्था और विश्वास रखने हुए मैं यह कहना चाहता हूँ ऐसी स्थितियाँ लोकतन्त्र में पैदा करने का दोषी कौन है? यदि लोग हल्नइवाजी करते हैं, वैचारिक विरोध को व्यक्तिगत विरोध बनाकर टीका-टिप्पणी प्रारम्भ करते हैं तो इन संस्कारों का दाता कौन होता है? मुझे लगता है कि जब जन-मंच पर छड़े होकर नेता ही हल्की बातें करते हैं, तब उस तरह की हल्की प्रतिक्रिया को कैसे रोका जा सकता है। जनता से पहले हम बटु भाव को नेताओं द्वारा पहचाना और समझा जाना जरूरी है।

प्रचार की इस स्थिति का एक पहलू और था—विम्वेश्वर लोगो द्वारा गैरविम्वेश्वराना बातें करना। भ्रष्टाचार का एक देखकर बोधनाहट में हम तरह की बातें कांग्रेसपक्ष में ज्यादा हो रही थी और घानाकरण को उनके अपने ही विरुद्ध बनाती जा रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकान्त बरत्रा ने चीन में घोषणा कर डाली कि कांग्रेस मसदीय दल की नेता श्रीमती गांधी हैं होगी। इस घोषणा ने न सिर्फ श्रीमती गांधी ने व्यक्तित्व को घोट पहुँचाई, बल्कि एक तरह से गवाही ही दे डाली कि कांग्रेस संस्था भीतर में उमो तरह की ताना-शाही मौल रही है, जैसी कुछ दिनों पहले देगलस बुका है। मामान्यतः मैंने उस समय लोगो को इस वक्तव्य पर महाहिया टिप्पणी करते सुना-देखा। कुछ लोग कहते थे कि किसी लोकतांत्रिक दल का अध्यक्ष बिना चुनाव हुए, ऐ-

घोषणा कैसे कर सकता है, और कुछ लोग कहते थे कि बरूआजी एक अस्तित्व-हीन अध्यक्ष है, जो श्रीमती गांधी की कठपुतली बने हुए हैं। उनका तर्क था कि यदि ऐसा न होता तो श्री बरूआ यह क्यों कहते—मैं जब भी कोई निर्णय लेता हूँ तो श्रीमती गांधी की सलाह पर ही लेता हूँ ! यह वहस की बात है कि श्री देवकांत बरूआ किन शब्दों में और किस तरह बात करना या कहना चाहते थे और वह किस तरह लोगों तक पहुंची, पर इतना सच है कि बड़े-बड़े नेता आयेन में यह बोलते रहे, जिसे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। और जैसा कि होता है, ज्यादा बोलना, ज्यादा खतरनाक है, कांग्रेसियों के साथ हुआ। तिस पर कई-कई नेता जनता से हाथ जोड़कर माफीनामा भी पेश करने लगे कि हमरजैसी में जो गलतियाँ और ज्यादतियाँ हुई हैं, उनके लिए उन्हें क्षमा कर दिया जाए !

उस तरह के माफीनामों और हाथजुड़ाई ने मतदाता के सामने उनको निष्चित तौर पर अपराधी साबित कर दिया। विरोधी मंच से कांग्रेस को लेकर जब-जब जितना कुछ कहा गया था, वह प्रमाणित हो गया। सरकारी स्तर पर यह घोषणा भी हुई कि आपातकाल में जो-जो ज्यादतियाँ हुई हैं, उनकी जांच की जाएगी तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा !

लोगों के मोचने का रूप बदला। एक नया तर्क उनके दिमाग में आया कि उन्हें राजनीतिक रिश्तत दी जा रही है और उनसे किसी तरह वोट हथियाने का प्रयत्न हो रहा है। कुछ लोग तर्क करते मुने जाते थे कि कांग्रेस सरकार ने उनमें पहले उस तरह का चतव्य क्यों नहीं दिया ?

उस तरह के आश्वासन जनसभाओं में स्वयं श्रीमती गांधी ने ही नहीं, कई कांग्रेस नेताओं ने दिए और यह प्रमाणित हो गया कि ज्यादतियाँ हुई हैं। जनता के जिस बड़े वर्ग से 'मैसर्स' की ताकत के कारण ज्यादतियाँ छिपी हुई थी, उसने उन्हीं लोगों के मुह यह स्वीकार सुना कि ज्यादतियाँ हुई हैं। तब भयमंश्वर की आमसभा में श्रीमती गांधी का यह कहना कि विपक्ष झूठ बोलता है—एकदम धेतुका हो गया।

श्री संजय गांधी ने वेहद हल्के और बचकाना शब्दों का प्रयोग करते हुए मुन्तानपुर की एक आमसभा में कहा डाला कि जनता पार्टी एक ऐसा रथ है, जिसे चार घोड़े नहीं, बल्कि चार गधे खींच रहे हैं और बहुत-सी छोटी-मोटी पार्टियाँ उनसे कीड़ों की तरह निपटी हुई हैं। इस टिप्पणी का परिणाम हुआ संभार और शिष्ट लोगों के दिमाग में एक आशंका का आ जाना कि कांग्रेस ने जिन रूप में संजय गांधी को उठाया है और एक तरह से बादशाहत के उत्तरा-

धिकारी या 'महज्जादा' बना रखा है क्या इसी तरह की शब्दावली में यह देश का नेतृत्व करेंगे ! आश्चर्य और दुःख की बात है कि कांग्रेस संस्था में बैठे तीस साला राजनीतिक कैरियरवाले लोग खुपचाप यह सब सुनते रहे, किन्तु किसीने हिम्मत न की कि मंजयजी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने में रोकें । स्थिति यहां तक पहुंची कि वे लोग, जो कभी मंजय गांधी को उठाए-उठाए धूम रहे थे और 'बाहू मरकार' 'जो गरीबपरवर' कहने थे, इस कोरिंग में लग गए कि मंजयजी की चुनाव-यात्रा में वही उनका चुनाव स्टेशन न आ जाए । यही कारण था कि चुनाव के बाद एक बड़े कांग्रेसी नेता ने कहा कि मंजय गांधी के दोरों ने भी हर उस इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार का प्रभाव गिराव दिया, जहां-जहां वह जाते रहे । यमोत्तल की भी यही स्थिति थी । उच्च, पद, कार्य सभीको भूलकर वह आमगभाओं में ऐसी उत्तेजित और अमन्युलित भागा का उपयोग कर रहे थे कि मतशक्ता भटक जाता था । हरियाणा के एक बड़े नेता ने फरमाया—“एक केन्द्रीय नेता हरियाणा में जब-जब पहुंचे, तब-तब कांग्रेसी उम्मीदवार के दस हजार मोट कम हों गए ।”

१३ अप्रैल के 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने लिखा—“हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बनारसीदास गुप्त ने कहा कि केन्द्रीय नेता की मांग थी कि उनकी हर गभा में कम से कम एक लाख श्रोता होने चाहिए । इन श्रोताओं को एकत्र करने की कोरिंग में हमें कई लोगों को नाराज करना पड़ा । जिनमें पुनिमवाने, गरकारी अफ-मर और ठेकेदार थे । उनकी गाड़िया कांग्रेस दल के लिए उपयोग करनी पड़ी ।”

राजा-महाराजाओं को लेकर कांग्रेस पिछले दस सालों में शोर मचानी रही थी कि उनके प्रबोधन में गलत है और समाजवाद में सामन्तवाद की कोई गुंजाइश नहीं है । सामन्त जननेता नहीं होता, किन्तु देखा गया कि इन चुनाव में बहुत-से कांग्रेस टिकिट उन राजा-महाराजाओं को ही गए थे या फिर उन्हें स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है । श्रीवानेश मार्नण्ड सिंह, ग्वानियर के महाराजा माधवराव मिन्धिया, महाराजा देव, कई नाम लोगों के सामने थे । एक महाराजा के चुनाव-शेख में तो मैंने देखा कि कांग्रेस और इन्दिराजी के अधिनायकवाद की विरोधी सहर पाकर महाराजा ने कांग्रेस समर्थित होते हुए भी जनता के सामने गिडगिहाना शुरू कर दिया कि नहीं-नहीं कांग्रेस से उनका कोई सेना-देना नहीं है । सब तो यह है कि कांग्रेस उनके न चाहने पर भी जबरदस्ती उनका समर्थन कर रही है ! इस तरह की स्थितियों के कारण भी कांग्रेस की भद्द हुई ।

श्री मुरारजी देसाई ने 'क्लिड्ज' के सम्पादक आर० के० करंजिया को एक भेंट देते हुए कहा था—“अगर हमारी खिचड़ी है तो उनका खिचड़ा है !” यह श्री देसाई ने उस समय कहा था जब करंजिया ने उन्हें बतलाया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जनता पार्टी को लेकर कहा है—“...नई सरकार खिचड़ी सरकार होगी !” उपर्युक्त दोनों ही बातें सामान्य व्यक्ति के लिए सहज भाव में मुन या पढ़कर टाल देने वाली हैं कि ऐसी टीकाटिप्पणी तो परस्पर चलती ही रहती है, किन्तु गंभीरतापूर्वक सोचा जाए तो मुरारजी भाई का सहज भाव से काग्रेस को खिचड़ा कह देना, काफी गंभीर अर्थ रखता है। खीझ, झल्लाहट, उद्योग की बेचैनी और उत्तेजना में कांग्रेस ने इस चुनाव के दौरान जो कुछ तानमेत बनाया वह विचित्र था। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनावी समझौता, राजाओं को टिकिट या समर्थन, फिल्म अभिनेताओं के नाच-गाने, भाषण, मनोरंजन, हिन्दू धर्मगुरुओं का इन्दिराजी के लिए समर्थन-विज्ञापन, जनता में माफीनामे, ऊलजलूल बक्तव्यवाजी, बेहूदा उदाहरण, कांग्रेस की विजय न होने पर विदेशी आक्रमण के खतरे बताना, विरोधी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं को देर तक जेलों में डाले रखना और अपने-आपको देश की राजनीतिक स्थिरता का अकेला वारिस घोषित किए जाना...ऐसी बातें थीं, जिनके कारण किमी वार स्पष्ट नहीं हो सका कि कांग्रेस का रूप क्या है या किन लक्ष्यों को लेकर वह देश को सुशासन देगी ? लोकतंत्र जीवित रख पाने का तो प्रश्न ही नहीं बचा था, क्योंकि गत १६ महीनों में कांग्रेस कितनी लोकतंत्रवादी रह गई है, इसका प्रमाण जनता को खूब मिल चुका था।

ऐसी बीच एक नई बात और हुई। श्रीमती गांधी ने एक चुनाव-सभा में भाषण करते हुए अपनी और अपने परिवार की देश-सेवाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा—“इस परिवार के सभी लोग जनता के सेवक हैं। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो, जिसने देश को इतना दिया हो—केवल जनसेवा के ही रूप में नहीं, भौतिक दृष्टि से भी। तमाम लोग मंत्री बने हैं, लेकिन शायद मैं ही ऐसी हूं, जिम्मे राष्ट्र को अपना मकान तक समर्पित किया है। अब मेरा कोई निजी मकान नहीं है। मेरे दोनों पुत्र ठोस काम में दिल-चस्पी लेते हैं। मेरे पति भी उसी तरह के थे।”

लोग हैरान हो गए। क्या अब राजनीतिक मुद्दों और संस्था के कार्यक्रम को परे कर केवल इस आधार पर श्रीमती गांधी वोट मांग रही हैं कि उनके परिवार ने और उन्होंने देश के लिए उतना किया है, जितना किसीने

नहीं किया। एक बात तो यही यही नहीं थी कि नेहरू परिवार ने जितना किया, उतना किसीने नहीं किया। इस तरह श्रीमती गांधी ने "सायब ही ऐसा कोई परिवार हो, जिसने देश को इतना दिया हो" बट्हर एवसाय हजारों प्रातिकारियों और देशभक्तों के किए-धरे पर पानी फेर दिया और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के यश को भी हल्का कर दिया। मुतसे दूग तोगों ने श्रीमती गांधी जैसी उच्चपदस्थ नेता के मुह में इतनी हल्की बात को पगन्द नहीं किया। निस्सन्देह भारतीय मतदाता को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि नेहरू परिवार ने देश के लिए क्या कुछ किया है।

बेचनी में इन्दिराजी यहा तक कह गई कि वे चाहती तो चुनाव को और टाल सकती थी, किन्तु उन्होंने आमचुनाव कराकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है। बार-बार दिया गया यह भी एक अनारक्षक यथन था। क्या एक लोकतन्त्रवादी को यह प्रमाणित करने के लिए कि वह मोनतन्त्रवादी है, प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है? कुन मिलाकर श्रीमती गांधी और उनकी काधेग का मारा चुनाव-प्रचार या ती विरोधियों पर ऊयड-छायड किस्म के आरोप रहे या अपनी सफाई देने रहना-भर रह गया। चुनाव-घोषणा को लेकर श्रीमती गांधी ने अपने लोकतन्त्रवाद को जो दुहाई दी, उसे जनता पार्टी के नेता श्री चन्द्रशेखर ने एक उमर में साफ कर दिया। श्री चन्द्रशेखर ने कहा—“चुनाव कराना जनता पर किसी तरह का एहमान करना नहीं है, बल्कि वोट देना तो भारतीय मतदाना का अधिकार है, जिसे उसने महारमा गांधी के नेतृत्व में एक लम्बी सड़ाई के बाद प्राप्त किया है। भारतीय जनता अपना यह अधिकार कभी नहीं छोड़ सकती।”

काधेग में वोट-प्राप्ति के लिए क्या कुछ हयकण्डे नहीं अपनाए, किम तरह मत्ता का दुरूपयोग नहीं किया, इसका एक और उदाहरण देना हू। इस उदाहरण का यह मतलब निश्चित ही नहीं है कि मैं जनता को रियायतें देने का विरोध कर रहा हूं, बल्कि मेरा कुन अभिप्राय यह है कि किसी छाम ममय पर, छाम तरह घोषित की गई रियायतें, रियायतें न होकर उपहार के रूप में उपयोग की जाने लगती हैं। हालाकि इस चुनाव ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अब किसी भी किस्म की 'रिश्वत' मतदाता की ममदा को बरगमाने की स्थिति में नहीं रही है।

मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और बिहार की सरकारों ने चुनाव/ दोरान जनता के लिए कुछ रियायतें या विशेष सुविधाएँ घोषित कीं।

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश लोकसेवा आयोग के गैर सरकारी सदस्यों की पेंशन रकम २५० रुपये से बढ़ाकर ५०० रुपये कर दी, जब कि यह पेंशन सन् १९७५ के जुलाई मास से लागू की गई। आदिवासियों को उनके अपने घरों में महुआ आदि मादक वस्तुएं जमा करने की सुविधा दे दी गई।

हैड क्लर्कों का वेतनक्रम १९५-३३० से बढ़ाकर २२० से ३७५ कर दिया गया और यह क्रम लागू हुआ जनवरी १९७७ से।

अतिरिक्त जिला और सेशन जजों का नया वेतनक्रम निर्धारित हुआ, जिसके अनुसार यह क्रम जनवरी १९७२ से लागू हुआ। वेतन-क्रम है—६५० से १४५० रुपये। इस निर्णय के अन्तर्गत इस वेतन-क्रम का लाभ उन सिविल जजों पर भी लागू होता है जो पदोन्नति पाकर अतिरिक्त और जिला सेशन जज बन चुके हैं।

स्वाधीनता-संग्राम के सेनानियों के १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा की सुविधा दी गई। पहले यह सुविधा केवल उन्हीं सेनानियों की पत्नी, माता-पिता या आश्रितों को प्राप्त थी, जिनकी मासिक आय ३५० रुपये से कम थी। नये निर्णयानुसार आय-सीमा का बन्धन तोड़ दिया गया था।

पोहा या मुरमुरा बनाने के धान से 'क्रय-कर' समाप्त कर दिया गया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा के तहत कोटा के ३०००० मकान मालिकों को ३० लाख रुपये के टैक्स की माफी दी।

उत्तरप्रदेश में असिचित कृषि भूमि पर प्रति हैक्टेयर लगान का दर १२ रुपये ५० पैसे से २५ रुपये तक था, जिसे नये आदेश में घटाकर आधा कर दिया गया। इसी तरह की विशेष सुविधा सिंचित भूमि पर भी दी गई। ऐसी भूमि के मालिकों को मौजूदा लगान की जगह अब आधी दर पर लगान देना था। राज्य सरकार को लगान से प्रति वर्ष ४२ करोड़ रुपये मिलते थे। उक्त घोषणा उत्तरप्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने १६ फरवरी, १९७७ को लखनऊ में की थी।

बिहार सरकार ने अपने एक निर्णय में कहा कि राज्य-कर्मचारियों को १ मार्च से प्रतिमाह ८ रुपये ४० पैसे चिकित्सा भत्ता मिला करेगा।

८० हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खोल दिया गया।

माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को सन् १९७४ में हुई हड़ताल के दौरान

का वेतन दिया जाना तय हुआ। इस निर्णय के अनुसार गिशा मदन को आदेश हुए कि उक्त राशि का भुगतान १ मार्च तक कर दिया जाना है।

विजली पर मे ३ पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त कर-भार उठा दिया गया।

विज्ञानों से कर्ज की वसूली का समय ३१ मार्च में बढ़ाकर ३० जून कर दिया गया। इस अवधि का व्याज न लेना भी घोषित हुआ।

१ मार्च, १९७७ में राज्य सरकार पर ५० लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय-भार लेते हुए निर्णय हुआ कि यू० डी० सी०, एन० डी० सी० तथा विभिन्न श्रेणियों के टाइपिस्टों, स्टैनो टाइपिस्टों आदि को एक ही श्रेणी में करते हुए एक वेतन-क्रम रखा जाए।

१ जनवरी, १९७७ से बिहार में ५०० रुपये वेतन पाने वाले को १२ रुपये प्रतिमाह और १२५० रुपये वेतन पाने वाले को ३६ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान किया गया।

उपर्युक्त सभी निर्णय बिहार सरकार ने फरवरी के अन्तिम सप्ताह में लिए।

दिल्ली नगर निगम ने फरवरी के पहले सप्ताह में कुछ निर्णय लिए, जिनके अनुसार कुछ शतों के सहित जून १९७५ से पहली बनी अधिभुक्त व्यक्तियों को अधिभुक्त कर दिया गया।

तागा, रेडा, छरछरा पर ३६ रुपये की जगह केवल १६ रुपये कर निश्चित हुआ। सालाना १०० रुपये सविस चार्ज में भी उन्हे भुक्त घोषित किया गया।

कुछ राहते बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, और ठेनेवानों के लिए भी दी गई।

गर्भ यह कि फरवरी और मार्च के भीतर-भीतर जनता को मुविधाओं या रिमापतों के टुकड़े फेंककर 'पटाने' की कोसिश की गई, पर ऐसा करने समर्थ कांग्रेस भूल गई कि उसने तानाशाही में जनता को पर्याप्त शिक्षित कर दिया है और वह प्रलोभनों पर अधिकार-शक्ति का दान करनेवाली नहीं है।

हृदयन्दीहीन नसबन्दी

'नवभारत टाइम्स' के ७ जनवरी, १९७७ के अंक में मैंने एक समाचार पढ़ा था। मालूम नहीं, इसे इतल काल में प्रकाशित करके मपारत की जनत

और दबाव पड़ा तो किसी भी तरह निर्धारित समय में निर्धारित कोटा पूरा कर लेने की जल्दी हुई। इस जल्दी में यह कार्यक्रम लोगों को मानसिक तौर पर शिक्षित करके उससे लाभ उठाने का कार्यक्रम न रहकर आतंक, भय, और जोर-जबरदस्ती से सम्पन्न कर लेने का कार्यक्रम बन गया। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं और बिना उसके दुष्परिणाम सोचे हुए अधिकारी निरंतर लक्ष्य पूरा करते गए।

कुछ घटनाएं बयान करता हूं। एक शिक्षिका से मेरी भेंट हुई। विधवा युवती थी वह। इस युवती को आदेश दिया गया था कि कैसे भी २ केस लाकर दे। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे ला सकेगी? साधारण पढ़ी-लिखी और गांव में काम करनेवाली पुराने खयालों की युवती और जिस वातावरण से उसे दो 'केस' लाकर देने थे, वह भी एकदम पुरातनपंथी। बोली, "मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, किसीसे क्या कहूं? कैसे समझाऊं? मैं उस तरह की बात कह नहीं सकूंगी। कहूंगी तो न सिर्फ मेरा मजाक उड़ेगा, बल्कि हो सकता है गांव में मेरा विरोध ही शुरू हो जाए। मेरी तो यह हालत है कि दूधर जाऊं तो कुओं, उधर जाऊं तो खाई।"

"तुम अपने अधिकारियों को क्यों नहीं बतलातीं अपनी लाचारी?"

"उन्हें भी क्या बतलाऊं? वह बेचारे तो 'ऊपर के हुक्म' से लाचार हैं।" निराश स्वर में युवती ने उत्तर दिया था, "लगता है यह न करवा सकी तो मनपेच हो जाऊंगी। हमारे यहां कई टीचरों का बुरा हाल हुआ है। किसी-की तनख्वाह रुकी पड़ी है, किसीका इन्क्रीमेंट।"

मालूम नहीं उसका क्या हुआ होगा।

एक और महाशय मिले। घुस थे, "साहब, मैं तो कन्फर्म हो गया! मेरे साधवाने सब धरे हुए हैं।"

"वह कैसे? तुम तो अभी एक महीना हुए नौकरी में लगे थे?" मुझे आश्चर्य हुआ था। घास तौर से इसलिए कि मुझे मालूम था, उससे पहले के आदमी अस्थायी हैं।

"मैंने पूरे चार केस दिए साहब!"

"वह कैसे?"

"देखाए साहब।" उसने बतलाया, "हमारे बड़े साहब बोले थे कि अगर तुम चार केस ला दोगे तो कन्फर्मेशन कर देंगे। मैंने चार केस दे दिए।"

"मगर लोग तो परेशान हैं, तुम्हें चार केस मिल कैसे गए?"

“अरे, अपने घर में ही चार बेस हो गए माह्व !” उमने बतलाया, “एक तो मेरे बाबा, दूसरे पिताजी, तीसरे चाचाजी और चौथे मेरे एक मौजाजी।”

मैं आश्चर्य में गिरा। मुझे मालूम था कि उस व्यक्ति के बाबा कम से कम सत्तर साल के होंगे। पिता भी पचास से ऊपर रहे होंगे। एक उसके चाचा हो थे, जो इस हान्त में होंगे, जिनको नसबन्दी का कोई मतलब हो।

मैंने पूछा, “तुम्हारे मौजाजी की क्या उमर होगी ?”

“यही कोई साठ-बामठ होगी माह्व।” उमने धुम होने हुए बतलाया, “रंडुए है। उसके लिए क्या था। नसबन्दी करो तो भत्ता, न करो तो भत्ता ! मैंने जाकर पाव पकड़ लिए कि मौसा, बचा लो और बग, उन्होंने बचा लिया !”

एक अन्य महाशय से भेंट हुई। इनका मुख अलग चिह्न का था। बोंने, “साहब, हमें तो सरकारी हुकम हुआ कि तुम्हारे घर बच्चे हैं, नसबन्दी करा लो। हमने ऐसा खेल खेला कि साप भी भर जाए, साठी भी न टूटे।

“सो कैसे ?”

इन महाशय ने फुसफुसाकर बतलाया, “हमने तो माह्व सौ रुपये घर पर किए और आठ दिन की छुट्टी मनाई, फिर हाब्टर में मर्टीफिकेट ले लिया कि अपना काम तमाम करवा लिया है। ये मर्टीफिकेट सरकार में पेश कर दिया और बस !” हसे। कहा, “बोलिए, कैसी रही ?”

और जनाब ‘क’ बड़े दुखी मिले। इनका दुख यह था कि इनके छोटे भाई की, जिसकी शादी दो साल हुए हुई थी और कोई बच्चा न था, पुनिम बानों ने खबरदस्ती पकड़कर नसबन्दी करवा दी थी। बोने, “भ्रमरजी, हम तो दो ही भाई हैं। मेरे कोई बच्चा नहीं है, एक छोटे पर ही उम्मीद थी कि बृलदीपक उसके जरिये आएगा, समझे कि हमारा ही बच्चा है, पर बाहरी सरकार !... तू ने न जीने का छोड़ा, न भरने का !”

सुनकर मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। कहा, “आपको गिरावत करनी चाहिए।”

“किससे ?” वह रडासे हो गए। “किसने निकायन करेगा माह्व ? कौन मुनेगा ? अंधेर नगरी में कौन मुनेगा ? ज्यादा जोर किया तो भीमा में भीतर घुसे जाएंगे !”

ग्यानिमर के पास है एक गांव पनिहार। अच्छी-गामी आवासी है। वहां जाना हुआ तो गांव वालों में मेरी कार के पहुंचते ही भगदड़ मच गई। ओरों

को समर्थन देंगे।”

गृहपति ने हंसकर उत्तर दिया, “ज़रूर। पर एक शर्त है साहब !”

“फरमाइए ?”

“आप सब अपनी नसबन्दी का सर्टीफिकेट दिखाइए, फिर हम कांग्रेस को वोट देंगे।”

अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह हाल कि उत्तर नहीं। चुपचाप उठकर चले आए। कुछेक ऐसी घटनाएं भी हुईं जब बेचारे कार्यकर्ताओं को सरकार की ज्यादतियों के प्रतिक्रियास्वरूप न सिर्फ अपमान, बल्कि थप्पड़ खाने पड़े। कारण था किसी ऐसे गांव में जा पहुंचना जहां परिवार-नियोजन के नाम पर ज्यादतियां हुई थीं। ऐसी जगह कांग्रेस के नाम-भर से ग्रामीणों ने उत्तेजित होकर प्रचार-कार्यकर्ताओं को घेर लिया और गाली-गुत्ते, लानत-मलामत करके वापस भेज दिया। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सों में तो यहां तक सुना गया कि तानाशाही सरकारी संस्था के कार्यकर्ताओं ने गांवों में जाना बन्द कर दिया और अपने उम्मीदवार को बतलाते रहे कि ‘उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है !’

इस तरह के कई लोगों ने मुझे बतलाया था कि क्या करें साहब ! इस सरकार ने हमें किसी जगह मुंह दिखाने का बिल नहीं छोड़ा। किस मुंह से वोट मांगा जा सकता है ? किस तर्क से बात की जा सकती है ? जो-जो अमानवीय कार्य हुए और निरंतर होते ही रहे, उनके बाद लोगों को क्या विश्वास दिलाया जा सकता है ?

तो इस तरह विश्वासहीन स्थिति बनाने के बाद भी कांग्रेस पक्ष का यह झूठा प्रचार चल रहा था कि देश और जनता ने आपातकाल में महान् उपलब्धियां की हैं। माफीनामे भी हो रहे थे। प्रलोभन भी दिए जा रहे थे। अनाप-शनाप पैसा भी व्यय किया जा रहा था।

येन केन प्रकारेण वोट-प्राप्ति के इस कांग्रेस महाभियान को सीधा-सरल मतदाता चकित भाव से ठिठका हुआ देख रहा था और उसकी निश्चित राय बनती जा रही थी कि अब वह झूठ की लपेट में नहीं आएगा !

उधर कांग्रेसी सेमे में आंकड़ों के हिसाब-किताब चल रहे थे और यह हिसाब-किताब निश्चित रूप से जतलाने लगा था कि कांग्रेस पराजय के द्वार पर आ खड़ी हुई है। आमचुनावों में अब तक कांग्रेस की विजय का कारण रहा था प्रतिपक्ष का विभिन्न झंडों, विभिन्न नामों में अलग-अलग दल

बना रहना और यही कारण था कि कांग्रेस हर चुनाव में प्रतिपक्षी दलों में बटे हुए वोटों के कारण सुविधा के साथ जीतती रही थी। हालाँकि उसे किसी भी चुनाव में ४० प्रतिशत में अधिक मत नहीं मिले थे। १९७१ के इन्दिरा गांधी (आधी) चुनाव में भी वह कुल ४२ प्रतिशत मत प्राप्त कर सकी थी। इस बार चूँकि शक्तिशाली विरोधी दल एक भ्रष्टा, एक नीति, एक घोषण-पत्र और एक विद्वत् पर जनता पार्टी के रूप में उदय हो गए थे, अतः स्पष्ट लगता था कि 'फूट से राज्य बनाए रखने का युग' बीत गया है।

चुनाव-आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी० स्वामिनाथन की मतकंटा और जननवीर्य आस्था ने बड़ी योग्यता और न्याय के साथ चुनाव-व्यवस्था की थी और प्रतिपक्ष उनमें पूरी तरह सन्तुष्ट था। यही नहीं, प्रतिपक्ष के अनेक नेताओं ने उनमें पूरी तरह से आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए जननश्रवाद में श्रद्धा दर्शाई थी। प्रतिपक्ष के ज्ञात, धर्मपूर्ण और लोकतंत्रीय विश्वास ने जनमत में उसके प्रति ज्यादा विश्वास पैदा किया था। उनके व्यवहार का मन्तुलन भी एक बड़ी सीमा में जन-विश्वास को जीतने में सफल हो रहा था। ठीक इसके विपरीत कांग्रेस नेताओं का आचरण मतदाता के रहें-सहें विश्वास का हिंगाता जा रहा था। यह विश्वास उस समय एकदम टूट गया, जब कुछेर नेताओं ने अपने मतस-सतत काम करने शुरू कर दिए और वे सब जन-नाचारण के सामने उजागर होने लगे।

जैसे-जैसे चुनाव-मसम करीब आता जा रहा था, कांग्रेस उम्मीदवार बीधताहट में 'साम दाम दंड भेद' हर तरह में अपने उभरे हुए प्रतिद्वंद्वी को मिटाने की कोशिश में जुट गए थे।

रायपुर में जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री पुरुषोत्तमलाल शीशिक की लोकप्रियता और बढ़ते प्रभाव को देखकर मध्य प्रदेश ही नहीं, केन्द्र तक काफी चिन्ता देखी जा रही थी। कारण था महाकोशल के छत्रपति बाघेमी का छत्र धिमकते जाना। विद्याचरण शुक्ल की लगने लगा था कि उनकी अपनी 'स्टेट' ही उनके हाथ से निकली जा रही है। परिणाम हुआ बद्रहवासी में हमेशा की तरह अपनी मता-शक्ति का दुष्प्रयोग।

मार्च की १८-१९ तारीख को रात के समय दो दिनीनी घटनाएँ घटी। कुछ लोगो ने श्री शीशिक को घेर कर मोहों की छड़ों में उनपर हमला कर दिया। उसी रात कम्युनिस्ट विधायक मुशीर मुग़र्ज़ों पर थारू में दहशत हुआ। जैसे-तैसे दोनों की जाने बच सकी। हालाँकि शीशिक और मुग़र्ज़ों की गहरी

चोटें आड़ें। इस घिनौने कृत्य पर रायपुर ही नहीं, आसपास के सारे इलाके में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दैनिक 'युगधर्म' और दैनिक 'नवभारत' ने इस हमले का विस्तृत समाचार प्रकाशित किया और जनता तक पूरा विवरण पहुंचाने की कोशिश की।

कहते हैं कि श्री शुक्ल ने तुरंत उच्चस्तरीय आदेश किए कि ये दोनों ही समाचारपत्र जनता तक नहीं पहुंचने चाहिए। परिणामतः अतिरिक्त जिलाधीश ने तुरंत अखबारों के व्यवस्था-विभाग को हुक्म किया कि अखबार बाहर नहीं जाएंगे। चूंकि इस हुक्म में कुछ देर हो गई थी अतः अखबारों के बंडल जहां-तहां रवाना हो चुके थे। दैनिक 'युगधर्म' की हजारों प्रतियां जप्त कर ली गईं और कुछेक बंडल जो यहां-वहां भेजे जा चुके थे, स्टेशनों पर उतरवा लिए गए। 'नवभारत' के भी कई बंडल रेलगाड़ियों से उतरवाए गए। और समाचारपत्रों को एक नया आदेश मिला कि खबर छपी जाए, किन्तु इतने मामूली ढंग से कि जनता को मालूम न हो सके कि मामला किस कदर गंभीर है। इस निरंकुशता का यह व्यवहार नया नहीं था, उस आपातकाल का स्वभाव ही था, जिसके अन्तर्गत बड़े तानाशाह के नीचे उप-तानाशाह पनपते रहे थे।

कोशिक की लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त है कि समाचार को बहुत दबाने, अखबारों को हर तरह से दमन करने के बावजूद जनता तक असलियत पहुंच गई और इस असलियत के साथ ही यह कहानी भी कि किस तरह असलियत को छुपाने के लिए मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई थी।

'न दलील, न वकील, न अपील' यह एक छोटा-सा नारा था, जिसका जनक कौन-सा दल है, मैं नहीं जानता, किन्तु इन तीन शब्दों में तानाशाही का जो चित्र है, वह चित्र चुनाव के दिन तक नहीं हटा था। दलील देने वाली हर आवाज बन्द थी। अपील करनेवाले गले दबा दिए गए थे। 'विल्ट्ज' (२ अप्रैल, १९७७) लिखता है—“मध्यप्रदेश में कम से कम ५०० अखबार बंद कर दिए गए।” मेमरंडम की आड़ में न केवल अधिकारियों ने अखबारों को बंद कर दिया, बल्कि सैकड़ों जिलास्तरीय पत्रकारों और एजेण्टों को जेल के अन्दर पहुंचा दिया। खरगोन जैसे आदिवासी जिले में कम से कम एक दर्जन संवाददाताओं या एजेण्टों को जेल में डाल दिया गया।”

कुल ५४२ स्थानों के लिए चुनाव हो रहे थे, जिनपर कुल प्रत्याशियों की संख्या २,४३१ थी। कुल स्थानों के मतदाता ३१,८३,४२,६०२ थे।

इनमें से मिक्किम और अरणाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रत्यासी निर्वाचित हो गए थे।

सन् १९७१ में कुल स्थान ५२० थे जबकि प्रत्यासियों की संख्या २,६७४ थी। १९७१ और १९७७ के चुनावों में एक अन्तर और स्पष्ट था। पांचवीं लोकसभा के चुनावों में, यानी १९७१ में केवल ३६ सीटों पर सीपा संघर्ष हुआ था, किन्तु इस बार १६३ स्थानों पर कांग्रेस और जनता पार्टी के उम्मीदवारों में सीपा मधपं था। १९७१ के चुनाव में कांग्रेस को ३५२ स्थान मिले थे और उसका जबरदस्त बहुमत सामने आया था। प्रान्तीय कांग्रेस-सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी :

प्रान्त	कुल स्थान	उम्मीदवार	कांग्रेस
असम	१४	४०	१३
आंध्र प्रदेश	४२	१६५	२६
उत्तर प्रदेश	८५	४१३	७३
उड़ीसा	२१	६१	१५
कर्नाटक	२८	६८	२६
केरल	२०	६३	६
गुजरात	२६	११२	११
जम्मू-कश्मीर	६	२६	५
तमिलनाडु	३६	१६५	६
पंजाब	१३	७६	१०
पश्चिम बंगाल	४२	१७१	१५
बिहार	५४	३४०	४०
मध्यप्रदेश	४०	१५७	७१
महाराष्ट्र	४८	२११	४३
राजस्थान	२५	१०२	१४
हरियाणा	१०	५०	७
हिमाचल प्रदेश	४	१४	६
नागालैंड	१	२	—
मणिपुर	२	११	२
अण्डमान निकोबार	१	२	१
गोवा दमन दीव	२	१५	१

चण्डीगढ़	१	१०	१
दादरा नगरहवेली	१	३	१
दिल्ली	७	४१	७
पांडिचेरी	१	४	१

चुनावों में निरंतर खराब स्थिति होते जाने के कारण जन-साधारण में एक सहज प्रतिक्रिया यह होने लगी थी कि कहीं श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव स्थगित करते हुए पुनः तानाशाही हथियार का उपयोग न करने लगे। यह वहम जनता ह्रां नहीं, नेताओं में भी खासा फैला हुआ था। इसके बावजूद वे पूर्णतः धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जन-अदालत में न्याय के लिए खड़े हुए थे।

और जन-अदालत ने जब न्याय देना शुरू किया तो उन सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिन्होंने उसपर दमन, अन्याय और अत्याचार में हिटलरशाही को भी लजा दिया था। हालांकि चुनाव प्रारंभ होने के कुछ समय पूर्व से ही चौंकानेवाली घटनाओं के समाचार जनता पर उछले थे। इनमें एक विशेष समाचार था श्री संजय गांधी की जीप पर गोली चालन। इसी तरह की कई बातें गुनने-पढ़ने में आई थीं। जैसाकि हमेशा होता है, चुनावों में मतदाता की संवेदना और भावनाओं को उभारकर भी वोट हासिल किए जाते हैं, इस चुनाव में भी कोशिश की गयी, किन्तु तानाशाही ने उसे इतना व्यावहारिक और यथार्थवादी बना दिया था कि इस तरह की बातें उसपर तनिक भी असर नहीं डाल सकीं और इसके परिणाम थे चुनाव-नतीजे जिन्होंने एक ही बार में गांधीवाद का चेहरा लगाए हुए हिटलरवाद को चकनाचूर कर डाला था।

श्रीमती गांधी को निश्चय ही उस दिन अहसास हुआ होगा कि नासूर को पट्टियों में छिपाए रखने से काम नहीं चलता। उसका इलाज होता है आपरेशन। कांग्रेस के जिस्म पर भ्रष्टाचार, झूठ, कपट, भाई-भतीजावाद और अत्याचार के जितने नासूर थे, अगर उन्हें समय रहते संस्था के जिम्मेदार लोगों ने काट फेंका होता तो वह दयनीय स्थिति न होती, जिसमें चुनाव के बाद कांग्रेस को जनता ने पहुंचा दिया था। उस दिन, जब जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की घोषणा हुई होगी, निश्चय ही कांग्रेसियों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के वे शब्द याद आए होंगे, जब उन्होंने बार-

थार चेतावनी दी थी कि दमन और मलत बारंबारियों एक न एक दिन आप सभी के लिए बनेशकारक बनेंगी।

कामराज को लेकर कभी कांग्रेस ने यह झूठा प्रचार प्रारंभ कर दिया था कि वह अत समय में कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, ताकि दक्षिण भारत के बोट हथियाए जा सकें, उस समय कामराज ने भी कहा था—“मैं कहता हूँ कि गिरफ्तार नेताओं को छोड़ दिया जाए देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। अगर देश में अधिनायकशाही आती है तो देश टुकड़े-टुकड़े होकर गगरे में पड़ जाएगा !”

बूढ़ और बीमार कामराज ने चेतावनी में केवल इतना ही कहा था कि ‘गिरफ्तार नेताओं को छोड़ दिया जाए क्योंकि देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है’ पर विस्तार पर लेटे हुए यथोक्त नेता को मालूम नहीं था कि देश अधिनायकवाद पर जा पहुँचा था। यदि श्री कामराज बीमार न होते तो बोन जाने उन्हें भी जेल के सीखचे ही देखने पड़ते ?

यो अग्नी तानाशाही के दौर में मानसिक और शारीरिक हत्याओं के डेरो मामले नई जनतंत्री सरकार की स्थापना के बाद सामने आए (और अब तक आते जा रहे हैं) किन्तु कुछेक हालात मुझे अपने उन विरोधी नेता मित्रों में उसी समय मुनने को मिल चुके थे, जब आपातकाल लागू था। दिसम्बर, १९७७ में किसी कार्यक्रम में अपने गृह-नगर स्वानियर पहुँचा तब मुझे मालूम हुआ कि वहाँ के सुप्रसिद्ध नेता और विधायक श्री शीतलासहाय जेल में ‘रिहा’ हो गए हैं। आश्चर्य हुआ था मुझे। पूछा, “शीतलासहाय रिहा कैसे हो गये हैं ?”

बतलाने वाले को हमने ज्यादा गूँथना नहीं थी। बोला : “यही तो दण्डा जानता हूँ साब, कि शीतलासहायजी नगर में दंगे जा रहे हैं।”

मैंने शीतलासहायजी से सम्पर्क साधा। भेट तब हुई। दर तक हम गाल बार्ते करते रहे। शीतलासहायजी ने बतलाया, “बीमार हो गया था। बीमारी सरकार ने सोचा कुछ दिन ज़हरी हवापानी खिला दिया जाए, अतः पाद १२०० के लिए पेंरोल पर छोड़ा है।”

मुझे मतलब हुआ। शीतलाजी के थारे में गूँथना देने वाले न मुझे पुरा परेशानी में डाल दिया था—‘रिहा’ शब्द बहुर। गूँथ जायगा हूँ शीतला-

सहाय को। मैत्री स्तर पर भी, नेता के स्तर पर भी। सत्य के लिए छात्र-जीवन से नग्नपरत रहे शीतलासहाय की डिक्शनरी में बौद्धिक और मानसिक स्तर पर किसी भी किस्म का 'समझौता' शब्द कभी नहीं रहा है। कांग्रेसी सरकार के लिए वह मध्यप्रदेश में हमेशा ही विरोधी के नाते सरदर्द रहे थे, ऐसे आदमी को 'रिहा' कर दिया जाए और वह भी तानाशाही में—भला कैसे संभव है? सन्तुष्ट हुआ कि शीतलासहाय रिहा नहीं हुए हैं, बल्कि रिहाई का घोखा मार रहे हैं। बात-बात में शीतलासहाय ने उस समय भी मुझे बहुत कुछ बतलाया था कि तानाशाही कितने नकाब ओढ़े हुए चल रही है। बोले, "जब भोपाल में मुझे जेल में रखा गया तब चिकित्सा-सुविधा नहीं के बराबर थी। यानी यह हालत हुई कि मैं और कई लोग बीमार हैं, पर सरकारी डॉक्टर अपनी उपस्थिति जतलाने के लिए जेल में आता है और बहुत कहने, निवेदन करने के बावजूद ऊपरवाले हिस्से में बैठकर जेल अधिकारियों से गर्प्य करते रहने के बाद वापस चला जाता है। दवा के नाम पर हमलोग सिर्फ बढ़ती हुई बीमारी भेलते रहते हैं।"

"आपने जेल-अधिकारियों को डपटकर नहीं कहा?"

शीतला हंसे, "कमाल करते हो रामकुमार, मैं तानाशाही का कैदी और डपटकर कहता? बीमारी ने १४ महीने में बुरी तरह तोड़ रखा था, सिर्फ निवेदन ही कर पाने की स्थिति थी। भोजन के नाम पर जैसा भी जो दे दिया जाए, खागे की लाचारी थी। न खाओ तो उनकी बला से। बस, बार-बार, रोज-बरोज प्रार्थना किया करता कि भाई मेरी तबीयत तो देखो, इलाज तो करवाओ, किन्तु वह डॉक्टर आश्वासन देता कि अभी आता हूँ और ऊपर जा बैठता।"

"इस तरह की उपेक्षा कब तक चली?"

"जब तक जेल में रहा, फिर एक दिन जांच हुई और अचानक डॉक्टर ने रिपोर्ट दी या न जाने भीतरी तौर पर क्या हुआ कि मुझे पैरोल पर रिहा कर दिया गया। अब यहां आकर हॉस्पिटल के काम में जुट गया हूँ। समय पूरा होते ही फिर वहीं पहुंच जाऊंगा, जहां से बाया हूँ।"

शीतलाजी के स्वर की भीतरी तड़प महसूस कर पा रहा था मैं। ज्यादा जिक्र नहीं बढ़ाया। सिर्फ सोचता ही रह गया था। ये तानाशाही जन-नेताओं और समाज-सेवियों की हत्या करके कितने दिन सांसें ले पाएंगी? शीतलासहाय २ जुलाई, १९७५ को गिरफ्तार किए गए थे। बवंर तानाशाही ने शीतला-

महाय को जेल में डालकर अपना विरोधी नेता ही गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि उन हजारों-साथों लोगों की मारों भी घोट डाली थी जो उस विशाल कैमर हॉस्पिटल से जुड़ा हुई थी, जिसे अकेले शीतलामहाय का प्रभुत्व प्राप्त रूप देने जा रहा है।

खालियर में बन रहे करोड़ों की लागत के कैमर अस्पताल की बुनियाद शीतलामहाय ने ही डाली है और वह अब तक केवल प्रमनिए धानू नहीं हो सका, क्योंकि शीतलामहाय को विरोधी विचारधारा के कारण तानाशाही ने सीखचों में बन्द कर दिया था। परिणामस्वरूप करोड़ों की लागत में बन रहा अस्पताल लम्बे समय तक अधूरा पड़ा रहा। उनका काम बन्द हो गया। पैरोल पर छूटने के बाद शीतलामहाय ने दिन-रात जूटकर उम्र काम को संपूर्णता देनी प्रारंभ की।

यह एक उदाहरण है तानाशाही और उसका हथियार बनी अप्रगल्भाही के अमानवीय कृत्यों की।

इसी बर्बर तानाशाही के पंर चुनाव में उछड़ चुके थे। कहते हैं कि जिन दिनों इन खूनी पंजों का उखड़ाव शुरू हुआ, देश में एक खबर सुनी जाने लगी थी। यह कि श्रीमती गांधी अपने को डूबता देखकर वही मार्गस-नों का सहारा न ले बैठें ! यह केवल जन-चर्चा नहीं थी। चुनाव के बाद रहस्योद्घाटन भी हुआ कि इस तरह का भीतरी गोलमाल चला था। श्री हेमवती-नदन बहुगुणा ने सम्बई में हुई एक आमसभा में कहा कि जिस दिन वह स्वयं यात्रु जगजीवनराम और नन्दिनी सतपथी आदि ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, उसी दिन जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री लालकृष्ण अडवानी उनके पास पहुंचे। बोले, "चुनाव तो एक तरह में चल रहे हैं और नतीजा स्पष्टतः सामने दीख रहा है, लेकिन आप क्या मोचते हैं कि इन्दिरा गांधी चुपचाप बैठी रहेंगी ? कहीं सत्ता-शक्ति का सहारा लेकर वह मार्गस-नों लागू न कर दें।" इसपर बहुगुणा ने सभा को बतलाया कि उन्होंने उत्तर दिया था, "चिन्ता मत कीजिए अडवानीजी, इन्दिराजी जिस प्रदान में निराली हैं, उसी प्रदान में मैं भी निकला हूँ।"

क्या श्री अडवानी की आज्ञा (या उन्हें गुप्त रूप में मिली सूचना) गलत थी ? ठीक है कि इन्दिराजी कोशिश करके भी बंसा कर नहीं पाई थी कि हो नहीं सका, पर यह इरादा था। इस इरादे का उद्घाटन मेसायूसेट्स की इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलॉजी के भूतपूर्व शिक्षक और राजनीतिक समीक्षक श्री

रॉबर्ट मैनोक ने किया।^१ उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित करवाए अपने एक लेख में कहा कि श्रीमती गांधी और उनकी सरकार ने अपनी अन्तिम सांसें लेते हुए बार-बार संविधान को रद्द करने तथा चुनाव रद्द करते हुए मार्शल-लॉ लागू करने की कोशिशें की थीं। श्री मैनोक ने लेख में लिखा कि श्रीमती गांधी ने यह कोशिशें अपनी ओर से कीं, किन्तु उनकी कोशिश पूरी न होने देने में कुछ ऐसे लोग बाधक बने, जो यह अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि तानाशाही के कारण वे और उनकी संस्था जितना कुछ खो चुके हैं, उससे ज्यादा खोने की भूल उन्हें नहीं करनी चाहिए। इनमें सबसे पहले व्यक्ति थे स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद। श्री मैनोक के अनुसार श्रीमती गांधी ने श्री अहमद से कहा था कि वे आपातकाल में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करके संविधान के कुछ हिस्सों को निष्क्रिय कर दें तथा उनकी यानी श्रीमती गांधी की समस्या हल करें, किन्तु श्री अहमद तैयार नहीं हुए। श्री मैनोक ने लेख में आगे कहा है कि इसपर इन्दिराजी रुष्ट हो गई। उन्होंने आवेश-भरे शब्दों में श्री अहमद से बहस की। दूसरे दिन श्री अहमद को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया।

श्री रॉबर्ट को यह जानकारीयां किन सूत्रों के आधार पर मिली थीं, इसका लेख में कहीं उल्लेख नहीं है किन्तु उन्होंने अनेक रहस्यपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है। उक्त लेख में वह आगे लिखते हैं कि श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति की ओर से निराश होकर इस सम्बन्ध में जनरल टी० एन० रैना से सम्पर्क साधा और कहा कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में इस आधार पर सेना लगा देनी चाहिए क्योंकि उन क्षेत्रों में जन-अशान्ति का भय है। कहते हैं कि श्री रैना ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसपर मंत्रिमंडल ने जनरल रैना को वैसा करने का आदेश प्रसारित कर दिया। श्री रैना ने सेना को इधर-उधर भेज तो दिया, किन्तु उससे श्रीमती गांधी के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

रॉबर्ट मैनोक ने लेख में यह भी लिखा है कि विधि मंत्री श्री गोखले इस दौर में संविधान के द्वारा कोई ऐसा कानूनी मुद्दा ढूंढने में व्यस्त रहे थे कि जिसे आधार बनाकर चुनाव स्थगित कराए जा सकें।

कुन मिलाकर यह कि निराश स्थिति में श्रीमती गांधी और उनकी सरकार निरंतर यह कोशिश करती रहीं कि किसी भी तरह सत्ता पर स्थापित रहे।

इससे भी ज्यादा रोमांचक सत्य यह है और जैसाकि तानाशाही के दौर में हमें गा होता है, इन्दिराजी की तानाशाही के पुरजों भी पूरे पंच की मुद्रिया निगरानी कर रहे थे। इन पुरजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे बंगोलान। चौधरी बमोलाल ने किम मफाई के साथ पूरे शासन-तंत्र पर अपना जामूनी चढ़ चला रखा था, इसका उद्घाटन करते हुए 'नवभारत टाइम्स' की आवाज बुनाम के बाद खुली।^१

“भूतपूर्व रक्षामंत्री श्री बमोलाल के जो कारनामे सामने आ रहे हैं, उनमें एक भयंकर कारनामा यह है कि हरियाणा तथा उन क्षेत्रों में जहाँ उनका प्रभाव था, मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा बड़े व्यापारियों सभी की गति निगरानी के लिए खुफिया जामून नियुक्त थे जो उनके परिवार तक की गतिविधियों पर हर वक्त नज़र रखते थे।

“इसमें भी भयानक बात यह है कि खुफिया जामून श्री बमोलाल के शिरो-धियों के यहाँ चोरी-डकैती से लेकर राम्ने चसते मारपीट तक कराने के लिए आज्ञा दे। हरियाणा के एक भूतपूर्व मंत्री के निजी सहायक ने आज बताया कि सी० आर्द० डी० के आदेश पर उस मंत्री द्वारा निष्पादित हर पत्र की एक अतिरिक्त प्रति टाइप करके सी० आर्द० डी० को देनी पड़ती थी।

“बमोलाल ने कुछ लोग इस कार्य के लिए भी लगा रने थे कि जो भी लोग प्रधानमंत्री से मिलें, उनकी बातचीत का विवरण श्री बमोलाल को तुरंत भिज जाए।

“हरियाणा में निर्वाचित राज्य सभा के दो सदस्य जो बमोलाल के गुट के ही थे, एक बार शिष्टाचार के नाते श्रीमती गांधी से मिलने गए थे। वे जैसे ही साउथ ऐवेन्यू स्थित अपने फ्लैटो में पहुँचे, उन्हें बमोलाल का यह मन्देश रखा हुआ मिला, कि तुरंत चढीगड आकर मुझसे मिलो। वे बेचारे जब श्री बमोलाल से मिले तो घुरी तरह डट पड़ी कि बिना मेरी इजाजत के आप कहा गए कैसे !

“श्री बमोलाल ने जो खुफिया जामून इस काम पर लगाए थे, उनके पास वायरलेस में सज्जित कार तथा जीपें तो थीं ही, उन्हें बिना पार्क घन घस करने की भी छुट थी।

“इनमें से ही एक जीप श्री मंजय गांधी की गाड़ी के साथ मारनि तन

आती-जाती थी। इसी कार्य पर प्रतिवर्ष दो लाख रुपया खर्च होता था।

“हरियाणा के कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों की गतिविधियों पर बराबर नज़र रखी जाती थी और यदि कोई अवांछित पाया गया तो उसे हटा दिया जाता था। जो प्राध्यापक ‘सुपर आका’ के विरुद्ध एक-आध शब्द भी भूलचूक से बोल जाते थे, वे तवादले के नाम पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए मजबूर थे।

“इतना ही नहीं, श्री वंसीलाल को गृह मंत्रालय के खुफिया विभाग पर भरोसा नहीं था, अतः उन्होंने अपना खुफिया विभाग अलग से स्थापित कर लिया था। एक बार जब उनके पुत्र सुरेन्द्रसिंह के बारे में खुफिया विभाग ने विरोधी रिपोर्ट दी तब नाराज़ होकर उन्होंने खुफिया विभाग की भी निगरानी करानी शुरू करा दी।

“रिवासा कांड की सही रिपोर्ट देने के लिए भिवानी के खुफिया पुलिस-इन्स्पेक्टर को दंडित होना पड़ा। सुरेन्द्रसिंह के विरोधी श्री भंवरसिंह की दादी की हत्या के लिए जिम्मेदार उप-अधीक्षक को पदोन्नत करके अधीक्षक बना दिया गया।

“इसी केस के प्रसंग में भिवानी के एक खुफिया अधिकारी को गिरफ्तार कराया गया और उसकी पत्नी को अपमानित किया गया।

“पोस्टमास्टर्स को आदेश थे कि वे पत्रकारों की निजी डाक को खोलकर उसकी जांच करें। सन्देहास्पद पत्रों को पहुँचने ही नहीं दिया जाता था।

“जब कुछ डाक अधिकारी इस आदेश का पालन न करते पाए गए तो उन्हें मुअत्तिल कर दिया गया। तब के संचार मंत्री ने जब उनकी सेवाएं बहाल कर दी तब उन्हें उसकी कीमत मंत्रिपद से चुकानी पड़ी।

“वंसीलाल की गलत गतिविधियों में सहायक न बनने के कारण श्री पोसवाल, श्री हरिद्वारीलाल, श्री खुर्शीद अहमद तथा श्रीमती चन्द्रावती को भारी कीमत चुकानी पड़ी।”

बहरलाल चुनाव शुरू हुआ और चार दिनों बाद ही झूठ के पांच बुरी तरह उखड़ गए। जनता के शान्त विद्रोह ने तानाशाही को उठाकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया। निम्न आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अहिंसात्मक शिष्ट क्रांति ने संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र में किस तरह सत्ता-परिवर्तन किया।

२३ मार्च, १९७७ को चुनाव आंकड़े और देश का भविष्य निर्णीत हुआ—

इस दिन सुबह तक ५४२ सीटों में से ५३६ सीटों के चुनाव परिणाम का चुके थे :

कुल स्थान	:	५४२
चुनाव-परिणाम	:	५३६
जनता पार्टी	:	२७२
सी० एफ० डी०	:	२८
कम्युनिस्ट (माक्सवादी)	:	२२
कांग्रेस	:	१५३
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया	:	७
अन्ना डी० एम० के०	:	१६
डी० एम० के०	:	१
अकाली दल	:	८
अन्य	:	२८
निर्दलीय	:	८

(जिन्हें अन्य के अन्तर्गत गिना गया है उनमें फारवर्ड ब्लॉक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया, मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट : नागालैंड, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मेघालय, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी आदि विभिन्न दल हैं।)

अगले चौबीस घण्टे में सम्पूर्ण चुनाव-भविष्य सामने था, किन्तु इससे पूर्व ही भारत का राजनीतिक भविष्य निश्चित हो चुका था और भारतीय मतदाता ने बहुमत से तानाशाही को अस्वीकार कर दिया था। इस मतदाता ने यदि श्रीमती गांधी को सिर-आखों उठाकर अपना विश्वास गोता था तो इसीने उनके अधिनायकवादी यद्ध्यत को अमफल करते हुए ऐसी पराजय दी थी, जिसने सदियों के इतिहास पर खड़ी एक महान मंमथा को ही सगमग धोख कर दिया था।

स्वयं श्रीमती गांधी रायबरेली में जनता पार्टी के राजनारायण ने ५५ हजार से अधिक मतों से पराजित हुईं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के १४ दिग्गज मंत्रियों ने भयावह पराजय का मुह देखा। सर्वश्री बर्गोन्नान, मंत्रयगांधी, विद्याचरण शुक्ल, एच० के० एन० भगत जैसे लोग घबराहानी हो गए। सगार ने विस्मय से देखा कि जिस देश के मतदाता को उन्होंने सदा ही 'अगम्य और

विश्वास और निष्ठा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, जिससे पीढ़ियाँ सबक लेती रहें।

अमरीकी राष्ट्रपति श्री जिमी कार्टर ने प्रजातंत्र के प्रति विश्वास और आस्था दिखाने पर भारत की प्रशंसा की और कहा कि भारतीय चुनाव शेष विश्व के लिए प्रेरणा-स्रोत हैं।

लोकतंत्र और तानाशाही के इस महान और शान्त युद्ध में लोकतंत्र की विजय पर सारे संसार के प्रमुख पत्रों ने जो टिप्पणियाँ कीं, वे भी इस बात की प्रमाण हैं कि श्रीमती गांधी के विश्वव्यापी शासकीय प्रचार के बावजूद समस्त संसार जानता था कि वे तानाशाह हैं। दी लंदन टाइम्स ने एक लम्बी टिप्पणी प्रकाशित करते हुए लिखा—“नेहरू वंश का शासन-काल समाप्त हो गया। मंजय गांधी के एकदम उभर आने से नेहरू वंश के सत्तारूढ़ रहने का खतरा बढ़ गया था। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय मतदाता संसदीय प्रणाली में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहता है और वह यह भी नहीं सह सकता कि समाचारपत्रों पर सेंसर लगाकर सत्य का गला घोंटा जाए या बिना मुकदमा चलाए किसीको भी जेल में डाल दिया जाए।

आस्ट्रेलिया से प्रकाशित होने वाले सिडनी मॉनिंग हेराल्ड ने लिखा—“इस महान मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जन लम्बे समय से चले आ रहे कांग्रेस प्रशासन से ऊब चुका था और उसे श्रीमती इन्दिरा गांधी की तानाशाही नीतियाँ तथा दमन-चक्र बिलकुल पसन्द नहीं थे।” इसी पत्र ने टिप्पणी में विश्वास व्यक्त किया था कि हो सकता है नई सरकार के स्थायित्व में दिक्कतें आएँ, पर मतदाता को तानाशाही स्वीकार नहीं है। आस्ट्रेलिया के ही अन्य पत्र ने लिखा—“यह भारत के आम आदमी की विजय है और विश्व-भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थायी आश्वासन भी है।”

मेलबोर्न एज ने कहा कि भारतीय चुनावों से यह पता चलता है कि वहाँ की जनता में लोकतंत्र के लिए अगाध प्रेम है और वहाँ का भविष्य प्रजातंत्र ही है।

केन्या के स्टैंडर्ड ने एक टिप्पणी में लिखा—“अनेक राजनीतिक उत्तार-चढ़ावों के बावजूद भारत के मतदाता ने लोकतंत्र को ही अन्तिम लक्ष्य माना। प्रकट है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं।”

गार्जियन के अनुसार भारतीय जनता ने एक बड़ा दांव लगाया है। इस क्रांति को राजनीतिक भूकम्प की संज्ञा देते हुए ‘गार्जियन’ ने स्वीकार किया कि

भारतीय मतदाता ने इस चुनाव के द्वारा यह पूरी तरह साबित कर दिया कि तानाशाही क्यादा नहीं चल सकती। और यह भी कि जनता का भाव आपन उसकी धज्जिया उड़ा डालता है।

इसी टेलिग्राफ की एक टिप्पणी में इस चुनाव को एक गम्भिर और युग का अन्त निरूपित किया गया। कहा गया कि गत आशाभिम्यति की निरपेक्षता और श्रीमती गांधी के ग्यारह वर्षों के सत्ताशाल और शांति के तीन वर्षों के राज्य को जनमत ने समाप्त कर दिया।

भयावह पराजय के करीब पहुँचते ही २० मार्च को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई। एक प्रमुख हिन्दी समाचारपत्र के अनुसार इस बैठक का कारण 'भावी कदम' पर विचार करना था। यही समाचारपत्र आगे सूचना देता है कि यह जानकारी करने की बहुत कोशिश की गई कि इस बैठक में प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर विचार हो रहा है या नहीं—किन्तु पता नहीं चल सका। यह बैठक घण्टों चलती रही। भीतरी तौर पर इस बैठक में काफी छीटाकझी हुई बताते हैं। ११ वर्ष ५६ दिन, जिनमें तानाशाही के बीस माह शरीक है, सत्ताहट रहने के बाद, लाचारी की हालत में श्रीमती गांधी ने २२ मार्च को सुबह १० बजे अपने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के बाद राष्ट्रपति-भवन पहुँचकर कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री बासप्पा दानप्पा ज्योती को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया।

२० माह लम्बी भयावह कालरात्रि समाप्त हुई।

सुबह के साथ, रात के चेहरे

२६ मार्च को देश की नई आजादी पर दूसरी मरकार बनी। १४ मंत्रियों के शपथ-ग्रहण के साथ पहले गैरबापेसी प्रधानमंत्री श्री मुरारजी भाई देसाई ने देश की बागडोर संभाली। यह एक नई सुबह थी, नई आशाओं और उमंगों में भरी सुबह, किन्तु इस सुबह के साथ ही रात के कितने अंधेरे अंधों ने अपने-आपको बदल कर इस रोशनी में छुपा लिया—निश्चित रूप से विरोध और विचार की बात है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि अक्सरवादी और निहित स्वार्थों वाले लोग, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और इन गिरगिटों ने हर समय देश को नुकसान पहुँचाया है।

इस सुबह के साथ ही यह सब होता शुरू हुआ, जिस क्षण तक यह पुम्पर

विश्वास और निष्ठा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, जिससे पीढ़ियाँ सबक लेती रहें।

अमरीकी राष्ट्रपति श्री जिमी कार्टर ने प्रजातंत्र के प्रति विश्वास और आस्था दिखाने पर भारत की प्रशंसा की और कहा कि भारतीय चुनाव शेष विश्व के लिए प्रेरणा-स्रोत हैं।

लोकतंत्र और तानाशाही के इस महान और शान्त युद्ध में लोकतंत्र की विजय पर सारे संसार के प्रमुख पत्रों ने जो टिप्पणियाँ कीं, वे भी इस बात की प्रमाण हैं कि श्रीमती गांधी के विश्वव्यापी शासकीय प्रचार के बावजूद समस्त संसार जानता था कि वे तानाशाह हैं। दी लंदन टाइम्स ने एक लम्बी टिप्पणी प्रकाशित करते हुए लिखा—“नेहरू वंश का शासन-काल समाप्त हो गया। मंजय गांधी के एकदम उभर आने से नेहरू वंश के सत्तारूढ़ रहने का खतरा बढ़ गया था। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय मतदाता संसदीय प्रणाली में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहता है और वह यह भी नहीं सह सकता कि समाचारपत्रों पर सेंसर लगाकर सत्य का गला घोंटा जाए या बिना मुकदमा चलाए किसीको भी जेल में डाल दिया जाए।

ऑस्ट्रेलिया से प्रकाशित होने वाले सिडनी मॉनिंग हेराल्ड ने लिखा—“इस महान मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जन लम्बे समय से चले आ रहे कांग्रेस प्रशासन से ऊब चुका था और उसे श्रीमती इन्दिरा गांधी की तानाशाही नीतियाँ तथा दमन-चक्र विलकुल पसन्द नहीं थे।” इसी पत्र ने टिप्पणी में विश्वास व्यक्त किया था कि हो सकता है नई सरकार के स्थायित्व में दिक्कतें आएँ, पर मतदाता को तानाशाही स्वीकार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ही अन्य पत्र ने लिखा—“यह भारत के आम आदमी की विजय है और विश्व-भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थायी आश्वासन भी है।”

मेलबोर्न एज ने कहा कि भारतीय चुनावों से यह पता चलता है कि वहाँ की जनता में लोकतंत्र के लिए अगाध प्रेम है और वहाँ का भविष्य प्रजातंत्र ही है।

केन्या के स्टैंडर्ड ने एक टिप्पणी में लिखा—“अनेक राजनीतिक उतार-चढ़ावों के बावजूद भारत के मतदाता ने लोकतंत्र को ही अन्तिम लक्ष्य माना। प्रकट है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं।”

गार्जियन के अनुसार भारतीय जनता ने एक बड़ा दांव लगाया है। इस क्रांति को राजनीतिक भूकम्प की संज्ञा देते हुए ‘गार्जियन’ ने स्वीकार किया कि

भारतीय मतदाता ने इस चुनाव के द्वारा यह पूरी तरह साबित कर दिया कि तानाशाही ज्यादा नहीं चल सकती। और यह भी कि जनता का शांत आश्रय उसकी धृजियाँ उड़ा डालता है।

डेमो टेलिफ़ोन की एक टिप्पणी में इस चुनाव को एक ग़लत समय और युग का अन्त निरूपित किया गया। कहा गया कि ग़त आपातस्थिति की निरवृत्ति और श्रीमती गांधी के ग्यारह वर्षों के सत्ताकाल और कांग्रेस के तीस वर्षों के राज्य को जनमन में समाप्त कर दिया।

भयावह पराजय के करीब पहुंचते ही २० मार्च को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई। एक प्रमुख हिन्दी समाचारपत्र के अनुसार इस बैठक का कारण 'भावो कदम' पर विचार करना था। यही समाचारपत्र आगे सूचना देता है कि यह जानकारी करने की बहुत कोशिश की गई कि इस बैठक में प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े पर विचार हो रहा है या नहीं—किन्तु पता नहीं चल सका। यह बैठक घण्टी चलती रही। भीतरी तौर पर इस बैठक में काफी छीटाकगी हुई बताते हैं। ११ वर्ष ५६ दिन, जिसमें तानाशाही के बीस माह शरीक है, सत्तामय रहने के बाद, साक्षरी की हालत में श्रीमती गांधी ने २२ मार्च को सुबह १० बजे अपने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के बाद राष्ट्रपति-भवन पहुंचकर कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री वासुधा दानप्पा जत्ती को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया।

२० माह लम्बी भयावह कालरात्रि समाप्त हुई।

सुबह के साथ, रात के चेहरे

२६ मार्च को देश की नई आज़ादी पर दूसरी मरकार बनी। १४ मंत्रियों के शपथ-ग्रहण के साथ पहले गैरकांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मुरारजी भाई देसाई ने देश की वागडोर सभानी। यह एक नई सुबह थी, नई आशाओं और उमंगों में भरी सुबह, किन्तु इस सुबह के साथ ही रात के कितने अंधेरे धब्बों ने अपने-आपको बदल कर इस रोगनी में छुपा लिया—निश्चित रूप से विश्लेषण और विचार की बात है। यह एक ऐतिहासिक मत्व है कि अबमरवादी और निहित स्वार्थी माने लोग, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और इन गिरगिटों ने हर समय देश को नुस्सान पहुंचाया है।

इस सुबह के साथ ही यह सब होना शुरू हुआ, जिस क्षण तक यह पुस्तक

प्रेस में जा रही है, उस क्षण तक गिरगिट रंग बदल रहे हैं। जाने कितने लेखक, कलाकार, राजनीतिज्ञ, अभिनेता, संपादक और अधिकारी मैंने रंग बदलते हुए देखे हैं—वे ही, जो कभी तानाशाही के हाथों में चाकू-छुरों की तरह रहकर जनता के शरीर, आत्मा और विश्वास पर प्रहार करते रहे थे। चूँकि उस समय तक जनता पार्टी की विधिवत् स्थापना नहीं हुई थी, और उसमें जनसंघ, संगठन कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल और समाजवादी पार्टी एकजुट थे, अतः यह कहते भी मैंने बहुतों को नुना कि उन्होंने अमुक दल के साथ रहकर मौन सेवा की या फिर अमुक दल के विचारों से वे जुड़े हुए थे अथवा जयप्रकाशजी की क्रांति के प्रति मौन समर्पण किए हुए थे। बहुत हैरानी की बात यह थी इन्हीं लोगों को मैंने कभी टेलिविज़न और रेडियो पर आपातकालीन स्थिति तथा श्रीमती गांधी का समर्थन करते देखा था और कभी सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखकर, या मंच में भाषण करते हुए अथवा नाटक करके आपातकाल रूपी जन-क्रांति के समर्थन का गीत गाने पाया था।

२३ या २४ अप्रैल को मुझे 'रसकलश' नामक एक संस्था द्वारा 'आपात-कालीन स्थितियाँ और साहित्यकार' विषय पर चर्चागोष्ठी में बुलाया गया। इस गोष्ठी के संयोजक थे सर्वश्री राजेन्द्र अवस्थी, मनोहरश्याम जोशी और लक्ष्मीनारायण लाल। जब यह निमंत्रण कार्ड मुझे मिला तो चकित भाव से कुछ क्षण मैं उसे देखता ही रह गया था। मुझे लगा था कि एक बार फिर वही मिलमिला धुलू हो गया है, जो कभी आपातकाल में था। यह कि जो जितने जोर से आपातकाल का समर्थन करेगा उतने जोर से 'सरकारी नज़र' में आ जाएगा। इस बार रख बदलकर अन्तर यह होना था कि जो जितने जोर से आपातकाल का विरोध करेगा, उतने जोर से सरकार की नज़र में आ जाएगा। मैंने निश्चय किया था कि इस तरह की 'भड़ती गोष्ठी' में मैं भाग नहीं लूंगा। बाद में इस गोष्ठी के क्रांतिकारी नमाचार (?) मुझे सुदर्शन चौपड़ा से सुनने को मिले। वतलाया गया कि इस गोष्ठी में लेखकों में खासी तू-तू मैं-मैं हुई और चर्चा का विषय आपातकालीन स्थितियाँ और साहित्यकार न रहकर आपात-कालीन भड़कियाँ और साहित्यकार हो गया। इस चर्चा के अनुसार कुछ आयोजकों पर कुछ साहित्यकारों ने यह आरोप लगाया कि आज वे आपात-कालीन तानाशाही ग्य की आलोचना कर रहे हैं, किन्तु उस समय उनका महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रचेता सम्पादक-लेखक कहाँ गायब हो गया था, जब वे दोन बजा-बजाकर उस सबका समर्थन कर रहे थे। श्री रमेश गौड़ ने आश्चर्य

मतदाताओं की संख्या का तोला-दो तोला भी नहीं निकलता। इस सत्य को हिन्दी लेखक स्वयं जानते हैं। श्री अमृतराय बीच में कहते हैं—यह कहा होता कि अधिकांश लेखक मौन रहे कारण बतलाया है कि मैं समझता हूँ कि इस बीच भी काफी कुछ लिखा गया है, प्रतिबन्धों के रहते छप नहीं सकता था, इसलिए नहीं छपा। आगे कहते हैं : अब धीरे-धीरे सामने आएगा। क्या फिर भी हिन्दी के अधिकांश लेखक चापलूस हैं ?

एक तरफ अमृतरायजी कह गए हैं कि अधिकांश लेखक मौन रहे, दूसरी तरफ कहते हैं कि इस बीच काफी कुछ लिखा गया, तीसरी ओर बतलाते हैं कि अब धीरे-धीरे सामने आएगा। ये बातें बहुत समझ में आने वाली तो नहीं हैं। आ भी जाएं तो मानी जानेवाली नहीं हैं और आपातकाल के बाद जिस तरह इन सम्पादकीय टिप्पणियों के साथ कविताएं, लेख, कहानियां छप रहे हैं कि यह अमुक कवि या लेखक साहब की आपातकालीन मनस्थिति थी, उससे लगता है कि जयप्रकाशजी की समग्र क्रांति हिन्दी लेखक अब कर रहा है। यह कहकर भी हिन्दी लेखक बच नहीं सकता कि उसने मौन धारण कर लिया। क्यों किया ? अगर वह सचमुच इन्कलाबी था, सच का पहचान था तो उसने चौराहे-चौराहे नागार्जुन की तरह कविताएं क्यों नहीं सुनाई ? कोई कुछ छापने को नैयार न था, तैसरके भय के कारण, तो उसने स्वयं क्यों नहीं कहा, सुनाया ? दुश्मन तो यह है कि अब वह मुखौटा बदलकर कागजी विद्रोह कर रहा है। इस तरह शहीदी मिलने से तो रही। अमृतरायजी के इस पत्र का उत्तर देते हुए इनी अंक में श्रीमती भागवत का पत्र भी 'धर्मयुग' ने छपा है। इस पत्र में बड़े जालीन ढंग से वह कहती है—“अमृतजी ने जो जानकारी हमें इमरजेंसी के दौरान हिन्दी लेखकों के बारे में दी है, उसके बारे में पूरी तरह मेरा जानना तो दूर की बात है, यहां के अधिकांश हिन्दी लेखकों और पत्रकारों को भी उसकी जानकारी नहीं थी।” लगता है अब अमृतरायजी को दूसरा पत्र लिखना पड़ेगा क्योंकि श्रीमती भागवत कभी प्रहार कर देती हैं, कभी चिजंटो ले लेती हैं।

यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। अच्छा तो यह है कि हिन्दी लेखक-पत्रकार स्वीकार लें, कि उनका मौन भी ठीक नहीं था, वगैरह कि सचमुच मौन था। 'तोला-दो तोला श्रेय ही सही' इस भाव से शहीदी न बटोरें। यों

भी श्राति तोल, मासे-रस्ती से नहीं होती। अगर होती, तो कभी भी हो गई होती। यहां मैं एक और हिन्दी लेखक की ईमानदार कलमबयानी लिखना चाहूंगा और इस सराहना-प्रशंसा के साथ लिखना चाहूंगा कि अधिकांश में न सही कुछ में इतना आत्मबल अवश्य है कि वे सत्य को स्वीकार लें :

शरद जोशी ने एक टिप्पणीनुमा लेख में लिखा है—“श्रीमती दुर्गा भागवत का यह कहना गलत है कि आपातकाल में हिन्दी लेखक सरकार के चापलूस हो गए। हम पहले से थे। हिन्दी के अधिकांश लेखक सरकारी, अर्ध सरकारी या मरकाजी महायत्ता प्राप्त मस्या में नौकरी करते हैं अथवा प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं अतः चापलूसी उनके सेवाधर्म का अंग है। आपातकाल में इसी काम में प्रगति हुई है।”

शरद जोशी ने आगे लिखा है—“वे (हिन्दी लेखक—भ्रमर) हमेशा उच्च सत्ताधारियों की राजशुओं के वकील रहे हैं। वे आम आदमी की तलाश के नारे लगाते हैं, पर इस चुनाव में आम आदमी ने जब अपना मत व्यक्त किया तो वे उरम्पित होने पर भी पहचानने में इन्कार करते हैं। हिन्दी माहित्य माजिनों का एक लम्बा सिलसिला है। श्रीमती भागवत परेशान न हों।”

आपातकाल और लेखकीय मन्दर्भ की बात खली है तो यहां मैं कुछ ऐसे लोगों की चर्चा करना चाहूंगा, जिन्हें अमृतराय अपने लेख में गिनाना भूल गए। क्या इसलिए कि ऐसे लोगों ने न तो हिन्दी या अंग्रेजी में अपना लेखकीय या पत्रकारीय नाम-बेहरा उजागर करवाने के लिए कोई आंदोलन चलाया है, न ही किसी तरह का दौंग-धतूरा करके हिन्दी भाषा की ठेकेदारी की है?

ये नाम हैं सर्वश्री बालेश्वर प्रसाद, दीनानाथ मिश्र, भानुप्रताप शुक्ल और बेशप्रकाश भाटिया। दीनानाथ जी मिश्र पर विभिन्न आरोप थे। गवर्नेर बहा आगे पठा कि ‘पाचजन्य’ के सम्पादन के दौरान और बाद में वह जनता का तानाशाही के विरुद्ध भड़काने की गुस्ताखी कर रहे थे। उन्हें दो बार गिरफ्तार किया गया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया। जुलाई, १९७४ में लगा-तार आठ महीने तक मिश्रजी अण्डरग्राउण्ड रहे और उस बीच उन्होंने ‘त्राति-सम्बन्धी माहित्य प्रकाशित करवाकर घर-घर पटुचाया तथा जनवाणी’ नामक एक पत्र का सम्पादन आपातकाल के अन्त तक किया। जिन दिनों मिश्रजी अण्डरग्राउण्ड थे, उन दिनों मुझे पता चला था कि वह अनेक विदेशी पत्रकारों तथा मूनिंगव त्रानिकारियों की भेंटें गुप्तरूप में आयोजित किया करने थे। इसी तरह श्री भानुप्रताप शुक्ल त्रानिकारी माहित्य की प्रकाशन-वितरण

व्यवस्था किया करते थे। श्री शुक्ल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भूमिगत छात्र आन्दोलन का भी आयोजन करते रहे थे। श्री वेदप्रकाश भाटिया भी भूमिगत साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन का कार्य देख रहे थे। उन्होंने उस दौरान 'सत्य समाचार' नामक एक पत्र का सम्पादन भी किया। वालेश्वरजी न मालूम तानाशाही की किस भूल के कारण छूटे रह गए थे और तानाशाही को ज्ञात नहीं था कि उनका सम्पर्क निरन्तर सभीसे रहा। 'भारतीय साहित्य परिषद्' की केवल दिल्ली कार्यसमिति की बैठक के १८ सदस्यों में से १४ आन्दोलन के दौरान जेल में रहे, जबकि ४ सदस्य अपनी नौकरी से मुअत्तिल पड़े रहे।

अपने पत्र में श्री अमृतराय के पास सही तरह गिना पाने के लिए हिन्दी पत्रकारों-लेखकों के नाम नहीं थे, अतः उनकी सूची उपर्युक्त नामों से बढ़ा रहा हूँ। ताकि सम्पादक के नाम अगला कोई पत्र लिखने में उन्हें सुविधा हो।

दूसरी आजादी ने यदि एक ओर कांग्रेस को चौखला दिया था तो दूसरी ओर उन मुखौटाधारियों को भी गहरी चोट पहुंची थी जो अवसरवाद में देश की जनता से गद्दारी करते रहे थे। सत्ताशक्ति और तानाशाही के अन्त का परिणाम तुरन्त ही कांग्रेस में देखा जाने लगा। जिस तरह कार्यसमिति की बैठकों में परस्पर दोषारोपण हुए, लोगों का रख-निकाल चला, पत्रों में वक्तव्य-बाजी प्रारम्भ हुई, श्रीमती गांधी ने कुछ दिनों तक 'संन्यास' लिए रहने की नाटकीय घोषणा की, फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मतदानबाजी हुई, उससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि पराजय का एक थपेड़ा भी कांग्रेस नहीं सह पाई है। क्या वह वही कांग्रेस है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लाठियों, गोलियों से टूटना तो दूर, लड़खड़ाती तक नहीं रही थी। अचरज से सारी दुनिया देख रही थी। क्या यह वही कांग्रेस है, जिसने संघर्ष की लम्बी मिताल कायम की थी?

यह कांग्रेस वह नहीं थी ! कांग्रेस के नाम से जिस दल रूपी सत्तासमुद्र में ज्वार आया था, उसने मर्यादा और अनुशासन के सारे कूल-किनारे तोड़ डाले थे। यही नहीं, बेहद हल्के और अमर्यादित शब्दों में कांग्रेस के दिग्गज एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने में लग गए थे। क्या इसलिए कि सत्ता-समझौता ही उन्हें एक किए हुए था ? क्या इसलिए कि जनता के शिष्ट श्क्लाव ने उनके स्वार्थों के सारे महल धराशायी कर दिए थे ? क्या इसलिए कि सत्ता चिन्तक जाने के कारण अचानक ही उनके कारनामों का वहीखाता जो दो

नम्बर का था और जिसे अब तक जनता में नहीं रखा गया था—सामने आने को हो गया था ?

आजाद देश की नई सरकार जब तानाशाही के दाग मिटाने में व्यस्त थी, तब कांग्रेस दल परस्पर आरोप करने में जुटा हुआ था। आपातकाल में अकारण ही प्रतिबन्धित कर दिए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों से प्रतिबन्ध उठाया गया। देश-भर की जेलों में बिना आरोप, मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिए गए नागरिकों की रिहाई शुरू हुई। 'आंसुका' में लगभग माछे तीन हजार व्यक्ति जेलों में पड़े हुए थे, उन्हें छोड़ा गया, प्रेस सेंसरशिप खत्म की गई ताकि लोकतन्त्र सत्य रूप में चल सके।

इधर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस की पराजय पर जब विचार-विमर्श हुआ, तब वे कई सदस्य, जो श्रीमती गांधी के सत्ताकाल में खामोश बैठे रहते थे, अचानक उबलकर सत्य बखानने लगे। इस कार्यसमिति में हरियाणा के श्री बंसीलाल के सम्बन्ध में खामी चूखचू रही। अनेक सदस्यों ने विचार व्यक्त किए और अन्त में एक प्रस्ताव के जरिये श्री बंसीलाल को छह वर्ष के लिए पार्टी, उसकी ममस्त समितियों और कांग्रेस की सदस्यता से निष्कामित कर दिया गया। श्री मजय गांधी, विद्याचरण शुक्ल और आंम मेहता को लेकर भी आलोचना हुई, किन्तु श्री गांधी के बारे में इसलिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने पहले ही दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, जबकि श्री विद्याचरण शुक्ल के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि उन्हें मत्ता के दुरुपयोग के आरोप में प्रताड़ित किया जाना चाहिए। आंम मेहता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श नहीं हुआ।

कांग्रेस : आत्मपरीक्षण की राजनीति

निस्सन्देह यह सबसे दुखद सत्य है कि जबरदस्त पराजय के बावजूद कांग्रेस नाथी भारत के पिछड़े मत्तारूढ़ दल के मोचने-समझने में तनिक भी अन्तर नहीं आया और निरन्तर यह दोहराया जाता रहा कि कांग्रेस इसीलिए नहीं हारी कि उसकी नीतियां गलत थी, बल्कि उनके क्रियान्वयन में दोष था। जब कांग्रेस के उच्चस्तरीय नेताओं के मुह से 'नीतियां' की बात सुनता हू तो लगता है कि वे अपने साथ ही नहीं, भारे देश की उस जनता के साथ, जिमने पिनीनी तानाशाही का दमनचक्र झेला था, क्रूर मजाक कर रहे हैं। क्या ताना-

जाही का नाम नीति है ? क्या बिना मुकदमे चलाए अकारण ही लोगों लोगों को जेल में सजा देना नीति है ? क्या विरोधी पक्ष को ताड़ित, अपमानित करते हुए सूरतापूर्वक दमन करना नीति है ? निजी स्वार्थों के राजगृह बनाना और कुछ खास लोगों को अपने लिए जन-भ्रम और सत्ताशक्ति का उपयोग करना नीति हो सकती है ? पर अफमोस 'कांग्रेस महासमिति' के अधिवेशन में जबकि कांग्रेस की हार के कारणों पर तथाकथित 'गुला बिनार' चल रहा था, अनेक नेता कह रहे थे कि बात उस तरह नहीं है, जिस तरह समझी जा रही है, बल्कि बात उम तरह है, जिस तरह वह (यानी नेता) समझा रहे है।

एक ओर यदि श्री गणपन्तराय चव्हाण ने तुलसी के साथ इस सत्य को स्वीकारा कि "कांग्रेस की पराजय अपनी नीतियों और परम्पराओं से हटने के कारण हुई है, तथा हमें यह देखना होगा कि भविष्य में हम अपने सिद्धांतों को न भूलें," तो दूसरी ओर श्रीमती गांधी ने कहा कि "कांग्रेसियों को हार से निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम यह समझते हैं कि भारत के नवनिर्माण की जो मुख्य आवश्यकता हमने रखी है, उसे किसीके लिए भी तोड़ना आसान नहीं है।"

इस समय पर तीसरी ओर कांग्रेस की भीतरी गुटबाजी और छिछोरी राजनीति का प्रदर्शन भी हो रहा था। जिसमें चुनावों की भयावह हार की हताश मनस्थिति में महाधिवेशन के दौरान हर भाषण में गुटबाजी, अधिकार प्रवृत्ति और व्यंग्य होते रहे। बैठक के प्रारम्भ में ही हंगामा हो गया। शोर, भीम-पुकार तथा धीमलाहट से भरे वातावरण में कुछ नेता समय की पुकार पर मुकता करने, मन की गौरवशाली परम्परा बनाए रखने और बड़ों की बात सुनने का उपदेश देते रहे।

कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए जिस सीमा तक हल्के आरोप-प्रत्यारोप हुए, श्रीमती गांधी और कांग्रेसमिति के पुराने लोगों तक दोड़ें चलती रहीं, ये भी गहरी स्पष्ट करती है कि कांग्रेस का सत्तारव्यवस्था समाप्त होते ही षायद ज्यादातर कांग्रेसी समझ रहे हैं कि उनका "सब कुछ धीत गया !"

जिन दिनों कांग्रेसी मेमे में यह उग्राड़-पछाड़ चल रही थी (और अब तक चल रही है) उन्ही दिनों नया लोकतांत्रिक दम सम्पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ देश को रक्षायी प्रणामन देने की लगभग सम्पूर्णता पा चुका था। पहली मई, १९७७ को जनता पार्टी के प्रथम महाधिवेशन में जनसंग, संगठन कांग्रेस,

भारतीय प्रातिदस, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस फार डेमोक्रेसी ने अपने-आपको 'जनता पार्टी' में विलीन करते हुए अपना-अपना पृथक् अस्तित्व समाप्त कर लिया। उन्होंने सर्वसम्मति से युवा नेता श्री चन्द्रशेखर को अपना अध्यक्ष चुना। जनता पार्टी की लोकतांत्रिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का विवरण देते हुए विद्रोही युवा नेता चन्द्रशेखर ने जनता को विश्वास दिलाया कि पार्टी देश में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का अस्त्र बनेगी।

जनता पार्टी के कई लोगों से बातचीत में मैंने महसूस किया कि वे कांग्रेस में चुनाव के उपरान्त हो रही गुटबन्दी और छीछालेदर से न सिर्फ दुखी हैं, बल्कि निराश हुए हैं। एक नेता ने तो यहां तक कहा कि "कांग्रेस दल भीतरी तौर पर कुछ गुमटिया^१ बनकर रह गया है और ये गुमटियां न केवल दल के अपने लिए घातक हैं, बल्कि देश के लिए भी घातक हैं, क्योंकि हम लोग (जनता पार्टी — भ्रमर) कांग्रेस से एक बढ़िया विरोधी दल की आशा करते थे, ताकि उसके विचारों से भी प्रशासन लाभान्वित हो। इसके विपरीत हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस केवल एक-दूसरे की टांग खींचने का अखाड़ा बन गया है।"

एक और तरह लगभग यही बात जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर के उस अनुरोध में भी दीखती है, जो उन्होंने कांग्रेस दल से किया। ४ मई को उन्होंने कहा—'कांग्रेस को चाहिए कि वह अपनी गलतियां स्वीकार करे और जनसेवा की दृष्टि से लोकतांत्रिक मंगठन के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार उनकी पार्टी में 'आत्म-परीक्षण' हो रहा है, लेकिन उसका वास्तविक प्रमाण कहीं देखने को नहीं मिलता। कुछ व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्ति पुराने ढंग की राजनीति में ही व्यस्त हैं। इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि उन्हें अपने किए-कराए पर पश्चात्ताप हो रहा है, यदि उन्होंने अपना यही रुख जारी रखा तो वह देश और पार्टी के लिए— जिसका कि देश की प्रतिविम्ब प्रगति में योगदान कम नहीं होगा—अच्छा नहीं होगा।"

१ गुमटियां : ऊबड़-खाबड़ धरती में जहां-तहां छिदरे हुए छोटे-छोटे टीले, जो न भिफं भरे दीखते हैं, बल्कि अनुपयोगी भी होते हैं। गुमटियों का जो बेतरतीब धरती पर पड़ने पंदा नहीं हो सकती।

दूसरी आज़ादी : कुछ खतरे

तानाशाही की वर्चस्वता का देश ने खूब ज़ायका ले लिया है। कभी-कभी लगता है कि एक पहलू से यह अच्छा ही हुआ है। ऐसा न होता तो संभवतः हम उस अधिकचरेपन में ही 'शुभ' की कल्पना-स्वप्न संजोए रहते, जिस कल्पना-स्वप्न में हमने पिछले तीस वरसों में पूरी एक पीढ़ी गंवा दी। शायद सत्ता पर बैठे लोग नारों से हमें ठगते रहते और मानसिक-आर्थिक शोषण की प्रक्रिया उसी तरह चलती जाती। हमने एक नई चेतना और नये विश्वास को पाया है। भारतीय जनमानस ने ज़बरदस्त बहुमत देकर एक बार पुनः लोकतंत्र को पुनर्जीवित कर दिया है, किन्तु कई बार 'शुभ' भी अन्धविश्वास बन जाता है। जैसाकि वयोवृद्ध जननेता आचार्य कृपलानी ने जनता पार्टी के विशाल बहुमत में आने के बाद हुई आम सभा में कहा था कि "राजनेता सामान्य मनुष्य होता है और उसमें वे सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, जो एक मनुष्य में होती हैं, अतः उसपर अंकुश रहना चाहिए। उसे अन्धविश्वास सौंपकर 'देवता' बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।" एक यथार्थवादी विश्लेषण है।

१९७१ के आमचुनाव में लगभग यही विश्वास देकर श्रीमती गांधी और उनकी कांग्रेस को भारतीय मतदाता ने विजयश्री दी थी, पर जब यही विश्वास अन्धविश्वास में बदल गया तो यह विजयश्री अंध सत्ताशक्ति के आधार पर तानाशाही में परिवर्तित हो गई। पिछले ३० वर्षों के कांग्रेस-काल में यदि जनता ने कांग्रेस के प्रति 'केवल विश्वास' रखा होता, उसे अंधविश्वास न बनने दिया होता, तो इन्दिराजी अपने व्यक्तिवाद को तानाशाही की ओर न ले जा पातीं और न ही तत्स्त भारतीय जन-मन को आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती। श्रीमती गांधी का सत्ताकाल, विशेष रूप से आपातकाल, एक शिक्षा है भारतीय लोकतंत्र और जनमानस के लिए—अगर उससे इतिहास रूप में जानकर सीखा-समझा जा सका तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा।

सहज मानवीय कमज़ोरियों के लिए मात्र दोष देते रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, गाहे-बगाहे उन कमज़ोरियों की ओर अपनों का और अपना ध्यान दिलाते रहना। मतदान करके ही मतदाता अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता, बल्कि उसपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, यह देखना कि उसके मतदान से विजयी हुआ उसका

प्रतिनिधि, या प्रतिनिधि दल क्या कर रहा है। यह ऐसी ही सामान्य प्रक्रिया है, जेने परिवार के मुखिया को परिवार-जनों का सहयोग-सलाह और अंकुश समक्ष पर मिलते रहना। एक परिवार से लेकर सम्पूर्ण राष्ट्र तक यह सहज प्रक्रिया चरनी है। इस प्रक्रिया का अंग बने रहना न केवल परिवार, समाज स्तर पर अनिवार्य है, बल्कि लोकतन्त्र की सुरक्षा की पहली शर्त है।